ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Center University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

एमबीए पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम कोड : MBA - 01

तृतीय सेमेस्टर

पाठ्यचर्या कोड : MS- 428

पाठ्यचर्या का शीर्षक : वित्तीय सेवाओं के मूल आधार

दूर शिक्षा निदेशालय

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट- हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र)

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of1997)

विषय कोड: MS 428 **क्रेडिट्स:** 2 क्रेडिट

विषय का नाम: वित्तीय सेवाओं के मूल आधार (Fundamentals of Financial Services)

पाठ्यक्रम के उद्देश्य:

- विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्तर पर वित्त एवं निवेश नियोजन में शामिल मुद्दों को समझने में सक्षम करना तथा उनको वित्तीय मुद्दों पर सलाह देने के स्तर तक बढ़ाना।
- विद्यार्थियों को वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय सेवाओं के बारे में समझाना जिसे वे अपने व्यावहारिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं।

मूल्यांकन के मानदंड:

1. सत्रांत परीक्षा : 70 %
2. सत्रीय कार्य : 30 %

पाठ्यक्रम सामग्री:

इकाई - I: वित्तीय प्रणाली का परिचय (Introduction to Financial System)

- वित्तीय प्रणाली: प्रकृति, विकास और संरचना (The Financial System: Nature, Evolution and structure)
- **भारतीय वित्तीय प्रणाली (**The Indian Financial System**)**
- **आर्थिक विकास में वित्तीय प्रणाली की भूमिका (**The Role of Financial System in Economic Development**)**
- **वित्तीय प्रपत्र (**Financial Instruments**)**
- **वित्तीय मध्यस्थों के कार्य** (The Functions of Financial Intermediaries)
- **वित्तीय सेवायें: अर्थ, महत्व और प्रकार (**Financial Services: Meaning, Importance and Types**)**

इकाई - II: बैंकिंग की उत्पत्ति एवं विकास (The Origin and Growth of Banking)

- बैंकिंग की उत्पत्ति (The Origin of Banking)
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली (The Indian Banking system)
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI)
- **बैंकों और प्रौद्योगिकी (**Banks and technology**)**
- **अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं (**International banking services**)**

इकाई - III: बीमा क्षेत्र (Insurance Sector)

- **बीमा क्षेत्र: परिचय, परिभाषा, जरूरत और महत्व (**Insurance Sector: Introduction, Definition, Need and Importance**)**
- **जीवन एवं गैर जीवन बीमा (**Life and non life insurance**)**
- **निजी क्षेत्र के लिए बीमा क्षेत्र को खोलने के तर्क** (Rationale for opening up of the Insurance sector to Private Sector)

- **आईआरडीए अधिनियम तथा बीमा अधिनियम, 1938 का संक्षिप्त परिचय** (A brief introduction to IRDA Act. Insurance Act, 1938)

इकाई - IV: मर्चेंट बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवायें (Merchant Banking and other Financial Services)

- मर्चेंट बैंकिंग: उत्पत्ति, अर्थ और कार्य (Merchant Banking: Origin, Meaning and Functions)
- मर्चेंट बैंकर की भूमिका (Role of a merchant Bankers)
- वाणिज्यिक बैंक और मर्चेंट बैंकिंग (Commercial Banks and Merchant Banking)
- मर्चेंट बैंकरों के लिए सेबी के दिशानिर्देश (SEBI guidelines for merchant bankers)
- पूंजी बाजार और शेयर बाजार (Capital market and Stock exchange)
- सेबी की भूमिका (Role of SEBI)
- क्रेडिट रेटिंग और बिल डिस्काउंटिंग (Credit Rating and Bill Discounting)
- उद्यम पूंजी (Venture Capital)

इकाई - V: म्युचुअल फंड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स (Mutual funds and Money Market Instruments)

- **म्युचुअल फंड: संरचना, प्रकार और लाभ (**Mutual Funds: Structure, Types and Advantages**)**
- **ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक बिल (**Treasury bill and Commercial bill**)**
- **कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी (**Call money, Notice money and Term money**)**
- **क्रेडिट कार्ड (**Credit card**)**

सम्बन्धित पुस्तकें:

- Khan M.Y. (2009), Financial Services, Fifth Edition, Tata McGraw Hill, New Delhi.
- Bhole L.M, (2011). Financial Institutions and Markets, Fifth Edition, Tata McGraw Hill, New Delhi.
- Siddaiah T. (2011), Financial Services. First Edition, Pearson, New Delhi.

इकाई - I:
वित्तीय प्रणाली का परिचय
(Introduction to Financial system)

विषय सूचि

- वित्तीय प्रणाली: प्रकृति, विकास और संरचना (The Financial system: Nature, Evolution and structure)
- भारतीय वित्तीय प्रणाली (The Indian Financial System)
- आर्थिक विकास में वित्तीय प्रणाली की भूमिका (The Role of Financial system in Economic Development)
- वित्तीय प्रपत्र (Financial Instruments)
- वित्तीय मध्यस्थों के कार्य (The Functions of Financial Intermediaries)
- वित्तीय सेवायें: अर्थ, महत्व और प्रकार (Financial Services: Meaning, Importance and Types)

वित्तीय प्रणाली के एक हिस्से के रूप में वित्तीय सेवा विभिन्न क्रेडिट उपकरणों, वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वित्त प्रदान करती है। वित्तीय उपकरणों में, हम चेक, बिल, प्रोमिसरी नोट्स, ऋण उपकरण, क्रेडिट लेटर इत्यादि में आते हैं। वित्तीय उत्पादों में, हम विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंडों में आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के निवेश के अवसरों का विस्तार करते हैं। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि जैसे उत्पाद भी हैं। सेवाओं में हमारे पास लीजिंग, फैक्टरिंग, किराया खरीद वित्त इत्यादि है, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों को या तो लीज पर स्वामित्व (या) के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पट्टे के साथ-साथ फैक्टरिंग भी हैं।

इस प्रकार, वित्तीय सेवाएं उपयोगकर्ता को उनकी सुविधा और उचित ब्याज दर पर क्रेडिट पर कोई भी संपत्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। इसे परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि वित्तीय सेवाएं वित्त उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सेवाएं हैं, जिनमें क्रेडिट यूनियनों, बैंकों, क्रेडिट कार्ड कंपनियों, बीमा कंपनियों, एकाउंटेंसी कंपनियों, उपभोक्ता-वित्त कंपनियों सहित धन का प्रबंधन करने वाले व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, स्टॉक ब्रोकरेज, निवेश निधि।

उद्देश्य (या) वित्तीय सेवाओं के कार्य

निम्नलिखित वित्तीय सेवाओं के उद्देश्य हैं जिन्हें आम तौर पर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है: -

1. धन उगाहने:

वित्तीय सेवाएं कई निवेशकों, व्यक्तियों, संस्थानों और कॉर्पोरेट से आवश्यक धन जुटाने में मदद करती हैं। इस उद्देश्य के लिए, वित्त के विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। कॉर्पोरेट घरों, व्यक्तियों, आदि द्वारा धन की मांग की जाती है।

2. निधि परिनियोजन:

वित्तीय बाजारों में वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला उपलब्ध है जो खिलाड़ियों को उठाए गए धन की लाभप्रद तैनाती सुनिश्चित करने में मदद करती है। वित्तीय सेवाएं वित्त पोषण मिश्रण के संबंध में निर्णय लेने में सहायता करती हैं। धन की कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बैंक छूट वित्तीय सेवाओं फर्मों द्वारा बिल छूट, देनदारों के फैक्टरिंग, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंडों की पार्किंग, क्रेडिट रेटिंग, ई-कॉमर्स और ऋणों को सुरक्षित करने जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

3. विशिष्ट सेवाएं:

वित्तीय सेवा क्षेत्र बैंकिंग और बीमा संस्थानों और एजेंसियों के अलावा क्रेडिट रेटिंग, उद्यम पूंजी वित्तपोषण, पट्टा वित्तपोषण, फैक्टरिंग, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक लोनिंग, डिपॉजिटरी, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग फाइनेंस, बुक बिल्डिंग इत्यादि जैसी विशेष सेवाएं प्रदान करता है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज, विशेष और सामान्य वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, वित्तीय संस्थानों की सहायक, बैंक और बीमा कंपनियां इन सेवाओं को भी प्रदान करती हैं।

4. विनियमन:

ऐसी एजेंसियां हैं जो वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों के विनियमन में शामिल हैं। भारत में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंकिंग और बीमा विभाग, भारत सरकार, विधायी उपायों के माध्यम से, वित्तीय सेवा के कामकाज को नियंत्रित करते हैं संस्थानों। इसका उद्देश्य वित्तीय बाजारों के व्यवस्थित कार्य को सुनिश्चित करना है।

5. आर्थिक विकास:

वित्तीय विकास, आर्थिक विकास और विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, अच्छी तरह से योगदान देता है। यह उत्पादक निवेश में उन्हें चैनल करने के उद्देश्य से लोगों के एक पार अनुभाग की बचत के आंदोलन के माध्यम से होता है।

वित्तीय सेवाओं के लक्षण:

1. असंगतता:

वित्तीय सेवाओं की बुनियादी विशेषताएं यह है कि वे प्रकृति में अमूर्त हैं। वित्तीय सेवाओं को सफलतापूर्वक बनाया और विपणन करने के लिए, उन्हें प्रदान करने वाले संस्थानों के पास एक अच्छी छवि होनी चाहिए और अपने ग्राहकों के विश्वास का आनंद लेना चाहिए।

2. ग्राहक अभिविन्यास:

वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान विस्तार से ग्राहकों की जरूरतों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन के परिणामों के आधार पर, वे अभिनव वित्तीय रणनीतियों के साथ बाहर आते हैं जो विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए लागत, तरलता और परिपक्वता विचारों के संबंध में उचित सम्मान देते हैं। इस तरह, वित्तीय सेवाएं ग्राहक उन्मुख हैं।

3. असमानता:

वित्तीय सेवाओं के उत्पादन और आपूर्ति के कार्यों को एक साथ किया जाना है। वित्तीय सेवा फर्मों और उनके ग्राहकों के बीच एक परियोजना समझने के लिए यह कारण है।

4. नाशशीलता:

वित्तीय सेवाओं को तत्काल लक्षित ग्राहकों को बनाया और वितरित किया जाना है। वे शुरू नहीं किया जा सकता है। उन्हें ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार आपूर्ति की जानी है। इसलिए यह जरूरी है कि वित्तीय सेवाओं के प्रदाता मांग और आपूर्ति के बीच एक मैच सुनिश्चित करें।

वित्तीय सेवाओं का महत्व:

यह वित्तीय सेवाओं की उपस्थिति है जो देश को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम बनाता है जहां आर्थिक विकास की ओर अग्रसर सभी क्षेत्रों में अधिक उत्पादन होता है। आर्थिक विकास का लाभ आर्थिक समृद्धि के रूप में लोगों पर प्रतिबिंबित होता है जहां व्यक्ति में जीवन स्तर के उच्च स्तर का आनंद मिलता है।

1. निवेश को बढ़ावा देना:

उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए अधिक निवेश के लिए वित्तीय सेवाओं की उपस्थिति उत्पादों और उत्पादकों की अधिक मांग पैदा करती है। इस स्तर पर, वित्तीय सेवा नए मुद्दे बाजार के माध्यम से व्यापारी बैंकर जैसे निवेशक के बचाव के लिए आती है, जिससे निर्माता पूंजी जुटाने में सक्षम बनाता है। शेयर बाजार निवेशक द्वारा अधिक धन जुटाने में मदद करता है। विदेश से निवेश आकर्षित है। घरेलू और विदेशी दोनों फैक्टरिंग और

लीजिंग कंपनियां न केवल उत्पाद बेचने के लिए बल्कि आगे के उत्पादन के लिए आधुनिक मशीनरी / प्रौद्योगिकी हासिल करने में सक्षम बनाती हैं।

2. बचत को बढ़ावा देना:

म्यूचुअल फंड जैसी वित्तीय सेवाएं विभिन्न प्रकार की बचत के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं। वास्तव में, पेंशनभोगियों के साथ-साथ वृद्ध लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उन्हें अपनी बचत के विकास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए अधिक जोखिम के बिना उचित वापसी का आश्वासन दिया जा सके, विभिन्न पुनर्निवेश अवसर प्रदान किए जाते हैं।

3. जोखिम को कम करना:

बीमा कंपनियों की उपस्थिति से वित्तीय सेवाओं के साथ-साथ उत्पादकों दोनों का जोखिम कम हो जाता है। विभिन्न प्रकार के जोखिम शामिल हैं जो न केवल उतार-चढ़ाव वाली व्यावसायिक स्थितियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जोखिमों से भी प्रदान करते हैं। बीमा न केवल वित्त का स्रोत है बल्कि बचत को कम करने के अलावा बचत का स्रोत भी है।

4. रिटर्न को अधिकतम करना:

वित्तीय सेवाओं की उपस्थिति व्यापारियों को उनके रिटर्न को अधिकतम करने में सक्षम बनाती है। उचित दर पर क्रेडिट की उपलब्धता के कारण यह संभव है। उत्पादक संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विभिन्न प्रकार की क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मामलों में, वे बहुत अधिक मूल्य की कुछ परिसंपत्तियों के पट्टे पर भी जा सकते हैं। फैक्टरिंग कंपनियां स्रोतों के साथ-साथ निर्माता को अपनी बारी बढ़ाने के लिए सक्षम करती हैं जिससे लाभ भी बढ़ जाता है।

5. अधिक उपज सुनिश्चित करता है:

जैसा कि पहले से देखा गया है, रिटर्न और उपज के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। यह उपज है जो अधिक उत्पादकों को बाजार में प्रवेश करने और उपभोक्ता की मांगों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन में वृद्धि को आकर्षित करती है। वित्तीय सेवाएं निर्माता को न केवल अधिक मुनाफा कमाने में सक्षम बनाती हैं बल्कि उनकी संपत्ति को अधिकतम भी बनाती हैं। वित्तीय सेवाएं उनकी सद्भावना को बढ़ाती हैं और उन्हें विविधता के लिए जाने के लिए प्रेरित करती हैं। शेयर बाजार और विभिन्न प्रकार के व्युत्पन्न बाजार निवेशक के लिए उच्च उपज प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं।

6. आर्थिक विकास:

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सभी क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। वित्तीय सेवाएं सभी तीन क्षेत्रों, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक को धनराशि के बराबर वितरण सुनिश्चित करती हैं ताकि सभी तीन क्षेत्रों में गतिविधियों को संतुलित तरीके से फैलाया जा सके।

7. आर्थिक विकास:

वित्तीय सेवाएं उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं जिससे वे अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं। किराया खरीद, पट्टे और आवास वित्त कंपनियों के माध्यम से कार, घर और अन्य आवश्यक और साथ ही शानदार वस्तुओं की खरीद संभव हो गई है।

सरकार को लाभ:

वित्तीय सेवाओं की उपस्थिति सरकार को मनी मार्केट के माध्यम से राजस्व और पूंजी व्यय दोनों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक फंड दोनों को बढ़ाने में सक्षम बनाती है, सरकार ट्रेजरी बिल जारी करने से अल्पकालिक धनराशि बढ़ाती है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके जमाकर्ता के पैसे से बाहर खरीदे जाते हैं। इसके अलावा, सरकार प्रतिभूति बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा दीर्घकालिक धन जुटाने में सक्षम है जो वित्तीय बाजार का हिस्सा बनती है। विदेशी मुद्रा बाजार में भी सरकार की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

9. वित्तीय संस्थानों की गतिविधियों का विस्तार:

वित्तीय सेवाओं की उपस्थिति वित्तीय संस्थानों को न केवल वित्त पोषित करने में सक्षम बनाती है बल्कि उन्हें अपने लाभ को सबसे लाभदायक तरीके से बांटने का अवसर भी मिलती है। म्यूचुअल फंड, फैक्टरिंग, क्रेडिट कार्ड, किराया खरीद वित्त कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

10. पूंजी बाजार:

किसी भी अर्थव्यवस्था के बैरोमीटर में से एक जीवंत पूंजी बाजार की उपस्थिति है। यदि पूंजी बाजार में व्यस्त गतिविधि है, तो यह सकारात्मक आर्थिक स्थिति की उपस्थिति का संकेत है। वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करती हैं कि सभी कंपनियां उत्पादन को बढ़ावा देने और अंततः अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि हासिल करने में सक्षम हैं।

11. घरेलू और विदेशी व्यापार का प्रचार:

वित्तीय सेवाएं घरेलू और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सुनिश्चित करती हैं। फैक्टरिंग और जब्त करने वाली कंपनियों की उपस्थिति घरेलू बाजार में माल की बिक्री में वृद्धि और विदेशी बाजार में माल के निर्यात को सुनिश्चित करता है। बैंकिंग और बीमा सेवाएं आगे बढ़ती ऐसी गतिविधियों को बढ़ाने में योगदान देती हैं।

12. संतुलित क्षेत्रीय विकास:

सरकार अर्थव्यवस्था और क्षेत्रों के विकास पर नजर रखती है जो आर्थिक रूप से पिछड़े रहती हैं, उन्हें कर और सस्ता क्रेडिट के माध्यम से राजकोषीय और मौद्रिक लाभ दिया जाता है जिसके द्वारा अधिक निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। इससे अधिक उत्पादन, रोजगार, आय, मांग और अंततः कीमतों में वृद्धि होती है।

वित्तीय सेवाओं के कार्य

1. फैक्टरिंग:

फैक्टरिंग को वित्तीय संस्थान और व्यापारिक चिंता के बीच एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो क्रेडिट पर सामान बेच रहा है। एक कारक समझौते में तीन पार्टियां हैं। बचत (या) सेवर, खरीदार और कारक। खरीदार को माल बचाने के बाद, बचतकर्ता समझौते के अनुसार 3 (या) 6 महीने की अवधि के लिए बिल तैयार करता है। यह बिल उस कारक को दिया जाता है जो सेवर को बिल मूल्य का 80% तक प्रदान करेगा। कारक खरीदार से देय तिथि पर धन इकट्ठा करने का प्रयास करता है, वहां शेष राशि को बचतकर्ता को सौंप दिया जाता है। इस समारोह के लिए कारक सेवर द्वारा एक कमीशन प्रदान किया जाता है।

2. लीजिंग:

कंपनियों (या) छोटी कंपनियों को उच्च मूल्य की संपत्ति प्राप्त करने के लिए सक्षम करने के लिए, लीजिंग कंपनियों को स्थापित किया गया था। लीजिंग कंपनी संपत्ति खरीद लेगी और 10 (या) 12 साल की अवधि के लिए निर्माता को पट्टे पर देगी, कंपनी को पट्टे पर रखने वाली कंपनी को कम करने वाला और निर्माता जो उपयोग के लिए संपत्ति ले रहा है उसे लीजिंग कहा जाता है। पट्टा संपत्ति के उपयोग के लिए किराए पर किराए पर भुगतान करेगा। मूल रूप से 2 प्रकार के लीज समझौते होते हैं।

(i) वित्तीय पट्टा

(ii) ऑपरेटिंग लीज

वित्तीय पट्टा :

एक वित्तीय पट्टे एक अनुबंध है जिसमें विशिष्ट परियोजना की पूंजीगत व्यय की एक निश्चित अवधि की निश्चित अवधि पर भुगतान शामिल होता है।

परिचालन लीज़ :

उपयोग के लिए लेसी को पट्टे पर एक उपकरण खरीदा जाता है और उत्पादन किया जाता है। लेसी के पास अनुबंध रद्द करने का विकल्प होता है और साथ ही, लेसी के पास उपकरण की लागत के लिए संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का विकल्प पट्टा राशि द्वारा पूरी तरह से वसूल नहीं किया जाता है और लीज अवधि सामान्य रूप से कम होती है संपत्ति का आर्थिक जीवन।

3. जब्त करना:

यह एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत निर्यातक को बैंकों को जब्त करके अपने बिलों के खिलाफ वित्त प्रदान किया जाता है। घरेलू व्यापार में, यह विदेशी बिल की छूट निर्यातक के पक्ष में है। यह निर्यातक बैंक के बीच एक समझ है: बैंक और आयातक बैंक को जब्त करना। इसके कारण, निर्यातक निर्यात के तुरंत बाद वित्त प्राप्त करने में सक्षम हैं और खराब ऋण का खतरा समाप्त हो गया है।

4. किराया खरीद वित्त:

किराया खरीद वित्त कंपनियां 2 से 5 (या) 10 साल की अवधि से संपत्ति के खरीदारों को वित्त प्रदान करती हैं। जब कोई खरीदार एक संपत्ति खरीदने में असमर्थ होता है उदाहरण के लिए एक कार किराया खरीद वित्त कंपनियां खरीदार को वित्त प्रदान करती हैं, जो कि 24 (या) 60 महीने की अवधि में मासिक किश्त पर चुकाया जा सकता है। पुनर्भुगतान की राशि एक बराबर राशि होगी, जिसमें से इसका एक हिस्सा प्रिंसिपल के लिए लिया जाएगा और शेष ब्याज की ओर रुख की खरीद वित्त कंपनियां 10 (या) 15% की एक फ्लैट दर पर ब्याज ले रही हैं। ऋण।

5. क्रेडिट कार्ड:

यह निश्चित आय (या) मध्यम और उच्च आय वर्ग के ग्राहकों को दी गई सुविधा है। क्रेडिट कार्ड बैंकर द्वारा ग्राहक को दिया गया एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें ग्राहक के नाम ब्लॉक अक्षरों में उभरा होता है। कार्ड के नाम पर कार्ड का नाम और जारी होने और समाप्ति की तारीख का भी उल्लेख किया गया है, कार्ड के विपरीत पक्ष ग्राहक के नमूने हस्ताक्षर को सहन करेगा। विक्रेताओं (या) सेवर की एक सूची बैंकर द्वारा ग्राहकों को दी जाएगी।

6. व्यापारी बैंकिंग:

एक व्यापारी बैंकर वह है जो कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों को अंडरराइट करता है और कॉर्पोरेट विलय जैसे मुद्दों पर ग्राहकों को सलाह देता है। व्यापारी बैंकर एक बैंक के रूप में हो सकता है, एक कंपनी फर्म (या) यहां तक कि एक मालिकाना चिंता भी। यह मूल रूप से सेवा बैंकिंग है जो गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि उन्हें प्रदान करने के बजाय धन की व्यवस्था करना। व्यापारी बैंकर व्यापार की चिंताओं की आवश्यकताओं को समझता है और वित्तीय संस्थानों, बैंकों, स्टॉक एक्सचेंजों और बाजार की मदद से वित्त की व्यवस्था करता है।

7. बुक बिल्डिंग:

जब जनता को सीधे शेयरों की पेशकश करने की बजाय एक कंपनी, शेयरों की बिक्री के लिए व्यापारी बैंकरों से बोलियां आमंत्रित करती है जिसे इसे पुस्तक निर्माण कहा जाता है। व्यापारी बैंकर शेयरों के मुद्दे की पूरी ज़िम्मेदारी ले लेंगे। शेयरों की सूची आवंटित करने की पूरी प्रक्रिया व्यापारी बैंकरों द्वारा की जाएगी। शेयर मूल्य बाजार में शेयरों की मांग पर निर्भर करता है।

8. संपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम):

यह बैंकों द्वारा संपत्तियों से उनकी देयता को समायोजित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है, जो सुरक्षा, तरलता और लाभप्रदता की तीन स्थितियों को अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जमाकर्ताओं से पैसा प्राप्त करने वाला एक बैंक निवेश (या) विभिन्न प्रकार के ऋणों के grating के लिए जाएगा।

बैंक इस तरह की संपत्तियों को पसंद करेगा (निवेश (या) उधार देने के दौरान) जिसमें सुरक्षा, तरलता और लाभप्रदता होगी। ऐसी कंपनियां हैं जो बैंकों को संपत्ति और देनदारियों को एक विश्वसनीय तरीके से प्रबंधित करने में सहायता करती हैं।

9. आवास वित्त:

आवास वित्त न केवल लोकप्रिय हो गया है। लेकिन ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और आवास घरों के लिए आवास ऋण आसानी से उपलब्ध कराए जाते हैं। परिवर्तन के कारण यह केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों की आवास नीति है। वाणिज्यिक बैंकों ने आवास वित्त में प्रवेश किया है। वास्तव में भारतीय स्टेट बैंक ने आवास वित्त के लिए एक अलग सहायक कंपनी की स्थापना की है। उद्देश्य के लिए 25 से 40 वर्षों में विश्व बैंक सॉफ्ट लोन चुकाना प्रदान कर रहा है।

10. पोर्टफोलियो वित्त:

पोर्टफोलियो वित्त पोर्टफोलियो निवेश के प्रबंधन के साथ सौदा करता है। पोर्टफोलियो प्रबंधन में शामिल एक कंपनी एक व्यक्ति (या) कंपनी के निवेश का प्रबंधन करने के लिए उपक्रम करती है, निवेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, निवेश पर बेहतर वापसी सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार पोर्टफोलियो वित्त में विभिन्न शेयरों (या) प्रतिभूतियों में वित्त बाजार और विशेष प्रतिभूतियों के विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां और निवेश ट्रस्ट कंपनियां पोर्टफोलियो वित्त का बहुत अच्छा उदाहरण हैं। वे व्यक्तियों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्त कंपनियों को विभिन्न पोर्टफोलियो में अपना निवेश वितरित करने में मदद करते हैं। पोर्टफोलियो प्रबंधन में शेयर डिबेंचर, सरकारी प्रतिभूतियां, वाणिज्यिक पेपर, बॉन्ड, ग्लोबल डिपॉजिट रसीद और अन्य निवेश प्रतिभूतियों जैसे कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंफ्रा स्ट्रक्चर बॉन्ड इत्यादि में निवेश शामिल है।

11. लेखन के तहत:

लेखन के तहत एक सार्वजनिक सीमित कंपनी द्वारा जारी कुछ न्यूनतम शेयरों और डिबेंचरों की बिक्री के लिए संगठन द्वारा गारंटी का एक अधिनियम है। कंपनियों के अधिनियम के मुताबिक, जब कोई व्यक्ति अंडरराइटिंग समझौते में निर्दिष्ट शेयरों को लेने के लिए सहमत होता है, जब सार्वजनिक (या) अन्य उनके लिए सदस्यता लेने में विफल रहते हैं, तो इसे अंडरराइटिंग अनुबंध कहा जाता है। इस उद्देश्य के लिए अंडरराइटर जो शेयरों की बिक्री के लिए गारंटी देता है उसे कमीशन दिया जाता है।

12. क्रेडिट रेटिंग:

यह एक कंपनी के उधारकर्ता (या) की क्रेडिट योग्यता का निर्धारण करने का एक तरीका है जिसमें निवेश को उधारकर्ता कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पिछले वर्ष, तरलता की स्थिति, बाजार हिस्सेदारी के आधार पर किया जाता है। जमा की कंपनी पुनर्भुगतान, कमाई मुनाफा, जमा और संपत्ति पोर्टफोलियो आदि पर ब्याज की पेशकश।

13. ब्याज और क्रेडिट स्वैप:

दो प्रकार की ब्याज दर निश्चित ब्याज दर और फ्लोटिंग ब्याज दर है। सावधि ब्याज दर पूरे ऋण के लिए लागू होती है जबकि ब्याज दर में ब्याज दर बदलती है। ब्याज स्वैप एक तरीका है जहां एक व्यक्ति जिसने उच्च ब्याज दर के साथ ऋण लिया है, वह अपने पिछले ऋण को नई फ्लोटिंग दर पर ले कर ब्याज की निम्न दर का लाभ लेना चाहता है, जिसमें कम ब्याज दर है।

जब किसी नए ऋण को ब्याज दर पर एक नए ऋण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे पुराने लेनदार की जगह लेने वाले नए लेनदारों की वजह से ब्याज स्वैप और क्रेडिट स्वैप भी कहा जाता है

14. म्यूचुअल फंड:

एक म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी है जो कई लोगों से मिलती है और निवेश करती है कि यह स्टॉक बॉन्ड (या) संपत्ति है। स्टॉक बॉन्ड (या) अन्य परिसंपत्तियों के संयुक्त होल्डिंग्स को फंड का मालिकाना पोर्टफोलियो के रूप में जाना जाता है। फंड में प्रत्येक निवेशक शेयर का मालिक है, जो इन होल्डिंग्स के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड एंड क्लोज-एंड फंड प्रदान करता है। ओपन एंड फंड को खुले रखा जाता है और निवेशकों के पास किसी भी समय और विकल्प पसंद करने का विकल्प होता है। लेकिन बंद-अंतराल फंड में समय और राशि की सीमा है और यह सुनिश्चित करता है कि म्यूचुअल फंड बेहतर रिटर्न प्राप्त करे। इसके अलावा विकास भी है। ओरिएंटेड फंड जो ग्राहकों द्वारा रिटर्न का पुनर्वितरण करता है ताकि भविष्य की तारीख पर उन्हें उच्च रिटर्न मिल सके। कर लाभ फंड के मामले में निवेश पर मिलने वाली वापसी के लिए कर राहत होती है।

भारतीय वित्तीय प्रणाली

किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली वित्तीय बाजार, वित्तीय मध्यस्थता और वित्तीय साधनों या वित्तीय उत्पादों के होते हैं। यह पत्र वित्त और भारतीय वित्तीय प्रणाली और वित्तीय बाजार, वित्तीय मध्यस्थों और वित्तीय साधनों पर ध्यान केंद्रित का अर्थ पर चर्चा करता है। विभिन्न मुद्रा बाजारलिखतों पर संक्षिप्त समीक्षा भी इस अध्ययन में शामिल रहे हैं।

शब्द 'वित्त' हमारी साधारण समझ में यह समकक्ष 'मनी' के रूप में माना जाता है। हम पैसे और अर्थशास्त्र में बैंकिंग के बारे में, मौद्रिक सिद्धांत और व्यवहार के बारे में और 'सार्वजनिक वित्त' के बारे में पढ़ें। लेकिन वित्त बिल्कुल पैसे नहीं है, यह एक विशेष गतिविधि के लिए धन उपलब्ध कराने का स्रोत है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त सरकार के साथ पैसे मतलब यह नहीं है, लेकिन यह एक सरकार के कार्यों और गतिविधियों के लिए राजस्व बढ़ाने के स्रोतों को संदर्भित करता है। यहाँ कुछ शब्द की परिभाषा का दोनों एक स्रोत के रूप में और के रूप में एक गतिविधि के एक संज्ञा और एक क्रिया के रूप में यानी वित्त'।

किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में विभिन्न आर्थिक इकाइयों, मोटे तौर पर निगमित क्षेत्र, सरकार औरघरेलू क्षेत्र में वर्गीकृत की प्रगति द्वारा परिलक्षित होता है। उनकी गतिविधियों के प्रदर्शन करतेसमय इन इकाइयों एक अधिशेष/घाटा/संतुलित बजट स्थितियों में रखा जाएगा। क्षेत्रों या लोगअधिशेष निधियों के साथ कर रहे हैं और वहाँ उन के घाटे के साथ कर रहे हैं। एक वित्तीय प्रणालीया वित्तीय क्षेत्र एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और घाटे के क्षेत्रों के लिए अधिशेष के क्षेत्रोंसे धन के प्रवाह की सुविधा। एक वित्तीय प्रणाली विभिन्न संस्थानों, बाजारों, विनियमों औरकानूनों, प्रथाओं, पैसे प्रबंधक, विश्लेषकों, लेन-देन और दावों और देयताओं की संरचना है।

वित्तीय प्रणाली

शब्द 'सिस्टम', 'वित्तीय प्रणाली', शब्द में जटिल और बारीकी से कनेक्टेड रहने या संस्थानों, एजेंटों, प्रथाओं, बाजार, लेन-देन, दावों और अर्थव्यवस्था में दायित्वों का एक सेट निकलता है। वित्तीय प्रणाली पैसे के बारे में चिंतित है, क्रेडिट और वित्त-तीन शर्तें अच्छी तरह संबंधित हैं अभी तक एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली वित्तीय बाजार, वित्तीय साधनोंऔर वित्तीय मध्यस्थता के होते हैं। ये संक्षेप में नीचे चर्चा कर रहे हैं-

वित्तीय बाजार

एक वित्तीय बाजार में जो वित्तीय आस्तियों बनाया स्थानांतरित किया या कर रहे हैं बाजार के रूपमें परिभाषित किया जा सकता। असली माल या सेवाओं के लिए पैसे का आदान-प्रदान शामिल हैकि एक वास्तविक लेन-देन हुई, एक वित्तीय लेनदेन के निर्माण या एक वित्तीय परिसंपत्ति काअंतरण शामिल है। वित्तीय संपत्ति या वित्तीय साधनों धन की राशि का भुगतान भविष्य में कुछसमय और ब्याज या लाभांश के रूप में या आवधिक भुगतान के लिए एक दावे का प्रतिनिधित्वकरता है।

मुद्रा बाजार

मुद्रा बाजार अगर एक थोक ऋण बाजार के लिए कम जोखिम, उच्च तरल, अल्पकालिक साधन। धन एक साल तक एक ही दिन से लेकर समय के लिए इस बाजार में उपलब्ध हैं। ज्यादातरसरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस बाजार का प्रभुत्व है। पूंजी बाजार - पूंजी बाजारलंबी अवधि के निवेश वित्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बाजार में हो रही लेन-देनअवधि के लिए एक वर्ष से अधिक हो जाएगा।

पूंजी बाजार

पूंजी बाजार में लंबी अवधि के निवेश के वित्तपोषण के लिए बनाया गया है। लेन-देन के इस बाजार में जगह लेने के एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा बाजार

विदेशी मुद्रा बाजार बहु मुद्रा आवश्यकताओं, जो मुद्राओं के विनिमय से मुलाकात कर रहे हैं के साथ सौदों। विनिमय दर के आधार पर लागू होता है, धन के हस्तांतरण इस बाजार में जगह लेता है। यह दुनिया भर में सबसे अधिक विकसित और एकीकृत बाजार में से एक है।

क्रेडिट बाजार

क्रेडिट बाजार जहां बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और एन बी एफ सी प्रबंध करना लघु, मध्यम और कॉर्पोरेट के लिए दीर्घकालीन ऋण और व्यक्तियों एक जगह है।

वित्तीय प्रणाली के संघटक

वित्तीय मध्यस्थता

लिखत डिजाइन करने के बाद, जारीकर्ता तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन वित्तीय आस्तियों के क्रम में आवश्यक राशि जुटाने में परम निवेशक तक पहुँचने। फंडों की ऋण लेने वाले वित्तीय बाजार धन जुटाने के लिए दृष्टिकोण, प्रतिभूतियों के मात्र मुद्दा पर्याप्त नहीं होगा। मुद्दा, जारीकर्ता और सुरक्षा की पर्याप्त जानकारी जगह लेने के लिए पर पारित किया जाना चाहिए। वहाँ वित्तीय प्रणाली के भीतर एक उचित चैनल इस तरह के हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। इस उद्देश्य की सेवा करने के लिए, वित्तीय मध्यस्थों अस्तित्व में आया। संगठित क्षेत्र में वित्तीय मध्यस्थता भारतीय रिजर्व बैंक के समग्र निगरानी के तहत कार्य कर संस्थानों की एक widerange द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक दौर में, मध्यस्थ की भूमिका ज्यादातर ऋणदाता से ऋण लेने के लिए धन के हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित था। इस सेवा के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, दलालों, और डीलरों द्वारा की पेशकश की थी। हालांकि, के रूप में वित्तीय प्रणाली के घटनाक्रम वित्तीय बाजारों में जगह लेने के साथ-साथ चौड़ी हो, अपने परिचालन का दायरा भी चौड़ी हो। ऑपरेटिंग स्याही वित्तीय बाजारों में शामिल महत्वपूर्ण बिचौलियों से कुछ; निवेश बैंकरों, शेयर बाजारों, रजिस्ट्रार, डिपॉजिटरी, संरक्षक, पोर्टफोलियो प्रबंधकों,

म्युचुअल फंड, वित्तीय विज्ञापनदाताओं वित्तीय सलाहकार, प्राथमिक डीलरों, उपग्रह डीलरों, आत्म नियामक संगठनों, आदि हालांकि बाजारों में अलग कर रहे हैं, वहाँ एक जैसे बाजार की तुलना में इस कदम में अपनी सेवाएं दे कुछ बिचौलियों हो सकता है हामीदार। हालांकि, उनके द्वारा की पेशकश की सेवाओं एक बाजार से दूसरे बदलती हैं।

वित्तीय प्रपत्र

मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स

मुद्रा बाजार के अल्पकालिक पैसे और वित्तीय आस्तियों है कि पैसे के लिए पास विकल्प हैं के लिए एक बाजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अवधि अल्पकालिक तक एक वर्ष और पैसे के लिए पास के विकल्प के किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति है जो जल्दी न्यूनतम लेन-देन लागत के साथ पैसे में परिवर्तित किया जा सकता निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है आम तौर पर एक अवधि का मतलब है।

पूंजी बाजार इंस्ट्रूमेंट्स

पूंजी बाजार में आम तौर पर निम्नलिखित दीर्घकालिक अवधि अर्थात, एक वर्ष से अधिक अवधि, वित्तीय साधनों के होते हैं; इक्विटी खंड इक्विटी शेयर, तरजीही शेयरों, परिवर्तनीय तरजीही शेयरों, गैर-परिवर्तनीय तरजीही शेयरों आदि और ऋण खंड डिबेंचरों में, जीरो कूपन बांड, गहरी डिस्काउंट बांड आदि

हाइब्रिड उपकरण

हाइब्रिड उपकरणों दोनों इक्विटी और डिबेंचर की विशेषताएं हैं। उपकरणों की इस तरह की संकर के साधन के रूप में कहा जाता है। उदाहरण परिवर्तनीय डिबेंचर, वारंट आदि कर रहे हैं

भारत में मुद्रा बाजार में भारत के भारत और प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। पूंजी बाजार प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के होते हैं। सभी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राथमिक बाजार के तहत आता है और सभी द्वितीयक बाजार लेनदेन द्वितीयक बाजार में सौदों। द्वितीयक बाजार में एक बाजार में जहां प्रतिभूतियों के बाद शुरू में स्टॉक एक्सचेंज पर प्राथमिक बाजार में जनता के लिए पेशकश की है और / या सूचीबद्ध किया जा रहा कारोबार कर रहे हैं करने के लिए संदर्भित करता है। द्वितीयक बाजार इक्विटी बाजार और ऋण बाजार के शामिल हैं। द्वितीयक बाजार लेनदेन बीएसई और एनएसई में पूंजी बाजार के उपकरणों के आदान-प्रदान में एक बड़ी भूमिका निभाता है।

भारत में वित्तीय स्रोतों की वृद्धि:

भारत में वित्तीय सेवाओं की वृद्धि विभिन्न चरणों के तहत हुई है। यह नीचे उल्लिखित है:

1. व्यापारी बैंकिंग युग:

1960 और 1980 के बीच की अवधि को 'मर्चेंट बैंकिंग युग' कहा जा सकता है। इस अवधि के दौरान, व्यापारी बैंकिंग, बीमा और पट्टे पर सेवाओं जैसे वित्तीय प्रश्नों में वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान, व्यापारी बैंकरों ने निम्नलिखित कार्यों को पूरा किया।

(i) परियोजनाओं की पहचान करना, व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना, और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विकसित करना।

(ii) अपने ग्राहकों की ओर से विपणन, प्रबंधकीय, वित्तीय और तकनीकी विश्लेषण का आयोजन।

(iii) उपयुक्त पूंजी संरचना तैयार करने में सहायता करें।

(iv) पूंजी बाजार और फंड-तलाश संस्थानों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करना।

(v) अंडरराइटिंग कार्यों को ले जाना।

(vi) स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध अपने मुद्दों को प्राप्त करने में उद्यमों की सहायता करना।

(vii) विलय और अधिग्रहण से संबंधित कानूनी सलाह प्रदान करना।

(viii) लीवर किए गए खरीद और टेकओवर पर तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(ix) परियोजना वित्त व्यवस्था के हिस्से के रूप में विस्तार सिंडिकेशन सुविधा।

(x) कार्यशील पूंजी ऋण की व्यवस्था करना।

2. निवेश कंपनियां युग:

इस युग ने विभिन्न निवेश संस्थानों और बैंकों की स्थापना को चिह्नित किया। निवेश कंपनियों में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया शामिल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का म्यूचुअल फंड है, भारत के जीवन बीमा निगम ने जीवन बीमा कारोबार और सामान्य बीमा निगमों की शुरुआत की।

3. आधुनिक सेवाएं युग:

इस चरण ने अस्सी के दौरान विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लॉन्च को चिह्नित किया। इन वित्तीय सेवाओं में ओवर-द-काउंटर सेवाएं शामिल थीं। शेयर ट्रांसफर, शेयरों की प्रतिज्ञा, म्यूचुअल फंड, फैक्टरिंग, छूट, उद्यम पूंजी और क्रेडिट रेटिंग साझा करें।

4. जमा राशि युग:

वैश्विक वित्तीय सेवा उद्योग के साथ भारतीय वित्तीय क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए, जमाकर्ताओं की स्थापना की गई थी। डिपॉजिटरी सिस्टम को शेयर और बॉन्ड के डिमटेरियलाइजेशन के माध्यम से पेपरलेस ट्रेडिंग की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए पेश किया गया था। भारत में एक मजबूत वित्तीय सेवा क्षेत्र के निर्माण की दिशा में पुस्तक निर्माण का परिचय और लोकप्रियता भी एक और कदम था। इसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कम्प्यूटरीकरण द्वारा पेश किए गए 'ऑन-लाइन ट्रेडिंग' इंटरफ़ेस, सभी भारत में एक मजबूत वित्तीय सेवा बाजार के विकास के लिए फुलक्रम के रूप में कार्य कर रहे हैं।

5. विधान युग:

वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक आधारित विकास की अनुमति देने के लिए कई कानून पेश किए गए थे। फेरा को फेमा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। सुरक्षित और व्यवस्थित व्यापार की सुविधा और लेनदेन के निपटारे के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम इत्यादि में दूरगामी संशोधन किए गए थे।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआईएस)

ये वे संस्थाएं होती है जिनकी रचना भारत में निवेश करने हेतु विदेश में की गई है। भारत में निवेश करने के लिए इन संस्थाओं को सेबी के साथ अपना पंजीकरण विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में करना होता है।सेबी के नियमों के मुताबिक इस तरह की संस्थाएं किसी भारतीय कंपनी के आईपीओ के कुल मूल्य के दस प्रतिशत से ज्यादा पर निवेश नहीं कर सकतीं। यह युग भारतीय वित्तीय बाजारों के विकास में नवीनतम चरण को चिह्नित करता है। सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधार उपायों को विभिन्न प्रतिभागियों के लिए अधिक मुफ्त खेल की आवश्यकता है। इसके हिस्से के रूप में, हाल के दिनों में सेबी द्वारा विघटन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जहां एफआईआई द्वारा भारतीय पूंजी बाजार में काम करने की अनुमति है।

वित्तीय सेवा क्षेत्र - भारतीय वित्तीय सेवाओं में समस्याएं:

(i) विशेषज्ञता की कमी

(ii) अपर्याप्त आवास

(iii) अपर्याप्त प्रौद्योगिकी

(iv) अपर्याप्त गुणवत्ता सेवा

(v) कैप्टिव संगठन

(vi) संचालन के प्रतिबंधित दायरे

(vii) सीमित नवाचार

(viii) ध्वनि संस्थागत तंत्र की कमी

(ix) कोर-योग्यता की कमी

वित्तीय सेवा और आर्थिक पर्यावरण:

किसी देश में वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए उचित आर्थिक वातावरण की आवश्यकता है। इसमें विभिन्न आर्थिक कारक शामिल हैं जैसे (ए) अनुकूल आर्थिक प्रणाली, (बी) आर्थिक कानून, (सी) आर्थिक नीतियां, (डी) आर्थिक नियोजन, (ई) आर्थिक स्थिति।

ए) अनुकूल आर्थिक प्रणाली:

वित्तीय सेवाएं विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों की आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। एक व्यवसाय बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा एकमात्र व्यापारी, साझेदारी फर्म, संयुक्त स्टॉक कंपनियों (या) के विभिन्न रूपों के तहत काम कर सकता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के माध्यम से सरकार द्वारा भी किया जा सकता है।

बी) आर्थिक कानून:

(1) उचित निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और विनियमन अधिनियम।

(2) कंपनियों के उचित प्रबंधन को विनियमित करने के लिए कंपनी अधिनियम

(3) स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेन को व्यवस्थित करने के लिए सिक्योरिटीज (अनुबंध और विनियमन) अधिनियम।

(4) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम।

(5) विदेशी निवेश विनियमन के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, जिसे अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) कहा जाता है।

सी) आर्थिक नीतियां:

अर्थव्यवस्था नीति में, हम देश की आर्थिक स्थितियों में सुधार के साथ जुड़े पहलुओं से निपटते हैं। सरकार ऐसी नीतियों को अपनाएगी जो निवेश, उत्पादन, रोजगार, विदेशी व्यापार, आर्थिक विकास इत्यादि को बढ़ावा देती हैं। उनके उद्देश्य के लिए, नीति का लक्ष्य घरेलू और विदेशी दोनों देशों से निवेश को प्रोत्साहित करना है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि उचित मूल्य निर्धारण नीति, खरीद नीति, भत्ता और सब्सिडी, कर रियायत आदि के माध्यम से की जानी है।

डी) आर्थिक योजना:

आर्थिक नियोजन में, लेखांकन अपने विकास के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम (या) पथ का निर्णय लेता है। योजना अर्थव्यवस्था के विकास की दर को ठीक करती है और तदनुसार वांछित विकास को प्राप्त करने के लिए सभी

भौतिक, वित्तीय और मौद्रिक संसाधनों को जोड़ती है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में तेजी से आर्थिक विकास हासिल करना है ताकि देश के लोगों को जीवन स्तर का उच्च स्तर अनुभव हो।

ई) आर्थिक हालत:

वित्तीय सेवाएं केवल अनुकूल आर्थिक स्थितियों के तहत सक्रिय हो सकती हैं। यदि गिरती कीमतों और उत्पादन को बंद करने के साथ अवसाद होता है, तो वित्तीय सेवाओं को और अधिक गुंजाइश का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए, निवेश और उत्पादन के लिए अधिक दायरे वाला एक नियंत्रित मुद्रास्फीति वित्तीय सेवाओं के विस्तार के लिए आदर्श होगी।

मैक्रो आर्थिक समेकन और नीतियां:

यहां, हम विभिन्न मैक्रो आर्थिक कारकों से निपटते हैं जो न केवल देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं बल्कि देश में वित्तीय सेवाओं के कामकाज को भी प्रभावित करते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक कारक, देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक समेकन के रूप में कहा जा सकता है। वहां

1. अर्थव्यवस्था की बचत।
2. निवेश
3. आर्थिक विकास
4. पूंजी निर्माण
5. पूंजी उत्पादन अनुपात
6. जनसंख्या वृद्धि
7. विदेशी व्यापार की वृद्धि
8. भुगतान संतुलन
9. विदेशी ऋण
10. विनिमय दर स्थिरता
11. रोजगार स्तर
12. पूंजी प्रवाह
13. आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में प्रति व्यक्ति आय

1. अर्थव्यवस्था की बचत:

अधिकांश विकसित देशों में, लोगों की बचत देश में निवेश का एक बड़ा हिस्सा बनती है। बचत केवल तभी हो सकती है जब लोगों का आय स्तर अधिक हो और लोग गरीबी के स्तर से ऊपर रह रहे हों। हमारे देश में, कुल सकल घरेलू उत्पाद का औसत केवल 9% औसत है। इसके विपरीत, विकसित देशों में, वे सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 28 से 30% हैं। (उदाहरण के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गहने की खरीद)। इसलिए खराब बचत के कारण हमारे देश में वित्तीय सेवाएं प्रमुख भूमिका निभाने में असमर्थ हैं।

2. निवेश:

अर्थव्यवस्था का विकास देश में किए गए निवेश की सीमा पर निर्भर करता है। निवेश को अधिक उत्पादन उत्पन्न करना चाहिए और उन्हें अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार, कृषि में अधिक उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र और सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि के लिए स्थितियां पैदा करेगा। निवेश सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा किया जा सकता है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवेश पर्याप्त होना चाहिए ताकि वांछित विकास अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हासिल किया जा सके।

3. आर्थिक विकास:

अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और सेवा के सभी तीन क्षेत्रों में भौतिक उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक विकास के रूप में जाना जाता है। आर्थिक विकास में वृद्धि से आर्थिक विकास में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि, बढ़ी हुई आबादी में बढ़ी हुई उत्पादन का उपभोग किया जा सकता है।

4. पूंजी निर्माण:

जब कोई कंपनी मुनाफा कमाती है, तो वह उस कारोबार में अपने मुनाफे का एक हिस्सा वापस ले सकती है जो इसकी पूंजी फैलती है। इस तरह, पूंजी निर्माण के लिए पूंजी निर्माण होता है, खपत में कमी बहुत जरूरी है। फायदेमंद निवेश के लिए कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ (या) को आकर्षित करके वित्तीय सेवाएं एक प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं।

5. पूंजी-उत्पादन अनुपात:

आउटपुट के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा पूंजी-उत्पादन अनुपात में निपटाई जाती है। इस अनुपात का महत्व अधिक तकनीक के साथ आवश्यक आउटपुट उत्पन्न करने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा है। कम पूंजी का उपयोग किया जाता है और अधिक मात्रा में निवेश के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, पूंजी-उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था को और अधिक लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य है। इसमें एक विकसित और विकसित देश के बीच अंतर - एक विकसित देश उपभोक्ताओं की कम पूंजी लेकिन अधिक उत्पादन लाती है, जबकि एक

विकसित देश उपभोक्ताओं के बीच अधिक पूंजी और खराब प्रौद्योगिकी के कारण कम उत्पादन में कमी आती है। हम अपनी कृषि में इसका बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं।

6. जनसंख्या वृद्धि:

आबादी में वृद्धि एक देश के आर्थिक विकास को रोक सकती है। यदि उत्पादित उद्देश्यों के लिए बढ़ी हुई आबादी का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से, उत्पादक बल एक उच्च प्रतिशत का है। देर से, सेवाओं का निर्यात जमीन प्राप्त कर रहा है और इस संदर्भ में, भारत ने आईटी उद्योग में अपनी 15% से अधिक विशेषज्ञ कमाई अर्जित की है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सेवाओं को निर्यात करके अधिक मानव स्पर्श की आवश्यकता है और यह यहां है कि वित्तीय सेवा में एक प्रशिक्षित व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए योगदानकर्ता अधिक।

7. विदेशी व्यापार की वृद्धि:

निर्यात किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा बनता है, जिसने तेजी से विकसित देशों को विदेशी व्यापार के लिए उचित महत्व दिया है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सेवाओं के सक्रिय समर्थन की आवश्यकता होती है। बैंक निर्यात वित्त प्रदान करता है। कारखाने और जब्त कंपनियों निर्यातक वित्तपोषण। इस तरह, वित्तीय सेवा के हर पहलू से विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है जो बदले में अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

8. भुगतान की शेष राशि:

विदेश से किसी देश की प्राप्तियां और भुगतान भुगतान विवरण के संतुलन द्वारा दर्शाए जाते हैं। यदि प्राप्तियां अधिक हैं और भुगतान कम है, तो देश को भुगतान की स्थिति के अनुकूल संतुलन का अनुभव होता है। लेकिन कभी-कभी, इसे एक रिवर्स स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें अधिक भुगतान और कम रसीदें होती हैं, जिससे भुगतान की प्रतिकूल शेष राशि होती है। इस प्रकार वित्तीय सेवाएं एक तरफ विदेशी निवेशक और दूसरे पर घरेलू उत्पादक के बीच एक पुल के रूप में कार्य कर सकती हैं।

9. विदेशी ऋण:

वित्तीय सेवाएं विदेशी ऋण को बढ़ाने में अर्थव्यवस्था की सहायता करती हैं। इस तरह के ऋण वैश्विक वित्तीय बाजार में ब्याज की प्रतिस्पर्धी दर पर प्राप्त किए जा सकते हैं। आम तौर पर, किसी विदेशी ऋण को विस्तारित करने से पहले देश की क्रेडिट रेटिंग को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए, ब्याज की प्रतिस्पर्धी दर पर विदेशी ऋण उठाना और उन्हें उचित उपयोग के लिए रखना एक और महत्वपूर्ण कारक है और वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करती हैं कि रिटर्न विदेशी ऋण पर ब्याज दर के अनुरूप है।

10. विनिमय दर स्थिरता:

जब एक देश विदेशी बाजार में भारी आयात के बाद लगातार उधार लेता है, तो उसे विदेशी मुद्रा के संबंध में मुद्रा मूल्य में गिरावट का अनुभव होगा। के लिए (उदाहरण के लिए) यदि भारत में आयात और विदेशी ऋण के बाद 1 अमेरिकी डॉलर = रुपये 8 / - की विनिमय दर है, तो इसकी विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = रु। 60 / -। यह स्लाइड भारत को प्रभावित करेगी, क्योंकि हमें अपने कर्ज के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है जो अब हमारे उधार के समय के मुकाबले 25% अधिक है।

11. रोजगार स्तर:

वित्तीय सेवाओं से प्रभावित एक और मार्को आर्थिक समग्र रोजगार का स्तर है। लीजिंग, किराया खरीद वित्त, आवास वित्त, बीमा इत्यादि जैसी अधिक वित्तीय सेवाओं के साथ, देश में रोजगार के अवसर का स्तर बढ़ाना है। यह अधिक मांग पैदा करेगा और अन्य उद्योग भी विस्तारित होंगे। इस प्रकार, देश पूर्ण रोजगार के स्तर तक पहुंच सकता है।

12. पूंजीगत मुद्रास्फीति:

देश में पूंजी बाजार अबोरैड से अधिक पूंजी आकर्षित कर सकता है, जिससे पूंजी प्रवाह होता है। यह तभी होगा जब पूंजी पर वापसी बहुत अधिक हो या ब्याज दर की पेशकश घरेलू देश में प्रचलित हो।

13. आर्थिक विकास :

आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में प्रति व्यक्ति आय: जब देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि और सेवाओं में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई है, तो लाभ आय के अनुसार जनसंख्या में लाभ आते हैं जो आर्थिक विकास का संकेतक है देश। वित्तीय सेवाएं विभिन्न प्रकार के ऋण प्रदान करके और स्वयं रोजगार योजनाओं को प्रोत्साहित करके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकती हैं। वे निवेश के विभिन्न स्रोत प्रदान करके बचत के आंदोलन में भी मदद कर सकते हैं।

वित्तीय प्रपत्र

भारतीय वित्तीय प्रणाली में वित्तीय उपकरणों को मनी मार्केट उपकरणों और पूंजी बाजार उपकरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स

मनी मार्केट में जो उपकरण सौदा करते हैं वे अल्पावधि प्रकृति के होते हैं। उनकी परिपक्वता अवधि आमतौर पर 14 और 364 दिनों के बीच बदलती है। मनी मार्केट यंत्र हैं:

- राजकोष चालान
- एक्सचेंज या ट्रेड बिल के बिल
- वित्त बिल या बिजनेस प्रोमिसरी नोट्स
- वाणिज्यिक पत्र
- जमा प्रमाणपत्र

पूंजी बाजार के उपकरण

पूंजी बाजार में जो उपकरण सौदा करते हैं वे लंबी अवधि की प्रकृति के हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां हैं जैसे कि:

- सामान्य शेयर
- प्रक्रिया के कर्ता - धर्ता
- डिबेंचर
- गिल्ट-एज वाली प्रतिभूतियां
- शून्य कूपन बांड
- दीप छूट बांड
- विकल्प बांड
- व्युत्पन्न प्रतिभूतियां - विकल्प, वायदा इत्यादि।

बी) बाजार के खिलाड़ी

बाजार में खिलाड़ियों में शामिल हैं:

i। वाणिज्यिक बैंक

ii। वित्त कंपनियां

iii। स्टॉक ब्रोकर

iv। कंसल्टेंट्स

वी। अंडरराइटर्स

vi। बाज़ार निर्माता

i। वाणिज्यिक बैंक

विकसित देशों में, वाणिज्यिक बैंक न केवल ऋण प्रदान करते हैं बल्कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के ऋण और इक्विटी वित्त में भी भाग लेते हैं। आजकल विकासशील देशों के सभी वाणिज्यिक बैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवाओं में भी शामिल हैं, क्रय वित्त, पट्टेबाजी, फैक्टरिंग, म्यूचुअल फंड, बीमा और अन्य सेवाएं किराए पर लेते हैं।

ii। वित्त कंपनियां

आर्थिक विकास में वित्त कंपनियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसे गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी भी कहा जाता है जिसका व्यवसाय निम्नलिखित में से किसी भी गतिविधि में शामिल होने के अलावा जमा प्राप्त कर रहा है:

- ऋण, अग्रिम आदि के माध्यम से वित्तपोषण,
- शेयर / स्टॉक / बॉन्ड / डिबेंचर / प्रतिभूतियों का अधिग्रहण
- किराया खरीद
- बीमा के किसी भी वर्ग, स्टॉक ब्रोकिंग इत्यादि।
- चिट फंड और
- इकाइयों या अन्य उपकरणों / किसी अन्य तरीके की सदस्यता / बिक्री के माध्यम से पैसे का संग्रह और उनके वितरण।

iii। स्टॉक ब्रोकर्स

शेयर बाजार में शेयर दलालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के खरीदार और विक्रेता के बीच एक एजेंट और पुल के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें सभी नियमों और शर्तों को पूरा

करने के बाद सेबी से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए था। स्टॉक ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए सेबी से प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उन्हें व्यक्तिगत सदस्यता या कॉर्पोरेट (फर्म) सदस्यता मिल सकती है।

vi। कंसल्टेंट्स

कॉर्पोरेट क्षेत्र को उनके निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञ सलाह या राय मिल सकती है। वे विशेषज्ञ वित्त के क्षेत्र में विशिष्ट हैं और उन्हें वित्त विशेषज्ञ या पेशेवर कहा जाता है। वे उत्पादन, वित्त, विपणन और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे कार्यात्मक प्रबंधन के सभी क्षेत्रों में केवल परामर्श सेवा देते हैं।

v। अंडरराइटर्स

अंडरराइट्स नए मुद्दे / प्राथमिक बाजार में पूंजी के मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं जो सिक्योरिटीज लेने के लिए सहमत हैं जो पूरी तरह से सदस्यता नहीं लेते हैं। वे स्वयं या दूसरों द्वारा सब्सक्राइब किए गए मुद्दे को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता बनाते हैं। इन मुद्दों पर लीड मैनेजर / मर्चेंट बैंकरों के परामर्श से जारी करने वाली कंपनियों द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। उन्हें जारी करने वाली कंपनी के शेयरों की सदस्यता लेने के आश्वासन के लिए जारी करने वाली कंपनी से कमीशन मिलता है।

vi। बाज़ार निर्माता

लंदन, न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे स्टॉक एक्सचेंजों में बाजार बनाने की प्रणाली लोकप्रिय है। एक बाजार निर्माता एक बैंक या ब्रोकरेज कंपनी है जो व्यापारिक दिन के हर दूसरे को एक फर्म 'पूछने और बोली मूल्य' के साथ तैयार करता है। वे वास्तव में खरीदारों के पक्ष से किसी भी प्रस्ताव के बिना भी विक्रेता से स्टॉक खरीदते हैं। बाजार निर्माता स्टॉक के मूल्य में गिरावट के जोखिम को रोकने के लिए प्रत्येक स्टॉक पर एक फैलाव बनाए रखता है। आपूर्ति के लिए आपूर्ति और मांग के बीच अस्थायी असमानता उनके द्वारा समाप्त हो जाती है।

सी) विशिष्ट संस्थानों

विशिष्ट संस्थान स्वीकृति गृह, डिस्काउंट हाउस, कारक, डिपॉजिटरीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, वेंचर कैपिटल इत्यादि जैसे विभिन्न रूपों में वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वित्तीय बाजार गतिशील है और इन विशेष सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कॉर्पोरेट क्षेत्रों के समकालीन मुद्दों को हल करता है।

डी) नियामक निकाय

नियामक निकाय वित्तीय प्रणाली का अधिकार नियंत्रित कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) भारतीय मौद्रिक प्रणाली का नियामक निकाय हैं। वे सांविधिक निकाय हैं जिनके पास भारत की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की निगरानी और विनियमन की शक्ति है। वित्तीय बाजार की बारीकी से निगरानी और विनियमन किया जाना चाहिए क्योंकि यह अत्यधिक अस्थिर है। आरबीआई भारत का केंद्रीय

बैंक है और यह हमारे देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के मामलों की निगरानी और नियंत्रण करने का प्रमुख अधिकार है। सेबी वित्तीय बाजार (शेयर बाजार) की निगरानी, निर्देशन, विनियमन और नियंत्रण का एकमात्र अधिकार है। कंपनी कानून बोर्ड, औद्योगिक बोर्ड इत्यादि जैसे कॉर्पोरेट मामलों को नियंत्रित करने के लिए अन्य नियामक निकाय हैं।

वित्तीय मध्यस्थों के कार्य:

1. वित्तीय सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो बैंक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए, बैंकों का नेतृत्व देश के केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, सहयोग बैंकों, विकास बैंकों, विदेशी बैंकों आदि के नेतृत्व में किया जाता है।
2. किराया खरीद फाइनेंसर वित्तीय सेवा क्षेत्र में भी एक खिलाड़ी है क्योंकि वह उपभोक्ता को क्रेडिट आधार पर उत्पाद खरीदने में सक्षम बनाता है।
3. वित्तीय और परिचालन पट्टे के माध्यम से लीजिंग कंपनियां एक उचित शुल्क पर दीर्घकालिक आधार पर उत्पादकों द्वारा संपत्तियों का अधिग्रहण सुनिश्चित करती हैं।
4. फैक्टरिंग सेवर को फैक्टरिंग सेवाओं के उपक्रम वाली वित्तीय कंपनियों से बिक्री का 80% मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
5. लेखकों और व्यापारी बैंकरों के तहत अतिरिक्त खिलाड़ी हैं जो न केवल कंपनियों को बढ़ावा देते हैं बल्कि पूंजी बाजार में गतिशील गतिविधि सुनिश्चित करते हैं।
6. बुक-बिल्डर्स निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों में शेयर आवंटित करने में कंपनियों की सहायता करते हैं।
7. म्यूचुअल फंड जनता द्वारा निवेश सुनिश्चित करते हैं और निवेशक को कर राहत सुनिश्चित करते हैं।
8. क्रेडिट कार्ड, वित्तीय सेवाओं में एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी, प्लास्टिक के पैसे का संचलन सुनिश्चित करता है और उपभोक्ता द्वारा क्रेडिट पर खरीद को सक्षम बनाता है।
9. क्रेडिट रेटिंग कंपनियां सार्वजनिक जमाओं को संगठित करने के लिए कंपनियों को अलग-अलग क्रेडिट रेटिंग देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
10. आवास वित्त कंपनियां और बीमा कंपनियां भी अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देती हैं क्योंकि वे वित्तीय सेवाओं में खिलाड़ियों का हिस्सा भी बनाती हैं।
11. संपत्ति देयता प्रबंधन कंपनी म्यूचुअल फंड को विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था में उचित निवेश करने में सक्षम बनाती है।
12. सामान्य रूप से वित्त कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के हिस्से के रूप में उपरोक्त खिलाड़ियों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में और अधिक गतिविधि हो।

वित्तीय सेवा बाजार

वित्तीय सेवाओं को विभिन्न वित्तीय लेनदेन और ऋण, बीमा, क्रेडिट कार्ड, निवेश के अवसर और धन प्रबंधन जैसे वित्त की दुनिया में अन्य संबंधित गतिविधियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के बैंकों जैसे संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शेयर बाजार और बाजार के रुझान जैसे अन्य मुद्दों पर जानकारी प्रदान करना

वित्तीय सेवाएं वित्त उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का संदर्भ देती हैं। वित्त उद्योग में संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो पैसे के प्रबंधन से निपटती हैं। इन संगठनों में से बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनियां, बीमा कंपनियां, उपभोक्ता वित्त कंपनियां, स्टॉक ब्रोकरेज, निवेश निधि और कुछ सरकारी प्रायोजित उद्यम हैं।

वित्तीय सेवाओं के कार्य

- अर्थव्यवस्था में लेनदेन (माल और सेवाओं का आदान-प्रदान) सुविधा।
- बचत को गतिशील करना (जिसके लिए आउटलेट अन्यथा सीमित होंगे)।
- पूंजीगत धन आवंटित करना (विशेष रूप से उत्पादक निवेश को वित्तपोषित करना)।
- निगरानी प्रबंधकों (ताकि आवंटित धन पर विचार किया जाएगा)।
- जोखिम को बदलना (इसे एकत्रीकरण के माध्यम से कम करना और इसे सहन करने के इच्छुक लोगों द्वारा इसे सक्षम करने में सक्षम बनाना)।

वित्तीय सेवाओं की विशेषताएं

- वित्तीय सेवाएं अमूर्त हैं
- वित्तीय सेवाएं ग्राहक उन्मुख हैं
- एक सेवा का उत्पादन और वितरण एक साथ काम करता है इसलिए अविभाज्य होते हैं
- वे प्रकृति में विनाशकारी हैं और संग्रहित नहीं किया जा सकता है
- वे प्रकृति में गतिशील हैं क्योंकि एक वित्तीय सेवा ग्राहक की बदलती आवश्यकताओं और सामाजिक-आर्थिक वातावरण के साथ बदलती है।
- गतिशील सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, डिस्पोजेबल आय होना चाहिए
- वे प्रकृति में सक्रिय हैं और बाजार की अपेक्षाओं को देखने में मदद करते हैं
- वे निवेशक और उधारकर्ता के बीच संबंध के रूप में कार्य करते हैं

- वे जोखिमों के वितरण में सहायता करते हैं

वित्तीय सेवाओं के प्रकार

- पूंजी बाजार सेवाएं - इसमें टर्म लोनिंग संस्थान शामिल हैं जो मुख्य रूप से दीर्घकालिक धन प्रदान करते हैं।
- मनी मार्केट सर्विसेज - इसमें वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, सहकारी बैंक होते हैं जो अल्पकालिक निधि एजेंसियां प्रदान करते हैं
- खुदरा सेवा - प्रत्यक्ष खपत के लिए व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
- थोक सेवा - कॉर्पोरेट संस्थानों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुदरा सेवाओं में परिवर्तित हो सकती हैं।

वित्तीय सेवाओं के लक्षण और विशेषताएं

1. ग्राहक-विशिष्ट: आमतौर पर वित्तीय सेवाएं ग्राहक केंद्रित होती हैं। इन सेवाओं को प्रदान करने वाली कंपनियां, अपनी वित्तीय रणनीति का निर्णय लेने से पहले विस्तार से अपने ग्राहकों की जरूरतों का अध्ययन करती हैं, लागत, तरलता और परिपक्वता विचारों के संबंध में उचित संबंध देती हैं। वित्तीय सेवा फर्म लगातार अपने ग्राहकों के संपर्क में रहती हैं, ताकि वे उन उत्पादों को डिज़ाइन कर सकें जो अपने ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। वित्तीय सेवाओं के प्रदाता लगातार बाजार सर्वेक्षण करते हैं, इसलिए वे जरूरतों और आने वाले कानूनों से पहले नए उत्पादों की पेशकश कर सकते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग अभिनव, ग्राहक अनुकूल उत्पादों और सेवाओं को शुरू करने के लिए किया जा रहा है जो स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि वित्तीय सेवाओं के प्रदाताओं की एकाग्रता फर्म / ग्राहक विशिष्ट सेवाओं को उत्पन्न करने पर है।

2. असंगतता: अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक पर्यावरण ब्रांड छवि में बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक वित्तीय संस्थानों और सेवाओं को प्रदान करने वाले वित्तीय संस्थानों में अच्छी छवि नहीं होती है, तो उनके ग्राहकों के विश्वास का आनंद लेते हुए, वे सफल नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार संस्थानों को अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए उनकी सेवाओं की गुणवत्ता और नवीनता पर ध्यान देना होगा।

3. संयोग: वित्तीय सेवाओं का उत्पादन और इन सेवाओं की आपूर्ति संगत होना चाहिए। इन दोनों कार्यों यानी नई और नवीन वित्तीय सेवाओं का उत्पादन और इन सेवाओं की आपूर्ति एक साथ किया जाना है।

4. नष्ट होने की प्रवृत्ति: किसी अन्य सेवा के विपरीत, वित्तीय सेवाओं का नाश होना पड़ता है और इसलिए इसे संग्रहीत नहीं किया जा सकता है। उन्हें ग्राहकों द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जानी है। इसलिए वित्तीय संस्थानों को मांग और आपूर्ति का उचित सिंक्रनाइज़ेशन सुनिश्चित करना है।

5. लोग आधारित सेवाएं: वित्तीय सेवाओं का विपणन लोगों को गहन होना चाहिए और इसलिए यह प्रदर्शन या सेवा की गुणवत्ता की विविधता के अधीन है। वित्तीय सेवा संगठन के कर्मियों को उनकी उपयुक्तता और प्रशिक्षित तरीके से आधार पर चयन करने की आवश्यकता है, ताकि वे अपनी गतिविधियों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर सकें।

6. बाजार गतिशीलता: बाजार गतिशीलता काफी हद तक निर्भर करती है, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन जैसे डिस्पोजेबल आय, जीवन स्तर और ग्राहकों के विभिन्न वर्गों से संबंधित शैक्षणिक परिवर्तन। इसलिए वित्तीय सेवाओं को लगातार बाजार परिभाषित किया जाना चाहिए और बाजार गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए परिष्कृत किया जाना चाहिए। वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान, नई सेवाओं को विकसित करते समय बाजार में क्या चाहते हैं, या उनकी सी की जरूरतों और प्रतिक्रियाओं के प्रति प्रतिक्रियाशील होने में सक्रिय हो सकते हैं।

6. बाजार गतिशीलता: बाजार गतिशीलता काफी हद तक निर्भर करती है, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन जैसे डिस्पोजेबल आय, जीवन स्तर और ग्राहकों के विभिन्न वर्गों से संबंधित शैक्षणिक परिवर्तन। इसलिए वित्तीय सेवाओं को लगातार बाजार परिभाषित किया जाना चाहिए और बाजार गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए परिष्कृत किया जाना चाहिए। वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान, नई सेवाओं को विकसित करते समय बाजार में क्या चाहते हैं, या अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति प्रतिक्रियाशील होने में सक्रिय हो सकते हैं।

वित्तीय सेवाओं का दायरा

वित्तीय सेवाओं में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उन्हें व्यापक रूप से दो में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:

1. पारंपरिक गतिविधियां

परंपरागत रूप से, वित्तीय मध्यस्थ पूंजी और मुद्रा बाजार गतिविधियों दोनों सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान कर रहे हैं। उन्हें दो सिर के नीचे समूहीकृत किया जा सकता है, जैसे।

1. फंड आधारित गतिविधियों और

2. गैर-निधि आधारित गतिविधियां।

निधि आधारित गतिविधियां: पारंपरिक सेवाएं जो फंड आधारित गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं निम्नलिखित हैं:

- नए मुद्दों (प्राथमिक बाजार गतिविधियों) के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड इत्यादि में अंडरराइटिंग या निवेश।

- द्वितीयक बाजार गतिविधियों में काम करना।
- वाणिज्यिक बाजारों, जमा प्रमाणपत्र, ट्रेजरी बिल, बिलों की छूट आदि जैसे मनी मार्केट उपकरणों में भाग लेना।
- उपकरण लीजिंग, किराया खरीद, उद्यम पूंजी, बीज पूंजी आदि में शामिल होना
- विदेशी मुद्रा बाजार गतिविधियों में काम करना। गैर फंड आधारित गतिविधियों

गैर-निधि आधारित गतिविधियां: वित्तीय मध्यस्थ गैर-निधि गतिविधियों के आधार पर सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इसे 'फीस आधारित' गतिविधि कहा जा सकता है। आज ग्राहक, चाहे व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट, वित्त के प्रावधानों से संतुष्ट न हों। वे वित्तीय सेवाओं की कंपनियों से अधिक उम्मीद करते हैं। इसलिए इस सिर के तहत विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उनमे शामिल है:

- सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजीगत मुद्दे से संबंधित पूर्व-मुद्दे और बाद के मुद्दे की गतिविधियों के पूंजीगत मुद्दे का प्रबंधन करना और इस प्रकार प्रमोटरों को उनके मुद्दे का विपणन करने में सक्षम बनाना।
- निवेश संस्थानों के साथ पूंजी और ऋण उपकरणों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था करना।
- ग्राहकों की परियोजना लागत या उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय संस्थानों से धन की व्यवस्था।
- सभी सरकार और अन्य मंजूरी मिलने की प्रक्रिया में सहायता करना।

2. आधुनिक गतिविधियां

उपर्युक्त पारंपरिक सेवाओं के अलावा, वित्तीय मध्यस्थ हाल के दिनों में असंख्य सेवाएं प्रदान करते हैं। उनमें से ज्यादातर गैर-निधि आधारित गतिविधि की प्रकृति में हैं। महत्व को ध्यान में रखते हुए, ये गतिविधियां 'नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं' के प्रमुख के तहत संक्षेप में हैं। हालांकि, उनके द्वारा प्रदान की गई कुछ आधुनिक सेवाएं यहां संक्षेप में दी गई हैं।

- आवश्यक सरकारी अनुमोदन के साथ परियोजना शुरू करने के लिए धन जुटाने तक परियोजना रिपोर्ट की तैयारी से सीधे परियोजना सलाहकार सेवाएं प्रस्तुत करना।
- एम एंड ए के लिए योजना बनाना और उनकी चिकनी परिचालन के लिए सहायता करना।
- पूंजी पुनर्गठन में कॉर्पोरेट ग्राहकों को मार्गदर्शन करना।
- डिबेंचर धारकों को ट्रस्टी के रूप में कार्य करना।

- बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रबंधन संरचना और प्रबंधन शैली में उपयुक्त परिवर्तनों की सिफारिश करना।
- उपयुक्त संयुक्त उद्यम भागीदारों की पहचान करके और संयुक्त उद्यम समझौतों की तैयारी करके वित्तीय सहयोग / संयुक्त उद्यमों का निर्माण करना।
- पुनर्निर्माण की उचित योजना और योजना के कार्यान्वयन की सुविधा के माध्यम से बीमार कंपनियों का पुनर्वास और पुनर्गठन।
- स्वैप और अन्य व्युत्पन्न उत्पादों का उपयोग करके विनिमय दर जोखिम, ब्याज दर जोखिम, आर्थिक जोखिम और राजनीतिक जोखिम के कारण जोखिमों का हेजिंग।
- बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के पोर्टफोलियो का प्रबंधन।
- बीमा सेवाओं, खरीद-वापसी विकल्प इत्यादि जैसे जोखिम प्रबंधन सेवाएं उपक्रम
- आवश्यक धनराशि की मात्रा, उनकी लागत, उधार अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए धन के सर्वोत्तम स्रोत का चयन करने के सवालों पर ग्राहकों को सलाह देना।
- ऋण की लागत को कम करने और इष्टतम ऋण-इक्विटी मिश्रण के निर्धारण में ग्राहकों को मार्गदर्शन करना।
- रेटिंग कंपनियों के उद्देश्य के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को बढ़ावा देना जो ऋण साधन के मुद्दे से सार्वजनिक होना चाहते हैं।
- पूंजी बाजार से संबंधित उपक्रम सेवाएं, जैसे कि 1) क्लियरिंग सेवाएं, 2) पंजीकरण और स्थानान्तरण, 3) प्रतिभूतियों की सुरक्षित हिरासत, 4) प्रतिभूतियों पर आय का संग्रह।

वर्तमान परिदृश्य में वित्तीय सेवाओं की उपयोगिता और महत्व -

वित्तीय सेवाओं का महत्व है -

आर्थिक विकास और देश के विकास और सरकार की मौद्रिक और ऋण प्रबंधन नीतियों को लागू करने के लिए धनराशि का आयोजन करना

इसकी उपयोगिता निम्नलिखित में निहित है:

- वित्तीय सेवा सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रमुख हिस्सा है
- यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादक उद्यमों के लिए धन की कोई कमी नहीं है
- यह पर्याप्त वित्तीय संरचना और प्रणाली प्रदान करके लेनदेन और उधार लेने की लागत को कम करता है

- यह अच्छे वित्तीय निर्णय लेने में मदद करता है
- यह जोखिम के आवंटन में सहायता करता है और जोखिम को कम करने में मदद करता है
- यह वित्तीय गहराई और विस्तार में सहायता करता है
- यह रोजगार पैदा करता है
- यह उद्यमियों को उधार देने के लिए निवेशकों और व्यापार संगठनों से जोड़ता है

वित्तीय सेवाओं का महत्व

- वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट।
- वित्तीय बाजारों की गतिविधियों का विस्तार।
- सरकार के लाभ।
- आर्थिक विकास।
- आर्थिक विकास
- ग्रेटर यील्ड सुनिश्चित करता है।
- रिटर्न अधिकतम करता है।
- जोखिम को कम करता है।
- बचत को बढ़ावा देता है।
- निवेश को बढ़ावा देता है।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास।
- घरेलू और विदेशी व्यापार का प्रचार।

सारांश

एक प्रणाली जिसका लक्ष्य वित्तीय प्रणाली के रूप में ज्ञात जमाकर्ताओं और निवेशकों के बीच नियमित चिकनी, कुशल और लागत प्रभावी संबंध स्थापित करना और प्रदान करना है। वित्तीय संस्थानों, वित्तीय सेवाओं, वित्तीय बाजारों और वित्तीय उपकरणों की एक वित्तीय प्रणाली कंपनियां। ये घटक निकट से संबंधित हैं और एक दूसरे के साथ संयोजन में काम करते हैं। एक वित्तीय संपत्ति वह है जिसका उत्पादन या खपत के लिए या परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। वित्तीय मध्यस्थों में सभी प्रकार के वित्तीय संस्थान और निवेश संस्थान

शामिल हैं जो वित्तीय बाजारों में वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। वित्तीय बाजार वित्तीय दावों, संपत्तियों, सेवाओं और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं।

वित्तीय बाजार को संगठित और असंगठित बाजारों में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय दावों और वित्तीय बाजार में निपटाई गई प्रतिभूतियों जैसे वित्तीय दावों को वित्तीय उपकरणों के रूप में जाना जाता है। वित्तीय उपकरणों को प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिभूतियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाने के साथ, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रणाली के विकास ने एक अलग मोड़ लिया। सरकार ने नए वित्तीय संस्थानों को बनाना शुरू कर दिया है और यह भी कुछ वित्तीय संस्थानों को राष्ट्रीयकृत करना शुरू कर दिया है ताकि वित्त का प्रवाह सही दिशा में हो। भारतीय वित्तीय प्रणाली आज 50 साल पहले की तुलना में अधिक विकसित और एकीकृत है, लेकिन यह कुछ कमजोरियों से ग्रस्त है।

अभ्यास प्रश्न

1. भारतीय वित्तीय बाजारों के वर्गीकरण पर चर्चा करें और प्रत्येक बाजार की विशेषताओं की व्याख्या करें।
2. भारतीय वित्तीय प्रणाली में काम कर रहे विभिन्न वित्तीय मध्यस्थों को वर्गीकृत करें और उनकी विशेषताओं को सामने लाएं।
3. वित्तीय उपकरणों को परिभाषित करें? उनकी विशेषताएं क्या हैं?
4. भारत में वित्तीय प्रणाली के विकास का पता लगाएं।
5. "उपयुक्त विधायी उपायों के बावजूद, भारतीय वित्तीय प्रणाली कमजोर बनी हुई है।" टिप्पणी।

पाठन स्रोत

1. Bansal, L.K., Merchant Banking and Financial Services, Unistar Books Pvt. Ltd., Chandigarh.
2. Bhole, L.M., Financial Institutions and Markets, Tata McGraw Hill, New Delhi.
3. Chandra, P., Financial Management, Tata McGraw Hill, New Delhi.
4. Khan, M.Y., Financial Services, Tata McGraw Hill, New Delhi.
5. Kothari, C.R., Investment Banking and Customer Service, Arihand Publishers, Jaipur.
6. Machiraju, H.R., Merchant Banking, New Age International Publishers, New Delhi.
7. Srivatsava, R.M., Essentials of Business Finance, Himalaya Publishing, New Delhi.
8. Pandey, I.M., Financial Management, Vikas Publishing House, New Delhi.

9. Varshney, P.N., and Mittal D.K., Indian Financial System, Sultan Chand & Sons, New Delhi.

इकाई - II:
बैंकिंग की उत्पत्ति एवं विकास
(The Origin and Growth of Banking)

विषय सूचि

- बैंकिंग की उत्पत्ति (The Origin of Banking)
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली (The Indian Banking system)
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI)।
- बैंकों और प्रौद्योगिकी (Banks and technology)
- अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं (Tnternational banking services)

एक राष्ट्र और इसकी अर्थव्यवस्था के विकास में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक कई सेवाएं प्रदान करते हैं जिन्हें विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक बैंक लोगों के एक समूह (जमाकर्ताओं) से पैसे लेता है और इसे दूसरे (उधारकर्ताओं) को उधार देता है। यह (लगभग) निश्चित है कि इसे जमाकर्ताओं को चुकाना होगा; यह निश्चित नहीं है कि उधारकर्ताओं द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब है कि ऋण उन्नत से बने सकल लाभ मार्जिन होना चाहिए जिसे उधारकर्ता चूक के खिलाफ सेट किया जा सकता है। उधार देने का व्यवसाय किसी भी अन्य व्यवसाय जैसा ही है, उस बढ़ते लाभ में बढ़े हुए जोखिम की कीमत पर आता है। इस प्रकार एक बैंक बहुत जोखिम भरा उधारकर्ताओं को बहुत अधिक दरों पर उधार दे सकता है और आशा करता है कि डिफ़ॉल्ट दर लाभ में छोड़ने के लिए पर्याप्त है या बहुत कम दरों पर क्रेडिट योग्य उधारकर्ताओं को उम्मीद है। और उम्मीद है कि लाभ मार्जिन किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

बैंक का अर्थ और प्रकृति

एक बैंक एक संस्था है, आमतौर पर धन के रूप में प्रसारित करने के इरादे से अपने प्रोमिसरी नोट जारी करने के लिए शक्ति के साथ शामिल किया जाता है (बैंक नोट्स के रूप में जाना जाता है); या सामान्य जमा पर दूसरों के पैसे प्राप्त करने के लिए, एक संयुक्त फंड बनाने के लिए जो संस्थान द्वारा उपयोग किया जाएगा, अपने फायदे के लिए, अस्थायी ऋण और छूट के एक या अधिक उद्देश्यों के लिए; नोट्स, विदेशी और घरेलू बिलों का आदान-प्रदान, सिक्का, बुलियन, क्रेडिट, और पैसे की छूट; या इन दोनों शक्तियों के साथ, और विशेषाधिकारों के साथ, इन मूलभूत शक्तियों के अतिरिक्त, विशेष जमा प्राप्त करने और परक्राम्य कागज के धारकों के लिए संग्रह बनाने के लिए, यदि संस्थान ऐसे व्यवसाय में शामिल होने के लिए उपयुक्त दिखता है।

शब्द के आधुनिक अर्थ में बैंकिंग मध्यकालीन और प्रारंभिक पुनर्जागरण इटली, उत्तरी में समृद्ध शहरों जैसे फ्लोरेंस, लुका, सिएना, वेनिस और जेनोआ के लिए खोजा जा सकता है। 14 वीं शताब्दी फ्लोरेंस में बर्दी और पेरुज़ी परिवारों ने बैंकिंग पर प्रभुत्व रखा, यूरोप के कई अन्य हिस्सों में शाखाएं स्थापित की। सबसे प्रसिद्ध इतालवी बैंकों में से एक मेडिसी बैंक था, जिसे 1397 में जियोवानी डि बिस्की डी 'मेडिसि द्वारा स्थापित किया गया था।

सबसे पहले ज्ञात राज्य जमा बैंक, बानको डी सैन जियोर्जियो (सेंट जॉर्ज बैंक), जेनोआ, इटली में 1407 में स्थापित किया गया था।

प्राचीन भारत में वैदिक काल (1750 ईसा पूर्व से) से ऋण का सबूत है। बाद में मौर्य राजवंश (321 से 185 ईसा पूर्व) के दौरान, आदेश नामक एक उपकरण उपयोग में था, जो कि बैंकर पर एक आदेश था कि वह तीसरे व्यक्ति को नोट का पैसा चुकाने की इच्छा रखता है, जो कि बिल की परिभाषा के अनुरूप है विनिमय के रूप में हम आज इसे समझते हैं। बौद्ध काल के दौरान, इन उपकरणों का काफी उपयोग किया गया था। बड़े शहरों में व्यापारियों ने एक-दूसरे को क्रेडिट पत्र दिए।

बैंक की परिभाषा देश से देश में भिन्न होती है। अंग्रेजी आम कानून के तहत, एक बैंकर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बैंकिंग के कारोबार पर चलता है, जिसे इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है:

_ अपने ग्राहकों के लिए चालू खाते का संचालन,

_ उसके द्वारा तैयार चेक भुगतान, और

_ अपने ग्राहकों के लिए चेक एकत्रित करना।

अधिकांश आम कानून क्षेत्राधिकारों में एक्सचेंज एक्ट का बिल होता है जो चेक सहित विवादास्पद उपकरणों के संबंध में कानून को संहिताबद्ध करता है, और इस अधिनियम में बैंकर शब्द की वैधानिक परिभाषा होती है: बैंकर में व्यक्तियों का एक निकाय शामिल होता है, चाहे वह शामिल हो या नहीं, बैंकिंग के कारोबार को जारी रखें। यद्यपि यह परिभाषा परिपत्र प्रतीत होती है, यह वास्तव में कार्यात्मक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि बैंक लेनदेन के लिए कानूनी आधार जैसे चेक बैंक इस बात पर निर्भर नहीं है कि बैंक कैसे व्यवस्थित या विनियमित है।

बैंकिंग का व्यवसाय कई अंग्रेजी आम कानून देशों में है जो कानून द्वारा परिभाषित नहीं हैं बल्कि आम कानून द्वारा, उपरोक्त परिभाषा है। अन्य अंग्रेजी आम कानून क्षेत्राधिकारों में बैंकिंग या बैंकिंग व्यवसाय के कारोबार की सांविधिक परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं को देखते समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वे कानून के प्रयोजनों के लिए बैंकिंग के कारोबार को परिभाषित कर रहे हैं, और सामान्य रूप से जरूरी नहीं। विशेष रूप से, अधिकांश परिभाषाएं कानून से हैं जिनके पास बैंकिंग के वास्तविक व्यवसाय को विनियमित करने के बजाय बैंकों को विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य हैं। हालांकि, कई मामलों में वैधानिक परिभाषा आम कानून को बारीकी से प्रतिबिंबित करती है।

EFTPOS- Electronic Funds Transfer at Point Of Sale (बिक्री के बिंदु पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर), प्रत्यक्ष क्रेडिट, प्रत्यक्ष डेबिट और इंटरनेट बैंकिंग के आगमन के बाद, चेक बैंकिंग सिस्टम में भुगतान साधन के रूप में चेक ने अपनी प्राथमिकता खो दी है। इसने कानूनी सिद्धांतकारों को यह सुझाव देने के लिए प्रेरित किया है कि चेक आधारित परिभाषा को वित्तीय संस्थानों को शामिल करने के लिए विस्तृत किया जाना चाहिए जो ग्राहकों के लिए मौजूदा खाते आयोजित करते हैं और नोट्स ग्राहकों को तीसरे पक्ष द्वारा भुगतान और भुगतान करने में सक्षम बनाता है, भले ही वे चेक का भुगतान न करें और जमा न करें।

एचएल हेनरी ने एक बैंकर को परिभाषित किया, "जिसने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में व्यक्तियों द्वारा चेक किए गए चेक और जिनके लिए उन्हें चालू खाते पर पैसा मिला"। यह परिभाषा इस अर्थ में बहुत ही सीमित है कि जमा करने के व्यवसाय में लगे किसी भी व्यक्ति या संस्था को बैंक के रूप में बुलाया जा सकता है।

किन्ले की परिभाषा, "एक बैंक एक ऐसी प्रतिष्ठान है जो व्यक्तियों को ऐसे पैसे की अग्रिम बनाता है, जिन्हें आवश्यक और सुरक्षित रूप से बनाया जा सकता है और जिनके लिए उपयोग करने के लिए आवश्यकतानुसार व्यक्ति पैसे देते हैं।"

आरएस की परिभाषा हालांकि, सियर्स आधुनिक बैंक के सच्चे चरित्र को प्रकट करते हैं। अपने शब्दों में, "बैंक ऐसे संस्थान होते हैं जिनके ऋण आमतौर पर बैंक जमा के रूप में संदर्भित होते हैं, आमतौर पर अन्य लोगों के ऋण के अंतिम निपटारे में स्वीकार किए जाते हैं"।

ब्रिटिश कानून के तहत, "एक बैंकर वह है जो अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में, उन लोगों द्वारा सम्मानित चेक पर चेक करता है जिनके लिए उन्हें वर्तमान खातों पर पैसा मिलता है"। (डॉ हर्बर्ट एल हार्ट)

भारतीय कानून के तहत, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 19 4 9, "ऋण, निवेश के उद्देश्य के लिए, जनता से पैसे जमा करने, मांग पर चुकाया जा सकता है या अन्यथा और चेक, ड्राफ्ट और ऑर्डर या अन्यथा वापस लेना" (धारा 5 बी)।

शब्द 'बैंक' की उत्पत्ति

नाम बैंक इतालवी शब्द बैंको "डेस्क / बेंच" से लिया गया है, जो फ़्लोरेंटाइन के बैंकरों द्वारा पुनर्जागरण के दौरान उपयोग किया जाता है। ये बैंकर एक हरे रंग के टेबलक्लोथ से ढके डेस्क से ऊपर अपने लेनदेन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। प्राचीन काल में भी बैंकिंग गतिविधि का निशान हैं। असल में, शब्द अपनी उत्पत्ति को प्राचीन रोमन साम्राज्य में वापस ले जाता है, जहां मनीलाइंडर्स एक बैंच नामक एक लंबी पीठ पर मैकेला नामक संलग्न आंगनों के बीच में अपने स्टालों की स्थापना करेंगे। यहां से बेंको और बैंक शब्द उभरे हैं। सरल शब्दों में, एक बैंक एक संस्था है जो विभिन्न प्रकार के जमा स्वीकार करता है और फिर लोगों को ऋण की रूप में धन के रूप में धन अग्रिम करता है। धन और क्रेडिट, पिवट (धुरी) प्रदान करते हैं जिसके आसपास सभी आर्थिक गतिविधियां घूमती हैं।

बैंक संस्थान हैं, जो जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देने के लिए इन फंडों का उपयोग करते हैं। बैंक लाखों व्यक्तिगत बचतकर्ताओं के अधिशेष धन इकट्ठा करते हैं जो व्यापक रूप से बिखरे हुए हैं। एकत्रित धन निवेशकों के लिए चैनल किया गया है यानी लोग आगे निवेश उद्देश्यों के लिए ऋण मांग रहे हैं। बैंक धन वृद्धि और पूंजी निर्माण में मदद करते हैं। वे आर्थिक विकास और देश के विकास के लिए संसाधनों के जलाशयों हैं। वे बुनियादी ढांचे के निर्माण, कृषि को बढ़ावा देने, उद्योग स्थापित करने और वैश्विक व्यापार में सहायता करने में मदद करते हैं। इस प्रकार, एक बैंक, अपने कार्यों को निर्वहन करके देश की उत्पादक और मेहनती क्षमता को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है और विकास की गति को बढ़ाता है। बैंक वित्तीय प्रणाली का दिल हैं।

वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से 90 के दशक के आरंभ में भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार शुरू किए गए थे; इन सुधारों ने उपभोक्ताओं के लिए अधिक पसंद की सुविधा प्रदान की है, जो विभिन्न

समझदार चैनलों के माध्यम से उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए मजबूर बैंकों को अधिक समझदार और मांग कर रहे हैं। केवल वित्तीय मध्यस्थों के रूप में बैंकों का पारंपरिक चेहरा बदल गया है और जोखिम प्रबंधन उनकी परिभाषित विशेषता के रूप में उभरा है। भारतीय वित्तीय प्रणाली की पहचान दो संस्थानों के साथ की जाती है जैसे कि। नियामकों और मध्यस्थों। नियामक संस्थान भारतीय वित्तीय प्रणाली (आईएफएस) के विभिन्न हिस्सों की निगरानी और नियंत्रण के काम के साथ आवंटित सांविधिक निकाय हैं। इन संस्थानों को उनके संबंधित अधिनियमों के वाहन के माध्यम से पर्याप्त शक्तियां दी जाती हैं ताकि उन्हें सौंपा गया सेगमेंट की निगरानी कर सकें।

यह नियामक का काम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सेगमेंट के खिलाड़ी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक मानकों के भीतर काम करते हैं, प्रकटीकरण के पर्याप्त स्तर और संचालन की पारदर्शिता बनाए रखते हैं और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ कार्य नहीं करते हैं। वर्तमान में, भारतीय नियामक से सीधे जुड़े दो नियामक हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक और भारत के सुरक्षा और विनिमय बोर्ड हैं। मध्यस्थ वित्तीय संस्थानों में बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

बैंकिंग वित्तीय संस्थान अर्थव्यवस्था के भुगतान तंत्र में भाग लेते हैं, यानी, वे लेनदेन सेवाएं प्रदान करते हैं, उनकी जमा देनदारी राष्ट्रीय मुद्रा आपूर्ति का एक प्रमुख हिस्सा बनती है, और वे पूरी तरह से जमा या क्रेडिट बना सकते हैं, जो पैसा है। बैंक, कानूनी आरक्षित आवश्यकताओं के अधीन, अपने खिलाफ दावे बनाकर क्रेडिट अग्रिम कर सकते हैं। अन्य वित्तीय संस्थान बचतकर्ताओं द्वारा अपने निपटान में केवल संसाधनों से उधार दे सकते हैं।

परंपरागत रूप से, उन्होंने अपने संसाधन आरबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, बैंकों और अन्यों द्वारा सब्सक्राइब किए गए बांड के रूप में उठाए। 199 0 के दशक के शुरू में रिजर्व बैंक से रियायती दीर्घकालिक परिचालन निधि के सूखने के साथ, वित्तीय संस्थानों ने जमा बाजार के कम अंत में संसाधनों को तेजी से बढ़ाया है।

इस सेगमेंट में व्यापक रूप से वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान वित्त पोषण गतिविधियों को पूरा करते हैं लेकिन उनके संसाधन सीधे बचतकर्ताओं से ऋण के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बजाए, ये संस्थान निवेश सहित अन्य वित्तीय सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक बचत को एकत्रित करते हैं। ऐसे सभी संस्थान वित्तीय मध्यस्थ हैं और जब वे उधार देते हैं, तो उन्हें गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ (एनबीएफआई) या निवेश संस्थान के रूप में जाना जाता है।

उदाहरण:

- यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया/ Unit Trust of India,
- लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन / Life Insurance Corporation (LIC) और
- जनरल इंश्योरेंस निगम/ General Insurance Corporation (GIC)

इन NBFI के अलावा, भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक और हिस्सा निजी तौर पर स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत, और अपेक्षाकृत छोटे आकार के वित्तीय मध्यस्थों में शामिल है। अलग-अलग स्थानों पर अलग परिवेश में अधिकांश काम और बाजार को अधिक व्यापक और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। हालांकि उनमें से कुछ खुद को फंड-आधारित व्यवसाय तक सीमित करते हैं, कई अन्य विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। पूर्व प्रकार की

इकाइयों को "गैर बैंक वित्तीय कंपनियों (Non-bank Financial Companies (NBFCs))" कहा जाता है। बाद के प्रकार को "गैर बैंक वित्तीय सेवा कंपनियों (Non-bank Financial Services Companies (NBFSCs))" कहा जाता है।

भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग संरचना में वाणिज्यिक बैंकों और अनुसूचित बैंकों के अनुसूचित खिलाड़ियों के दो प्रमुख सेट शामिल हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों का गठन करते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

आरबीआई बदले में इस कार्यक्रम में केवल उन बैंकों को शामिल करता है जो अधिनियम की धारा 42 (60) के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। इस उप क्षेत्र में व्यापक रूप से निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक शामिल हैं।

1.2 भारतीय बैंकिंग प्रणाली की विशेषताएं

पिछले खंड में उल्लिखित बैंकों के अर्थ और प्रकृति से, बैंक की विशेषताओं / विशेषताओं को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है:

1. धन में लेनदेन: बैंक एक व्यावसायिक गतिविधि है जो अन्य लोगों के पैसे से संबंधित है यानी जमाकर्ताओं से धन प्राप्त करना और उधारकर्ताओं को उधार देना।

2. बैंकिंग व्यवसाय: एक बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो घरेलू ऋण, व्यापार ऋण, लॉकर्स, सावधि जमा इत्यादि जैसी वित्तीय सेवाओं को बेचने की बैंकिंग गतिविधियों को करता है ताकि लोगों को यह पुष्टि करने में सक्षम किया जा सके कि यह एक बैंक है और पैसे में काम कर रहा है, आसान पहचान के लिए, बैंक को "बैंक" शब्द को अंतिम नाम के रूप में जोड़ना चाहिए।

3. जमा की स्वीकृति: एक बैंक जमा राशि के रूप में लोगों से धन स्वीकार करता है जहां मांग पर जमा राशि वापस करने या एक निश्चित कार्यकाल की समाप्ति के बाद कोई दायित्व है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह धन जमा करने का सबसे सुरक्षित स्थान है।

4. धन उधार: एक बैंक व्यवसाय के प्रचार और विकास, घर की खरीद, कार आदि के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण के रूप में अग्रिम धन प्रदान करता है।

5. आसान भुगतान और निकासी सुविधा: हाथों में पैसे ले जाने की आवश्यकता के बिना चेक और ड्राफ्ट, एटीएम, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर जारी करने के माध्यम से पैसे का भुगतान और निकासी की जा सकती है। एक बैंक अपने ग्राहकों को चेक, ड्राफ्ट, एटीएम और ईटीएफ के रूप में आसान भुगतान और निकासी सुविधा प्रदान करता है।

6. सेवा अभिविन्यास के साथ लाभ का उद्देश्य: बैंक के पास सेवा उन्मुख दृष्टिकोण के साथ लाभदायक ढंग से जनता से जमा के रूप में प्राप्त धनराशि को नियोजित करने का एक मकसद है।

7. लिंकिंग ब्रिज: बैंक उन लोगों से धन इकट्ठा करते हैं जिनके पास अतिरिक्त धन है और उन्हें पैसे की जरूरत वाले लोगों को भी देना है। यह अपने ग्राहकों के धन के ट्रस्ट / संरक्षक के रूप में कार्य करता है। बैंक एक उधारकर्ताओं और धन के उधारदाताओं के बीच ब्रिजिंग लिंक के रूप में कार्य करता है।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली

बैंकिंग की स्वस्थ और कुशल प्रणाली के बिना, भारत में स्वस्थ अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली न केवल मुक्त होनी चाहिए बल्कि यह प्रौद्योगिकी और किसी अन्य आंतरिक और बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न नए खतरों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। पिछले तीन दशकों से भारत की बैंकिंग प्रणाली के अपने क्रेडिट में कई हड़ताली उपलब्धियां हैं। सबसे उत्कृष्ट इसकी व्यापक पहुंच है। भारत की बैंकिंग प्रणाली भारत के शहरी लोगों या विश्वमंडल तक सीमित नहीं है, लेकिन यह देश के दूर-दराज के हिस्सों तक भी पहुंच गई है।

इतिहास

आधुनिक बैंकिंग प्रणाली 1964 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के उद्घाटन के साथ शुरू हुई। बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक था। ब्रिटिश शासन के तहत बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने वाले सबसे शुरुआती संस्थान एजेंसी हाउस थे जो बैंकिंग व्यवसाय में थे उनकी व्यापारिक गतिविधियों के अलावा। इनमें से अधिकतर एजेंसी हाउस 1929 -32 के दौरान बंद कर दिए गए थे। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में क्रमश: 180 9, 1840 और 1843 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास नामक तीन प्रेसीडेंसी बैंक खुले थे। बाद में 1919 में बैंकिंग संकट के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया।

भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित देयता का पहला बैंक औध वाणिज्यिक बैंक 1881 में 1865 और 1870 के बीच शुरू हुआ था, केवल एक बैंक, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई थी। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने 1894 में लाहौर के अनारकली मार्केट (अब पाकिस्तान में) स्वदेशी आंदोलन में अपने कार्यालय के साथ 19 06 में शुरू किया, जिसने 1956 में शुरू किया, कई बैंकों जैसे बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल बैंक भारत, इंडियन बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड 1913-1917 के बीच बैंकिंग संकट ने 588 बैंकों की विफलता देखी। बैंकिंग कंपनियां (निरीक्षण अध्यादेश) जनवरी 1946 में आईं और बैंकिंग कंपनियों (शाखाओं का प्रतिबंध) अधिनियम फरवरी 1946 में पारित किया गया था। बैंकिंग कंपनी अधिनियम फरवरी 1946 में पारित किया गया था जिसे बाद में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 194 9 के रूप में जाना जाने लगा ।

इस बीच, आरबीआई अधिनियम, 1934 पारित किया गया था और 01.04.1935 को भारतीय रिजर्व बैंक देश का पहला केंद्रीय बैंक बन गया, इसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सेंट्रल बैंकिंग गतिविधियों को संभाला। भारतीय रिजर्व बैंक को 1/1/1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को आंशिक रूप से 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत किया गया था। 1959 में एसबीआई की सहायक कंपनियां, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की स्थापना की गई। 19 जुलाई, 1969 को सरकार भारत ने देश में 14 प्रमुख बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण को संभाला, जिसमें प्रत्येक को 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि थी। 15 अप्रैल 1980 को फिर से, 200 करोड़ से अधिक कुल समय

और मांग देनदारियों के साथ छह और बैंक राष्ट्रीयकृत थे। 1993 में, राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक अर्थात् न्यू बैंक ऑफ इंडिया को एक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया गया था।

भारत में बैंकों का वर्गीकरण

भारत में बैंकिंग संरचना में केंद्रीय बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। बैंकों को विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित आंकड़े बैंकिंग संरचना को इंगित करते हैं:

A) सेंट्रल बैंक:

भारतीय रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक है। यह पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है। यह एक केंद्रीय बोर्ड द्वारा शासित है और एक राज्यपाल की अध्यक्षता में है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह देश के भीतर चल रहे सभी बैंकों के कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी करता है।

B) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक:

1. स्टेट बैंक समूह: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी बैंक
2. 20 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित हैं

C) निजी क्षेत्र के बैंक:

1. निजी बैंक
2. भारत में संचालित विदेशी बैंक
3. अनुसूचित सहकारी बैंक
4. गैर अनुसूचित बैंक

D) सहकारी बैंक:

सहकारी क्षेत्र के बैंक ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं और मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों की सेवा करते हैं। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:

1. राज्य सहकारी बैंक
2. केंद्रीय सहकारी बैंक
3. प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसाइटीज

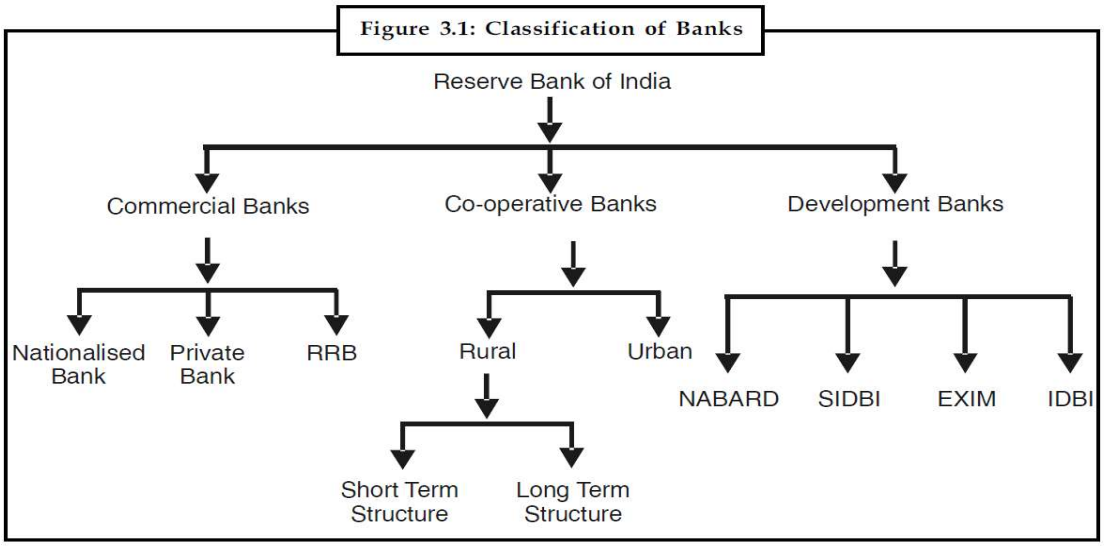

बैंकों को विभिन्न समूहों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण समूहों को नीचे समझाया गया है:

स्टेट बैंक समूह (आठ बैंक)

इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और एसबीआई के सहयोगी बैंक शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) एसबीआई के बहुमत और एसबीआई के कुछ सहयोगी बैंकों का मालिक है। एसबीआई के पास केंद्रीय बोर्ड की देखरेख में निदेशक मंडल द्वारा प्रत्येक 13 प्रमुख कार्यालयों को नियंत्रित किया जाता है। निदेशकों और उनकी समितियों के बोर्ड मासिक बैठकें करते हैं जबकि प्रत्येक केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति हर हफ्ते मिलती है।

राष्ट्रीयकृत बैंक (19 बैंक)

1969 में, सरकार ने शाखा नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 14 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था की, इसके बाद 1980 में छह और हो गए। एक विलय ने 20 से 19 तक की संख्या घटा दी। राष्ट्रीयकृत बैंक पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में हैं, हालांकि कुछ उन्होंने सार्वजनिक मुद्दों को बनाया है। राज्य बैंक समूह के विपरीत, राष्ट्रीयकृत बैंक केंद्रीय रूप से शासित होते हैं, यानी, उनके संबंधित प्रमुख कार्यालयों द्वारा। इस प्रकार, प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के लिए केवल एक बोर्ड होता है और मीटिंग कम होती है (आमतौर पर, महीने में एक बार)। राज्य बैंक समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों को एक साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) के रूप में जाना जाता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

19 75 में, स्टेट बैंक समूह और राष्ट्रीयकृत बैंकों को ग्रामीण राज्यों को कम लागत वाली वित्तपोषण और क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए अलग-अलग राज्यों के साथ साझेदारी में आरआरबी को प्रायोजित और स्थापित करने की आवश्यकता थी।

निजी बैंक

निजी बैंक ग्राहकों के उन्मुख उत्पादों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इस प्रक्रिया में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक स्पष्ट क्षेत्र के नियमों, निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व और शासन पर उनके दिशानिर्देशों पर आ गया है।

सहकारी बैंक

भारत में सहकारी बैंक 1904 में कृषि ऋण सहकारी समिति अधिनियम के अधिनियमन के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। यह ग्रामीण जनता के लिए बैंकिंग पहुंच का एक महत्वपूर्ण साधन है और भारतीय वित्तीय प्रणाली के लोकतांत्रिककरण के लिए एक वाहन है।

आरबीआई 1 मार्च, 1966 से इन बैंकों को नियंत्रित करता है। वित्तीय वर्ष 2001 में कुछ सहकारी बैंकों द्वारा की गई तरलता और दिवालियापन की समस्याओं के प्रकाश में, आरबीआई ने उधार देने से संबंधित उपायों सहित औपचारिक विधायी परिवर्तनों के लंबित मुद्दों को हल करने के लिए कई अंतरिम उपाय किए। शेयरों के खिलाफ, कॉल बाजार में उधार और अन्य शहरी सहकारी बैंकों के साथ सावधि जमा।

भारत में बैंकिंग सिस्टम का वर्तमान परिदृश्य

जिस दर पर भारत के बैंकिंग उद्योग ने पिछले दशक में भारी वृद्धि देखी है। जब वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान पूरी दुनिया स्पिन पर थी, तो भारत का बैंकिंग क्षेत्र अपनी लचीलापन को एक साथ विकास के अवसर प्रदान करने में सक्षम रहा है, जो कि दुनिया के अन्य विकसित बाजारों की तुलना में एक असंभव काम है। विश्व अर्थव्यवस्था ने विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के विलंब और हाल के दिनों में मांग को कम करने के मामले में गंभीर समस्याएं विकसित की हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के कारण संभावनाएं अनिश्चित हो गईं। हालांकि, इन सभी के बीच भारत के बैंकिंग क्षेत्र में लचीलापन बनाए रखने के लिए कुछ लोगों में से कुछ रहा है। एक प्रगतिशील बढ़ती बैलेंस शीट, क्रेडिट विस्तार की उच्च दर, विकसित बाजारों में बैंकों के समान लाभप्रदता और उत्पादकता का विस्तार, गैर-निष्पादित संपत्तियों की कम घटनाओं और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने से भारतीय बैंकिंग को जीवंत और मजबूत बनाने में योगदान दिया गया है। भारतीय बैंकों ने अपने विकास दृष्टिकोण को संशोधित करना शुरू कर दिया है और अर्थव्यवस्था पहिया को बनाए रखने के लिए संभावनाओं को फिर से हासिल किया है।

भारत के बैंकों के लिए आगे बढ़ने का तरीका नए व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए और साथ ही जोखिमों के निरंतर मूल्यांकन को सुनिश्चित करना है। ब्रिटिश शासन के दौरान सुधार की अवधि के दौरान पारंपरिक बैंकिंग प्रथाओं से, निजीकरण के लिए राष्ट्रीयकरण और विदेशी बैंकों की बढ़ती संख्या की वर्तमान प्रवृत्ति के लिए, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। पुराने से नए कारोबारी माहौल के कदम ने भारतीय बैंकों पर बढ़िया काम प्रवाह, इलेक्ट्रॉनिक मोड आदि के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन के लिए ग्राहकों की पूर्ण पहुंच आदि पर ताजा मांगें बनाई हैं। नियंत्रण और प्रौद्योगिकी के समानांतर बल द्वारा समर्थित कटघल प्रतियोगिता के उभरते परिदृश्य में डिग्री भारतीय वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का अभूतपूर्व स्तर बढ़ गया है। इसलिए बैंकों की कार्यात्मक दक्षता ने वर्तमान परिदृश्य में अपने अस्तित्व के लिए बहुत महत्व हासिल किया है। कामकाजी, आधुनिक

दृष्टिकोण और परंपरागत बैंकों के लिए काम करने के तकनीकी-समझदार तरीकों के कामकाज के पहले 4-6-4 विधि (4% पर उधार; 6% पर ऋण; 4 पर घर पर जाएं) (Borrow at 4%; Lend at 6%; Go home at 4) की शुरुआत की गई है। इससे सब कुछ भारत में खुदरा उछाल आया है। लोग सिर्फ अपने बैंकों से ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि अधिक प्राप्त कर रहे हैं। आसान क्रेडिट सुविधाओं के साथ बैंक आसानी से मासिक किश्तों ईएमआई पर माइक्रोवेव ओवन से घरों पर बिक्री के लिए भारतीयों की खपत प्रवृत्ति को बदल रहे हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, बैंकों ने बेहतर सिस्टम सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम) बड़े शहरों के अधिकांश इलाकों में किसी भी समय पैसा बांटती हैं और उपयोगकर्ता बैंकों के दौरे के बिना बैंकिंग लेनदेन का तेजी से जवाब दे रहे हैं। ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग ने बैंकों को अपने दरवाजे पर लगभग लाया है।

हालांकि, इसने बैंकों को नए प्रकार के जोखिमों का खुलासा किया है। बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच अंतरंगता तेजी से दूर हो गई है। हालांकि बैंक जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न बैक एंड एंड फ्रंट एंड ऑपरेशंस आवंटित करते हैं और सॉकेट परतों एसएसएल, डिजिटल सर्टिफिकेट्स और ऑनलाइन लेनदेन में जोखिम को कम करने के लिए वर्चुअल कुंजी बोर्ड जैसी सुविधाओं को सुरक्षित करते हैं, फ़िशिंग और फार्मिंग जैसे हमलों को प्रभावित किया गया है। चूंकि लेहमन ब्रदर्स ने 2008 में दिवालिया होने की घोषणा की, इसलिए, हर समय और घटनाओं ने वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर चिंताओं को बरकरार रखा है।

जबकि भारत सहित अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई) वैश्विक वित्तीय संकट से ठीक हो गई हैं, उन्नत देशों को निराशाजनक दिखने वाले विकास आंकड़ों से पीड़ित होना जारी है। यूरो क्षेत्र संकट यूरोपीय संघ के देशों में लहर प्रभाव के बाद फैल रहा प्रतीत होता है, राजनीतिक अशांति मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी (मेना) क्षेत्र में बनी हुई है, और अमेरिकी पूर्वानुमान में आर्थिक ठहराव खराब वैश्विक स्थिति से कोई राहत नहीं है। हालांकि, भारतीय बैंकों ने न केवल वैश्विक वित्तीय संकट से बेकार उभरा बल्कि 2010-11 के दौरान लचीलापन के साथ विकास का प्रबंधन जारी रखा। वर्तमान में, घरेलू मांग में वृद्धि की धीमी गति और कमोडिटी कीमतों के उच्च स्तर के कारण घरेलू मांग बरकरार रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुकूल जनसांख्यिकी और विकास क्षमता लंबे समय तक धुंधला प्रभाव को कम करने की उम्मीद है। जनगणना 2011 के अनुसार, लगभग 40% परिवार अभी भी बैंकिंग सुविधाओं का लाभ नहीं उठाते हैं। बैंकों की अग्रेषित रणनीतियों, बेहतर ग्राहक संबंध, राजस्व स्रोतों के विविधीकरण आदि के साथ उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को जारी रखने की उम्मीद है। प्रतियोगिता पर लेने के लिए बड़े बैंक बनाने का विचार आकर्षक लगता है। भारत के बैंकों के लिए वैश्विक स्तर की कमी हाल के वित्तीय संकट के दौरान तेज ध्यान में आई, जिसमें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैंकों ने भारतीय कंपनियों को अपनी वित्त पोषण प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार देखा, लेकिन स्थानीय बैंक बैलेंस शीट सीमाओं के कारण उल्लंघन में कदम नहीं उठा सके। इस प्रकाश में, हमारे सर्वेक्षण में सभी उत्तरदाताओं का 93.75% भविष्य में अपने परिचालनों का विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं।

बैंक की अपनी व्यावसायिक गतिविधि में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक साधन, और अकार्बनिक अर्थों में विलय या टेकओवर शामिल हैं। पिछले दशक में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में कई सकारात्मक विकास हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), वित्त मंत्रालय और संबंधित सरकारी और वित्तीय क्षेत्र नियामक संस्थाओं सहित नीति निर्माताओं ने इस क्षेत्र में विनियमन में सुधार के लिए कई उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। इस क्षेत्र में विकास,

लाभप्रदता और गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) जैसी मीट्रिक पर क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्रों के साथ अनुकूलता की तुलना की जाती है। कुछ बैंकों ने नवाचार, विकास और मूल्य निर्माण का एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह उनके बाजार मूल्यांकन में परिलक्षित होता है। हालांकि, इस क्षेत्र में सुधारित नियम, नवाचार, विकास और मूल्य निर्माण इसके एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित है। भारत में बैंकिंग मध्यस्थता की लागत अधिक है और अन्य बाजारों में बैंक प्रवेश बहुत कम है। भारत के बैंकिंग उद्योग को खुद को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है क्योंकि इसे जीवंत और आधुनिक अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है जिसे भारत चाहता है। इस परिवर्तन के बोझ के साथ बैंक के प्रबंधन की सफलता के लिए एक सक्षम नीति और अच्छा नियामक ढांचा बहुत महत्वपूर्ण होगा। कई विकसित देश बदलते बाजार वास्तविकताओं पर प्रतिक्रिया करने में असफल रहे हैं और इससे ही उनके वित्तीय क्षेत्रों के विकास को रोक दिया गया है। एक कमजोर बैंकिंग संरचना अपने निरंतर विकास को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं हो सकती है जिसने अपनी अर्थव्यवस्थाओं के दीर्घकालिक विकास को नुकसान पहुंचाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक: भूमिका और कार्य

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना के बाद, उसने भारत सरकार से पेपर मुद्रा जारी करने और इंपीरियल बैंक से क्रेडिट नियंत्रित करने का कार्यभार संभाला भारत की। यह मूल रूप से 5 करोड़ की एक पेड-अप पूंजी के साथ शेयरधारकों के बैंक के रूप में शुरू हुआ। इसे 1 जनवरी 1956 को राष्ट्रीयकृत किया गया था और तब से यह राज्य के स्वामित्व वाली और राज्य नियंत्रित सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य कर रहा है।

आरबीआई की भूमिका

रिज़र्व बैंक की `5 करोड़ की एक पेड अप पूंजी थी जो प्रत्येक 100 के 5 लाख शेयरों में विभाजित थी। भारत सरकार के सभी शेयरों का मालिक है। प्रबंधन केंद्रीय निदेशक मंडल में निहित है, जिसमें बीस सदस्य हैं जैसा कि नीचे दिया गया है:

1. पांच साल की नोटिस अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल और चार उप गवर्नर। उनके वेतन, इत्यादि का निर्णय केंद्रीय सरकार के निदेशक मंडल द्वारा भारत सरकार के परामर्श से किया जाता है।

2. बॉम्बे (मुंबई), कलकत्ता (कोलकाता), मद्रास (चेन्नई) और नई दिल्ली में स्थित स्थानीय बोर्डों से नामित चार निदेशक भारत सरकार द्वारा। उनका कार्यकाल भी पांच साल है।

3. भारत सरकार द्वारा नामित दस अन्य निदेशक जिनकी अवधि चार साल है।

4. केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार का एक अधिकारी। उनका कार्यकाल तय नहीं है और उन्हें बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं है।

5. अधिनियम के तहत, केंद्रीय बोर्ड को वर्ष में कम से कम छह बार मिलने के लिए आवश्यक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर केंद्रीय बोर्ड की बैठक को कॉल कर सकते हैं, जब भी वह आवश्यक सोचता है। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में कम से कम चार सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा चार साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और

सभी हितों का प्रतिनिधित्व करता है। स्थानीय बोर्ड केंद्रीय बोर्ड को सलाह देते हैं और केंद्रीय बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपी गई विभिन्न नौकरियां भी करते हैं।

आरबीआई के कार्य

मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक शीर्ष मौद्रिक संस्था है। यह देश के मौद्रिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और सरकारी बैंक के साथ-साथ बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। यह सरकार के प्रमुख वित्तीय संचालन करता है। यह वित्तीय संस्थानों के व्यवहार को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित करता है कि वे सरकार की आर्थिक नीति का समर्थन करते हैं। सेंट्रल बैंक का मुख्य कार्य मुद्रा, बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम से जुड़े मौद्रिक तंत्र को नियंत्रित करना है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक को व्यापक शक्तियां दी जाती हैं। केंद्रीय बैंक का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सरकार के बैंकिंग और वित्तीय संचालन का संचालन करना है। इसके अलावा, यह कुछ अन्य कार्यों को निर्वहन करता है। ये कार्य सेवा उद्देश्य के साथ किए जाते हैं न कि मुनाफा कमाते हैं

Figure 3.2: Role and Functions of Central Bank

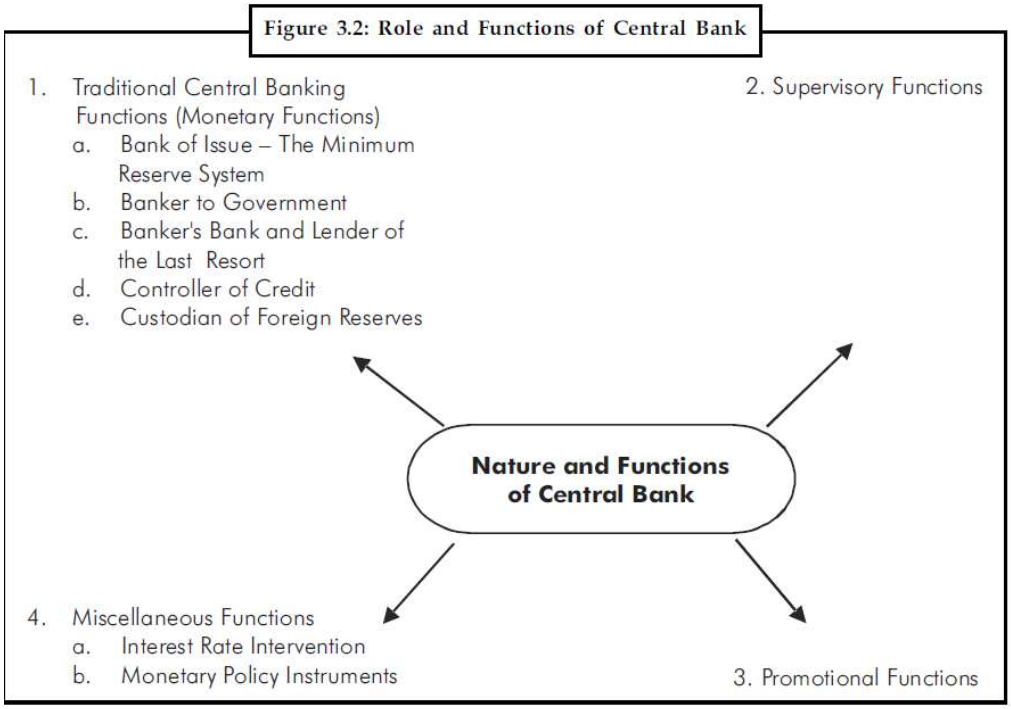

पारंपरिक केंद्रीय बैंकिंग कार्य (मौद्रिक कार्य)

Traditional Central Banking Functions (Monetary Functions)

बैंक ऑफ इश्यु - न्यूनतम रिजर्व सिस्टम

- _ रिज़र्व बैंक का एक अलग मुद्दा विभाग है, जिसे मुद्रा नोट जारी करने के साथ सौंपा गया है। जारी विभाग की संपत्ति और देनदारियों को बैंकिंग विभाग से अलग रखा जाता है।
- _ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत, बैंक को सभी संप्रदायों के बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है।

- _ भारत सरकार एक रुपये के नोट्स और सिक्कों और छोटे सिक्के और भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी ओर से बनाती है, पूरे देश में सरकार के एजेंट के रूप में वितरित करती है।
- _ मूल रूप से, जारी विभाग की संपत्ति में सोना सिक्का, स्वर्ण बुलियन या प्रतिभूतियों के दो-पांचवें से कम नहीं थे, बशर्ते सोने की मात्रा `40 करोड़ से कम न हो।
- _ परिसंपत्तियों का शेष तीन-पांचवां हिस्सा रुपए के सिक्कों के रूप में हो सकता है, भारत सरकार रुपये प्रतिभूतियां, विनिमय के योग्य बिल और भारत में देय प्रोमिसरी नोट्स।
- _ द्वितीय विश्व युद्ध की आपात स्थिति और युद्ध के बाद की अवधि के कारण, इन प्रावधानों में काफी सुधार हुआ था।
- _ 1957 से, भारतीय रिजर्व बैंक को 200 करोड़ रुपये के सोने और विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने की आवश्यकता है, जिनमें से कम से कम 115 करोड़ सोने में होना चाहिए। प्रणाली आज के रूप में मौजूद है इसे न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

सरकार के लिए बैंकर/ Banker to Government

भारतीय रिजर्व बैंक एक सरकारी बैंकर, एजेंट और सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

- _ रिजर्व बैंक जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, भारत सरकार और भारत की सभी राज्य सरकारों का एजेंट है।
- _ रिजर्व बैंक को सरकारी कारोबार को पारित करने का दायित्व है, नकद शेष को ब्याज से मुक्त रखने, सरकार की तरफ से भुगतान करने और भुगतान करने के लिए।
- _ सरकारी विनिमय प्रेषण और अन्य बैंकिंग परिचालनों को पूरा करें।
- _ भारतीय रिजर्व बैंक सरकार और संघ दोनों राज्यों को नए ऋण तैरने और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने में मदद करता है।
- _ यह 90 दिनों के लिए सरकारों को तरीके और साधन अग्रिम (डब्लूएमए) बनाता है।
- _ यह राज्यों और स्थानीय अधिकारियों को ऋण और अग्रिम बनाता है।
- _ यह सभी मौद्रिक और बैंकिंग मामलों पर सरकार के सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

बैंकर बैंक और अंतिम रिज़ॉर्ट का ऋणदाता / Bankers' Bank and Lender of the Last Resort

भारतीय रिजर्व बैंक बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है:

- _ 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिज़र्व बैंक के साथ अपनी मांग देनदारियों के 5% के बराबर नकदी शेष और भारत में अपनी देनदारियों का 2% बनाए रखने की आवश्यकता थी। 1962 में एक संशोधन से, मांग और समय देनदारियों के बीच भेद समाप्त कर दिया गया था और बैंकों को उनके कुल जमा देनदारियों के 3% के बराबर नकद भंडार रखने के लिए कहा गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक न्यूनतम नकदी आवश्यकताओं को बदल सकता है।

- _ वाणिज्यिक बैंक हमेशा बैंकिंग संकट के समय भारतीय रिजर्व बैंक की मदद के लिए आ सकते हैं; रिज़र्व बैंक न केवल बैंकर का बैंक बनता है बल्कि अंतिम उपाय का ऋणदाता भी बनता है।
- _ अनुसूचित बैंक पात्र प्रतिभूतियों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार ले सकते हैं।
- _ विनिमय के बिलों को फिर से जमा करके आवश्यकता या सख्तता के समय वित्तीय आवास प्राप्त कर सकते हैं।

क्रेडिट नियंत्रक/ Controller of Credit

भारतीय रिज़र्व बैंक क्रेडिट का नियंत्रक है। इसकी कुछ विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- _ खुले बाजार संचालन के माध्यम से, एक केंद्रीय बैंक सीधे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है।
- _ 19 4 9 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक किसी विशेष बैंक या पूरी बैंकिंग प्रणाली से कुछ प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर विशेष समूहों या व्यक्तियों को उधार देने के लिए नहीं कह सकता है।
- _ 19 56 से, क्रेडिट के चुनिंदा नियंत्रण तेजी से रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं।
- _ प्रत्येक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से भारत के भीतर बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
- _ अगर कुछ निश्चित शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो लाइसेंस रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द किया जा सकता है। एक नई शाखा खोलने से पहले प्रत्येक बैंक को रिज़र्व बैंक की अनुमति लेनी होगी।
- _ प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिज़र्व बैंक को एक साप्ताहिक रिपोर्ट भेजनी होगी, जो विस्तार से, इसकी संपत्तियों और देनदारियों को दिखाती है।
- _ रिज़र्व बैंक के पास किसी भी वाणिज्यिक बैंक के खातों का निरीक्षण करने की शक्ति भी है।
- _ जानकारी के लिए कॉल करने के लिए बैंक की ये शक्तियों का उद्देश्य क्रेडिट सिस्टम का प्रभावी नियंत्रण देना है।

विदेशी भंडार के संरक्षक / Custodian of Foreign Reserves

भारतीय रिज़र्व बैंक की आदान-प्रदान की आधिकारिक दर को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी है।

- _ 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार, बैंक को निश्चित दरों पर खरीदने और बेचने की आवश्यकता थी, जो कि 10,000 से कम नहीं है। तय विनिमय की दर `1 = sh थी। 6d। 1935 से, बैंक एलएसएच पर तय विनिमय दर को बनाए रखने में सक्षम था। 6d। हालांकि रुपये के पक्ष में या उसके पक्ष में अत्यधिक दबाव की अवधि थी।
- _ भारत 19 45 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने के बाद, रिजर्व बैंक की आईएमएफ के अन्य सभी सदस्य देशों के साथ निश्चित विनिमय दरों को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी है।

- _ रिजर्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के भारत के आरक्षित के संरक्षक के रूप में कार्य करना है, अर्थात विदेशी मुद्रा शेष बैंक द्वारा अधिग्रहण और प्रबंधित किया जाता है।
- आरबीआई की देश के विनिमय नियंत्रण को प्रशासित करने की ज़िम्मेदारी है।
- इस प्रकार, देश में सर्वोच्च बैंकिंग प्राधिकरण के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक के पास निम्नलिखित शक्तियां हैं:
- _ इसमें सभी अनुसूचित बैंकों का नकद भंडार है।
- _ यह मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण के माध्यम से बैंकों के क्रेडिट संचालन को नियंत्रित करता है।
- _ यह लाइसेंसिंग, निरीक्षण और जानकारी के लिए कॉलिंग प्रणाली के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है।
- _ यह अनुसूचित बैंकों को पुनर्वितरण सुविधाओं को प्रदान करके अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करता है।
- _ देश के विदेशी मुद्रा भंडार के नियंत्रक।
- _ अपने पारंपरिक केंद्रीय बैंकिंग कार्यों के अलावा, रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की निगरानी और भारत में ध्वनि बैंकिंग के प्रचार की प्रकृति के कुछ गैर-मौद्रिक कार्य हैं।

पर्यवेक्षी कार्य (गैर-मौद्रिक कार्य)/ Supervisory Functions (Non-monetary Functions)

- _ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 19 34, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 19 4 9 ने आरबीआई की व्यापक शक्तियां दी हैं।
- _ भारतीय रिजर्व बैंक को लाइसेंसिंग और प्रतिष्ठानों, शाखा विस्तार, उनकी संपत्ति की तरलता, प्रबंधन और काम करने, समामेलन, पुनर्निर्माण और परिसमापन के तरीकों के संबंध में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की निगरानी और नियंत्रण करना है।
- _ आरबीआई बैंकों के आवधिक निरीक्षण करने और रिटर्न और उनसे आवश्यक जानकारी के लिए कॉल करने के लिए अधिकृत है।
- _ जुलाई 19 6 9 में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने आरबीआई पर अर्थव्यवस्था के अधिक तेज़ी से विकास और कुछ वांछित सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में बैंकिंग और क्रेडिट नीतियों के विकास को निर्देशित करने के लिए नई जिम्मेदारियों को लागू किया।
- _ आरबीआई के पर्यवेक्षी कार्यों ने भारत में बैंकिंग के मानक में सुधार करने और ध्वनि संचालन के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए भारत में बैंकिंग के मानक में सुधार करने में काफी मदद की है।

प्रोमोशनल फ़ंक्शंस (गैर मौद्रिक कार्य)/ Promotional Functions (Non-monetary Functions)

आजादी के बाद, आर्थिक विकास के साथ, रिज़र्व बैंक के कार्यों की सीमा लगातार बढ़ी है। बैंक अब विभिन्न प्रकार के विकास और प्रचार कार्यों का प्रदर्शन करता है, जिसे एक समय में केंद्रीय बैंकिंग के सामान्य दायरे से बाहर माना जाता था।

1. रिज़र्व बैंक बैंकिंग आदत को बढ़ावा देता है।
2. ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाता है।
3. नई विशेष वित्त पोषण एजेंसियों अर्थात औद्योगिक विकास बैंकों की स्थापना और प्रचार करता है।
4. बचत को प्रोत्साहित करने और गांवों से धन उधारदाताओं को खत्म करने और कृषि को अल्पकालिक क्रेडिट मार्ग तक पहुंचाने के लिए सहकारी ऋण आंदोलन का विकास।

उदाहरण: कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम किसानों को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए।

बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी

Information Technology in Banking

कंप्यूटर और संचार तकनीकों के एकीकरण ने बैंकों के लिए विभिन्न अभिनव और ग्राहक अनुकूल उत्पादों / सेवाओं को प्रदान करने और उनके आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को फिर से डिजाइन करने के अवसर खोले हैं। डेटा संचार नेटवर्क सिस्टम इंटरफ़ेस और बैंकों की अंतःक्रियाशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेजी से बदलती तकनीकी समर्थित दुनिया के साथ, भारत में बैंक एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। कंप्यूटर से कंप्यूटर पर डेटा संचारित करने के लिए वर्षों से विभिन्न विधियों का उपयोग किया गया है। आंकड़ों को डेटा संचार मीडिया जैसे स्थलीय केबल्स, माइक्रोवेव और उपग्रह के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, सरफ कमेटी की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश के प्रमुख केंद्रों को जोड़ने वाले बैंकों के लिए एक देशव्यापी डेटा संचार नेटवर्क स्थापित किया है, जिसे जाना जाता है इंफिनेट (इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क) के रूप में और यह नेटवर्क पृथ्वी स्टेशनों के रूप में बहुत छोटे एपर्चर टर्मिनलों (वीएसएटी) के साथ उपग्रह संचार का उपयोग करता है। वीएसएटी नेटवर्क बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के विशेष उपयोग के लिए एक एकल बंद उपयोगकर्ता समूह नेटवर्क है। वीएसएटी का स्वामित्व व्यक्तिगत बैंकों और आरबीआई के पास है। हब आरबीआई और बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी) में विकास और अनुसंधान संस्थान के स्वामित्व में है। वीएसएटी प्रौद्योगिकी के आधार पर उपग्रह सेवाएं सभी साइटों के विश्वसनीय लिंक स्थापित कर सकती हैं। केंद्रीय केंद्र नेटवर्क यातायात के प्रवाह पर नज़र रखता है और नियंत्रित करता है

स्विफ्ट/ SWIFT

सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटर बैंक वित्तीय दूरसंचार (एसडब्ल्यूआईएफटी) बेल्जियम कानून के तहत स्थापित एक सहकारी गैर-लाभकारी संगठन है जो ब्रुसेल्स में अपने प्रमुख क्वार्टर के साथ स्थापित है। स्विफ्ट पूरी तरह से अपने सदस्य बैंकों के स्वामित्व में है। स्विफ्ट एक पेपरलेस संदेश ट्रांसमिशन सिस्टम है।

स्विफ्ट की विशेषताएं

1. पूरे साल 24x7 आधार पर संचालित होता है
2. सभी संदेश तुरंत दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रेषित होते हैं
3. संदेश प्रारूप मानकीकृत हैं
4. सूचना गोपनीय है और अनधिकृत प्रकटीकरण के खिलाफ सुरक्षित है
5. स्विफ्ट सटीकता और समय पर वितरण के लिए वित्तीय जिम्मेदारी मानता है

बैंकों के लिए स्विफ्ट का महत्व

- स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह सदस्य बैंकों को निम्नलिखित में सहायता करता है
- यह प्रमाणित वित्तीय और गैर वित्तीय संदेश संचारित करता है
- इसमें अच्छी तरह से मानकीकृत और संरचित संदेश प्रारूप हैं और संदेश संचरण की एक विश्वसनीय प्रणाली प्रदान करता है
- बैंक वित्तीय वित्त (विदेशी मुद्रा सौदों का निपटान) और अंतरराष्ट्रीय व्यापार (क्रेडिट के पत्र की सलाह, क्रेडिट पत्र आदि में संशोधन आदि) को कवर करने वाले वित्तीय और गैर वित्तीय संदेशों के संचरण के लिए स्विफ्ट मंच का उपयोग करते हैं।

स्वचालित समाशोधन प्रणाली/ Automated Clearing System

बैंकों ने मुख्य रूप से तीन प्रकार की समाशोधन प्रणाली का उपयोग किया- अर्थात् चिप्स, चैप्स और चैट (CHIPS , CHAPS and CHATS)।

1. **क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक भुगतान प्रणाली/ Clearing House Inter-bank Payment System (CHIPS) -** यह न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस द्वारा संचालित एक समाशोधन प्रणाली है। वित्तीय लेनदेन जैसे - विदेशी और घरेलू व्यापार सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय ऋण, सिंडिकेटेड ऋण, विदेशी मुद्रा व्यापार बस्तियों, CHIPS के माध्यम से किए जाते हैं। CHIPS के पास स्विफ्ट सिस्टम के साथ सीधा इंटरफ़ेस है।
2. **क्लियरिंग हाउस स्वचालित भुगतान प्रणाली/ Clearing House Automated Payment System (CHAPS) --**CHAPS ब्रिटेन में स्थापित एक स्वचालित प्रणाली है जो भुगतान के तुरंत निपटारे को सुनिश्चित करती है।
3. **क्लियरिंग हाउस स्वचालित ट्रांसफर सिस्टम/ Clearing House Automated Transfer System (CHATS)** -CHATS हांगकांग में इंटरबैंक स्थानांतरण सुविधाएं प्रदान करता है। CHATS उसी दिन अंतर बैंक निपटान, तत्काल आदेश पुष्टि और पूछताछ सुविधाएं प्रदान करते हैं। संदेश संचरण की अखंडता प्रमाणीकरण और एन्क्रिप्शन तकनीकों के माध्यम से की जाती है

इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन/ Electronic Fund Management

वर्षों और दशकों में बैंकिंग परिचालन में कई बदलाव हुए हैं और समय-समय पर नए नवाचारों को अपनाते रहे हैं। विशेष रूप से सूचना और प्रौद्योगिकी के मोर्चे में तकनीकी क्रांति ने बैंकों के कामकाज को बदल दिया है। आज के वैश्वीकृत प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल में बैंक टर्नअराउंड समय को कम करने, लागत में कटौती और दक्षता में वृद्धि के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

कई नवीन उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से "ई बैंकिंग" ने बैंकिंग परिचालन में क्रांति की है। बैंकों में धन प्रबंधन को संभालने के लिए बैंकों ने विभिन्न प्रणालियों को लागू करने के लिए आईटी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया है। इस पद्धति को सामूहिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन के रूप में पहचाना जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (Electronic Clearing System (ECS))

धन हस्तांतरण के शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक रूपों में से एक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। ईसीएस भुगतान (उपयोगिता बिल, लाभांश, ब्याज, इत्यादि) को प्रभावित करने के लिए एक खुदरा निधि हस्तांतरण प्रणाली है। ईसीएस निगमों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उपयोगिता सेवा प्रदाताओं को थोक भुगतान प्राप्त करने और / या भुगतान करने में सहायता करता है। ईसीएस ईसीएस (क्रेडिट) और ईसीएस (डेबिट) में बांटा गया है

ईसीएस - महत्वपूर्ण पहलुओं / विशेषताओं

आवश्यक जनादेश प्राप्त होने पर, ईसीएस के माध्यम से बैंक द्वारा धन (भुगतान / रसीद) को संभाला जा सकता है। ईसीएस (डेबिट) आमतौर पर बिजली कंपनियों, टेलीफोन कंपनियों और अन्य कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपयोगिता कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है ताकि वे सीधे अपने ग्राहकों के बैंक खातों से बिल भुगतान प्राप्त कर सकें। नकद या चेक भुगतान के माध्यम से उपयोगिता बिलों के भुगतान के बजाय, एक व्यक्ति या कंपनी ईसीएस के माध्यम से भुगतान कर सकती है। यदि कंपनी के पास ईसीएस के माध्यम से भुगतान की सुविधा है, तो ग्राहक कंपनी को अपने बैंक खाते से उपयोगिता बिल राशि प्राप्त करने के लिए एक जनादेश दे सकता है। ग्राहक द्वारा दिए गए ईसीएस जनादेश के आधार पर उपयोगिता कंपनी (सेवा प्रदाता), ग्राहक के बैंक को देय तिथि पर ग्राहक राशि के बिल राशि को डेबिट करने की सलाह देगी (या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार देय तिथि से पहले किसी भी तिथि पर) और राशि को कंपनी के अपने बैंक खाते में स्थानांतरित करें। इसी प्रकार, ईसीएस (क्रेडिट) लाभांश वारंट, वार्षिकियों के परिपक्वता मूल्य जैसे विभिन्न ग्राहकों को भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकता है।

वास्तविक समय सकल निपटान (Real Time Gross Settlement (RTGS))

भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में महत्वपूर्ण आईटी क्रांति में से एक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रीयल टाइम सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली का कार्यान्वयन था। मैन्युअल पर्यावरण से इलेक्ट्रॉनिक मोड में बदलते परिदृश्य के साथ, बैंकों ने धन हस्तांतरण के लिए तेज़, सुरक्षित और कुशल तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। आरटीजीएस एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है, जहां भुगतान निर्देशों को 'सतत' या 'वास्तविक समय' आधार पर संसाधित किया जाता है और क्रेडिट के खिलाफ डेबिट को नेट किए बिना 'ग्रॉस' या 'व्यक्तिगत' आधार पर निपटाया जाता है। भारत में, आरबीआई ने इस प्रणाली की शुरुआत की और प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है। इतने प्रभावित भुगतान 'अंतिम' और 'अपरिवर्तनीय' हैं। समझौता केंद्रीय बैंक (आरबीआई) की किताबों में किया जाता है। आरटीजीएस प्रणाली वास्तविक समय (तत्काल) आधार पर बैंकों में धनराशि के हस्तांतरण की अनुमति देती है। प्रत्येक प्रतिभागी बैंक को अपने आरटीजीएस लेनदेन के माध्यम से एक समर्पित निपटान खाता खोलने की जरूरत है। न केवल यह धनराशि के हस्तांतरण की अनुमति देता है, बल्कि यह क्रेडिट जोखिम को भी कम करता है। दोनों ग्राहक और बैंक बैंकिंग घंटों के भीतर नियमित अंतराल पर उसी दिन धनराशि को स्थानांतरित कर सकते हैं।

आरटीजीएस की विशेषताएं

1. वास्तविक समय सकल निपटान बैंकों को इंटरबैंक और विदेशी मुद्रा बस्तियों को सुलझाने में मदद करता है
2. यह बैंकों को बड़े टिकट धन हस्तांतरण को संभालने में भी मदद करता है
3. चूंकि आरटीजीएस इसे आरबीआई मंच के माध्यम से भेजा जाता है, इसलिए क्रेडिट जोखिम कम हो जाता है (यह धन के निपटारे में मुख्य लाभों में से एक है)
4. चेक क्लीयरेंस के मामले में, चेक का दराज फ्लोट टाइम का आनंद नहीं ले सकता है (चेक जारी करने की तारीख और जिस तारीख को उसे अपने बैंकर द्वारा अंदरूनी समाशोधन और डेबिट में प्राप्त किया जाता है) हालांकि, आरटीजीएस के मामले में, प्रेषक का खाता पहले डेबिट किया जाता है और फिर केवल धन हस्तांतरित किया जाता है
5. यदि लाभार्थी के नाम, खाता संख्या, प्राप्तकर्ता शाखा का आईएफएससी कोड, लाभार्थी बैंक का नाम इत्यादि के सभी प्रासंगिक विवरण सही तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं तो यह प्रेषण बैंक को तुरंत स्थानांतरण को प्रभावी करने में सहायता करेगा
6. इस मामले में, हस्तांतरण तंत्र वास्तविक समय पर काम करता है और इसलिए, लाभार्थी शाखा / बैंक को तुरंत धन प्राप्त करना चाहिए। लाभार्थी की शाखा / बैंक को धन हस्तांतरण संदेश प्राप्त करने के 2 घंटे के भीतर तत्काल या नवीनतम लाभार्थी के खाते को क्रेडिट देना चाहिए। हालांकि, यदि किसी भी कारण से धन जमा नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे फंड मूल शाखा में दो घंटों के भीतर वापस लौटाए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति में, जैसे ही धन वापस आ जाता है, प्रेषण बैंक को क्लाइंट के (प्रेषक) खाते में मूल डेबिट प्रविष्टि को उलट देना चाहिए। यह प्रणाली कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पर बैंक / शाखाओं के बीच लागू है

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (National Electronic Funds Transfer (NEFT))

एनईएफटी कुछ अंतरों के साथ आरटीजीएस के समान प्रणाली है। आरटीजीएस बड़े टिकट लेनदेन को संभालता है, जबकि एनईएफटी छोटे आकार के लेनदेन को संभालता है। अधिकांश शाखाएं इस सुविधा का उपयोग कुशलतापूर्वक धन हस्तांतरण के लिए कर रही हैं। एक बार आवेदक निधि के हस्तांतरण के लिए पूर्ण और सही विवरण प्रस्तुत करता है (सही खाता विवरण लाभार्थी का सही नाम, सही खाता संख्या, लाभार्थी की शाखा और बैंक, और सही आईएफएस कोड इत्यादि) को स्थानांतरित किया जा सकता है प्रेषण बैंक द्वारा लाभार्थी के खाते में। एनईएफटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरण सुरक्षित, त्वरित है। यह कागज के काम को कम करता है और लागत प्रभावी है। एनईएफटी फंडों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए एक अभिनव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।

एनईएफटी की विशेषताएं

एनईएफटी की प्रमुख विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं-

1. यह एक धन हस्तांतरण प्रणाली है जो किसी बैंक के किसी ग्राहक को किसी अन्य बैंक के किसी अन्य ग्राहक को धनराशि स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है जिसमें किसी भी भाग लेने वाले बैंक के खाते होते हैं

2. यह एक शहर और शहरों के भीतर अंतर और अंतर बैंक दोनों धन हस्तांतरण की अनुमति देता है
3. इसमें उपकरणों के किसी भौतिक आंदोलन को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए, धन को तुरंत स्थानांतरित किया जा सकता है
4. लाभार्थी ग्राहक को उसी दिन या अगले दिन जल्द से जल्द निपटारे के समय के आधार पर अपने खाते में धन मिलता है
5. मूल और गंतव्य बैंक शाखाएं एनईएफटी मंच पर होनी चाहिए
6. आईएफएससी, लाभार्थी का नाम, खाता संख्या इत्यादि का सही विवरण मूल बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
7. मूल बैंक शाखा एनईएफटी लेनदेन की स्थिति का ट्रैक रख सकती है।
8. किसी भी कारण से गंतव्य शाखा लाभार्थी के खाते में क्रेडिट नहीं दे पाती है, गंतव्य शाखा / बैंक को बैच के पूरा होने के दो घंटे के भीतर मूल बैंक को धन वापस करना होगा जिसके माध्यम से लेनदेन संसाधित किया गया था
9. यह धनराशि के हस्तांतरण का एकमात्र आसान तरीका नहीं है, बल्कि प्रेषकों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और लागत प्रभावी हस्तांतरण को सक्षम बनाता है

भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता (Indian Financial System Code (IFSC))

आईएफएससी एक अल्फा-न्यूमेरिक कोड है जो आरटीजीएस / एनईएफटी सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करता है। आईएफएससी के पास 11 अंक कोड हैं और पहले चार अल्फा वर्ण बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, 5 वां कोड 0 (शून्य) है, जो भविष्य के उपयोग के लिए आरक्षित है और अंतिम छः अंक संख्यात्मक वर्ण शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाभार्थी की शाखा और बैंक को धन हस्तांतरण के लिए गंतव्य के रूप में पहचानने के लिए सही आईएफएससी कोड आवश्यक है। जैसे सिंडिकेट बैंक कफ परेड शाखा, मुंबई- SYNB0005087

स्वचालित टेलर मशीनें (Automated Teller Machines (ATMs))

व्यक्तिगत ग्राहकों के नकद प्रबंधन के लिए एटीएम का उपयोग चैनल के रूप में किया जाता है। एटीएम को एटीएम कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। ग्राहक तक पहुंचने के लिए (कार्डधारक) को अपने बैंकर द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) और पासवर्ड तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। आम तौर पर नकदी जमा और निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले एटीएम का उपयोग यूटिलिटी बिलों के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है, जिससे धन हस्तांतरण होता है जिससे एटीएम इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। नई चेक बुक और खातों के बयान के लिए अनुरोध एटीएम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं।

व्हाइट लेबल एटीएम- आरबीआई ने 20 जून, 2012 की अधिसूचनाओं की सूचना दी है, गैर-बैंकिंग इकाइयों को एटीएम स्थापित करने या शुरू करने की अनुमति है जिसे व्हाइट लेबल एटीएम (डब्लूएलए) कहा जाता है। ऐसे एटीएम से किसी भी बैंक के ग्राहक पैसे वापस ले सकते हैं, टेकआउट स्टेटमेंट, पिन बदल सकते हैं। ये डब्लूएलए किसी भी बैंक के लोगो को प्रदर्शित नहीं करेंगे। हालांकि, डब्लूएलए ऑपरेटर को विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई है, और नियमों के अनुसार मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश की गई है। जबकि

डब्लूएलए ऑपरेटर बैंकों से अपने ग्राहकों द्वारा एटीएम संसाधनों के उपयोग के लिए शुल्क प्राप्त करने का हकदार है, डब्ल्यूएलए को सीधे डब्लूएलए के उपयोग के लिए बैंक ग्राहकों को चार्ज करने की अनुमति नहीं है।

इंटरनेट बैंकिंग/ Internet Banking

इंटरनेट बैंकिंग लोकप्रिय ई-बैंकिंग मोड में से एक ने बैंकिंग परिचालन को बदल दिया है और ग्राहकों को 24 x7 आधार पर वर्चुअल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इसे सुविधाजनक बैंकिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ग्राहक (खाता धारक) किसी भी समय बैंक के वेब साइट के माध्यम से किसी भी समय से अपने बैंक खाते तक पहुंच सकता है। ग्राहक को खाता विवरण और भुगतान और धन हस्तांतरण सुविधाओं तक ऑनलाइन पहुंच की अनुमति है। किसी बैंक की नेट बैंकिंग सेवाओं को व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) और एटीएम के मामले में एक्सेस पासवर्ड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। नेट बैंकिंग में बैंक ग्राहक के लिए लाभ यह है कि फंड को ग्राहक के बैंक खाते से दूसरे खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से उसी बैंक या किसी अन्य बैंक के साथ स्थानांतरित किया जा सकता है। धन हस्तांतरण सुविधा का एक अन्य तरीका करों का ऑनलाइन भुगतान है। बैंक ग्राहक आयकर, सेवा कर इत्यादि जैसे विभिन्न करों का भुगतान कर सकता है; नेट बैंकिंग को ग्राहक द्वारा उपयोगिता बिल (बिजली बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि) का भुगतान करने के लिए ग्राहक द्वारा एक चैनल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ग्राहक बीमा प्रीमियम और इसी तरह के अन्य भुगतान का भुगतान करने के लिए नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं।

कोर बैंकिंग/ Core Banking

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) बैंकिंग परिचालन और लेखांकन की देखभाल करने के लिए दुनिया भर में उपयोग किया जाने वाला बैंकिंग सॉफ्टवेयर है। यह पूरे बैंकिंग परिचालनों के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है। हालांकि, एक सीबीएस के कार्यों की श्रृंखला दूसरे से भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी सीबीएस की मूल विशेषता ऑनलाइन वास्तविक समय विनिमय का केंद्रीकृत है।

सीबीएस आवेदन एक केंद्रीय स्थान पर स्थापित किया गया है, जिसमें बैंक की सभी शाखाएं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डेटा संचार मोडों जैसे लीज्ड लैंडलाइन (Leased Landline), बहुत छोटे एपर्चर टर्मिनल (Very Small Aperture Terminal (VSAT)), इंटरनेट और मोबाइल इत्यादि से जुड़े हुए हैं। बैंक के सभी संचालन ऑनलाइन आयोजित किए जाते हैं सीबीएस प्लेटफार्म पर वास्तविक समय के माहौल में। लेन-देन एक स्थान पर संसाधित हो जाता है चाहे वह स्थान कहां से शुरू किया गया हो। इसलिए, ग्राहक किसी भी शाखा से परिचालन करने में सक्षम है, भले ही वह अपना खाता कहां रखती है। खाताधारक अब केवल शाखा के ग्राहक नहीं रहेंगे। वे बैंक के ग्राहक बन जाते हैं। व्यक्तिगत ध्यान पाने के उद्देश्य से वे एक शाखा से जुड़े हुए हैं। विभिन्न बैंकों के बीच सेवाओं की सीमा भिन्न हो सकती है क्योंकि कुछ बैंक अन्य शाखाओं में लेनदेन की राशि और आवृत्ति पर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तकनीक बाधा है, लेकिन यह बैंकों की आंतरिक परिचालन सीमाओं और नियंत्रणों के कारण है।

चूंकि शाखाओं में किए गए कई गतिविधियां सीबीएस के माध्यम से केंद्रीकृत होती हैं, इसलिए एक तरफ दक्षता में सुधार होता है और दूसरी तरफ लागत कम हो जाती है। शाखाएं ग्राहक सेवा और बिक्री पर अपना ध्यान केंद्रित

कर सकती हैं, जिससे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होता है, जो बदले में व्यावसायिक विकास में मदद करता है।

कई सीबीएस सॉफ़्टवेयर समाधान उपलब्ध हैं, जैसे फिनाकल/ Finacle, फ्लेक्सक्यूब/ Flexcube, BaNCS, T-24 इत्यादि। कई वैश्विक बैंकों ने अपनी बहुराष्ट्रीय आवश्यकताओं का ख्याल रखने के लिए अपने स्वयं के मालिकाना समाधान विकसित किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान पर भी काम कर रहा है, जिसे ई-कुबेर के रूप में नामित किया गया है, जो बैंकरों के बैंक के रूप में और सरकार के बैंकर के रूप में अपनी अनूठी आवश्यकताओं के लिए विधिवत अनुकूलित है।

कोर बैंकिंग समाधान का विवरण

कोर बैंकिंग समाधान को व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है:

कोर का अर्थ केन्द्रीय ऑनलाइन वास्तविक समय पर्यावरण अर्थात, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग वातावरण में मौलिक विशेषताओं का पालन करना है:

1. यह एक केंद्रीकृत मंच पर काम करता है
2. लेनदेन ऑनलाइन हैं
3. लेन-देन वास्तविक समय में किया जाता है यानी, कोई स्टोर और अग्रेषित प्रणाली नहीं है

'कोर' के शाब्दिक अर्थ के साथ-साथ "मूल और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा", सीबीएस मुख्य बैंकिंग कार्यों का ख्याल रखता है जैसे कि:

1. बचत, वर्तमान, फिक्स्ड और आवर्ती जमा आदि जैसे जमा उत्पादों की पूरी श्रृंखला।
2. ऋण, नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट इत्यादि जैसे उधार उत्पादों की पूरी श्रृंखला
3. प्रेषण, विदेशी मुद्रा, बिल संग्रह / भुगतान इत्यादि जैसे लेनदेन सुविधाओं की पूरी श्रृंखला।
4. उपरोक्त बैंकिंग उत्पादों से संबंधित लाभ और हानि खाते

अन्य सभी खातों के मामले में, कोर बैंकिंग से संबंधित नहीं, लेकिन लाभ और हानि और बैंक के सामान्य लेजर से संबंधित, इन खातों के अंतर्निहित लेनदेन की प्रक्रिया सीबीएस के बाहर की जा सकती है जबकि अंतिम खाता प्रविष्टियां पोस्ट की जाती हैं सीबीएस

उदाहरण में एक मामला डेबिट / क्रेडिट कार्ड लेनदेन है। कार्ड प्रबंधन प्रणाली लेनदेन की कार्ड से संबंधित प्रसंस्करण का ख्याल रखती है। एक बार कार्ड सत्यापन होने के बाद, लेनदेन के खाते से संबंधित हिस्से के लिए लेनदेन सीबीएस को भेजा जाता है। सीबीएस के मुख्य कार्यों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

1. सीबीएस में लाभ और हानि के साथ-साथ बैंक की संपत्ति और देनदारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सामान्य लेजर खाते शामिल हैं
2. कोर बैंकिंग व्यवसाय यानी, जमा, ऋण और अन्य बैंकिंग कार्यों को संसाधित करने के लिए सभी कंप्यूटिंग कार्यक्रम सीबीएस में रहते हैं

3. सीबीएस में क्लीयरिंग, ड्राफ्ट इश्यू, प्रेषण इत्यादि जैसे विभिन्न भुगतान प्रणालियों के संचालन के लिए सॉफ़्टवेयर समाधान शामिल है।
4. कोर बैंकिंग के संबंध में आय और व्यय खातों की गणना करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीबीएस में रहता है
5. उपरोक्त कोर बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े कार्यालय खातों को प्रबंधित करने के लिए सॉफ़्टवेयर समाधान सीबीएस का एक अभिन्न हिस्सा भी है

सीबीएस एक बैक एंड सिस्टम है, और यह दैनिक बैंकिंग लेनदेन को संसाधित करता है और उसके अनुसार रिकॉर्ड अपडेट करता है। सीबीएस ग्राहकों को किसी भी सीबीएस शाखा से अपने खातों को संचालित करने में मदद करता है। सीबीएस शाखा ग्राहकों को त्वरित धनराशि के समय में अपने धन हस्तांतरण को संभालने में सहायता करती है। यह ग्राहक को मूल शाखा के अलावा अन्य शाखाओं में धन वापस लेने और जमा करने में सहायता करता है, जहां वह अपना खाता बनाए रखता है।

किसी भी बैंकिंग सुविधा के तहत बैंकों द्वारा निम्नलिखित प्रकार के बैंकिंग संचालन की अनुमति दी जाती है:

1. खाते में शेष, डेबिट या क्रेडिट प्रविष्टियों के बारे में पूछताछ
2. चेक के माध्यम से खाते से नकद भुगतान
3. खाते में क्रेडिट के लिए चेक की जमा राशि
4. खाते में नकद जमा करना
5. खाते का विवरण प्राप्त करना
6. किसी अन्य शाखा में एक खाते से दूसरे खाते में धनराशि हस्तांतरण
7. डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर की जांच प्राप्त करना

विवरण भण्डारण/ Data Warehousing

डेटा वेयरहाउस या एंटरप्राइज़ डेटा वेयरहाउस (DWH/EDW) एक डेटाबेस है जो रिपोर्टिंग और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। यह डेटा का एक केंद्रीय भंडार है जो एक या एक से अधिक अलग स्रोतों से डेटा को एकीकृत करके बनाया गया है। डीडब्ल्यूएच स्टोर के साथ-साथ ऐतिहासिक डेटा और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा उपयोग के लिए ट्रेंडिंग रिपोर्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वेयरहाउस में संग्रहीत डेटा ऑपरेशन सिस्टम से अपलोड किया जाता है। डेटा खनन, ऑनलाइन विश्लेषणात्मक प्रसंस्करण और निर्णय समर्थन के लिए प्रबंधकों द्वारा उपयोग के लिए डेटा का मुख्य स्रोत साफ, रूपांतरित, सूचीबद्ध और उपलब्ध कराया गया है।

चेक की समाशोधन का कम्प्यूटरीकरण

पिछले कुछ सालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सुविधा के रूप में अभिनव प्रणालियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ताकि बैंक न केवल प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें बल्कि बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान कर सकें। आरबीआई समाशोधन घर और समाशोधन संचालन का प्रभारी है। इसने हमेशा क्लीयरिंग प्रक्रिया को तेज करने के साथ-साथ धन की निकासी में बदलाव के समय को कम करने के लिए नए सिस्टम पेश करने का नेतृत्व किया है। रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए पहले बड़े कदम आरबीआई द्वारा शुरू किए गए पहले बड़े कदम

थे, आरबीआई ने नए बदलावों के साथ सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। समाशोधन तंत्र के माध्यम से चेक की बढ़ती मात्रा को दूर करने के लिए, आरबीआई ने क्लीयरिंग हाउस ऑपरेशंस को पूरी तरह से स्वचालित कर दिया है। यह चुंबकीय इंक कैरेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है; आरबीआई ने एमआईसीआर चेक के नए सेट के साथ समाशोधन कार्यों को अपग्रेड किया। इस नई प्रणाली के तहत, चेक में एमआईसीआर कोड होना चाहिए जिसमें 9 अंक होंगे। प्रत्येक चेक में चेक नंबर के साथ अद्वितीय 9 अंकों का एमआईसीआर कोड होगा। एमआईसीआर कोड में 9 अंकों के रूप में शामिल हैं:

1. पहले तीन अंक शहर को इंगित करते हैं {शहर के पोस्टल पिन कोड के पहले तीन अंकों के समान (उदाहरण के लिए: मुंबई के मामले में, यह 400 होगा)}
2. अगले तीन अंक बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक बैंक को तीन कोड कोड दिया जाता है जिसे बैंक कोड कहा जाता है
3. पिछले तीन अंक शाखा कोड को इंगित करते हैं इस एमआईसीआर प्रणाली के तहत कंप्यूटर प्रोग्राम कोड के आधार पर चेक को पढ़ और सॉर्ट करेगा, इस प्रकार, त्वरित बदलाव समय में, सिस्टम वॉल्यूम को संभालने में सक्षम है।

जांच छंटनी प्रणाली (Cheque Truncation System (CTS))

चेक का उपयोग धन के आदान-प्रदान के लिए माध्यम के रूप में किया जा रहा है, जो ग्राहकों और बैंकों के धन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुशल चेक क्लियरिंग सिस्टम रसीदों और भुगतानों के निपटारे में मदद करता है। चेक बैंकिंग भारतीय बैंकिंग परिदृश्य में पेश की गई एक नई प्रणाली है। यह इलेक्ट्रॉनिक डेटा और / या छवियों के आधार पर बैंकों के बीच चेक क्लीयरेंस और निपटान की प्रणाली है, बिना भौतिक जांच और मांग ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, लाभांश वारंट इत्यादि जैसे परक्राम्य उपकरणों की आवश्यकता के बिना। चेक ट्रंकेशन सिस्टम की विशेषताएं प्रदान की जाती हैं। नीचे।

1. बैंक के ग्राहकों को उनकी जांच तेजी से महसूस हो जाएगी
2. त्वरित अहसास बेहतर नकद प्रबंधन (प्राप्तियां / देय) में मदद करता है
3. लंबे समय तक, यह बैंक के लिए प्रशासनिक लागत को कम करेगा
4. महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों को सुलह में और धोखाधड़ी को मंजूरी में कमी में मदद मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली
International Payment System

आज की तेजी से बढ़ती ई वाणिज्यिक गतिविधियों में, वैश्विक ई-कॉमर्स की सफलता के लिए बैंकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ई-कॉमर्स को अंत में समाप्त होना चाहिए, जैसे ग्राहक के अंत से, लाइन उत्पादों का चयन, ऑर्डर की नियुक्ति, और भुगतान करना और निपटाना। एक प्रभावी वैश्विक भुगतान चैनल वैश्विक ई वाणिज्य का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। वैश्विक भुगतान चैनल स्थापित करने से पहले, किसी संगठन को कुछ पहलुओं पर विचार करना चाहिए

1. **भुगतान का प्रकार:** क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन स्थानांतरण जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। ग्राहकों को भुगतान व्यवस्थित करने के लिए किसी भी विधि का

चयन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। आंतरिक जांच और संतुलित कार्य प्रणाली में एम्बेडेड होना चाहिए

2. **कानूनी फ्रेम कार्य / नियामक अनुपालन:** सिस्टम को केंद्रों में कानूनी और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए
3. **कर:** विभिन्न देशों में कराधान कानून अलग-अलग हैं। भुगतान प्रणाली में स्थानीय कर कानूनों के अनुसार आवश्यक करों, कर्तव्यों की गणना और गणना करने की क्षमता होनी चाहिए
4. **बैंकिंग संबंध:** वैश्विक ई वाणिज्य में सीमा पार व्यापार गतिविधियों को शामिल किया गया है और भुगतान के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों द्वारा इन भुगतानों को संसाधित करने के लिए सिस्टम को समर्थित किया जाना चाहिए। विभिन्न केंद्रों पर लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, भुगतान प्रणाली को अच्छी तरह से स्थापित बैंकों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।
5. **जोखिम:** वैश्विक ई वाणिज्य जोखिम के अधीन है। ऑनलाइन भुगतान जोखिम निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
    - क्रेडिट जोखिम: भुगतान करने के लिए ग्राहक के पास पर्याप्त धनराशि नहीं हो सकती है
    - धोखाधड़ी: भुगतान गलत तरीके से पहचान पर किया जा सकता है
    - अस्वीकार: ग्राहक भुगतान का सम्मान करने से इंकार कर सकता है
6. **सुरक्षा:** वैश्विक ई वाणिज्य विभिन्न सीमा सीमा राष्ट्रों के सामने आ गया है, इसलिए यह विभिन्न कानूनों और विनियमों के अधीन है। इसलिए, भुगतान प्रणाली देश विशिष्ट सुरक्षा नियमों / दिशानिर्देशों को संभालने में सक्षम होना चाहिए।

भुगतान प्रणाली की विशेषताएं

एक कुशल वैश्विक भुगतान प्रसंस्करण प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए;

1. एक एकल प्रणाली को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भुगतान सक्षम करना चाहिए
2. यह बहु मुद्रा और बहु भुगतान प्रकार का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए
3. प्रसंस्करण सुविधा 24 x 7 के लिए सक्रिय होना चाहिए
4. प्रणाली उच्च मूल्य लेनदेन को संभालने में सक्षम होना चाहिए
5. इंटरफ़ेस सुविधाओं को प्रणाली में उपलब्ध होना चाहिए ताकि सिस्टम को एक प्रकार के भुगतान को दूसरे प्रकार में स्विच करने में सक्षम बनाया जा सके (रीयल टाइम सकल निपटान (आरटीजीएस) स्वचालित क्लियरिंग हाउस (एसीएच)
6. स्विफ्ट जैसे संदेश स्विचिंग सिस्टम के साथ इंटर कनेक्टिविटी सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए
7. यह वर्तमान और भविष्य के प्रवाह / बहिर्वाह को संभालने में भी सक्षम होना चाहिए
8. महत्वपूर्ण बात यह है कि नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए इसमें सुविधा होनी चाहिए

जोखिम

भुगतान प्रणाली से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जोखिम हैं:

1. क्रेडिट जोखिम: वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पार्टी द्वारा विफलता
2. तरलता जोखिम: सिस्टम में एक पार्टी अपर्याप्त धन के कारण भुगतान करने में विफल रहता है
3. परिचालन जोखिम: मानव त्रुटि, सिस्टम विफलता, धोखाधड़ी आदि के कारण जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
4. कानूनी जोखिम: कानूनी या नियामक ढांचे का अनुपालन कानूनी जोखिम पैदा कर सकता है
5. सिस्टमिक जोखिम: पार्टियों में से किसी एक के डिफ़ॉल्ट होने के कारण सिस्टम में इसका चेन प्रभाव हो सकता है

कानूनी ढांचे

निम्नलिखित अधिनियम और विनियम भारत में भुगतान और निपटारे को संभालते हैं:

1. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007
2. भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन 2008
3. भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन 2008 के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड

अंतर्राष्ट्रीय पहल

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बेसल) ने वैश्विक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पहल की हैं। यह वैश्विक वित्तीय आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए भी कार्रवाई कर रहा है। भुगतान और निपटान प्रणाली (सीपीएसएस) की समिति के अनुसार, नियंत्रित भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए मूल सिद्धांत हैं:

1. प्रणाली सभी प्रासंगिक अधिकार क्षेत्र के तहत एक स्पष्ट कानूनी ढांचे पर आधारित होना चाहिए
2. सभी प्रतिभागियों को सिस्टम के नियमों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम होना चाहिए। प्रत्येक वित्तीय जोखिम पर सिस्टम के प्रभाव के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए
3. ई-कॉमर्स पर्यावरण में क्रेडिट और तरलता जोखिम महत्वपूर्ण जोखिम हैं। इसलिए बैंक भुगतान प्रणाली क्रेडिट और तरलता जोखिम प्रबंधन क्षेत्र को कवर करना चाहिए iv। तरलता प्रबंधन धन के समय पर निपटारे पर निर्भर करता है। इसके संदर्भ में, बैंकों के निपटारे प्रणालियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य तिथियों (दिन के दौरान और / या निश्चित रूप से दिन के अंत में बिना किसी विफलता के निपटारे हो। बहुपक्षीय जाल के मामले में, न्यूनतम पर, प्रणाली होना चाहिए एक बड़े टिकट लेनदेन के प्रतिभागी निपटारे में असमर्थ होने के मामले में दैनिक बस्तियों को पूरा करने में सक्षम है
4. प्रणाली में एकीकृत उच्च स्तर की सुरक्षा और परिचालन विश्वसनीयता होनी चाहिए
5. दैनिक प्रसंस्करण के समय पर पूरा होने के लिए किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों को संभालने के लिए सिस्टम में बैकअप सिस्टम होना चाहिए

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग:

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एक प्रकार का बैंकिंग है जिसमें राष्ट्रीय सीमा पार शाखाएं हैं। यह राष्ट्रीय बैंक के समान है लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को भी एक ही सेवा प्रदान करता है। इसमें व्यक्तियों और व्यवसायों जैसे दोनों प्रकार के क्लाइंट शामिल हैं। सेवा के प्रकार की पेशकश की

1) व्यापार वित्त व्यवस्था की व्यवस्था

एक अंतरराष्ट्रीय बैंक उन व्यापारियों के लिए वित्त व्यवस्था करता है जो विदेशी देश से निपटना चाहते हैं।

2) विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिए

अंतरराष्ट्रीय बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली मूल सेवाएं आयात-निर्यात उद्देश्य के लिए एक विदेशी मुद्रा व्यवस्था की व्यवस्था करना है।

3) धन को संभालने के लिए

अंतरराष्ट्रीय बैंक कम कीमत के स्तर पर प्रतिभूतियों को खरीदकर धनराशि को संभालने और मूल्य स्तर बढ़ने पर इसे बेचते हैं।

4) निवेश बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करें

यह शेयरों के अंडरराइटिंग, निवेश के लिए वित्तीय निर्णयों पर हस्ताक्षर करके एक निवेश बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता है।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के प्रकार

1) संवाददाता बैंक

संवाददाता बैंकों में अलग-अलग देशों में अलग-अलग बैंकों के बीच संबंध शामिल हैं। इस प्रकार का बैंक आम तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनके अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के बैंक छोटे आकार में हैं और उन ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं जो अपने देश से बाहर हैं।

2) एज अधिनियम बैंक

एज अधिनियम बैंक 19 19 के संवैधानिक संशोधन पर आधारित हैं। वे संशोधन के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार संचालित करेंगे।

3) ऑफ शोर बैंकिंग सेंटर

यह एक प्रकार का बैंकिंग क्षेत्र है जो विदेशी खातों की अनुमति देता है। ऑफशोर बैंकिंग उस विशेष देश के बैंकिंग विनियमन से मुक्त है। यह सभी प्रकार के उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करता है।

4) सहायक

सहायक वे बैंक हैं जो एक ऐसे देश में शामिल होते हैं जो किसी अन्य देश में आंशिक रूप से या पूरी तरह से मूल बैंक द्वारा स्वामित्व में है। सहयोगी सहायक कंपनियों से कुछ अलग हैं जैसे कि यह एक मूल बैंक के स्वामित्व में नहीं है और यह स्वतंत्र रूप से काम करता है।

5) विदेशी शाखा बैंक

विदेशी बैंक वे बैंक हैं जो कानूनी रूप से मूल बैंक के साथ बंधे होते हैं लेकिन एक विदेशी देश में काम करते हैं। एक विदेशी बैंक दोनों देशों के घर और एक मेजबान देश के नियमों और विनियमों का पालन करता है।

जोखिम के प्रकार

1) मुद्रा जोखिम

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करते समय एक अंतरराष्ट्रीय बैंक को मुद्रा विनिमय दर से परिचित होना पड़ता है। वे कंपनियां जो एक विदेशी देश में काम करना चुनती हैं और उस समय उन्हें मुद्रा जोखिम से निपटना पड़ता है।

2) राजनीतिक जोखिम

राजनीतिक जोखिम व्यापार को भी प्रभावित करता है क्योंकि व्यवसाय को मेजबान देश के नियमों और विनियमन का पालन करना पड़ता है और प्रत्येक देश के व्यापार पर उनका राजनीतिक प्रभाव पड़ता है। यदि राजनीतिक निर्णय प्रतिकूल हैं तो यह व्यवसाय को प्रभावित करता है।

3) प्रतिष्ठा जोखिम

प्रतिष्ठा जोखिम का मतलब प्रतिष्ठित पूंजी में वास्तविक या मनाए गए नुकसान के आधार पर प्रतिष्ठित पूंजी में संभावित हानि है। बैंक को बैंक, डेटा मैनिपुलेशन, खराब ग्राहक सेवा और अनुभव के बारे में अफवाहों जैसे प्रतिष्ठित जोखिम का सामना करना पड़ता है। ग्राहकों, निवेशकों, नेताओं और आलोचकों द्वारा बैंक की प्रतिष्ठा का निर्धारण किया जाता है।

4) व्यवस्थित जोखिम

व्यवस्थित जोखिम विशेष बैंक से संबंधित नहीं है लेकिन यह पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। एक व्यवस्थित जोखिम बड़ी इकाई की असफलताओं से जुड़ा हुआ है और यह पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के उदाहरण

1. सिटी समूह
2. एचएसबीसी होल्डिंग्स
3. बैंक ऑफ अमरीका
4. जेपी मॉर्गन चेस

5. रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड समूह।

सारांश

एक बैंक एक संस्था है जो इस तरह से धन और क्रेडिट से संबंधित है कि यह जनता से जमा स्वीकार करता है और अधिशेष निधि उन लोगों को उपलब्ध कराता है जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजने में मदद करता है। बैंकों को रिजर्व बैंक अनुसूची, स्वामित्व, निवास और कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वाणिज्यिक बैंक बुनियादी कार्य, एजेंसी कार्य और सामान्य उपयोगिता कार्य करते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. एक बैंक परिभाषित करें। आधुनिक अर्थ में बैंकिंग की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करें।

2. एक संस्था को बैंक क्यों कहा जाता है? बैंक के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

3. उन कार्यों को समझाएं जो एक आधुनिक बैंक प्रदर्शन करते हैं।

पाठन स्रोत

1. Sundharam, K.P.M., and Varshney, P.N., Banking and Financial System, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
2. Meir, Kohn, Financial Institutions and Markets, Tata McGraw Hill, New Delhi.
3. Maheshwari, S.N., Banking Law and Practice, Kalyani Publishers, Ludhiana.
4. Sundharam, Money Banking and International Trade, Sultan Chand & Sons, New Delhi.
5. Bedi, Suresh, Business Environment, Excel Books, New Delhi.

इकाई - III:
बीमा क्षेत्र
(Insurance Sector)

विषय सूचि

- बीमा क्षेत्र: परिचय, परिभाषा, जरूरत और महत्व (Insurance sector: Introduction, Definition, Need and Importance)
- जीवन एवं गैर जीवन बीमा (Life and non life insurance)
- निजी क्षेत्र के लिए बीमा क्षेत्र को खोलने के तर्क (Rationale for opening up of the Insurance sector to Private Sector)
- आईआरडीए अधिनियम तथा बीमा अधिनियम, 1938 का संक्षिप्त परिचय (A brief introduction to IRDA Act. Insurance Act, 1938)

"बिजनेस एंड फाइनेंस के शब्दकोश" में बीमा का अर्थ है "अनुबंध या समझौते का एक रूप जिसके तहत एक पार्टी किसी अन्य पार्टी को एक नुकसान, क्षति, या अच्छा करने के लिए एक सहमत राशि का भुगतान करने पर विचार करने के लिए बदले में सहमत होती है। कुछ अनिश्चित घटना के परिणामस्वरूप बीमित व्यक्ति के पास मूल्यवान कुछ हद तक चोट लगती है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा अनिश्चित घटना के कारण होने वाली हानि कई व्यक्तियों पर फैली हुई है जो इस बात से अवगत कराए जाते हैं और जिन्होंने इस तरह के आयोजन के खिलाफ खुद को बीमा करने का प्रस्ताव रखा था। "इस समझौते या अनुबंध को लिखित में जाना जाता है नीति के रूप में जिस व्यक्ति का जोखिम बीमित होता है उसे बीमित / आश्वासन दिया जाता है और वह व्यक्ति, जो बीमा करता है उसे बीमाकर्ता / आश्वासन / बीमाकर्ता के रूप में जाना जाता है। विचार वापस लौटाया जाता है जिसके लिए बीमाकर्ता बीमा करने के लिए सहमत होता है, बीमाकृत मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या सालाना नियमित रूप से भुगतान किया जाता है।

बीमा को दो स्तरों पर परिभाषित किया गया है:

1. कार्यात्मक स्तर और

2. कानूनी स्तर

कार्यात्मक परिभाषा

जॉन मेगी के मुताबिक, "बीमा एक ऐसी योजना है जहां व्यक्तियों में सामूहिक रूप से जोखिम का नुकसान साझा होता है"। रीगेल और मिलकर राज्य: बीमा मुख्य रूप से घटनाओं की अनिश्चितता को कम करने के लिए है। विलियम बेवरिज के अनुसार, जोखिम का सामूहिक असर बीमा है। उपर्युक्त परिभाषा से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ...

1. बीमा सुरक्षा प्रदान करता है

2. बीमा एक सहकारी व्यवस्था है जो बड़ी संख्या में लोगों के बीच जोखिम के नुकसान को वितरित करती है

3. बीमा एक फंड प्रदान करता है जिसमें से सदस्यों के नुकसान का मुआवजा दिया जाता है।

कानूनी परिभाषाएं।

टिंडल के मुताबिक, बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता द्वारा दिए गए आकस्मिकता पर बड़ी राशि का भुगतान करके बीमाकर्ता द्वारा जोखिम का भुगतान करने पर विचार किया जाता है।

ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, बीमा को एक सामाजिक उपकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है जहां समान योगदान के एक प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति के एक बड़े समूह द्वारा समूह के सभी सदस्यों को आम तौर पर आर्थिक नुकसान के कुछ मापनीय जोखिमों को कम या समाप्त कर सकते हैं।

आमतौर पर बीमा को किसी अप्रत्याशित स्थिति जैसे मृत्यु, स्थायी शारीरिक अक्षमता, व्यावसायिक उद्यम में क्षति, दुर्घटना से आर्थिक नुकसानों के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में देखा जा सकता है। बीमा कम्पनियां इन अप्रत्याशित स्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रीमियम लेती हैं। दावे का भुगतान पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों से संचित प्रीमियमों की राशि से किया जाता है और बीमा कम्पनियां प्रीमियम के रूप में संचित राशि के ट्रस्टी के रूप में कार्य करती हैं।

लाभार्थी का परिवर्तन

बीमा की पॉलिसी पर लाभार्थी का परिवर्तन एक सामान्य बात है। इसके लिए आपको बस अपनी बीमा कम्पनी से संपर्क करना होता है और लाभार्थी में परिवर्तन के लिए इसके निर्देशों का पालन करना होता है।

यद्यपि किसी व्यक्ति के लिए अपने पति या पत्नी, बच्चे, माता-पिता अथवा अन्य निकट संबंधियों का नाम बीमा लाभार्थी के रूप में देना आम बात है, किंतु गैर-संबंधी परिज, स्टेट, ट्रस्ट, व्यापार भागीदा, ऋण-दाता अथवा घरेलू भागीदार भी आपकी बीमा पॉलिसी के लाभार्थी नामांकित किए जा सकते हैं। आप अपनी बीमा पॉलिसी का परोपकारी कार्य हेतु दान भी कर सकते हैं।

बीमा महत्वपूर्ण है

एक नितांत अकेला व्यक्ति प्राय: सोचता है कि उसे बीमा पॉलिसी की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से कारक हैं जो यह तय करते हैं कि आपको बीमा की आवश्यकता है। यद्यपि आपके पास आमदनी का एक अच्छा जरिया है, किंतु जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अप्रत्याशित होती हैं। बीमा पॉलिसी आपको इन अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार करती है।

अलग पॉलिसी एक निवेश है

यदि आप अपने बच्चे का बीमा करवाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे के जीवन के लिए एक अलग पॉलिसी ले सकते हैं। आपका यह कदम आपके निवेश का मूल्यवर्धन करता है। आपको कब बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए यह

आपकी अपनी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। ऐसा कहना सही है कि कुछ भी अच्छा शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती।

यह निर्भर करता है सुरक्षा की प्रकृति पर और उस पर जिसे आप सुरक्षित करना चाहते हैं। कोई बीमा पॉलिसी लेने के लिए आपके द्वारा बीमा कम्पनी को प्रीमियम का भुगतान करना होता है। प्रीमियम के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाना है यह अनेक बातों पर निर्भर करता है जैसे पॉलिसी का प्रकार, पॉलिसी अनुबंध की अवधि, बीमाकृत राशि और आपकी उम्र।

प्रकार की बचत

आयकर अधिनियम के तहत बीमा एक प्रकार की बचत है

इन दिनों उपलब्ध ज्यादातर बीमा योजनाएं बचत के स्वरूप वाली होती हैं। ये पॉलिसियां आपके भविष्य की अज्ञात परिस्थितियों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। बीमा पॉलिसियां लेकर आप कर बचा सकते हैं। कर में छूट आयकर अधिनियम की धारा 80C, 80CCC के तहत दी जाती है।

एनडोमेन्ट पॉलिसी क्या है?

एनडोमेन्ट पॉलिसी बचतों के साथ-साथ जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा का एक मिलाजुला रूप है। ये पॉलिसियां खासतौर पर धन संचय के लिए और साथ ही अज्ञात भविष्य की परिस्थितियों में सुरक्षा के लिए बनाई जाती हैं। यह पॉलिसी की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। आमतौर पर बीमा पॉलिसियां वार्षिक, अर्ध-वार्षिक तथा त्रैमासिक रूप से प्रीमियम भुगतान की सुविधा प्रदान करती हैं। प्रीमियम के भुगतान में हमेशा नियमित रहें। प्रीमियम के भुगतान में देर होने पर बीमा कम्पनियां एक राहत अवधि (ग्रेस पीरियड) देती है। यदि आप इस राहत अवधि के दौरान प्रीमियम का भुगतान नहीं करते तो आपकी पॉलिसी रद्द हो जाती है।

बीमा एवं मैच्योरिटी

यह आपके द्वारा कराई गई बीमा की पॉलिसी पर निर्भर करता है। यदि यह जीवन बीमा है तो मैच्योरिटी पर आपको बीमाकृत राशि अथवा एक्युमुलेशन अमाउंट में से जो अधिक होगी वह मिलेगी। यदि यह ऑटो बीमा है तो मैच्योरिटी के बाद, यदि लागू होने योग्य है, तो आपकी पॉलिसी नवीकरण पर नो-क्लेम बोनस के अतिरिक्त आपको अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। यह याद रखें कि कुछ बीमा पॉलिसियां केवल जोखिम से सुरक्षा के लिए होती हैं।

यदि आपको बीमा प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त होता अथवा यह खो जाता है तो खो जाने अथवा नहीं प्राप्त होने की स्थिति बताकर डुप्लिकेट बीमा प्रमाणपत्र संबंधित कम्पनी से प्राप्त किया जा सकता है।

अब, भारतीय बीमा क्षेत्र में अनेक कम्पनियां कार्यरत हैं। बढ़ती प्रतियोगिता के कारण ये कम्पनियां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेहतर से बेहतर सेवा देने की कोशिश करती हैं। आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन-दोनों रूपों में पॉलिसी ले सकते हैं।

भारत में बीमा का उद्भव व विकास

भारत में समुद्री एवं अग्नि बीमा का वर्तमान स्वरूप इंग्लैण्ड से आया है। भारत में जीवन बीमा का शुभारम्भ 1818 में कलकत्ता में 'ओरिएन्टल लाइफ इन्श्योयोरेन्स कम्पनी' की स्थापना के साथ हुआ। 1823, 1829, 1847 में भी अन्य कम्पनियां स्थापित हुई। सन् 1850 में कलकत्ता में साधारण बीमा व्यवसाय हेतु ट्रिटोन इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. स्थापित की गयी। 1871 में बॉम्बे म्युचुअल लाइफ एश्योरेन्स सोसाइटी" नामक भारतीय संस्था की स्थापना की गई जो सामान्य प्रीमियम दरों पर भारतीयों का बीमा करने लगी। बाद में भी 1912, 1928 में भी अन्य अधिनियम बनाये गये। परन्तु 1938 में सभी अधिनियमों को एकीकृत करके बीमा नियमन हेतु एक बीमा अधिनियम बनाया गया

1907 में इण्डियन मर्केन्टाइल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. मुम्बई में स्थापित की गयी जिसने सर्वप्रथम अग्नि बीमा करना प्रारम्भ किया। फिर इस क्षेत्र में कई भारतीय व विदेशी संस्थानों ने कार्य करना प्रारम्भ किया। इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली का नियमन एवं नियन्त्रण करने हेतु भारत में बीमा अधिनियम 1 938 बनाया गया। इसी प्रकार सन् 1956 में इण्डिया रिइन्श्योरेन्स कार्पोरेशन लि. की स्थापना की गई जिसने देश की बड़ी बीमा कम्पनियों का बहुत बड़ी सीमा तक पुनर्बीमा करना प्रारम्भ कर दिया। 1956 में जीवन बीमा व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया व व्यवसाय संचालन हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना की गई व 245 देशी विदेशी बीमा कर्ताओं के व्यवसाय का अधिग्रहण कर जीवन बीमा निगम को सौंपा गया।

सन् 1971 में भारत के साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। समुद्री, अग्नि व विविध बीमा करने वाली 107 कम्पनियों को अधिगृहित कर भारतीय साधारण बीमा निगम व इसकी चार सहायक कम्पनियों को सौंप दिया। भारत में बीमाक्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारम्भ व 1993 में मल्होत्रा समिति के गठन के साथ ही हो गया था परन्तु विधिवत रूप से 1 दिसम्बर 1999 में लोकसभा में एक 31 विधेयक पारित कर निजीकरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया जब बीमा नियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 को बनाया गया।

मार्च 2003 से साधारण बीमा निगम की चारों सहायक कम्पनियों को भी इससे पृथक कर दिया गया। अब ये स्वतन्त्र कम्पनियों के रूप में बीमा व्यवसाय कर रही है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) ने भारतीय साधारण बीमा निगम को भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अधिकृत कर दिया गया है। अब सामान्य बीमा जीवन बीमा के क्षेत्र में कई निजी कम्पनियां कार्य कर रही है

बीमा की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है: यह एक बीमाकार (बिमा कंपनी) और बीमीत (व्यक्ति और कम्पनी) के बीच अनुबन्ध है जिसके तहत बीमाकार (बिमा कंपनी) निश्चित धनराशि (प्रीमियम) के बदले बीमित (व्यक्ति और कम्पनी) को एक निश्चित घटना (चोट लगना, मृत्यु होना, आग लगना इतियादी) के घटित होने पर एक निश्चित राशि देने का वादा करता है अथवा जिस जोखिम का बीमा कराया गया है उसकी वास्तविक हानि होने पर उसकी पूर्ति का वादा बीमाकार (बिमा कंपनी) करती है।

बीमा के सिद्धांत**:**

1. **पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत :** पूर्ण विश्वाश का सिधांत : इस सिद्धांत के तहत बीमा कंपनी और व्यक्ति दोनों के बीच में पूरा विश्वास होना चाहिए. जब कोई बीमा कंपनी किसी का बीमा करती है तो उसे पूरे विश्वास के साथ जानकारी देनी चाहिए. बीमा के बारे में पूरी सच्चाई बतानी चाहिए कि हमारी कंपनी किस तरह का जोखिम कवर करती है क्या-क्या कंडीशन लागू होती है और इस बीमा प्लान के अंदर क्या करने से आपको दिक्कत इन सभी के बारे में बीमा कंपनी का कर्तव्य है कि वह हमें पूरी सच्चाई बताएं.

   इसी तरह से जब कोई व्यक्ति अपना बीमा करवाता है तो उसे भी बीमा कंपनी को पूरी सच्चाई बताने चाहिए की उसे किसी भी तरह का तो नहीं है, क्या उसने पहले भी कोई बीमा करवाया है यानी कि अपने बारे में बीमा कंपनी जॉब ही पूछे पूरी पूरी सच्चाई बताना.

2. क्षतिपूर्ति का सिद्धांत :**Principle of Indemnity :** इस सिद्धांत के तहत यह होता है कि जिस व्यक्ति या कंपनी में बीमा करवाया है उसे केवल उसकी कारण के लिए क्षति पूर्ति या मुआवजा मिलेगा जिसके लिए उसने बीमा करवाया. आसान भाषा में समझे तो हम मान के चलते हैं किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान का फायर इंश्योरेंस करवाया है और कुछ समय बाद उनकी दुकान में लाखों रुपए की चोरी हो जाती है बीमा कंपनी चोरी हुए सामान का कलीम नहीं देगी.

3. योगदान के सिद्धांत / **Principle of Contribution :** इस सिद्धांत के तहत यह होता है कि अगर व्यक्ति ने किसी वस्तु के लिए एक से अधिक बीमा पॉलिसी ले रखी है तो वह नुकसान होने के दौरान एक से अधिक क्लेम नहीं ले सकता.

   हम मान के चलते हैं कि राजेश ने अपनी दुकान का कंपनी नंबर 1 से तीन लाख रूपय का बीमा करवाया है और कंपनी नंबर दो से उसने 200000 रूपय का बीमा करवाया है और जब उसकी दुकान में किसी भी तरह का नुकसान हो जाता है तो वह या तो कंपनी नंबर 1 से मुआवजा ले सकता है या फिर कंपनी नंबर 2 से एक साथ वह दोनों कंपनियों से मुआवजा नहीं ले सकता.

4. **प्रस्थापन का** सिद्धांत / **Principle of Subornation** : इस सिद्धांत के अंदर यह होता है कि बीमा करवाने वाला व्यक्ति अपनी वस्तु का क्लेम लेने के बाद में उस वस्तु का मालिक नहीं रहता अब उस वस्तु पर पूर्ण अधिकार बीमा कंपनी का हो जाता है.

जैसे कि मान के चलते हैं राजेश ने अपनी किसी मशीन का इंश्योरेंस करवाया है और आग लगने के कारण उसकी मशीन खराब हो गई. राजेश को बीमा कंपनी से पूरा क्लेम मिल गया अब खराब हुई मशीन को राजेश बेत नहीं सकता उस मशीन को बेचने का अधिकार बीमा कंपनी को है.

5. **न्यूनतम हानि का सिद्धांत / Principle of Loss Minimization** : यह सिद्धांत हमें बताता है कि बीमा धारक को अपनी संपत्ति का कम से कम नुकसान होने की कोशिश करनी चाहिए. मान के चलते हैं कि सुनील ने अपनी दुकान के लिए आग बीमा करवाया है और कुछ समय बाद उनकी दुकान में आग लग गई तो इस दौरान सुनील को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड को सूचित करें, पुलिस को इसके बारे में बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता लें ताकि उसकी दुकान कम से कम नुकसान हो.

बीमा की विशेषताएँ एवं प्रकृति

1. जोखिम से सुरक्षा - बीमा जोखिमों से का सशक्त उपाय है। जीवन में व्याप्त सभी अनिश्चितताओं से व्यक्ति को चिन्तामुक्त करता है। ये जोखिमें जीवन , स्वास्थ्य, अधिकारों तथा वित्तीय साधनों, सम्पत्तियों से सम्बन्धित हो सकती है। अत: इन सभी जोखिमों से सुरक्षा का एक उपाय बीमा ही है।

2. जोखिमों को फैलाने का तरीका - बीमा में सहकारिता की भावना के आधार पर "एक सब के लिए व सब एक के लिए कार्य किया जाता है। समान प्रकार की जोखिमों से घिरे व्यक्तियों को एकत्रित कर एक कोष का निर्माण किया जाता है ताकि एक व्यक्ति की जोखिम समस्त सदस्यों में बँट जाये व किसी एक सदस्य को जोखिम उत्पन्न होने पर उस कोष से उस सदस्य विशेष को भुगतान कर दिया जाता है।

3. **जोखिम का बीमितों से बीमाकर्ता को हस्तान्तरण** - बीमा में समस्त बीमितों की जोखिमों को बीमाकर्ता को अन्तरण कर दिया जाता है। बीमाकर्ता द्वारा बीमित को हानि होने पर निश्चित भुगतान कर दिया जाता है।

4. **बीमा एक प्रक्रिया** - बीमा एक प्रक्रिया भी है जो पूर्व निर्धारित विधि से संचालित की जाती है। पहले बीमित अपनी जोखिम का अन्तरण बीमाकर्ता को निश्चित प्रीमियम के बदले करता है तत्पश्चात् बीमा कर्तव्यता द्वारा उस जोखिम के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है।

5. **बीमा एक अनुबन्ध** - बीमा में वैधानिकता का गुण होने से यह एक वै ध अनुबन्ध है। इसमें बीमित द्वारा बीमाकर्ता को प्रस्ताव दिया जाता है व बीमाकर्ता द्वारा स्वीकृति दे ने पर निश्चित प्रतिफल (प्रीमियम) के बदले दोनों के मध्य एक वैध अनुबन्ध निर्मित होता है। जिसमें एक निश्चित घटना के घटित होने पर बीमाकर्ता उसकी हानि की पूर्ति करने का वचन दे ता है।

6. **बीमा सहकारी तरीका है** - बीमा सहकारिता की भावना पर आधारित है। समान प्रकार की जोखिमों से घिरे व्यक्ति एक निश्चित कोष में अंशदान करते है , उसमें से किसी भी सदस्य को जोखिम उत्पन्न होने पर उस कोष से भुगतान कर दिया जाता है। इस प्रकार "सब एक के लिए व एक सब के लिए *की भावना पर कार्य किया जाता है।*

7. **हानियों' जोखिमों को निश्चित करना** - बीमा में जोखिमों को समाप्त नहीं किया जा सकता है , परन्तु जोखिमों की अनिश्चितता को कम व निश्चित अवश्य किया जाता है। बीमित द्वारा बीमा कम्पनी को जोखिमों का अन्तरण किया जाता है व एक निश्चित प्रतिफल / प्रीमियम से उस जोखिम का मू ल्य निश्चित कर दिया जाता है। अर्थात् निश्चित प्रीमियम के बदले अनिश्चित हानियों को बीमा कम्पनी द्वारा मिलने वाली बीमा राशि के रूप में निर्धारित कर दिया जाता है। यही राशि बीमा दावा राशि कहलाती है।

8. **घटना के घटित होने पर ही भुगतान** - बीमा में घटना के घटित होने पर ही भुगतान किया जाता है। जीवन बीमा में घटना का घटित होना निश्चित है , जैसे - व्यक्ति की मृत्यु होना , किसी विशेष बीमारी से ग्रसित होना, बीमा अवधि का पूर्ण हो जाना तो ऐसी स्थिति में बीमित को भुगतान होता ही है। परन्तु सामान्य बीमों में घटना के घटित होने पर ही भुगतान होगा अन्यथा बीमित भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं माना जायेगा।

9. **जोखिम का मू ल्यांकन व निर्धारण** - बीमा में जोखिम का मू ल्यांकन बीमा अनुबन्ध के पूर्व ही कर लिया जाता है। जोखिम की राशि व जोखिम के उत्पन्न होने की सम्भावना के आधार पर प्रीमियम का पूर्व निर्धारण कर लिया जाता है। इस निश्चित प्रतिफल / प्रीमियम के बदले निश्चित जोखिम उत्पन्न होने पर निश्चित बीमित राशि का भुगतान किया जाता है।

10. **भुगतान का आधार** - जीवन बीमा में विनियोग तत्व निहित होता है अत: पक्षकार की मृत्यु होने अथवा अवधि पूर्ण होने पर निश्चित राशि का भुगतान बीमित को कर दिया जाता है। परन्तु अन्य बीमा में वास्तविक क्षति के बराबर ही भुगतान किया जायेगा। यह क्षति अनुबन्धानुसार बीमित कारणों से जोखिम उत्पन्न होने पर व बीमित राशि की सीमा में ही भुगतान किया जायेगा उससे अधिक राशि का भुगतान नहीं।

11. **व्यापक क्षेत्र** - बीमा का क्षेत्र अब बहुत विस्तृत हो गया है। पहले केवल जीवन बीमा, समुद्री बीमा व अग्नि बीमा का ही बीमा होता था पर अब परम्परागत जोखिमों के साथ गैर परम्परागत जोखिमों का भी बीमा किया जाता है। अब विविध बीमा का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। इसमे चोरी बीमा दुर्घटना बीमा, पशुधन बीमा, फसल बीमा आदि अनेक प्रकार बीमों को सम्मिलित किया गया किया गया है।

12. **संस्थागत ढांचा** - सम्पूर्ण विश्व में बड़ी-बड़ी संस्थाएं बीमा कार्य में लगी हुई है। भारत में जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम एवं उसकी चार सहायक कम्पनियां व कई निजी कम्पनियां बीमा के कार्य में लगी है।

13. **बीमा जुआ नहीं है** - बीमा में वास्तविक क्षति के बराबर ही क्षतिपूर्ति या सामान्य क्षति होने पर ही क्षति पूर्ति की जाती है , अत: बीमा की तुलना जुए से करना गलत है। जुए में एक पक्षकार लाभ में तो दूसरा पक्षकार हमे शा हानि में ही रहता है परन्तु बीमा में ऐसा नहीं होता है।

14. **बीमा दान नहीं , अधिकार है** - बीमा में बीमित द्वारा अंशदान दे कर अधिकार प्राप्त किया जाता है अनुबन्धात्मक सम्बन्धों के आधार पर बीमाकर्ता निश्चित प्रतिफल (प्रीमियम) के बदले बीमित को निश्चित समयावधि पश्चात् बीमा धन / दावा का भुगतान करता है।

15. **सामाजिक समस्याओं के निवारण का उपाय** - समाज में व्याप्त अनेक सामाजिक समस्याओं का निवारण बीमा के द्वारा किया जाता है क्योंकि बीमा से समाज की अनिश्चितताओं को निश्चिताओं में व जोखिमों को कम किया जाता है।

16. **बीमा कानून अनिवार्य** - आधुनिक युग में बीमा का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है इसके साथ ही सरकारों का कर्तव्य होता जा रहा है कि बीमा से सम्बन्धित नियामक अधिनियम बनाये। भारत में भी जीवन बीमा, समुद्री बीमा , साधारण बीमा हेतु अधिनियम बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त *बीमा नियन्त्रण एवं विकास प्राधिकरण" द्वारा सम्पूर्ण बीमा व्यवसाय का नियमन एवं नियन्त्रण किया जाता है।*

17. **बीमा सिद्धान्तों की अनिवार्यता** - बीमा अनुबन्ध हेतु कुछ सिद्धान्तों का होना अनिवार्य है। इनमें बीमा योग्य हित, परम सदविश्वास का सिद्धान्त, सहकारिता व संभाविता आदि मुख्य सिद्धान्त है। बीमा योग्य हित के सिद्धान्त के अभाव में बीमा जुए के समान माना जायेगा।

18. **वैध सम्पत्तियों / कार्यों का ही बीमा** - बीमा केवल वैध सम्पत्तियों का किया जा सकता है। चोरी, डकै ती तस्करी आदि के सामान का बीमा नही करवाया जा सकता है।

19. **बीमितों की बड़ी संख्या का होना** - एक ही प्रकार की जोखिम से घिरे व्यक्तियों का जितना बड़ा समूह होगा उतना ही बीमितों को कम प्रीमियम के बदले सुरक्षा प्राप्त होगी।

20. **हानि बीमित के नियन्त्रण के बाहर हो** - अज्ञात व अनिश्चित हानियों का ही बीमा करवाया जा सकता है। हानि होगी अथवा नहीं होगी, हानि की गहनता व तीव्रता क्या होगी ये सभी नियन्त्रण से बाहर होनी चाहिये

बीमा के प्रकार

बीमा के अनुबंध दो प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। वे अनुबंध जिनमें क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व होता है और वे जिनमें क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं होता वरन् एक निश्चित धनराशि अदा करने का अनुबंध होता है। क्षतिपूर्ति विषयक बीमा सामुद्रीय (मैरीन इंश्योरेंस) भी हो सकता है और गैरसामुद्रीय भी। पहले का उदाहरण समुद्र द्वारा विदेशों को भेजे जानेवाले समान की सुरक्षा का बीमा है और दूसरे का उदाहरण अग्निभय अथवा मोटर का बीमा है। क्षतिपूर्ति के अनुबंध में केवल क्षति की पूर्ति की जाती है। यदि एक ही वस्तु का बीमा एक से अधिक स्थानों (बीमा संस्थानों) में है तो भी बीमा करानेवाले को क्षतिपूर्ति की ही धनराशि उपलब्ध होती है। हाँ, वे बीमा कंपनियाँ आपस में अदायगी की धनराशि का भाग निश्चित कर लेती हैं। अतः क्षतिपूर्ति अनुबंध का यह सिद्धांत जीवन बीमा तथा दुर्घटना बीमा पर लागू नहीं होता। अत: जीवन बीमा तथा दुर्घटना बीमा कितनी भी धनराशि के लिए किया गया है, बीमा करानेवाले को (यदि वह जीवित है) अथवा उसके मनोनीत व्यक्ति को वह पूरी रकम उपलब्ध होती है।

बीमा की विषय वस्तु अथवा प्रकृति के आधार पर बीमा को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है 1. जीवन बीमा 2. अग्नि बीमा 3. सामुद्रिक बीमा 4.अन्य प्रकार के बीमा ।

1. जीवन बीमा

मानव जीवन अनिश्चितताओं से भरा होता है। जीवन यापन के लिए मनुष्य को अनेक क्रियाएं करनी होती है, जिनमें कदम-कदम पर जोखिम होते हैं। किसी दुर्घटना या बीमारी से असमय मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार को वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पडता है। इसी प्रकार बुढ़ापे मे व्यक्ति के पास आराम से जीवन-यापन करने, चिकित्सा कराने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। अपने बच्चों के विवाह या उसे उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। जीवन बीमा के द्वारा हमें भविष्य की इन परिस्थितियों से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। इसमें बीमाकार एक निश्चित राशि बीमित व्यक्ति की मृत्यु अथवा एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देने का वचन देता है। इसके बदले मे बीमाकार (बीमा कंपनी) किश्तों में एक निश्चित प्रीमियम राशि लेता है. अब क्योकिं बीमित जोखिम का घटित होना सुनिश्चित है। अत: बीमित व्यक्ति को बीमा राशि देर-सबेर प्राप्त होना भी सुनिश्चित है. बीमित व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है अत: जीवन बीमा को जीवन आश्वासन भी कहा जाता है।

जीवन बीमा जीवन की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। लेकिन धीरे-धीरे इसके क्षेत्र को स्वास्थ्य बीमा, विकलांगता बीमा, पैंशन योजना आदि तक बढ़ा दिया गया है। मूल रूप से जीवन बीमा पालिसियां दो प्रकार की होती हैं। क. आजीवन बीमा पालिसी एवं ख. बंदोबस्ती बीमा पालिसी. आजीवन बीमा-पालिसी में प्रीमियम की राशि का भुगतान बीमित को आजीवन अथवा एक निश्चित अवधि के लिए नियमित रूप से करना होता है. बीमा राशि बीमित के उतराधिकारियों को उसकी मृत्यु के पश्चात देय होती है। यह पालिसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ली जाती है जो अपनी मृत्यु के पश्चात अपने पर आश्रित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता पहुंचाना चाहता है। दूसरी ओर बंदोबस्ती बीमा पालिसी एक निश्चित अवधि के लिए होती है अर्थात् बीमित व्यक्ति द्वारा एक निश्चित आयु को प्राप्त करने अथवा उस आयु को प्राप्ति करने से पूर्व उसकी मृत्यु की स्थिति में, बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि का भुगतान किया जाता हैं। आजीवन और बंदोबस्ती पालिसियों के अतिरिक्त कई अन्य पालिसियाँ भी शुरू की गई। जिनका उद्देश्य ग्राहकों को राशि निवेश हेतु प्रोत्साहन देना है। जोखिमों से सुरक्षा और बचत का लाभ साथ-साथ मिलने से इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ पालिसियों का संक्षिप्त विवरण-

1. संयुक्त जीवन बीमा पालिसी-

यह पालिसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जीवन को संयुक्त रूप से बीमित करती है। उनमें से किसी एक की मृत्यु होने पर जीवित व्यक्ति/व्यक्तियों को बीमा राशि देय होती है। सामान्यत: यह पालिसी पति पत्नी के जीवन पर अथवा दो साझेदारों के जीवन पर संयुक्त रूप से की जाती है।

2. धनवापसी (Money Back) पालिसी-

इस योजना में पालिसीधारक को कुछ समय के अंतराल पर भुगतान किया जता ा है। यह सामान्य स्थायी निधि बीमा पालिसी से हटकर हैं जिसमें जीवित रहने पर कुल भुगतान का लाभ केवल एक निश्चित आयु की प्राप्ति के बाद ही मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि धनवापसी पालिसी 20 वर्ष के लिए ली गई है तो बीमित राशि का 20 प्रतिशत प्रति पाँचं वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष एवं शेष 40 प्रतिशत बोनस सहित 20 वें वर्ष के पश्चात देय हो जाता है।

3. पेंशन योजना-

इस योजना के अंतर्गत पालिसी की अवधि के पश्चात ही जीवित रहने पर पालिसी धारक को पालिसी की राशि का भुगतान किया जाता है। बीमित राशि अथवा पालिसी की राशि का भुगतान जैसे-मासिक, छमाई अथवा वार्षिक किस्तों पर किया जाता है। उन लोगों के लिए उपयोगी है जो एक निश्चित आयु के पश्चात नियमित आय चाहते हैं।

4. यूनिट योजनाएं-

यह योजनाएं दोहरे लाभ अर्थात निवेश एवं बीमा दोनों का लाभ प्रदान करती हैं। पालिसी धारक द्वारा जिस प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जाता है उसे विभिन्न कंपनियों के अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय पर खर्च किया जाता है। परिपक्वता राशि मुख्य रूप से निवेश के बाजार मूल्य पर निर्भर करती है।

5. सामूहिक बीमा-

सामूहिक बीमा योजनाएं कुछ व्यक्तियों कुछ व्यक्तियों के समूह को कम लागत पर जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है। यह योजना किसी भी व्यावसायिक इकाई अथवा कार्यालय के कर्मचारियों के समूह के लिए

उपयोगी है। हमारे देश में जीवन बीमा का भारतीय जीवन बीमा निगम करती है। जिसका 19 जनवरी 1956 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बहुत सारी निजी कंपनियां भी जीवन बीमा व्यवसाय से आ गई है।

2. अग्नि बीमा

आग से होने वाली हानियों से सुरक्षा प्राप्त करने अग्नि बीमा कराया जाता है। अग्नि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकार प्रीमियम के बदले में अग्नि से होने वाली हानि की राशि या क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। अग्नि बीमा सामान्यत: एक वर्ष के लिए किया जाता है। इसका हर वर्ष नवीनीकरण भी कराया जा सकता है।

अग्नि से होने वाली हानि का भुगतान दो शर्तों के पूरा होने पर ही किया जाता है।

1. आग वास्तव में लगी हो, एवं
2. आग जानबूझ नहीं लगाई गई हो बल्कि दुर्घटनावश लगी हो. यहाँ आग लगने का कारण महत्व नहीं रखता।

अग्नि बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध है अर्थात बीमित सम्पत्ति की कीमत, अग्नि से क्षति अथवा पालिसी की राशि तीनों में से जो भी कम हो, से अधिक राशि का दावा नहीं कर सकता। अग्नि से हानि अथवा क्षति में हानि को कम करने के लिए की गई कोशिशों से होने वाली हानि अथवा क्षति भी सम्मिलित होती है।

3. सामुद्रिक बीमा

आज सामुद्रिक व्यापार काफी बढ़ गया है, साथ ही साथ इसके खतरे भी बढ़ गये है। सामुद्रिक बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी जहाज अथवा जहाजी माल को समुदी्र यात्रा के दरम्यान होने वाले जोखिम से क्षति की पूि र्त का आवश्वासन देती है। समुद्री यात्रा के मध्य जहाज को विभिन्न प्रकार का जोखिम होता है, तुफान, चट्टान या किसी अन्य जहाज से टकरा जाना आदि। सामुद्रिक हानियां तीन प्रकार की हो सकती हैं 1. जहाज को हानि 2. जहाजी माल की हानि एवं 3. माल भाड़े की हानि. इन हानियों का पृथक-पृथक बीमा किया जाता है। जहाज के बीमा को हल बीमा, माल के बीमा को माल बीमा (कार्गो) और भाड़े के बीमे को भाडा बीमा कहते हैं। अग्नि बीमा और समुद्री बीमा, सामान्य बीमे के अंतर्गत आते है. सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण 13 मई 1971 को किया गया।

4. अन्य प्रकार के बीमा

साधारण बीमा कंपनियां कई अन्य जोखिमों का बीमा का बीमा करती हैं जिनमें से कुछ बीमा पालिसियों का संक्षिप्त विवरण है :

1. वाहन बीमा-

यात्री कार, वैन, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि का बीमा दुर्घटना से वाहन को होने वाली क्षति, चोरी से होने वाली हानि तथा दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष को चोट पहुँचने अथवा मृत्यु हो जाने से उत्पन्न देनदारी के विरूद्ध बीमा है। वास्तव में वाहन का तीसरे पक्ष के संबंध में बीमा अनिवार्य है।

2. स्वास्थ्य बीमा-

यह पालिसी धारक को बीमारी अथवा चोट लगने आदि से होने वाले इलाज पर व्यय से सुरक्षा प्रदान करती है। इससे चिकित्सा दावा बीमा अथवा मैडीक्लेम बीमा कहते हैं। आजकल यह सर्वाधिक लोकप्रिय बीमा है।

3. फसल का बीमा-

यह सूखा अथवा बाढ़ के कारण फसल हो होने वाली हानि से किसानों को संरक्षण प्रदान करता है।

4. रोकड़ का बीमा-

यह बैंक एक अन्य व्यावसायिक ससं् थानों को नकदी एक स्थान से दसू रे स्थान पर ले जाते समय रास्ते में चोरी या किसी अन्य कारण से होने वाली हानि के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है।

5. पशुओ का बीमा -

यह गायें भैसें, बैल आदि के दुर्घटनावश, बीमारी आदि से मृत्यु के कारण होने वाली हानि के जोखिम का बीमा है।

6. राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना-

यह योजना बीमित महिला की मृत्यु अथवा उसके विकलांग हो जाने पर परिवार के सदस्यों को राहत पहुंचाती है।

7. अमत्र्य शिक्षा योजना बीमा पालिसी-

यह आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए ली जाने वाली पालिसी है। यदि बीमित व्यक्ति को कोई शारीरिक चोट पहुंचती है जिसके का कारण उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थाई रूप से विकलांग हो जाता है तो बीमा कम्पनी बीमित अविभावकों को आश्रित बच्चों की पढ़ाइर् का खर्च वहन करेगी।

8. चोरी से क्षति का बीमा-

इस प्रकार के बीमे में बीमा कम्पनी बीमित को चोरी से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देती है। चोरी या डकैती से हानि का अर्थ है चल-संपत्ति की लूटपात, चोरी आदि से हानि।

9. विश्वसनीयता का बीमा-

कर्मचारियों के द्वारा रोकड़ (नकदी) का घोटाला या फिर वस्तुओं के दुरूपयोग से हानि के जोखिम से संरक्षण के लिए व्यवसायी उन कर्मचारियों की, जो रोकड़ को संभालते हैं या फिर स्टोर के प्रभारी हैं, बेइमानी अथवा धोखे से होने वाली हानि के जोखिम के विरूद्ध बीमा कराता है। इसे विश्वसनीयता का बीमा कहते हैं।

बीमा की आवश्यकता

व्यक्तियों का जीवन अनेक प्रकार की अनिश्चितताओं एवं जोखिमों से घिरा हुआ है। उसे कुछ सम्पत्ति से सम्बन्धित जोखिमें है तो कभी जीवन को जोखिम है अत: वह इन जोखिमों के प्रति कै से सुरक्षा प्राप्त करे इसी विचार ने बीमा को एक आवश्यकता बना दिया है। वर्तमान औद्योगिक विकास का आधार ही प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से यदि बीमा

को कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी। मनुष्य जीवन को तनाव मुक्त करने हेतु बीमा एक महती आवश्यकता बन गया है। निम्न बिन्दुओं के आधार पर बीमा की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकता है-

1. जोखिमों के विरूद्ध सुरक्षा प्राप्ति हेतु -सम्पत्तियों का इसलिए बीमा किया जाता है कि उनके नष्ट होने की सम्भावना निरन्तर बनी रहती है या आकस्मिक घटना के घटित होने से अपने अपेक्षित जीवनकाल से पहले ही वे निष्क्रिय हो सकती है।

2. संभावित जोखिमों से सुरक्षा प्राप्ति हेतु -बीमाकृत विषयवस्तु को क्षति हो भी सकती है और नहीं भी, भू कम्प आ भी सकता है , और नहीं भी, भू कम्प आये तो हो सकता है सम्पत्ति को क्षति पहु$1चे अथवा नहीं। मनुष्य की मौत होना निश्चित है ले किन मृत्यु कब होगी समय अनिश्चित है , अत: इस अनिश्चितता या संभावित जोखिमों से सुरक्षा प्राप्ति हेतु बीमा आवश्यकता बन गया है।

3. जोखिमों के प्रभाव को कम करने हेतु - बीमा बीमाकृत विषयवस्तु को संरक्षण प्रदान नही करता है , खतरे के कारण पहु$1चाने वाली हानि को भी नही रोकता है खतरे को घटित होने से टाला भी नही जा सकता है। परन्तु कभी-कभी बेहतर सुरक्षातथा क्षतिनियन्त्रक उपायों द्वारा खतरे को टाला या तीव्रता को कम किया जा सकता है जिससे उस विषयवस्तु पर निर्भर व्यक्तियों के जीवन व सम्पत्ति पर खतरे के प्रभाव को कम अवश्य किया जा सकता है।

4. सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता से मुक्ति हेतु -बीमा उद्योगपतियों, व्यवसायियों एवं अन्य व्यक्तियों को सुरक्षा के लिए पूंजी वि नियोग से मुक्त कर दे ता है। थोड़ी सी प्रीमियम का भुगतान करके जोखिम को उस सीमा तक सीमित कर लिया जाता है। अतः इस व्यवस्था में लगने वाले धन का अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है।

5. वृहत स्तरीय उपक्रमों के विकास हेतु आवश्यक -वृहतस्तरीय उपक्रमों में इतनी अधिक जोखिम होती है कि बीमा के बिना प्रारम्भ करना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव भी हो सकता है।

6. वित्तीय संस्थाओं से वित्त प्राप्ति हेतु -वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी इन औद्योगिक व व्यावसायिक संस्थाओं को वित्त तभी प्रदान किया जाता है जबकि इनकी सम्पत्तियों का बीमा हो चुका है। अत : भारी मात्रा में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी बीमा आवश्यक है।

7. विदेशी व्यापार विकास हेतु आवश्यक -निर्यात व्यापार के प्रोत्साहन हेतु भी बीमा आवश्यक है। बीमा माल के मू ल्य की क्षति की दशा में भी पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है व जिससे निर्यातक क्षति की अनिश्चितता से मुक्त होकर निर्यात कर सकते हैं।

8. बचत व निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु -जीवन बीमा बचत व विनियोग का अच्छा स्रोत है। जीवन की अनिश्चितताओं को बीमा द्वारा निश्चित करने हेतु अधिक राशि का बी मा कराता है , जिससे अपव्यय कम होकर बचत को प्रोत्साहन मिलता है।

बीमा का महत्व

सभ्यता के विकास के साथ-साथ बीमा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है , क्योंकि जोखिमों, दुर्घटनाओं व अनिश्चितताओं , में वृद्धि होती जा रही हे आज हम ऐसे किसी दे श की कल्पना नहीं कर सकते जो बीमा का लाभ नहीं उठा रहा हो। आज बीमा प्रारम्भिक स्वरूप से हट कर सामाजिक व व्यावसायिक जगत के प्रत्येक क्षेत्र में पदार्पण कर चुका है और अपनी उपयोगिता के आधार पर लोकप्रियता प्राप्त करता जा रहा है। बीमा की उपयोगिता से प्रभावित होकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर विन्स्टन चर्चिल ने कहा था "यदि मेरा वश चले तो मैं द्वार-द्वार पर यह अंकित करा दूं कि बीमा कराओ।"

बीमा सम्पूर्ण मानवजाति एवं इससे सम्बन्धित सभी वर्गों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाता है। संक्षेप में कह सकते है कि आधुनिक युग में बीमा का महत्व दिन दुगुना रात चौगुना होता चला जा रहा है। बीमा के महत्व अथवा लाभों को निम्नांकित वर्गीकरण द्वारा समझा जा सकता है।

1. **जोखिम से सुरक्षा-** बीमा व्यवसाय को विभिन्न जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। यह सुरक्षा बीमित को हानि की पूर्ति के लिए प्रावधान के रूप में होती है।
2. **जोखिम का अनेक लोगों में विभाजन-**बीमा जोखिम को आपस में बांटने में सहायता प्रदान करता है. व्यवहार में बड़ी संख्या में लोग प्रीमियम देकर बीमा करवाते हैं। इससे बीमाकोष तैयार हो जाता है। इस कोष का उपयोग उन लोगों की क्षतिपूि र्त के लिए किया जाता है जिनको वास्तव में यह हानि होती है। इस प्रकार से हानि को बड़ी संख्या में लोगों में बाँट दिया जाता हैं।
3. **ऋण लेने मे सहायक-** बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं सामान्य: ऋण देने से पहले उन वस्तुओं एवं सम्पत्तियों का बीमा कराने पर जोर देते हैं जिनकी जमानत पर वह ऋण दे रहे हैं। इस प्रकार से बीमा वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करने को सुगम बनाता हैं।
4. **विभिन्न श्रम कानूनो के अंतर्गत देनदारी से सुरक्षा-** बीमा व्यवसायी को कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होने पर जिसके कारण गंभीर चोट, विकलांगता अथवा बीमारी हो जाने पर तथा प्रसूति आदि की स्थिति में क्षतिपूर्ति संबंधी भुगतान के समय सुरक्षा प्रदान करता है।
5. **आर्थिक विकास में योगदान-** बीमा कपं नियों के पास जमा धन को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूि तयों एवं परियोजनाओं में निवेश किया जाता है जो दश्े ा के आर्थिक विकास में योगदान देता है।
6. **रोजगार के अवसरों की उपलब्धता-** बीमा कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों को नियमित रोजगार देती हैं। कई लोग बीमा एजेन्ट के रूप में कार्य कर अपनी जीविका अर्जित करते हैं।
7. **सामाजिक सुरक्षा-** जीवन बीमा बुढ़ापे एवं समय से पूर्व मृत्यु के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है. इसके साथ साथ कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के माध्यम से जिसमें दुर्घटना बीमा भी सम्मिलित है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता हैं।

वैयक्तिक या पारिवारिक दृष्टि से महत्व

बीमा से व्यष्टि स्तर पर निम्न लाभ हो सकते हैं।

1. मितव्ययता व बचत को प्रोत्साहन – बीमा करा ले ने से व्यक्ति को प्रब्याजि जमा कराने की चिन्ता रहती है अत: वह प्रारम्भ से ही बचत करना व मितव्ययता को अपनाना प्रारम्भ कर दे ता है। प्रो. रीगल, मिलर तथा विलियम्स के अनुसार - "'बीमा बचत को प्रोत्साहन दे ने वाला वातावरण प्रदान करता है।" यदि उसने प्रीमियम नहीं चुकाया हो तो वह उस धन राशि का अपव्यय भी कर सकता है। प्रति वर्ष बचत योजना के अन्तर्गत करोड़ों रू. का प्रीमियम जमा होता है , जो बचत की आदत से ही संभव है।

2. जोखिमों से सुरक्षा- मनुष्य का जीवन ही नही व्यापार भी जोखिमों से भरा हुआ है , बीमा उन अनिश्चितताओं को दूर करता है। प्रो. एन्जे ल के अनुसार- *बीमा अनिश्चित हानियों से सुरक्षा का स्थायी आधार है। बीमा के कारण ही व्यवसाय व उद्योग विकसित हुए है और व्यक्ति के रोजगार को उत्पन्न जोखिम भी समाप्त होती है।"*

3. विनियोग- जीवन बीमा में विनियोग तत्व भी विद्यमान है। व्यक्ति जो राशि प्रीमियम के रूप में जमा करवाता है। वह उसकी बचत है। निश्चित अवधि के पूर्ण होने अथवा निश्चित घटना के घटित होने पर बीमित को अथवा उसके उत्तराधिकारियों को निश्चित राशि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार बीमा व्यक्ति के लिए सुरक्षा के साथ -साथ विनियोग का साधन भी बन जाता है।

4**. बीमित व उसके उत्तराधिकारियों को पूर्ण सुरक्षा -** बीमा कराने से बीमित व उसके उत्तराधिकारियों को पूर्ण वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। बीमित मृत्यु से पूर्व इच्छित व्यक्ति के नाम बीमापत्र का नामांकन कर सकता है जिससे पारिवारिक धन सम्बन्धी, बँ टवारे के झगड़े दूर हो सकते है व उत्तराधिकारी भी पूर्णत: सुरक्षित रहते हैं।

5. करों में छूट - बीमा से करों में भी छूट मिलती है। भा२त में चुकायी गयी प्रीमियम की राशि पर आयकर में छूट प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार सम्पदा कर में भी छूट मिलती है।

6. आय क्षमता का पूंजीकरण:- बीमा के द्वारा व्यक्ति अपनी आय क्षमता का पूंजीकरण भी कर सकता है। वह भविष्य में उसके द्वारा कमायी जा सकने वाली राशि का भी बीमा करवा कर अपनी आय का पूंजीकरण कर सकता है। यदि बीमित की मृत्यु हो जाती है या कार्यक्षमता समाप्त हो जाती है तो भी इतनी ही राशि बीमापत्र पर प्राप्त हो सकेगी।

7. साख सुविधाऐं - ऋणदाता ऐसे व्यक्तियों को ऋण दे ना अधिक पसन्द करते हैं जिनका, बीमा करवाया हु आ है। वित्तीय संस्थाएं भी बीमित-व्यक्ति को ही ऋण दे ना चाहती है। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी से भी साख सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है।

8. वैधानिक दायित्वों से मुक्ति - व्यक्ति वैधानिक दायित्व बीमा करवा कर तृतीय पक्षकारों के प्रति अपने दायित्वों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। निश्चित प्रीमियम के बदले बीमा कम्पनी उन दायित्वों का भुगतान करे गी।

9. कार्यक्षमता में वृद्धि - अनिश्चितता जीवन की सबसे बड़ी चिन्ता होती है और बीमा व्यक्तियों को उस अनिश्चितता से ही मुक्ति दिलाता है। व्यक्ति जब चिन्ता मुक्त होकर कार्य करता है तो पूर्ण एकाग्रता से कार्य करने में समर्थ हो पाता है , जिससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

10. मानसिक शान्ति - जब व्यक्ति अनिश्चितताओं से मुक्त हो जाता है तो वह प्रसन्न मन से कार्य करता है। उसे मृत्यु के पश्चात् उत्पन्न होने वाले दायित्वों की भी चिन्ता नहीं रहती है क्योंकि वह वर्तमान में ही उनका बीमा करा चुका होता है।

11. स्वावलम्बन को प्रोत्साहन - बीमित व्यक्ति में आर्थिक आत्मनिर्भरता की भावना पैदा हो जाती है। व्यक्ति जीवित अवस्था में भी ऋण आसानी से प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के पश्चात् भी आश्रित परिवार को बीमा धन राशि मिलने से आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है।

12. भविष्य की आवश्यकताओं का नियोजन - बीमा कम्पनी के द्वारा कई प्रकार के बीमा पत्रों जैसे शिक्षा, विवाह, पें शन आदि को जारी किया जाता है। व्यक्ति अपनी सीमित आय में से वर्तमान में ही भविष्य की तैयारी कर ले ता है कि उसे कब, किस आवश्यकता पर, कितनी राशि की आवश्यकता होगी। इस आधार पर वह उन विशेष बीमापत्रों का चयन करने में सफल हो सकता है , यहाँ तक की मृत्यु के पश्चात् भी परिवार की आवश्यकताऐं पूर्ण नियोजित तरीके से पूरी कर सकता है।

13. सतर्कता को प्रोत्साहन - बीमा कम्पनियां हानियों से बचने के कई सुरक्षात्मक सुझाव दे ती रहती है। इन सुरक्षात्मक उपायों से मानव जीवन अधिक सुरक्षित हो जाता है वह समय-समय पर विभिन्न बीमारियों से बचने के उपाय करता है। क्षतिपूरक बीमों में सतर्कता उपाय अपनाने व सामान्य औसत से कम दाता प्रस्तुत करने पर प्रीमियम में छू ट भी प्रदान की जाती है जो अंनत: बीमा लागत को कम करती है।

14. सामाजिक प्रतिष्ठा व आत्म सम्मान में वृद्धि - बीमा समाज में व्यक्ति के आत्म सम्मान व प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। जिन लोगों का बीमा होता है समाज उन्हे अधिक सुरक्षित समझ कर सम्मान करता है , मुसीबत के समय उन्हें दूसरों की ओर नहीं दे खना पड़ता है , वे आसानी से बीमा पत्र पर ऋण भी प्राप्त कर सकते है।

15. वृद्धावस्था में सहारा:- वर्तमान में जबकि संयुक्त परिवार प्रथा का लोप हो रहा है बीमा व्यक्ति की वृद्धावस्था का सहारा ब नता जा रहा है। वृद्धावस्था मे आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं व उत्तरदायित्व बढ़ जाते है , ऐसे में बीमा से प्राप्त धन ही उसका प्रमुख सहारा बनता है।

व्यावसायिक / आर्थिक दृष्टि से महत्व

वर्तमान आर्थिक जगत की कल्पना बीमा के बिना अधूरी है। व्यवसायी बीमा करवाने की रूपरे खा बना ले ता है ताकि वह पूर्ण शान्ति व तन्मयता के साथ व्यावसायिक क्रियाओं को पूरा कर सके। विख्यात प्रबन्ध विचारक पीटर एफ ड्रकर के अनुसार- "यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है कि बीमा के बिना औद्योगिक अर्थव्यवस्था कोई भी कार्य नहीं कर सकती है।" वास्तविक स्थिति यही है कि बीमा व्यवसाय के सफल संचालन के लिए अपरिहार्य है। आर्थिक दृष्टि से बीमा का महत्व निम्न प्रकार से दृष्टिगोचर होता है -

1. बचतों को प्रोत्साहन - बीमा अनिवार्य बचत का एक साधन है। बीमा लोगों को छोटी-छोटी बचतें करने की आदत को प्रोत्साहन दे ता है। छोटी सी प्रीमियम के द्वारा वह भविष्य के कई बड़े सपनों को आसानी से पूरा कर सकता है। बीमा कम्पनी को इन बीमितों की छोटी-छोटी बचतों से करोड़ों रुपयों की प्रीमियम राशि प्राप्त होती है जो संचित होकर एक मोटी धन राशि बन जाती है। जिन्हें बीमा कम्पनी आवश्यक खर्चों की पूर्ति के पश्चात् सामाजिक व राष्ट्रीय हित की योजनाओं में विनियोग कर दे ती है।

2. पूंजी निर्माण - बीमितों से प्राप्त प्रब्याजि की राशि को बीमा कम्पनी जब विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं में विनियोग करती है , तो उससे व्यापार व व्यवसाय को आसानी से पूंजी की प्राप्तिहो जाती है , व कई लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी होती है।

3**. विनियोग का साधन -** बीमा अनुबन्ध में प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि से पूंजी का सृजन होता है इस पूंजी का विनियोग व्यापार , व्यवसाय उद्योग व अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में उतनी छोटी राशि का विनियोग कर लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है पर इस अप्रत्यक्ष विनियोग के द्वारा बीमितों को बीमापत्र पर अधिक बोनस की प्राप्ति होती है साथ ही राष्ट्र का आर्थिक विकास भी होता है।

4. व्यापार व वाणिज्य में वृद्धि - बीमा के द्वारा विभिन्न प्रकार की जोखिमों को सुरक्षा प्रदान की जाती है जिससे दे शी व विदे शी दोनों ही प्रकार के व्यापार में वृद्धि होती है। बीमा का प्रादुर्भाव व विकास ही मूलत : सामुद्रिक बीमा के रूप में हुआ है। जिससे जोखिम युक्त व्यापारिक समुद्री यात्राओं को सुरक्षा प्रदान की जाती थी, फिर अग्नि बीमा का विकास हुआ जिसमें कारखानों, गोदामों, कार्यालयों व अन्य सम्पत्तियों की अग्नि से सुरक्षा हेतु उपाय व बीमा किया जाने लगा।

इस प्रकार की हानियों से सुरक्षा मिलने पर व्यवसायी भयमुक्त होकर निश्चितता के साथ व्यापार करते हैं और जोखिम उत्पन्न होने पर बीमा एक सच्चे दोस्त के रूप में सहायता करता है।

5. औद्योगिकरण के लिए आधारभूत संरचना के विकास में सहायक - बीमा संस्थाएँ दे श में शक्ति, परिवहन, संचार, औद्योगिक सम्पदा आदि साधनों के विकास के लिए भारी मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराती है जिससे दे श में औद्योगीकरण हेतु आधारभूत ढ़ाँ चा तैयार होता है।

6**. वृहत् पैमाने के व्यवसायों का विकास :-** बीमा ने अनेक बड़े व्यवसायों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रो. मे गी ने लिखा भी है कि बीमा के बिना वृहत व्यावसायिक संस्थाओं का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। बीमा कम्पनी इन विशाल व्यवसायिक संस्थाओं हेतु वित्त उपलब्ध तो करती ही है साथ ही बहुत कम प्रीमियम पर सुरक्षा भी प्रदान करती है।

7. लघु व कुटीर उद्योगों का विकास:- वृहत पैमाने के उद्योगों के साधन भी विस्तृत होते हैं। वे आकस्मिक हानि को वहन कर सकते हैं , परन्तु लघु पैमाने के उद्योगों में यदि कोई जोखिम उत्पन्न हो जाये तो वे उसका सामना नही कर सकते व उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है परन्तु बीमा के द्वारा इन उद्योगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है अत : वे पूर्ण निश्चितता के साथ व्यवसाय का संचालन करते हैं।

8. उद्यमिता का विकास - बीमा के द्वारा उद्यमिता का विकास होता है , क्योंकि व्यवसाय व उद्योग का बीमा होने से उद्यमियों की जोखिम कम हो जाती है। वे पूर्ण आत्मविश्वास व निश्चितता के साथ नये व्यवसाय को प्रारम्भ करते हैं। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ऋण भी आसान शर्तों पर प्राप्त हो जाता है। कई तकनीकी व पेशेवर शिक्षा प्राप्त युवक, कई बड़े उपक्रम स्थापित कर रहे हैं।

9. सेवा क्षेत्र के उपक्रमों का विकास - वर्तमान में सभी दे शों में से वा क्षे त्र के उपक्रमों का विकास हो रहा है। इन उपक्रमों की सफलता इनके द्वारा दी जाने वाली से वाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ये संस्थाएं भी दायित्व बीमा करवाती है ताकि जोखिमों को सीमित किया जा सके। इससे इन उपक्रमों के विकास में पर्याप्त योगदान मिल रहा है।

10. विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन - विदेशी व्यापार में कई जोखिमें होती है जैसे - समुद्री मार्ग से माल भे जने की जोखिम, आयातक व निर्यातक दे श के राजनायिक सम्बन्धों से उत्पन्न जोखिमें आदि। बीमा कम्पनी से सुरक्षा मिलने पर व्यवसायी विदे शी व्यापार की जोखिमों से बच सकता है।

11. **साझेदारी व्यवसाय में स्थायिता -** साझेदारी फर्म में किसी साझेदार की मृत्यु होने या अचानक कोई जोखिम उत्पन्न होने पर फर्म में भारी संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे संकटों से निपटने के लिए साझेदारों का संयुक्त बीमा करवाया जा सकता है जिससे किसी साझेदार की मृत्यु होने पर प्राप्त राशि से फर्म से उसके हिस्से को चुकाया जा सकता है व दूसरी ओर बीमा राशि की पूर्ति नहीं होने से उस बीमा राशि से साझेदारों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है।

12. **रोजगार के अवसरों का विकास -** बीमा व्यवसाय से दे श में रोजगार के अवसरों का विकास होता है। बीमा से दे श में व्यवसाय व उद्योगों का विस्तार होता है जिससे उसमें अनेक स्तरों पर कार्य करने हेतु व्यक्तियों को रोजगार मिल ता है। बीमा व्यवसाय के कारण विभिन्न प्रकार के बीमों यथा-समुद्री , अग्नि, दुर्घटना, जीवन, व अन्य प्रकार के बीमों का विस्तार होता है जिससे बीमा संगठन में ही बड़ी मात्रा में कर्मचारियों व एजे न्टों की नियुक्ति की जाती है।

13. व्यावसायिक स्थायित्व में सहायक - बीमा दे श में व्यावसायिक स्थायित्व के लिए आधार तैयार करता है। इसका कारण है कि व्यावसायिक जोखिमों को बीमा के माध्यम से सीमित किया जा सकता है जिससे दे श में व्यावसायिक विकास हेतु अनुकू ल परिस्थितियों बनती है व व्यावसायिक स्थिरता आती है।

14. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हानि से सुरक्षा - प्रत्येक संस्था के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जीवन अमूल्य होता है। उन व्यक्तियों की ख्याति, क्षमता, प्रबन्ध चातुर्य आदि के कारण संस्थाएं लाभ अर्जित करती है। उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के न रहने पर संस्थाखतरे में पड़ जाती है अत: इस आर्थिक खतरे से संस्था को बचाने हेतु इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बीमा करवा लिया जाता है। इन व्यक्तियों की मृत्यु होने पर संस्था को बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति प्राप्त हो जाती है।

15. सुरक्षा विधियों को प्रोत्साहन - बीमा कम्पनी बीमितों को सुरक्षा विधियां अपनाने पर जोर दे ती है। जो संस्था इन उपायों को अपनाती है उन्हें प्रीमियम में छू ट भी प्रदान की जाती है। 16. दुर्घटनाओं की लागत को निश्चित करना:- कुछ दुर्घटना बड़ी तो कुछ छोटी होती है। यदि इन दुर्घटनाओं की लागत को वस्तु की लागत में जोड़ा जाये तो लागतें बहु त बढ़ जायेगी व वह उद्यमी प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जायेगा। अत: इन दुर्घटनाओं की अनिश्चितता को बीमा द्वारा निश्चितता में बदला जा सकता है।

17. कर्मचारी हितों की सुरक्षा - व्यवसाय में लाभ व हानि दोनों की संभावनाएं होती है। हानि की स्थिति का बुरा प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ता है और उन्हें नौकरी से निकलना भी पड़ सकता है। यदि व्यावसायिक संस्थाएं कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी, पें शन, तथा अन्य लाभों का बीमा करवा दे तो उनके हित सुरक्षित हो जाते हैं।

18. कर्मचारी सुरक्षा योजनाओं का आसान प्रबन्ध - दे श के कानू नों के अनुसार से वायोजकों को कर्मचारियों के कल्याण हेतु अनेक योजनाओं जैसे - पें शन, ग्रे च्युटी, बीमारी लाभ, अपंगता या मृत्यु पर आश्रितों की आय की सु रक्षा, गर्भावस्था व शिशु जन्म पर लाभ आदि का संचालन बीमा के द्वारा जैसे सामू हिक बीमा योजना , सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन कर के पूरा करती है। साथ ही कानूनी दायित्वों की भी पूर्ति कर सकते है।

19. मानव संसाधन विकास में योगदान - बीमा संस्थाओं द्वारा एजे ण्टों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है जो उनके व्यक्तित्व व कुशलता में योगदान दे ते हैं। यही नहीं बल्कि बीमित संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी परिसम्पत्तियों के रखरखाव व सु रक्षा के लिए प्रशिक्षण दे ती है। इससे मानव संसाधन विकास में योगदान मिलता है।

सामाजिक दृष्टि से महत्व

समाज में स्थायित्व व सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु बीमा एक महत्वपूर्ण औजार है। समाज को बीमा से अनेक लाभ है जो इस प्रकार है -

1. सामाजिक सुरक्षा का साधन - बीमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा करा कर व्यक्ति अपनी चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है। जीवन बीमा के द्वारा वृद्धावस्था, अपंगता, बीमारी व मृत्यु होने पर आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। अग्नि बीमा से बहुमू ल्य सम्पत्तियों , औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा, तो सामुद्रिक बीमा से मार्ग की कठिनाईयों व माल को होने वाली क्षति से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। इन सुरक्षा तत्वों के कारण बीमा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनता जा रहा है।

2. जोखिमों का अन्तरण - बीमा के द्वारा बीमित एक व्यक्ति की जोखिमों को अनेक व्यक्तियों के समू ह में बाँट दिया जाता है। क्षति का दायित्व बीमित प र या किसी एक व्यक्ति पर नहीं रह कर सम्पूर्ण समू ह को (बीमाकर्ता) वितरित हो जाता है जो पूरे समाज के लिए हितकर होता हैं।

3. पारिवारिक जीवन में स्थायित्वता - बीमे के द्वारा परिवार में स्थायिता लायी जा सकती है। परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर पूरा पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। किन्तु जीवन बीमा के द्वारा व्यक्ति मृत्यु के पश्चात् भी परिवा र को स्थायित्व प्रदान कर सकता है।

4**. पारिवारिक विघटन से सुरक्षा -** संयुक्त परिवार तो स्वयं बीमे के समान सुरक्षा प्रदान करता है परन्तु एकल परिवारों में यदि मुखिया की मृत्यु हो जाये तो उसकी विधवा पत्नी एवं बच्चों पर ही परिवार का पूरा दायित्व आ जाता है। ऐसी स्थिति में सभी पारिवारिक सम्बन्धों को बनाये रखने पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई बार तो माँ की व्यस्तता व शोकाकुलता के कारण बच्चे गलत राह पर भी अग्रसर हो जाते हैं। परन्तु जीवन बीमा से बीमा राशि समय पर उपलब्ध होने से परिवार का पूर्व नियोजित तरीके से विकास में योगदान मिलता है।

5. सामाजिक सन्तोष - बीमा से समाज के सभी वर्गों को लाभ पहु$1चता है अत : समाज में सामाजिक सन्तोष की भावना पनपती है व सामाजिक सन्तुष्टि रहती हैं।

6. सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक - बीमा आज के युग में सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक भी माना जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन व सम्पतियों का जितना अधिक व उपयुक्त बीमा करवाता है वह उतना ही प्रतिष्ठित माना जाता है। समाज शिक्षित व उन्नत होता है।

7. सामाजिक बुराइयों की रोकथाम - बीमा के द्वारा व्यक्तियों के जीवन में आर्थिक निश्चितता आती 'है , जिससे व्यक्ति की मृत्यु पर भी आश्रित बेसहारा नहीं होते हैं। इसी प्रकार अन्य क्षतिपूरक बीमों से भी व्यक्ति की सम्पतियां सुरक्षित हो जाती है। अत: जोखिम उत्पन्न होने पर उसकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति खराब नही होती है तथा सामाजिक बुराइयां जन्म भी नहीं ले ती है।

8. शिक्षा को प्रोत्साहन:- बीमा के द्वारा शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा बीमापत्र क्रय करके माता-पिता बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं।

9. सतर्कता को प्रोत्साहन - बीमा समाज में लोगों को सतर्कता हेतु भी प्रोत्साहित करता है। बीमा कम्पनियां उन सम्पत्तियों के बीमा प्रीमियम राशि में छू ट दे ती है जो सतर्कता उपायों को अपनाती है व सामान्य औसत से कम दावा राशि प्रस्तुत करती है। बीमा कम्पनी स्वयं भी समय-समय पर सतर्कता उपायों से अवगत कराती रहती है।

10. सभ्यता और संस्कृति का विकास - कोई भी समाज कितना सभ्य, सुसंस्कृत और विकसित है इसकी कसौटी वहाँ की बीमा प्रणाली है। जिस दे श में बीमा का विकास नहीं उसे पिछड़ा ही माना जाता है। सामाजिक परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ बीमा समाज की मानवीय व मौलिक सम्पत्तियों की सुरक्षा करता है। बीमा अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के अनुसार इन संसाधनों की सुरक्षा की व्यवस्था बीमित को करनी होती है। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनियां बीमित विषय-वस्तु की सुरक्षा के बारे में जनशिक्षण भी दे ती है। परिणाम स्वरूप बीमा के द्वारा सामाजिक परिसम्पत्तियों की सुरक्षा होती है।

11**. रोजगार अवसरों का विकास -** बीमा से समाज में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। बीमा कम्पनियों में कई हजार कर्मचारी विभिन्न पदों पर व कई बीमा एजे ण्ट भी कार्यरत है। एक अनुमान के अनुसार सामान्य बीमा निगम व उसकी सहायक कम्पनियों में लगभग 85000 तथा जीवन बीमा निगम में लगभग सवा लाख कर्मचारी कार्य रत है। इतना ही नहीं , जीवन बीमा निगम के ही पाँच लाख से अधिक एजे ण्ट भी कार्यरत है।

12. सामाजिक उत्थान कार्यों में योगदान - दे श का विकास सामाजिक उत्थान के बिना अधू रा ही है। सामाजिक उत्थान हेतु गरीबी एवं आर्थिक असमानता का निवारण करना होता है। बीमा कम्पनी सामाजिक क्षेत्र में असंगठित लोगों जैसे -श्रमिक, खाती, मोची, लौहार आदि, आर्थिक रूप से गरीब पिछड़े लोगों, अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों जैसे - स्वयं नियोजित व्यक्ति-फुटकर व्यापारी. नल- बिजली का कार्य करने वाले व्यक्ति आदि का बीमा करती है। बीमा कम्पनी इन व्यक्तियों का बीमा स्वयं की ओर से व केन्द्रीय व राज्य सरकार के सहयोग से भी करती है जैसे -जनश्री बीमा योजना। "बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण" ने भी सभी बीमाकर्ताओं के लिए सामाजिक क्षेत्र के पिछड़े लोगों का बीमा करना अनिवार्य कर दिया है। प्राधिकरण के नियमानुसार प्रत्येक नये बीमाकर्ता के लिए प्रथम वर्ष ऐसे 5000 जीवन व पाँच वर्षों में यह संख्या 20,000 तक पहु$1च नी होती है।

13. नागरिक दायित्वों से सुरक्षा - कई औद्योगिक संस्थाओं में कई खतरनाक रसायनों व गैसों का उपयोग करना होता है , खतरनाक अपशिष्ट भी निकलते है , औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया भी आसपड़ौस के लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसी संस्थाएँ अपना नागरिक दायित्व बीमा करवा ले ती है और जोखिम के प्रभावों से बच जाती है।

14. जीवनस्तर में सुधार - बीमा लोगों को बचत करने व जोखिमों को बीमा कम्पनी को अन्तरित करने का अवसर दे ती है। इससे लोगों की आर्थिक स्थिति सन्तुलित होती है व जीवन स्तर के सुधार हेतु अतिरिक्त साधनों का उपयोग किया जा सकता है।

15. परोपकारी कार्यों को प्रोत्साहन - व्यक्ति अपनी वृद्धावस्था में अथवा मृत्यु के पश्चात् किसी संस्था को दान दे ना चाहते हैं परन्तु जीवित रहते हुए स्वयं की आर्थि क सुरक्षा भी चाहते है ऐसे में वे बीमापत्र क्रय कर के उसका नामांकन उस संस्था के नाम कर दे ते हैं जिसको दान दिया जाना है। बीमित की मृत्यु पर नामांकित को उस बीमापत्र का भुगतान हो जाता है।

16. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता - बीमा कम्पनियां बीमा करते समय भी कई प्रकार की जांच करवाती है जिससे कई बीमारियों की जानकारी हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाये रखने हेतु शिक्षाप्रद सामग्री का भी वितरण करती है। इन सभी उपायों से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है।

राष्ट्रीय दृष्टि से उपादेयता

बीमा से केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र को लाभ होता है। जिसका विवरण इस प्रकार है-

1. राष्ट्रीय बचत में वृद्धि - बीमा करवाने हेतु प्रत्येक व्यक्ति बचत करता है। ये छोटी-छोटी बचतें कुल राष्ट्रीय बचत में वृद्धि करती है।

2. मुद्रा बाजार के विकास में योगदान - बीमा प्रीमियमों की बड़ी राशि से दे श के मुद्रा बाजार के विकास में भी योगदान मिलता है। फलत: अल्पकालीन व दीर्घकालीन प्रतिभू तियों का ले नदे न आसान हो जाता है। सरकारी बैंक तथा कम्पनियां , सभी अपनी आवश्यकतानुसार मुद्रा तत्काल प्राप्त व विनियोग भी कर सकती है।

3. प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा - बीमा सुविधा से ही अर्थव्यवस्था के सभी घटकों को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक जोखिमों से सुरक्षा उपल ब्ध हो रही है। बीमा कम्पनियां अग्नि, अतिवृष्टि, समुद्री मार्ग की जोखिमों , तटीय क्षेत्रों की जोखिमों आदि का बीमा करती है और उन लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करती है और राष्ट्र के आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाने में योगदान दे ती है।

4. मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण - बीमा प्रीमियम के रूप में एकत्रित धन बाजार में मुद्रा प्रसार को रोकता है , बाद में इसी धन का उद्योगों के विकास में उपयोग किया जाता है। भारत में कुल प्रचलित मुद्रा का लगभग 5 प्रतिशत भाग बीमा प्रीमियम के रूप में एकत्रित होता है।

5. विनियोग को प्रोत्साहन - बीमा के द्वारा व्यक्ति छोटी-छोटी बचतें एकत्रित कर के विभिन्न प्रकार के बीमापत्रों को खरीदता है उस प्रीमियम राशि का निश्चित प्रतिशत भाग उद्योगों में विनियोजित किया जाता है।

6. विदेशी मुद्रा कोष में योगदान - बीमा संस्थाओं द्वारा विदे श में भी बीमा व्यवसाय किया जाता है। विदे शों में बीमा व्यवसाय से विदे शी मुद्रा की प्राप्ति होती है।

7. स्कन्ध विनियम केन्द्रों का विकास - बीमा कम्पनी अपने सं चय कोषों का एक भाग स्कन्ध विनिमय केन्द्रों में भी विनियोग करती है व निरन्तर सक्रियता से अंश विनिमय व्यवसाय में हिस्सा ले ती है अत: स्कन्ध विनियम केन्द्रों का भी विकास होता है।

8. वृहत पैमाने के उद्योगों को पूंजी की उपलब्धता - बीमा कम्पनियां अपने संचय कोषों से उद्योगों के अंश व ऋणपत्रों को क्रय करती है जिससे इन उद्योगों को भारी मात्रा में दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोनों ही प्रकार की अंशपूंजी प्राप्त होती है।

9. सरकारी प्रतिभू तियों में निवेश द्वारा आर्थिक परियोजनाओं में योगदान - बीमा संस्थाओं ने केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की प्रतिभू तियों तथा इनके द्वारा गारन्टी युक्त अन्य प्रतिभू तियों में निवेश कर दे श के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन प्रतिभू तियों में निवेशित राशि दे श की आर्थिक परियोजनाओं को पूरा करने में व्यय की जाती है। जिससे दे श का आर्थिक विकास होता है।

10. मध्यम व लघु व्यवसायों को प्रोत्साहन - ये संस्थाएं सम्पूर्ण व्यवसाय का बीमा करवा कर व्यवसाय के कुशल संचालन पर पूर्ण ध्यान दे सकती है। बैंक व वित्तीय संस्थाएं भी बीमा के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाती है। ये लघु व मध्यम व्यवसायी दे शी व विदे शी व्यापार को योगदान के साथ ही कुल राष्ट्रीय उत्पादन व आय में वृद्धि भी करते हैं।

11. देश में रोजगार को बढ़ावा - बीमा कम्पनी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दे श में रोजगार को बढ़ावा दे ती है। वह स्वयं कई व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है व इनके द्वारा बीमित संस्थाएं भी रोजगार का सृजन कर कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर रही है।

12. राष्ट्रीय महत्व के जोखिम युक्त कार्यों को प्रोत्साहन - बीमा ने ऐसे कई कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहन दिया है जिनमें बहुत अधिक जोखिम विद्यमान होती है। उदाहरण -विश्वस्तरीय खेलकू द प्रतियोगिताओं , आधुनिक सैनिक उपकरणों का परीक्षण, अन्तरिक्ष यान एवं प्रयोगशालाएं आदि जोखिमयुक्त कार्यों में बीमा सहयोग कर रहा है।

13. राष्ट्रीय आय व उत्पादन में भी निरन्तरता - राष्ट्रीय आय की निरन्तरता को बनाये रखने में भी बीमा का योगदान है। अनेक प्राकृतिक व मनुष्यकृत कारणों से प्रतिवर्ष कई उद्योगों व्यवसाय, जहाज आदि नष्ट होते हे जिनसे सरकार को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों की प्राप्ति होती है , लाखों लोगों को रोजगार व करोडों रूपये के माल व से वाओं का उत्पादन होता है , यदि इनका बीमा न हो तो इनमें से अधिकांश इकाईयां पुन:स्थापित नहीं हो सकेगी व बेरोजगारी फै ल जायेगी। परन्तु बीमा के कारण ये उद्योग पुन : स्थापित हो जाते है व राष्ट्रीय आय व उत्पादन में निरन्तरता बनी रहती है।

14. सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास में योगदान - उद्योगों के विकास, रोजगार अवसरों के विकास, अधिक बचत व पूंजी निर्माण आदि सभी घट क सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास में योगदान करते हैं। बीमा के उपरोक्त लाभों व महत्व को दे खकर हम कह सकते हैं कि- *बीमा में दया समान गुण होते हैं। इसमें बीमाकर्ता व बीमित दोनों सौभाग्यशाली होते हैं तथा बीमा जन्म से ले कर मृत्यु तक सहायक सिद्ध होता है। ”*

बीमा की सीमाएँ

अनिश्चितताओं एवं आशंकाओं से भरे जीवन में बीमा अत्यधिक महत्वपूर्ण है , आज बीमा - सम्पूर्ण व्यावसायिक जगत एवं मानव समु दाय की प्राथमिक आवश्यकता बन गया है फिर भी बीमा की अपनी कुछ सीमाएँ है जिनके कारण बीमा के वांछित लाभ नही मिल पाते हैं। बीमा की कुछ सीमाएं इस प्रकार है -

1. **सभी जोखिमों का बीमा नहीं कराया जा सकता** - जीवन में अनेक जोखिमें विद्यमान है परन्तु सभी का बीमा सम्भव नहीं है केवल शुद्ध जोखिमों का ही बीमा करवाया जा सकता है , परिकल्पी जोखिमों का बीमा नहीं करवाया जा सकता है।

2. **ऊंची प्रीमियम दरें** - दे श में जीवन बीमा के प्रति लोगों की विशेष रूचि नहीं है। वाहन बीमा भी कानूनी अनिवार्यता के कारण करवाया जाता है। बड़े कारखानों का बीमा प्रचलित है परन्तु मकान, दुकान, चोरी आदि का बीमा अधिक चलन में नहीं है। इन सब का मुख्य कारण बीमा प्रीमियम का ऊंचा होना है।

3. **नैतिक संकट**- बीमा करवाने वाले कुछ लोग बीमा का दुरूपयोग भी करते है। निम्न परिस्थितियों में व्यक्ति की नैतिक कमजोरियों के कारण बीमा की सफलता संदिग्ध हो जाती है -

- (क) कुछ लोग बीमा सेवा का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना चाहते हैं जैसे -आवश्यकता से अधिक समय अस्पताल में रुक कर ईलाज करवाना क्योंकि बीमा कम्पनी भुगतान कर रही है।
- (ख) कुछ लोग बीमाकृत जीवन व सम्पति को अपनी से वाएं दे ने के बदले अधिक पारिश्रमिक वसूल करते हैं। उदाहरण-बीमित रोगी से डॉक्टर द्वारा अधिक फीस वसू ल करना।
- (ग) बीमाकृत सम्पत्ति का लापरवाही से प्रयोग करना।
- (घ) बीमितों द्वारा नुकसान को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाना।

4. **बीमा लाभकारी विनियोग नहीं है** - बीमा सुरक्षा के साथ-साथ निवेश भी है किन्तु यह बहुत आकर्षक निवेश भी नहीं है। इससे प्राप्त होने वाला लाभ अन्य निवेशों से कम ही है। क्षतिपूरक बीमा में व्यक्ति को केवल वास्तविक क्षति प्राप्ति का ही अधिकार होता है। अत इसे आकर्षक निवेश नहीं माना जाता है।

5. **बीमा की ऊंची संचालन लागतें** - बीमा कम्पनियां प्रीमियम का लगभग 20 प्रतिशत भाग अपने संचालन पर ही खर्च कर दे ती है। जिससे अन्तत: प्रीमियम दरों में वृद्धि होती है।

6. **एकाकी व्यक्ति की जोखिम का सीमा समग्र नही** - बीमा की सफलता तभी संभव है जब समान प्रकार की जोखिमों से घिरे व्यक्तियों का बड़ा समूह हो। यदि किसी एक व्यक्ति या बहुत कम व्यक्तियों को जोखिम हो तो उनका बीमा करना संभव नहीं होता है।

7. **बीमा केवल वित्तीय मूल्य तक ही सीमित** - किसी घटित होने वाली घटना की वास्तविक हानि का मुद्रा में मापन हो सके तो ही बीमा संभव है। इस प्रकार केवल भौतिक हानियों का बीमा, पर अमौद्रिक हानियों जैसे मानसिक पीड़ा, उत्पीडन, तनाव, चिन्ता, आदि की क्षतिपूर्ति का मापन व बीमा दोनों ही संभव नहीं है।

8. **कुछ बीमा पत्र केवल सरकारी सहयोग पर निर्भर**- निजी बीमाकर्ता कुछ विशिष्ट प्रकार की जोखिमों का बीमा नहीं कर सकते हैं , उनमें सरकारी सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे -बेरोजगारी बीमा आदि।

बीमा का कार्य

बीमा के कार्यो के दो भागो में विभक्त किया जा सकता है - (1) प्राथमिक कार्य (2) द्वितीयक कार्य ।

1. प्राथमिक कार्य -

1. **निश्चितता प्रदान करना:-** बीमा हानि की अनिश्चतता के हानि के पूर्ति की निश्चितता प्रदान करता है। व्यक्ति हानि के प्रति कुशल नियोजन करके निश्चिंत हो सकता है परन्तु इस कृत्य में बहुत से बाधायें उत्पन्न हो सकती है। बीमा हानि की कठिनाइयों को दूर करके हानि के प्रति निश्चितता प्रदान करता है। जोखिम हानि की अनिश्चिता है जिसमें हानि का कब होगी, कैसे होगी कितनी होगी इस सबका पता नही रहता यदि जोखिम हो गयी तो व्यक्ति को और उससे पूर्व वह व्यक्ति हानि के प्रति चिन्तित रहता हैं, लेकिन

बीमा से इस प्रकार की चिंता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति निश्चिय हो जाता है इसके लिये व्यक्ति को बहुत थोडी प्रीमियम देनी होती है जो हानि का बहुत छोटा भाग होता है।

2. **सुरक्षा प्रदान करना:-** बीमा का मुख्य कार्य संभाव्य हानि से सुरक्षा प्रदान करना है क्योकि मानव जीवन जोखिम पूर्ण है। विभिन्न जोखिमो के कारण या अनिश्चित रहता है कि भविष्य की आपदाओ से कब तथा कितना हानि भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार मनुष्य को असुरक्षा का अनुभव होता है वह सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा तभी मिल सकती है जब जोखिमों के अनिश्तिता से मुक्ति मिले । बीमा इस अनिश्चितता से मुक्ति देकर सुरक्षा प्रदान करता है ।

3. **जोखिम (हानि) का वितरण:-** बीमा का मुख्य कार्य जोखिमों से होने वाले हानि का विभाजन है। आपदा या जोखिम को बाँटा नहीं जा सकता है परन्तु उन से होने वाली हानियों को उन व्यक्तियों में बाँटा जा सकता है जो हानियों से सुरक्षित होना चाहते है। प्राचीनकाल में हानियों का विभाजन जोखिमों के समय किया जाता था। परन्तु बीमा संविदा में ं उन हानियों का भुगतान बाद में किया जाता था। जिसके लिये सीमित व्यक्तियों से उनसे हानि का अंश प्रीमियम के रूप में पहले से लिया जाता था। प्रीमियम की गणना हानि की संभावना के अनुसार होगी।

2. द्वितीयक कार्य -

सुरक्षा की व्यवस्था द्वारा बीमा व्यवसायिक कार्यकलाप में ऐसे अनेक सुविधायें अवसर एवं लाभ प्रदान करता है जो इस प्रकार महत्वपूर्ण है ।

1. **हानि के रोकना-** बीमा हानि को स्वयं नही रोकता है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओ को साथ देता है जो हानि को रोकने के लिये कार्य कर रहे है। यदि हानि में कमी हो जायेगी तो हानि रूक जायेगी। बीमाकर्ता कम भुगतान करेगा। इस प्रकार उसे हानि नही सहनी पड़ेगी। हानि की कमी से प्रीमियम दर में कमी की जा सकती है इस प्रकार बीमा के विकाश से सहायता मिल सकता है।

2. **पूँजी की पूर्ति-** बीमा समाज को पूंजी की आपुर्ति करता है बीमा के पर्याप्त रकम प्रीमियम के रूप में आती है जिससे विनियोजित करके उत्पादन में वृद्धि की जाती है और समाज को पूँजी की कमी को पूरा किया जाता है। भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ पूँजी ी की अपर्याप्तता है बीमा के इस कार्य का विशेष महत्व है बीमा द्वारा पूजी का संचय दो प्रकार से किया जा सकता है- (1)बीमा के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति, व्यवसायी या संस्था हानियों को पूरा करने के लिये कुछ संचय रखते है जिसका उपभोग नही करते। (2) बीमा पूंजी का संचय करता है।

3. **वित्तीय स्थिरता प्रदान-** करना बीमा का महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके कारण शुद्ध जोखिमों द्वारा अस्थिरता नही आने पाती। यदि बीमा की सुविधा उपलब्ध न हो तब अग्निकांड, दुर्घटना चोरी, दंगा, और इसी प्रकार अन्य उपद्रवो के कारण बड़ें पैमाने पर चलने वाले कारबार या उद्योग का अपूरणीय हानि पहुँच सकती है। यदि बीमा है तो ऐसी हानि की पूर्ति की व्यवस्था हो जाती है, और व्यवसाय एवं उद्योग में तथा समाज मे स्थिरता सुनिश्चितता की जा सकती है।

बीमा की उपयोगिता

बीमा की उपयोगिता का सामान्यत: अध्ययन-व्यक्तिगत उपयोंगिता व्यवसायिक, और सामाजिक लाभों के अन्तगर्त किया जा सकता है जो इस प्रकार है

(क) बीमा सुरक्षा दाप्रन करता है-

बीमा निर्धारित जोखिम से होनें वाली हानि के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन बीमा में मृत्यु या जीवन से घटित घटना पर बीमित रकम का भुगतान कर दिया जाता है। जीवन के अनेक आवश्यकताओ के लिये अलग अलग प्रकार के बीमापात्र खरीदे जाते है जो बीमित व्यक्ति से सम्बन्धित होते है। इसी प्रकार सम्पत्ति बीमा की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं जोखिम से सम्बन्धित है। बीमित जोखिम घटित होने पर भुगतान का दिया जाता है, सम्पत्ति के नष्ट होने पर या हानि होने पर हानि का भुगतान समान्य बीमा द्वारा किया जाता है।

(ख) बीमा व्यक्ति को चिन्ता से मुक्त करता है-

सुरक्षा मनुष्य का मुख्य प्रेरक है। यदि व्यक्ति का भविष्य जोखिम से असुरक्षित है तो उसे हमेशा चिन्ता लगी रहती है और कार्य करने में मन नही लगता परन्तु हानि के प्रति सुरक्षा रहने पर व्यक्ति उस से चिन्ता मुक्त हो जाता है। क्योकि वह समझाता है कि जोखिम उसके परिवार को कोई हानि नहीं देगा क्योकि हानि का भुगतान बीमा द्वारा कर दिया जाता है। यह हानि सम्पत्ति, जीवन और दायित्व के सम्बन्ध में हो सकती है। जिसके लिये बीमा विभिन्न स्वरूपों में मौजूद है। जोखिम से सुरक्षा न रहने पर मनुष्य को चिनता, हतोत्साह, मानसिक कमजोरी आदि रहती है।

(ग) बीमा बन्धक सम्पत्ति में सुरक्षित करता है -

बीमा बन्धक सम्पत्ति को सुरक्षित रखता है व्यक्ति की मृत्यु से बंधक पर रखी गयी सम्पत्ति ऋणदाता की हो जाती है, और परिवार को कष्ट होता है। दूसरी ओर ऋणदाता ऋण देने के पहले सम्पत्ति को बीमित करने के लिये बल देता है क्योकि सम्पत्ति के नष्ट होने पर क्षति पहुँचने, चोरी होने आदि के कारण बन्धक ऋण का भुगतान प्राप्त करना संभव नही रहता है। और ग्रहणदाता को हानि होती है। यदि सम्पत्तियों का बीमा होता, तो क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के होने से चोरी आदि हो जाने पर ऋण का भुगतान ऋणदाता को बीमा होने के कारण बंधक सम्पत्ति का दिया जाता है।

(घ) बीमा सहायक के रूप में कार्य करता है-

बीमा यदि हुआ है तो चाहे परिवार के मुखिया की मृत्यु हो या सम्पत्ति को हानि हो दोनो के प्रति चिन्ता करने की आवश्यकता नही होती, क्यो कि क्षति पहुँचने की स्थिति में बीमा कार्य करती है। बीमा उन सभी कठिनाई से मुक्त प्रदान करता है जो ऐसी समास्याओं को दूर करती है, जो व्यक्ति के लिये मुसीबत हो सकती है, क्योकि जोखिम होने की स्थित में आर्थिक कठिनाइयों से राहत प्रदान करती है।

(ड़) बीमा बचत को प्रोत्साहित करता है एवं लाभकारी विनियोग में सहायक है-

जीवन बीमा बचत एवं सुरक्षा दोनो प्रदान करता है जबकि अन्य बीमा में केवल सुरक्षा सन्निहित रहती है। जीवन बीमा में बचत एवं विनियोग का लाभ मिलता है। बचत करके व्यक्ति वृद्धावस्था की कठिनाईयों सें सुरक्षित हो जाता है यदि मृत्यु आकस्मिक हो भी जाती है तो इसमें सहायता मिलता है। क्योकि उस दशा में एक निश्चित रकम

का भुगतान कर दिया जाता है और इसके साथ ही साथ अन्य लाभ भी प्राप्त होते है ै क्योकि बीमित रकम का भुगतान केवल एक निश्चत समय एवं घटना के घटित होने पर ही किया जाता है। जीवन बीमा के बीमित रकम के साथ ही साथ बोनस का भी भुगतान होता है क्योकि बीमाकारी अपने एकत्रितकोष को विनियोजित करता रहता है और प्राप्त हुयी आय से खर्चे और संचय निकालकर शेष रकम बीमापत्र धारी दे देता है। बीमा सुरक्षा के साथ साथ लाभकारी विनियोग का भी कार्य करती है।

1. व्यवसायिक उपयोगिता

(क) व्यक्तिगत हानियों की अनिश्चितता कम हो जाती है -

बीमा अनेक जोखिमों से होने वाली हानि को पूरा करता है जिनके लिये बीमा की सुविधाये प्रदान की जाती है। व्यवसायिक जगत में अत्यधिक मानवीय और भौतिक सम्पत्ति का उपयोग किया जाता है और थोड़ी सी चूक के कारण अरबो की सम्पत्ति क्षणभर में नष्ट हो जाती है। इन जोखिमों से निजात पाने के लिये व्यसायिक जगत में बीमा भी अवश्यकता एवं भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्योकि बीमा से इस हानियों को पूरा किया जाता है और ऐसी अनिश्चिता को दूर किया जात है और भुगतान किया जाता है जिससे व्यापार वृद्धि में सहायता मिलती है।

(ख) बीमा से व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि और साख में वृद्धि होती है -

बीमा होने से व्यवसायी हानियों के प्रति स्वतन्त्र हो जाते है और मन लगाकर कार्य करते है। व्यवासाय में संलग्न व्यक्ति सम्पत्ति आदि के बारे बीमा रहने पर चिंता नही करते क्योकि बीमा द्वारा पूर्णक्षति की पूर्ति कर दी जाती है। जिससे व्यसासय की निरन्तरता बनी रहती है। बीमा रखने पर साख में वृद्धि हो जाती है, क्योकि ऋणदाता यह समझते है कि यदि ऋणी की मृत्यु या बन्धक पर रखी गयी सम्पत्ति नष्ट हो जाने पर खो जाने, पर भी उन्हे भुगतान बीमा के माध्यम से किया जायेगा इसलिये बीमा होने से साख में और अधिक वृद्धि हो सकती है।

(ग) महत्वपूर्ण कर्मचारी की बीमा एवं कर्मचारी कल्याण की सुविधा:-

अधिक महत्वपूर्ण कर्मचारी वह है जिसके जीवित रहने पर व्यापार को लाभ-हानि को तुरन्त पूरा न किया जा सके। महत्वपूर्ण कर्मचारी का बीमा करा लेने पर उसकी मृत्यु पर व्यवसाय बन्द होने या हानि होने की संभावना समाप्त हो जाती है। कर्मचारी के मृत्यु पर उनके परिवार को कुछ रकम देनी पड़ती है, जिसके लिये बीमा खरीदार उन्हे भुगतान किया जा सकता है। कर्मचारियों के निवास स्थान आदि के प्रबन्ध के लिये बीमा से ऋण भी मिल जाता है।

2. सामाजिक उपयोगिता

(क) समाज की मानवीय एवं भौतिक सम्पित्त की सुरक्षा-

समाज की मानवीय एवं भौतिक सम्पित्त की सुरक्षा जीवन बीमा एवं सम्पित्त्ा बीमा से ही सकती है। जीवन बीमा में यह संभावना रहती है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जोखिम के प्रति स्वतन्त्र रखते हैं, क्योंकि उसके भौतिक सम्पित्त का बीमा रहने पर सम्पित्त्ा की सुरक्षा आदि रहती है। यदि वह नष्ट होती है तो हानि का पूर्ण भुगतान बीमा द्वारा किया जायेगा। बीमा होने से कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात आदि में प्रगति होती है, और मानवीय एवं भौतिक सम्पित्त्ा को सुरक्षा प्राप्त होती है।

(ख) राष्ट्र प्रगति मे सहायक एवं मुद्रा प्रसार में कमी-

राष्ट्र प्रगति में बीमा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योकि बीमा के माध्यम से देश की सम्पत्ति सुरक्षित रहती है, और विनियोग के लिये पर्याप्त रकम मिल जाती है। बीमा मुद्रा प्रसार में कमी दो प्रकार की होती है-

1. प्रीमियम की रकम एकत्रित करके मुद्रापूर्ति में कमी पूरा करता है। राष्ट्र में मुद्रा की मात्रा कम हों जाने से मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती है ै उसको भी पूरा करता है।
2. एकत्रित प्रीमियम को विनियोजित करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती हैं बीमा के समाजिक लाभ के तरीके महत्वपूर्ण है। क्योकि बीमा समाज के व्यवस्थित अस्थिरता से मुक्ति दिलाता है, और साथ ही साथ जीवन स्तर भी स्थिरता को बढ़ाता है और पूॅजी निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

बीमा के सिद्धांत

सभी बीमों के बीमा अनुबन्ध कुछ स्थापित सिद्धांतों पर निर्भर करते है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है-

(1) पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत-

बीमा अनुबंध पारस्परिक विश्वास का अनुबंध है। बीमाकर एवं बीमित दोनों पक्षों को बीमा की विषय वस्तु से सम्बन्धित सभी आवश्यक सूचनाओं को उजागर कर देना चाहिए। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा में प्रस्तावक को (बीमा करवाने में इच्छुक व्यक्ति) अपने स्वास्थ्य, आदतों, व्यक्तिगत इतिहास, पारिवारिक इतिहास आदि की सूचना को ईमानदारी से उजागर कर देना चाहिए। यदि महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया है तो अनुबंध वैध नहीं होगा, क्योंकि बीमा की विषय वस्तु से सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर ही जोखिम का मूल्यांकन किया जा सकता है।

(2) बीमोचित स्वार्थ का सिद्धांत-

इस सिद्धांत के अनुसार बीमित व्यक्ति का बीमा की विषय वस्तु में बीमोचित हित होना चाहिए। बीमा योग्य हित का अर्थ होता है बीमा की विषय वस्तु में वित्तीय अथवा लाभ प्राप्ति का स्वार्थ। किसी व्यक्ति का किसी सम्पत्ति अथवा जीवन में बीमा योग्य हित तब माना जाता है, यदि उसके बने रहने से उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का अपने स्वयं के जीवन में व अपनी पत्नि के जीवन में बीमोचित स्वार्थ ह ै इसी प्रकार उसकी पत्नी का अपने पति के जीवन में बीमायोग्य हित होता है। जहां तक सम्पत्ति का प्रश्न है तो उसमें उसके स्वामी का बीमा योग्य हित होता है। जीवन बीमा में पालिसी लेते समय, समुद्री बीमा में क्षति होते समय और अग्नि बीमा में दोनों समय बीमा योग्य हित मौजूद रहना आवश्यक है।

(3) क्षतिपूर्ति का सिद्धांत-

क्षतिपूर्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक हानि की पूर्ति करना अथवा उसे बीमा कराने से पूर्व की स्थिति में ले आना। यह सिद्धांत सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा एवं साधारण बीमा में लागू होता है। यह जीवन बीमा में लागू नहीं होता क्योंकि जीवन की हानि अर्थात् मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति सम्भव नहीं है।

क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से अभिप्राय है कि बीमित को बीमे की घटना के घटित होने पर बीमा अनुबंध से कोई लाभ कमाने की छूट नहीं है। क्षति की पूर्ति का भुगतान वास्तविक हानि अथवा बीमा की राशि, जो भी कम हो, का किया जाता है। आइए, इसे एक उदाहरण से समझें। माना कि एक व्यक्ति ने अपने मकान का 20 लाख रूपये का बीमा कराया है। आग से क्षति पर उसे मरम्मत के लिए मकान पर 5 लाख रूपया खर्च करना पड़ा तो वह बीमाकर से केवल 5 लाख रूपये का दावा ही कर सकता है, न कि बीमा की कुल राशि का।

(4) योदान का सिद्धांत-

किसी विषय वस्तु का बीमा एक से अधिक बीमाकारों से भी कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में बीमित को बीमा के दावे की देय राशि में सभी बीमाकार अपनी भागीदारी के अनुपात में योगदान देंगे। यदि एक बीमाकार ने बीमित को उसकी पूरी क्षति की पूर्ति कर दी है तो वह बीमाकार अन्य बीमाकारों से इस हानि में अनुपातिक भागीदारी के लिए मांग कर सकता है। ध्यान रहे कि कई पालिसियां ले लेने पर बीमित किसी भी बीमाकार से हानि की पूर्ति का दावा कर सकता है लेकिन शर्त है कि बीमित सभी बीमाकारों से मिलाकर वास्तविक हानि की राशि से अधिक की वसूली नहीं कर सकता।

(5) प्रतिस्थापन का सिद्धांत-

इस सिद्धांत के अनुसार यदि बीमित के दावे का निपटारा हो जाता है तो बीमा की विषय वस्तु पर स्वामित्व बीमाकार को प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का कोई मूल्य है तो यह सम्पत्ति बीमाकार की हो जाती है अन्यथा बीमित वास्तविक हानि से अधिक की वसूली कर लेगा जो कि क्षतिपूर्ति के सिद्धातं के विरूद्ध होगा। इसीलिए, यदि 1,00,000 रूपय ी की कीमत के माल की दुर्घटना से क्षति होती है तथा बीमा कम्पनी बीमित को पूरी क्षति की पूर्ति करती है तो बीमा कम्पनी उस क्षतिग्रस्त माल को अपने अधिकार में ले लेगी तथा उसे उस क्षतिग्रस्त माल को बेचने का अधिकार होगा।

(6) क्षति को कम करने का सिद्धात-

दुर्घटना होने पर बीमित को बीमा की विषय वस्तु की हानि अथवा क्षति को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि बीमित बीमा पालिसी लेने के पश्चात बीमा की गई वस्तु की सुरक्षा के प्रति असावधान न हो जाये। बीमित से आशा की जाती है कि उसे इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जैसे कि विषय वस्तु का बीमा कराया ही नहीं है। यदि सम्पत्ति को बचाने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो बीमित को बीमा कंपनी से पूरा हर्जाना नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, माना एक मकान का अग्नि बीमा है और उसमें आग लग जाती है तो स्वामी को हानि को कम करने के लिए आग बुझाने के सभी प्रयत्न करने चाहिए। इसी प्रकार से जब चोरी के विरूद्ध बीमा कराया गया है तो भी मकान मालिक को मकान की सुरक्षा की ओर असावधान न होकर चोरी को रोकने के सभी कदम उठाने चाहिए।

(7) हानि के निकटतम कारण का सिद्धांत-

इस सिद्धांत के अनुसार बीमित का केवल उसी दशा में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है जब कि हानि उसी कारण से हुई हो जिससे सुरक्षा के लिए बीमा करवाया गया था। दसू रे शब्दों म,ें यदि हानि का निकटतम

कारण वह नहीं है जिसके लिए बीमा करवाया गया था तो बीमित बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, संतरा से लदे एक जहाज का बीमा दुघर्टना के कारण होने वाली हानि के लिए कराया गया था। जहाज तो बन्दरगाह पर सुरक्षित पहुँच गया पर जहाज से संतरों को उतारने में देरी कर दी। इस स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी क्योंकि संतरे खराब होने का कारण उनको उतारने में हुई देरी थी न कि दुर्घटना।

निजी क्षेत्र के लिए बीमा क्षेत्र को खोलने के तर्क

Rationale for opening up of the Insurance sector to Private Sector

निजीकरण का तर्क कई औद्योगिक उन्नत देशों, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों ने पिछले दो-तीन दशकों के दौरान निजीकरण का विशाल एजेंडा पेश किया है। कई औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्थाओं ने अपने विशेषाधिकार पर निजीकरण के कार्यक्रम को लाया है, जबकि कई विकासशील देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक द्वारा आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के तहत सहायता के लिए एक शर्त के रूप में निजीकरण करने के लिए अनिवार्य थे। निजीकरण को आम तौर पर सकारात्मक परिणाम माना जाता है। निजीकरण में कल्याण, लाभप्रदता, मालिकों और हितधारकों के लिए रिटर्न, और आर्थिक दक्षता में सुधार हुआ है। लेकिन निजीकरण की सार्वजनिक धारणाएं आम तौर पर ऋणात्मक होती हैं और वे बदतर हो रही हैं । वित्तीय उदारीकरण पर इंगित इस सुधार प्रक्रिया के संभावित परिणामों के बारे में दो व्यापक समूह हैं: गोल्डस्मिथ- मैककिन्नॉन-शॉ स्कूल और केनेस-टोबिन-स्टिग्लिट्ज (जिसे स्ट्रक्चरलिस्ट और नियोस्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल भी कहा जाता है)। इनमें से प्रत्येक समूह वित्तीय उदारीकरण के लिए पृष्ठभूमि, तर्क और बौद्धिक औचित्य प्रदान करता है। मैककिन्नन और शॉ ने यह स्पष्ट कर दिया कि वित्तीय गहराई की कमी विकास में एक बड़ी बाधा थी।

वित्तीय उदारीकरण सबसे अधिक उत्पादक और लाभप्रद परियोजनाओं को धन आवंटन को बचाने और बढ़ाने के लिए उच्च प्रोत्साहन प्रदान करके अर्थव्यवस्था में उत्पादकता को प्रोत्साहित करता है। इस विचार का विचार केनेसियन टोबिन-स्टिग्लिट्ज स्कूल के विचार से किया जाता है। इस समूह (जिसे नेस्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाता है) ने वित्तीय प्रणाली के बीमाकर्ता के रूप में सरकार की वास्तविक भूमिका के कारण, समझदार विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को न्यायसंगत बनाने के लिए कई आर्थिक तर्कसंगतों को आगे बढ़ाया है। निजीकरण पर कुछ विद्वानों के मुताबिक, निजीकरण के लिए तर्क निम्नानुसार है:

- सकारात्मक तर्क सामान्य रूप से,
- आर्थिक दक्षता में वृद्धि,
- सार्वजनिक क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने,
- सरकारी उधार को कम करने,
- घाटे को कम करने,
- सरकारी राजस्व पैदा करने,
- राज्य को कम करने के तहत निजीकरण किया गया है।

अर्थव्यवस्था में प्रभाव, बाजार बलों को मनाने, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, ग्राहकों के विकल्पों में वृद्धि और सेवा की गुणवत्ता को अपग्रेड करना । दुनिया भर के अधिकांश देशों और क्षेत्रों में निजीकरण फर्म स्तर और व्यापक आर्थिक स्तर पर बहुत अधिक लाभ प्राप्त करता है और उदारीकरण के बीच मजबूत संबंध है और विकास पर लौटने के बीच मजबूत संबंध है। वित्तीय उदारीकरण कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से विकास दर बढ़ाने में मदद करता है। इनमें से कुछ घरेलू बचत में वृद्धि, पूंजी की लागत में कमी और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से आर्थिक विकास के चालकों को सीधे प्रभावित करते हैं। अप्रत्यक्ष चैनल जो कुछ मामलों में प्रत्यक्ष लोगों की तुलना में और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनमें उत्पादन विशेषज्ञता, बेहतर जोखिम प्रबंधन और समष्टि आर्थिक नीतियों में सुधार शामिल हैं। विकासशील दुनिया में निजीकरण कार्यक्रमों के पीछे तर्क यह विश्वास है कि यह उद्यमशीलता प्रबंधन और प्रतिस्पर्धा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी के विकास के आधार पर माल और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि, और घरेलू बाजार में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए दक्षता में वृद्धि करेगा ।

बीमा कानून और विनियम

भारत में, बीमा अधिनियम 1938 में पारित किया गया था और इसे 1 जुलाई 1939 से लागू किया गया था, जिसके द्वारा निजी बीमा कंपनियां अस्तित्व में थीं। बीमा केवल एक सार्वजनिक कंपनी या सहकारी समिति द्वारा या भारत के बाहर पंजीकृत किसी अन्य सीमित कंपनी द्वारा व्यवसाय के रूप में की जा सकती है। 1956 में, एक जीवन बीमा

भारत का निगम सार्वजनिक क्षेत्र के तहत जीवन बीमा कारोबार करना था। इस उद्देश्य के लिए, जीवन बीमा कारोबार में लगे सभी निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां एलआईसी द्वारा ली गईं। हालांकि, 1 99 0 के बाद, नई आर्थिक नीति को अपनाने के साथ, सरकार ने निजी क्षेत्र में भी बीमा कारोबार की अनुमति दी है। इसने घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों को जीवन बीमा सहित बीमा कारोबार में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है।

इंसुरेंस ईरगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority / IRDA) भारत सरकार का एक प्राधिकरण (एजेंसी) है। इसका उद्देश्य बीमा की पालसी धारकों के हितों कि रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। इसका मुख्यालय हैदराबादमें है। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम आईआरडीए अधिनियम, 1999 द्वारा की गई थी।

यह प्राधिकरण विनियमों को जारी कर रही है जिसमें बीमा एजेंटों, विलेयता लाभ, पुन: बीमा, बीमाकर्ताओं का पंजीकरण, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के दायित्व, लेखांकन की प्रक्रियाओं आदि सहित बीमा उद्योग को लगभग सम्पूर्ण भाग शामिल है।

बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) उपभोक्ता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण करती है। वह आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार,

सभी कंपनियों का मौके पर और मौके के अलावा निरीक्षण करता है। आईआरडीए मौके के अलावा निरीक्षणों के माध्यम से उनके शोध क्षमता मामलों और वित्तीय रिर्पोटिंग मानदडों की नियमित निगरानी करता है।

आईआरडीए ने बीमा कंपनियों के कार्यालयों का स्थल पर निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण विभाग की अलग से स्थापना की है। स्थल पर निरीक्षणों के दौरान, आईआरडीए, बीमा कंपनियों के मार्किट संचालन, परिचालन के तरीके और अभिशासन के मानदंडों सहित उनके सांविधिक प्रावधानों और विनियामक निर्देशों के अनुपालन की सीमा का निरीक्षण करता है।

आईआरडीए पर बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने की ज़िम्मेदारी है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, प्राधिकरण ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

- आईआरडीए ने पॉलिसीधारक हित संरक्षण विनियम 2001 को अधिसूचित किया है ताकि इन बातों की व्यवस्था की जा सके :- पॉलिसी प्रस्ताव दस्तावेज़ आसानी से समझी जाने वाली भाषा में हो; जीवन और गैर जीवन दोनों से संबंधी दावा-प्रक्रिया; शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना; दावों का शीघ्र निपटान; और पॉलिसीधारकों की सेवा आदि। इन विनियमों में दावों के निपटान में होने वाली देश के लिए बीमाकर्ता द्वारा ब्याज की अदायगी का भी प्रावधान किया गया है।
- बीमाकर्ताओं से शोधन-क्षमता मार्जिन रखने की अपेक्षा की जाती है ताकि वे दावों के भुगतान के संबंध में पॉलिसीधारकों के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने की स्थिति में हो।
- बीमा कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पॉलिसी के अंतर्गत लाभ, निबंधन एवं शर्तों का खुलासा करें। बीमाकर्ता द्वारा निकाले गए विज्ञापनों से बीमा कराने वाली जनता भ्रमित नहीं होनी चाहिए।
- सभी बीमाकर्ताओं को अपने मुख्य कार्यालयों में तथा अन्य कार्यालयों में उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- प्राधिकरण बीमाकर्ताओं द्वारा बीमा संविदा के तहत प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में पॉलिसीधारकों से प्राप्त किसी शिकायत का मामला बीमकर्ता के समक्ष रखता है।

इतिहास

बीमा उद्योग में पहले २६% विदेशी निवेश (एफडीआई) था इसे बढ़ा कर ४९% किया गया था। वर्तमान में विदेशी निवेश का प्रावधान १००% कर दिया गया है।

- १९९१- भारत सरकार ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम और वित्तीय क्षेत्र में सुधार शुरू किया।
- १९९३- श्री आर एन मल्होत्रा के नेतृत्व में एक समिति बीमा क्षेत्र में सुधार करने के लिए सेटअप किया गया था।
- १९९४- मल्होत्रा समिति क्षेत्र का अध्ययन किया और हितधारकों के बाहर सुनवाई कुछ सुधारों की सिफारिश की।

संगठनात्मक संरचना

आईआरडीए अधिनियम ' 1999 की धारा 4 के अनुसार,बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण सम्पादन(आईआरडीए , जो संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था प्राधिकरण की संरचना निर्दिष्ट दस लोगों के हाथ में होगी। वे इस प्रकार में है:

- एक अध्यक्ष - टी.एस. विजयन।
- पांच पूर्णकालिक सदस्यों - आर नायर , एम राम प्रसाद , एस रॉय चौधरी, डी.डी. सिंह।
- चार अंशकालिक सदस्यों - अनूप वाधवान , एस.बी. माथुर , प्रो वि.के.गुप्ता , सीए सुबोध केआर.अग्रवाल

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल

1. अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों का कार्यकाल ५ वर्ष है और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, मगर उनकी आयु ६५ से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।
2. अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल ५ वर्ष है, लेकिन वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है।
3. सदस्य अपने कार्यालय त्याग सकता है किन्तु उसे केन्द्रीया सरकार को ३ महिने पहले सुचित करना होगा।

हटाने या कार्यालय से बर्खास्त

1. अगर सदस्य दिवालिया घोषित किया जाते है।
2. अगर किसी भी अपराध का दोषी पाया गया हो।
3. अगर उसने जनता के हित के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग किया हो।
4. अगर उसने वित्तीय स्थिति किसी कंपनी में अधिग्रहण किया हो।

भूमिका और कार्य

1. पंजीकरण को संशोधित करने, नवीनीकृत, वापस लेने, निलंबित या किसी भी तरह के पंजीकरण कि अयोग्य समझा जाता है तो पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार भी है।
2. बीमा पॉलिसी के बताए से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करता है, बीमा दावे का निपटारा,बीमा योग्य ब्याज इत्यादि।
3. यह सर्वे करनेवालो और नुकसान मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आचार संहिता देता है।
4. यह बीमा कारोबार में दक्षता को बढ़ावा देता है।
5. जीवन बीमा कारोबार और सामान्य (या गैर - जीवन) बीमा कारोबार का प्रतिशत को निर्दिष्ट ग्रामीण या सामाजिक क्षेत्र में बीमा कंपनी द्वारा किए जा सके।
6. प्रभावी ढंग से टैरिफ सलाहकार समिति के कामकाज की निगरानी रखथा है।
7. शोधन क्षमता के मार्जिन के रखरखाव के विनियमन करना।
8. बीमा कंपनी और बीमा (ग्राहक) के बीच विवादों का निपटारा करता है।
9. बीमा कंपनियों द्वारा धन के निवेश को नियंत्रण और औरविनियमित रखना।

सारांश

बीमित व्यक्ति द्वारा कुछ निर्दिष्ट घटनाओं की घटना पर होने वाली हानि या क्षति के लिए मुआवजे का अनुबंध बीमा कहा जाता है। बीमा की अवधि के लिए प्रीमियम देय है। एक बीमा अनुबंध कुछ सिद्धांतों, जैसे कि भरोसेमंद, बीमा योग्य ब्याज, मुआवजे, उपद्रव, योगदान इत्यादि पर बनाया गया है। एक जीवन बीमा अनुबंध सुरक्षा के उद्देश्य के साथ-साथ एक निवेश अनुबंध भी प्रदान करता है। यह एक सुरक्षा अनुबंध है क्योंकि यह बीमा राशि की पूरी राशि का भुगतान करके मृत्यु की स्थिति में आश्वासन को सुरक्षा प्रदान करता है। यह एक निवेश अनुबंध भी है, क्योंकि यह पॉलिसी के अंत में ब्याज और बोनस के साथ पैसे वापस करने का आश्वासन देता है। सामान्य बीमा का एक अनुबंध केवल एक सुरक्षा अनुबंध के रूप में और नहीं एक निवेश अनुबंध है, जहां पैसा प्रीमियम के रूप में भुगतान वापस बीमा करने के लिए आ जाएगा, दावों के माध्यम से, केवल कुछ निर्दिष्ट घटनाओं के घटित होने पर के रूप में कार्य करता है।

अभ्यास प्रश्न

1. "बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनिश्चितताएं निश्चित की जाती हैं।" बयान पर चर्चा करें और बीमा के महत्व की व्याख्या करें।
2. बीमा परिभाषित करें और इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें।
3. विभिन्न प्रकार के बीमा का वर्णन करें।
4. "बीमा का अनुबंध अत्यंत भरोसेमंद का अनुबंध है।" चर्चा करें।
5. बीमा योग्य ब्याज परिभाषित करें। इस सिद्धांत के महत्व पर चर्चा करें।

पाठन स्रोत

1. Gupta, P.K., Insurance and Risk Management, Himalaya Publishing House, New Delhi.
2. Mathew, M.J., Insurance, RBSA Publishers, Jaipur.
3. Ganguly, Anand, Insurance Management, New Age Publishers, New Delhi.
4. Mishra, M.N., Insurance, S.Chand and Sons, New Delhi.

इकाई - IV:
मर्चेंट बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवायें
(Merchant Banking and other Financial Services)

विषय सूचि

- मर्चेंट बैंकिंग: उत्पत्ति, अर्थ और कार्य (Merchant Banking: Origin, Meaning and Functions)
- मर्चेंट बैंकर की भूमिका (Role of a merchant Bankers)
- वाणिज्यिक बैंक और मर्चेंट बैंकिंग (Commercial Banks and Merchant Banking)
- मर्चेंट बैंकरों के लिए सेबी के दिशानिर्देश (SEBI guide11nes for merchant bankers)
- पूंजी बाजार और शेयर बाजार (Capital market and stock exchange)
- सेबी की भूमिका (Ro1e Of SEBI)
- क्रेडिट रेटिंग और बिल डिस्काउंटिंग (Credit Rating and Bill Discounting) |
- उद्यम पूंजी (Venture Capital)

मर्चेंट बैंकिंग

मर्चेंट बैंकिंग की उत्पत्ति इटली है। इतालवी अनाज व्यापारियों ने कमोडिटी व्यापारियों और कार्गो मालिकों के लिए धन उपलब्ध कराया। उनकी अन्य गतिविधियां माल की खरीद, बिक्री और शिपिंग कर रही थीं। मर्चेंट बैंकर या तो व्यक्ति या बैंकिंग हाउस थे। बाद में, व्यापारी बैंकिंग परिचालनों का केंद्र इटली से एम्स्टर्डम और उसके बाद लंदन में स्थानांतरित कर दिया गया।

सेबी द्वारा निर्धारित कानूनी ढांचे ने इन मध्यस्थों के संचालन को नियंत्रित किया। सिक्योरिटीज मार्केट से संबंधित धोखेबाज और अनुचित व्यापार प्रथाओं के निषेध और अंदरूनी व्यापार से संबंधित मामलों पर परामर्श / परामर्श पर प्रतिबंध लगाने के लिए सेबी द्वारा नियम और विनियम तैयार किए गए थे।

इन मध्यस्थों और सेबी के नियमों की उनकी गतिविधियों पर पूंजी / प्रतिभूतियों के मुद्दों से संबंधित मुद्दे की प्रक्रिया को इस इकाई में व्यापक रूप से निपटाया जाता है।

मर्चेंट बैंकर परिभाषा

"एक मर्चेंट बैंकर का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो इश्यू प्रबंधन के कारोबार में लगी हुई है या तो प्रतिभूतियों को बेचने, खरीदने या सब्सक्राइब करने या प्रबंधक / परामर्शदाता / सलाहकार के रूप में कार्य करने या इस तरह के मुद्दे के संबंध में कॉर्पोरेट सलाहकार सेवा प्रदान करने के संबंध में व्यवस्था करके"।

परिभाषा में 'मुद्दे' शब्द किसी भी बॉडी-कॉरपोरेट / अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, या जनता से या जनता के धारकों द्वारा प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद के प्रस्ताव को संदर्भित करता है एक मर्चेंट बैंकर के माध्यम से प्रतिभूतियां।

मर्चेंट बैंकरों की श्रेणियां

मर्चेंट बैंकर चार श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं: -

1. श्रेणी 1 - इस श्रेणी के व्यापारी बैंकर मुद्दे प्रबंधन से संबंधित किसी भी गतिविधि को ले जा सकते हैं। गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- प्रॉस्पेक्टस की तैयारी और मुद्दे से संबंधित अन्य जानकारी,
- वित्तीय संरचना का निर्धारण,
- फाइनेंसरों का टाई-अप,
- प्रतिभूतियों का अंतिम आवंटन
- सदस्यता की वापसी आदि,

वे सलाहकार, परामर्शदाता, सह-प्रबंधकों, अंडरराइटर्स या पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

2. श्रेणी II - इस श्रेणी के व्यापारी बैंकर सलाहकार, परामर्शदाता, सह-प्रबंधकों, अंडरराइटर्स और पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

3. श्रेणी III - इस श्रेणी के व्यापारी बैंकर किसी मुद्दे पर अंडरराइटर्स, सलाहकार और सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं।

4. श्रेणी IV - इस श्रेणी के व्यापारी बैंकर केवल सलाहकार या सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं।

श्रेणी 1 के नीचे सभी श्रेणियां 5 सितंबर 1997 को सेबी द्वारा समाप्त कर दी गई थीं। श्रेणी -1 के नीचे काम करने वाले लोगों को श्रेणी -1 स्थिति के लिए आवेदन करना होगा।

मर्चेंट बैंकरों के कार्य

1. कॉर्पोरेट परामर्श
2. परियोजना परामर्श
3. पूर्व निवेश अध्ययन
4. पूंजी पुनर्गठन
5. क्रेडिट सिंडिकेशन और परियोजना वित्त
6. अंक प्रबंधन और अंडरराइटिंग
7. पोर्टफोलियो प्रबंधन
8. कार्यशील पूंजी वित्त
9. क्रेडिट और बिल छूट की स्वीकृति
10. विलय, समामेलन और अधिग्रहण
11. उद्यम पूंजी
12. लीज वित्तपोषण
13. विदेशी मुद्रा वित्त पोषण
14. सावधि जमा ब्रोकिंग
15. म्यूचुअल फंड

इन कार्यों के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं:

कॉर्पोरेट परामर्श

एक कॉर्पोरेट उद्यम के कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किए गए गतिविधियों का एक सेट कॉर्पोरेट परामर्श के रूप में जाना जाता है। व्यापारी बैंकर निम्नलिखित गतिविधियों में मार्गदर्शन कर रहा है:

- सरकार की आर्थिक और लाइसेंसिंग नीतियों के आधार पर विविधीकरण।
- उत्पाद लाइनों का मूल्यांकन, उनके विकास और लाभप्रदता का विश्लेषण और भविष्य के रुझानों का पूर्वानुमान।
- बीमार इकाइयों का निदान, आधुनिकीकरण और विविधीकरण के माध्यम से पुनर्वास के लिए पुनरुद्धार संभावनाओं का आकलन, उनकी उत्पादन तकनीक और वित्तीय संरचना में सुधार के लिए उपयुक्त रणनीति का सुझाव देना।
- बैंक / वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पुनर्वास के लिए धन की व्यवस्था करना।
- पुनर्वास योजनाओं की निगरानी।
- बीमार इकाइयों के अधिग्रहण की सहायता करना

परियोजना परामर्श

परियोजना परामर्श वित्तीय, आर्थिक, वाणिज्यिक तकनीकी आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन है ... इसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

- परियोजना विचार की समीक्षा, व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करना और कार्यान्वयन के लिए सलाह प्रदान करना।
- परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना सर्वेक्षण तैयार करने, बाजार सर्वेक्षण आयोजित करने और सरकारी सहमति (अनुमोदन / लाइसेंस / अनुमति / अनुदान) प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
- भारत और विदेशों में भारतीय परियोजनाओं में निवेश करने में मार्गदर्शन प्रदान करना।
- विदेशी सहयोग, समामेलन, विलय, और टेकओवर की व्यवस्था और बातचीत।

प्री-इनवेस्टमेंट स्टडीज

विकास और लाभ संभावनाओं के संदर्भ में पूंजीगत निवेश के वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन करने के लिए यह विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन है। पूर्व निवेश अध्ययन से संबंधित गतिविधियां हैं:

- पर्यावरण और नियामक कारकों का विश्लेषण करना
- कच्चे माल के स्रोतों की पहचान
- मांग का आकलन
- वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन

पूंजी पुनर्गठन सेवाएं

पूंजी पुनर्गठन का लक्ष्य पूंजी की लागत को कम करना और शेयरधारकों की संपत्ति को अधिकतम करना है। व्यापारी बैंकर पूंजी पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं:

- कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप इष्टतम पूंजी संरचना का निर्धारण।
- बोनस शेयर जारी करने के माध्यम से रिजर्व के पूंजीकरण के लिए पूंजीगत मुद्दों के नियंत्रक की सहमति प्राप्त करना।

क्रेडिट सिंडिकेशन

क्रेडिट सिंडिकेशन क्रेडिट खरीद और परियोजना वित्तपोषण से जुड़ी गतिविधियों को संदर्भित करता है, जिसका लक्ष्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भारतीय और विदेशी मुद्रा ऋण को बढ़ाने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से 'क्रेडिट सिंडिकेशन' के रूप में जाना जाता है। गतिविधियां हैं:

- परियोजना की कुल लागत का आकलन और कुल परियोजना लागत के लिए एक वित्त पोषण योजना तैयार करना।
- टर्म लोनर्स / वित्तीय संस्थानों / बैंकों से वित्तीय सहायता के लिए ऋण आवेदन तैयार करना, और पूर्व-स्वीकृति वार्ता सहित उनकी प्रगति की निगरानी करना।
- वित्त पोषण के लिए भागीदारी के लिए संस्थानों और बैंकों का चयन करना।

पूंजी बाजार(Capital market)

पूंजी बाजार भारतीय वित्तीय प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खण्ड है। यह कंपनियों को उपलब्ध एक ऐसा बाजार है जो उनकी दीर्घावधिक निधियों की जरुरतों को पूरा करता है। यह निधियां उधार लेने और उधार देने की सभी सुविधाओं और संस्थागत व्यवस्थाओं से संबंधित है। अन्य शब्दों में, यह दीर्घावधि निवेश करने के प्रयोजनों के लिए मुद्रा पूंजी जुटाने के कार्य से जुड़ा है। इस बाजार में कई व्यक्ति और संस्थाएं (सरकार सहित) शामिल हैं जो दीर्घावधि पूंजी की मांग और आपूर्ति को सारणीबद्ध करते हैं और उसकी मांग करते हैं। दीर्घावधि पूंजी की मांग मुख्य रूप से निजी क्षेत्र विनिर्माण उद्योगों, कृषि क्षेत्र, व्यापार और सरकारी एजेंसियों की तरफ से होती है। जबकि पूंजी बाजार के लिए निधियों की आपूर्ति अधिकतर व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट बचतों, बैंकों, बीमा कंपनियां, विशिष्ट वित्त पोषण एजेंसियों और सरकार के अधिशेषों से होती है।

भारतीय पूंजी बाजार स्थूल रूप से गिल्ट एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में विभाजित है -

उत्कृष्ट बाजार: सरकार और अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई). का समर्थन प्राप्त है। सरकारी प्रतिभूतियां सरकार द्वारा जारी की गई बिक्री योग्य ऋण लिखते हैं, जो इसकी वित्तीय जरुरतों को पूरा करती हैं। 'उत्कृष्ट' शब्द का अर्थ है 'सर्वोत्तम क्वालिटी'। इसी कारण सरकारी प्रतिभूतियों को बाकीदारी का कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ता और इनसे काफी मात्रा में नकदी प्राप्त होती है (क्योंकि इसे बाजार में चालू मूल्यों पर बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है।) भारतीय रिजर्व बैंक के खुले बाजार संचालन की ऐसी प्रतिभूतियों में किए जाते हैं।

औद्योगिक प्रतिभूति बाजार: ऐसा बाजार है जो कंपनियों की इक्विटियों और ऋण-पत्रों (डिबेंचरों) का लेन-देन करता है। इसे आगे प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में विभाजित किया गया है।

प्राथमिक बाजार (नया निर्गम बाजार):- यह बाजार नई प्रतिभूतियों अर्थात् ऐसी प्रतिभूतियां जो पहले उपलब्ध नहीं थी और निवेश करने वाली जनता को पहली बार पेश की गई हैं, का लेन-देन करता है। यह बाजार शेयरों और डिबेचरों के रूप में नए सिरे से पूंजी जुटाने के लिए है। यह निर्गमकर्ता कंपनी को नया उद्यम शुरू करने अथवा मौजूदा उद्यम का विस्तार करने अथवा उसमें विविधता लाने के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करता है, और इस प्रकार कंपनी के वित्त पोषण में इसका योगदान प्रत्यक्ष है। कंपनियों द्वारा नई पेशकश या तो प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) अथवा राइट्स इश्यु के रूप में की जाती हैं।

द्वितीयक बाजार/शेयर बाजार (पुराना निर्गम बाजार अथवा शेयर बाजार):- यह वर्तमान कंपनियों की प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का बाजार है। इसके तहत प्रतिभूतियों का लेन-देन प्राथमिक बाजार में जनता को पहले इनकी पेशकश करने और/अथवा शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने के बाद ही किया जाता है। यह एक संवेदी बेरोमीटर है और विभिन्न प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के माध्यम से अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों को परिलक्षित करता है। इसे "व्यक्तियों को एक निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, जो प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री और लेन-देन के व्यवसाय में सहायता देना, उसे विनियमित अथवा नियमित करने के लिए गठित किया गया है" के रूप में परिभाषित किया गया है। शेयर बाजार में सूचीबद्धता शेयर धारकों को शेयर की कीमतों में घट-बढ़ की कारगार ढंग से निगरानी करने में समर्थ बनाती है। इससे उन्हें इस संबंध में विवकेपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या वे अपनी धारिताओं को बनाए रखें अथवा बेच दे अथवा आगे और भी संचित कर लें। लेकिन शेयर बाजार प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराने के लिए निर्गमकर्ता कंपनियों को कई निर्धारित मानदण्डों और प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।

विनियामक ढांचा

भारत में, पूंजी बाजार आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के पूंजी बाजार प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाता है। यह प्रभाग प्रतिभूति बाजरों (अर्थात् शेयर, ऋण और व्युत्पन्न) की सुव्यवस्थित संबृद्धि और विकास और साथ ही साथ निवेशकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। विशेष रूप से , यह निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है

(i) प्रतिभूति बाजारों में संस्थागत सुधार,

(ii) विनियामक और बाजार संस्थाओं की स्थापना,

(iii) निवेशक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना,और

(iv) प्रतिभूति बाजारों के लिए सक्षम विधायी ढांचा प्रदान करना, जैसे कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम 1992); प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956; और निक्षेपागार (डिपाजिटरी) अधिनियम, 1996.यह प्रभाग इन विधानों और इनके तहत बनाए गए नियमों की प्रशासित करता है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)

एक विनियामक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने एवं पूंजी बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए सेबी अधिनियम, 1992 के अधीन की गई थी। इसके कार्यों में शेयर बाजारों के व्यापार को विनियमित करना; शेयर दलालों, शेयर हस्तांतरण एजेंटों, व्यापारी बैंकरों, हामीदारों आदि का निरीक्षण करना; तथा प्रतिभूति बाजारों की अनुचित व्यापार प्रणालियों का निषेध करना शामिल है। सेबी के निम्नलिखित विभाग द्वितीयक बाजार के कार्यकलापों की निगरानी करते हैं:-

1. **बाजार मध्यवर्ती पंजीकरण एवं पर्यवेक्षण (एम आई आर एस डी)** – बाजारों के सभी खण्डों जैसे कि इक्विटी, इक्विटी व्युत्पन्नों, ऋण और ऋण से संबंधित व्युत्पन्नों के संबंध में सभी बाजार मध्यवर्तियों के पंजीकरण, पर्यवेक्षण, अनुपालना निगरानी और निरीक्षण से संबंधित हैं।
2. **बाजार विनियमन विभाग (एन आर डी)** – यह नई नीतियां तैयार करने, प्रतिभूति बाजारों, उनके सहायक बाजारों और बाजार संस्थाओं जैसे कि समशोधन और निपटान संगठन और निक्षेपागार की कार्यप्रणाली और संचालनों (व्युत्पन्नों से संबंधित संचालनों को छोड़कर) को निरीक्षण से संबंधित है।
3. **व्युत्पन्न और नए उत्पाद विभाग (डी एन पी डी)** – यह विभाग शेयर बाजारों के व्युत्पन्न खंडों में लेन-देन का निरीक्षण करने, लेन-देन किए जाने वाले नए उत्पादों को शुरू करने और परिणामी नीतिगत परिवर्तन करने के कार्य से संबंधित है।

नीतिगत उपाय और पहलें

पूंजी बाजार के प्राथमिक और द्वितीयक खंडों में वित्तीय और विनियामक सुधार करने के लिए सरकार ने, समय-समय पर, कई पहलें शुरू की हैं। मुख्य तौर पर इन उपायों का उद्देश्य देश के पूंजी बाजार में निवेशकों (घरेलू और विदेशी दोनों) का विश्वास कायम रखना है। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राथमिक बाजार में शुरू की गई नीतिगत पहलें निम्नलिखित हैं:-

सेबी ने भारत में जमाकर्ताओं को रसीदें जारी करने की इच्छुक कंपनियों के प्रकटीकरणों और अन्य संबंधित अपेक्षाओं की अधिसूचित किया है। इसे यह अधिदेश दिया गया है कि:-

(i) निर्गमकर्ता अपने देश में सूचीबद्ध होना चाहिए;

(ii) यह किसी भी विनियामक निकाय द्वारा वर्जित नहीं किया गया होना चाहिए; और

(iii) उनका प्रतिभूति बाजार विनियमों का अनुपालन करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए.

निरन्तर सूचीबद्ध रहने की एक शर्त के तौर पर सूचीबद्ध कंपनियों को, जारी किए गए कुल शेयरों के 25 प्रतिशत की सार्वजनिक शेयरधारिता न्यूनतम स्तर पर बनाए रखना होगी। इसके कुछ अपवाद हैं:-

(i) वे कंपनियां जिन्हें प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियमावली, 1957 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन 25 प्रतिशत से कम का स्तर बनाए रखना अपेक्षित है; और

(ii) वे कंपनियां जिनके दो करोड़ अथवा इससे अधिक सूचीबद्ध शेयर और 1,000 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक और बाजार पूंजी है।

सेबी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्गमकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पेशकश प्रलेख के आवरण पृष्ठ पर इस बात का उल्लेख करें कि क्या उन्होंने रेटिंग एजेंसियों से आईपीओ (आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश) ग्रेडिंग के लिए विकल्प दिया है। यदि निर्गमकर्ता ग्रेडिंग का विकल्प देते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे विवरण पत्रिका में अस्वीकृत ग्रेडों सहित ग्रेडों का प्रकटीकरण करें।

सेबी ने निधियां जुटाने की एक त्वरित और किफायती प्रणाली जिसे 'पात्र संस्थागत नियोजन (क्युआईपी)' कहा जाता है, की सुविधा प्रदान की है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति बाजार से प्रतिभूतियों के निजी नियोजन अथवा पात्र संस्थागत विक्रेता के परिवर्तनीय बॉण्डों के जरिए निधियां जुटाई जाती हैं।

सेबी ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि आरम्भिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) करने वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के निर्गम-पूर्व शेयरों पर 'लॉक इन अवधि' न होने के लाभ को, जो इस समय उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ)/विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (एफवीसीआई) द्वारा धारित शेयरों के लिए उपलब्ध हैं, निम्नलिखित तक सीमित कर दिया जाएगा:- (i) सेबी को प्रारूप विवरणिका प्रस्तुत करने की तारीख को सेबी में कम से कम एक वर्ष से पंजीकृत वीसीएफ अथवा एफवीसीआई के द्वारा धारित शेयर; और (ii) सेबी में पंजीकृत वीसीएफ/एफवीसीआई को सेबी में प्रारूप विवरणिका प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व एक वर्ष की अवधि के दौरान परिवर्तनीय लिखतों के रूपातंरण पर जारी शेयर।

सेबी ने, प्रतिभूतियों के निर्गम की आयोजना करने वाली कंपनियों द्वारा निर्गम-पूर्व प्रचार को नियंत्रित करने के लिए 'प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों' में संशोधन करके निर्गम – पूर्व प्रचार पर प्रतिबंध को लागू किया है। प्रतिबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ निर्गमकर्ता कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि इसका प्रचार विगत प्रणालियों के सुसंगत है, उसमें कोई ऐसे पूर्वानुमान/ अनुमान/सूचना निहित नहीं है जो सेबी में प्रस्तुत किए गए पेशकश प्रलेख से अलग हो।

इसी प्रकार वर्ष 2016-17 के दौरान द्वितीयक बाजार में शुरू की गई नीतिगत पहले निम्नलिखित हैं:-

- वर्ष 2015 से नकदी बाजार के टी+2 चल निपटान परिदृश्य में लागू व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली के भ्रम में, शेयर बाजारों को सलाह दी गई है कि वे व्यापार शुरू करने के पिछले दिवस के समापन मूल्य और प्रात: 11 बजे, दोपहर 12.30 बजे, 2.00 बजे के मूल्यों और व्यापारी सत्र की समाप्ति पर मूल्य को हिसाब में लेते हुए, लागू जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के मार्जिन को एक दिन में कम से कम 5 बार अद्यतन करें। ऐसा, जोखिम प्रबंधन ढांचे को नकदी और व्युत्पन्न बाजारों के साथ जोड़ने के लिए किया गया है।
- 'अपने ग्राहक को पहचानें' संबंधी मानदंडों को सुदृढ़ बनाने और प्रतिभूति बाजार में लेन-देन की एक ठोस लेखा-परीक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए दृष्टि से लाभानुभोगी मालिक का खाता खोलने और नकदी खंड में लेन-देन करने के लिए 1 जनवरी, 2007 से 'स्थाई लेखा संख्या (पैन) को अनिवार्य बना दिया गया है।
- सेबी ने, कॉर्पोरेट बाण्डों के लेन-देन के लिए एक सम्मिलित मंच का निर्माण करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की दृष्टि से यह विनिर्दिष्ट किया है कि बीएसई लिमिटेड कॉर्पोरेट बाण्ड सूचना मंच की स्थापना करेगा और उसका रखरखाव करेगा। सभी संस्थाओं जैसे कि बैंकों, सरकारी क्षेत्र उद्यमों, नगर

निगमों, निगमित (कॉर्पोरेट) निकायों और कंपनियों द्वारा जारी की गई सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के सभी लेन-देन की सूचना दी जाएगी।

- भारतीय प्रतिभूति बाजार की आधारभूत ढांचा कंपनियों में विदेशी निवेश संबंधी भारत सरकार की नीति के अनुरूप शेयर बाजारों, निक्षेपगार और समाशोधन निगमों में विदेशी निवेश की सीमाएं इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई है:- (i) इन कंपनियों में 26 प्रतिशत की पृथक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सीमा और 23 प्रतिशत विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) सीमा के साथ 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। (ii) एफडीआई की अनुमति विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के विशेष पूर्वानुमोदन पर दी जाएगी; (iii) एफडीआई की अनुमति केवल द्वितीयक बाजार में खरीदों के माध्यम से दी जाएगी; और (iv) एफआईआई निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करेगा और न ही उसे प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।
- एफआईआई निवेश के आवेदन की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है और एचआईआई के तहत निवेश की नई श्रेणियों (बीमा और पुनर्बीमा कंपनियां, विदेशी सेंट्रल बैंक, निवेश प्रबंधक, अंतरराष्ट्रीय संगठन) को शामिल किया गया है।
- म्युचुअल फंडों की प्रारम्भिक निर्गम खर्च और लाभांश वितरण प्रक्रिया को युक्तिसंगत कर दिया गया है।
- म्युचुअल फंडों को स्वर्ण विनिमय व्यापारिक निधियां लागू करने की अनुमति दी गई है।
- सरकारी प्रतिभूति बाजार में, भारतीय रिजर्व बैंक ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एचआरबीएम)के उपबंधो के अनुसार केंद्र सरकार नके प्राथमिक निर्गमों में भाग लेना छोड़ दिया है।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश की अनुमति दी गई है।

इस प्रकार, पूंजी बाजार देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जैसा कि यह वास्तविक बचतों की मात्रा बढ़ाता है; निवेश की जाने योग्य निधियों का आबंटन बढ़ाकर निवेशों की क्षमता को बढ़ाता है; और अर्थव्यवस्था में पूंजी की लागत को कम करता है।

माध्यमिक बाजार / स्टॉक एक्सचेंज

शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे-बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाज़ार की तरह शेयर बाज़ार में भी खरीदने और बेचने वाले एक-दूसरे से मिलते हैं और मोल-भाव कर के सौदे पक्के करते हैं। पहले शेयरों की खरीद-बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने-बेचने वाले मुंहजबानी ही सौदे किया करते थे। लेकिन अब यह सारा लेन-देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिये होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिलती है। आज स्थिति यह है कि खरीदने-बेचने वाले एक-दूसरे को जान भी नहीं पाते।

एक प्रकार से देखे तो यहा पे शेयरो की नीलामी होती है। अगर किसी को बेंचना होता है तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ये शेयर बेंच दिया जाता है। या अगर कोई शेयर खरीदना चाह्ता है तो बेचने वालो मे से जो सबसे कम कीमत पे तैयार होता है उससे शेयर खरीद लिया जता है। शेयर मन्डी (जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इस तरह कि बोलियाँ लगाने के लिये ज़रूरी सभी तरह कि सुविधाये मुहैया कराते है। सोचिये, एक दिन मे करोड़ो शेयरों का आदान-प्रदान होता है। कित्ना मुश्किल हो जाये अगर सभी कारोबरियोँ को चिल्ला चिल्ला के ही खरीदे और बेंचने वालो को ढूंढ्ना हो। अगर ऐसा हो तो शेयर खरीद्ना और बेंचना कमोबेश असम्भव हो जायेगा। शेयर मन्डियाँ इस काम को सरल और सही ढंग से करने का मूलभूत ढांचा प्रदान करती है। कई प्रकार

के नियम, कम्प्यूटर की मदत, शेयर ब्रोकर, इंटेर्नेट के मध्यम से ये मूलभूत ढांचा दिया जाता है। असल मे शेयर बाज़ार एक बहुत ही सुविधाजनक सब्ज़ी मंडी से ज़्यादा कुछ भी नही है।

कुछ साल पहले तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मे सीधे खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। पिछले कुछ सालो से कम्प्यूटरो और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी घर बैठे शेयर खरीद और बेंच सकता है। सूचना क्रांति का ये एक उत्कृष्ट नमुना है। जो काम पहले कुछ पैसे वाले लोग ही कर सकते थे अब वो सब एक आम आदमी भी कर सक्ता है। आजकल सभी शेयर डीमटीरिअलाइज़्ड होते है। शेयरो के अलावा निवेशक भारतीय म्यूचुअल फंड मे भी पैसा लगा सक्ते है।आम ग्राहक को किसी डीमैट सर्विस देने वाले बैंक मे अपना खाता खोलना पडता है। आजकल कई बैंक जैसे आइसीआइसीआइ, एच डी एफ सी, भारतीय स्टटे बैंक, इत्यादि डीमैट सर्विस देते है। इस तरह के खाते की सालाना फीस 500-800 रु तक होती है।

शेयर बाज़ार किसी भी विकसित देश की अर्थ्व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते है। जिस तरह से किसी देश, गाँव या शहर के विकास के लिये सडके, रेल यातायात, बिजली, पानी सबसे ज़रूरी होते है, वैसे ही देश के उद्योगों के विकास के लिये शेयर बाज़ार ज़रूरी है। उद्योग धंधो को चलाने के लिये कैपिटल चहिये होता है। ये उन्हे शेयर बाज़ार से मिलता है। शेयर बाज़ार के माध्यम से हर आम आदमी बड़े से बड़े उद्योग मे अपनी भागिदारी कर सकता है। इस तरह की भागीदारी से वो बड़े उद्योगों मे होने वाले मुनाफे मे बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। मान लीजिये, अगर किसी भी नागरिक को ये लग्ता है कि आने वाले समय मे रिलायंस या इंफोसिस भारी मुनाफा कमाने वाली है, तो वह इस कम्पनियों के शेयर खरीद के इस मुनाफे मे भागीदार बन सकता है। और ऐसा करने के लिये तो व्यवस्था चहिये वो शेयर बाज़ार प्रदान करता है। एक अछा शेयर बाज़ार इस बात का ख्याल रखता है कि किसी भी निवेशक को बराबर का मौका मिले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज व नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा देशभरर मे 27 क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज है।

स्टॉक एक्सचेंज का अर्थ है कि व्यक्तियों में से किसी को भी प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या निपटने के व्यवसाय को विनियमित करने या नियंत्रित करने के उद्देश्य से गठित किया गया है या नहीं। इन प्रतिभूतियों में शामिल हैं:

(i) शेयर, स्क्रिप्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक या किसी भी शामिल कंपनी या अन्य बॉडी कॉरपोरेट की तरह किसी प्रकृति की अन्य मार्केबल सिक्योरिटीज;

(ii) सरकारी प्रतिभूतियां; तथा

(iii) प्रतिभूतियों में अधिकार या रुचि।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

एशिया के सबसे प्राचीन शेयर बाजार 'बीएसई' की स्थापना 1875 में लोकप्रिय `बाम्बे स्टाक एक्सचेंज' के रूप में हुई थी। भारतीय पूंजी बाजार के विकास में इस एक्सचेंज की व्यापक भूमिका रही है और इसका सूचकांक विश्वविख्यात है। मैनेजिंग डायरेक्टर के नेतृत्व में डायरेक्टर्स बोर्ड द्वारा एक्सचेंज का संचालन होता है। इस बोर्ड में प्रतिष्ठित प्रोफेशनल्स, ट्रेडिंग सदस्यों के प्रतिनिधियों और सार्वजनिक प्रतिनिधियों का समावेश है। एक्सचेंज भारत के छोटे - बड़े शहरों में अपनी उपस्थिति के साथ राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। बीएसई की सिस्टम और प्रक्रिया ऐसी है कि बाजार की पारदर्शिता और सुरक्षा बनी रहे। वैश्विक कीर्तिमान स्थापित कर, सर्वोच्च स्टाक एक्सचेंज के रूप में उभरने वाले इस एक्सचेंज के पास सवा सौ से अधिक वर्षों के भव्य इतिहास की समृद्ध विरासत है।

एक्सचेंज में `ट्रेडिंग राइट' और `ओनरशिप राइट' एक दूसरे से अलग है। ऐसी परिस्थिती में निवेशकों के हितों पर विशेष सावधानी बरती जाती है। एक्सचेंज इक्विटी, डेब्ट तथा प्युचर्स और ऑप्शन के व्यापार के लिए ढांचा एवं पारदर्शक ट्रेडिंग सिस्टम सुनिश्चित करता है। बीएसई की आनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली बेहतरीन गुणवत्तावाली है। वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त इन्फार्मेशन सिक्युरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का दर्जा BS 7799-2:2002 सर्टिफिकेट वाला है। BS 7799 ऑडिट डीएनवी (Det Norske Veritas) द्वारा किया गया था। यह प्रमाणपत्र प्राप्त करनेवाला बीएसई भारत का एकमात्र और विश्व का दूसरा एक्सचेंज है। जानकारी एकत्रित करने, जोखिम को नियंत्रित करने तथा तकनीकी प्रणाली और लोगों की सम्पत्ती की सुरक्षा के लिए BS 7799 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक है।

स्टॉक एक्सचेंज के उद्देश्य हैं

- एक्सचेंज पर सार्वजनिक लेनदेन करने के निवेश के हितों की रक्षा करना।
- प्रतिभूति लेनदेन में सम्माननीय और केवल प्रथाओं को स्थापित और बढ़ावा देना।
- प्रतिभूतियों में निपटने के लिए अच्छी तरह से विनियमित बाजार को बढ़ावा देना, विकसित करना और बनाए रखना।
- कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से कुशल संसाधन मोबिलिज़ेशन के माध्यम से देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना देश भर से निवेशकों को समान पैर पर पहुंच प्रदान करने के लिए की गई थी। एनएसई को भारत सरकार के आदेश पर अग्रणी वित्तीय संस्थानों द्वारा पदोन्नत किया गया था और देश में अन्य स्टॉक एक्सचेंजों के विपरीत, नवंबर 1992 में कर-भुगतान कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। अप्रैल 1993 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1956 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अपनी मान्यता पर, एनएसई ने जून 1994 में थोक ऋण बाजार (डब्लूडीएम) सेगमेंट में परिचालन शुरू किया। पूंजी बाजार (इक्विटी) सेगमेंट ने नवंबर 1994 में परिचालन शुरू किया, और डेरिवेटिव्स सेगमेंट में संचालन जून 2000 में शुरू हुआ। एनएसई (चित्र) की संगठनात्मक संरचना नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएससीसीएल), इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आईआईएसएल), नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड के बीच के लिंक के माध्यम से है। (एनएसडीएल), डॉटएक्स इंटरनेशनल लिमिटेड (डॉटएक्स) और एनएसईआईआईटी लिमिटेड एनएसई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अगस्त 199 5 में शामिल किया गया था। इसे समाशोधन में विश्वास लाने और बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था। और कम और निरंतर निपटान चक्रों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियों का निपटान, और प्रतिपक्ष जोखिम गारंटी प्रदान करने के लिए।

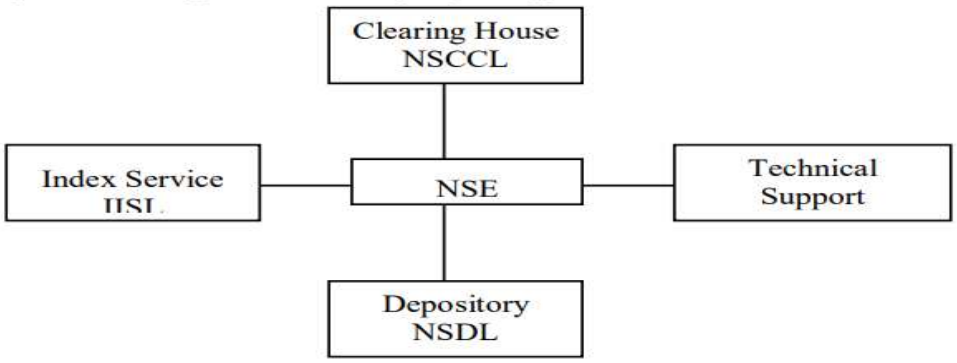

भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) मुंबई, 3 नवंबर 1994 को मुंबई में पूंजी बाजार खंड में परिचालित हो गया। एनएसई की उत्पत्ति फेरवानी कमेटी (199 1) की सिफारिशों में निहित है। एनएसई के अलावा, उसने राष्ट्रीय स्टॉक मार्केट सिस्टम की स्थापना के लिए भी सिफारिश की थी। समिति ने भारतीय शेयर बाजार में पांच प्रमुख दोषों की ओर इशारा किया। निर्दिष्ट दोष हैं

1. गहराई और चौड़ाई के मामले में अधिकांश बाजारों में तरलता की कमी।
2. ऋण के लिए बाजार विकसित करने की क्षमता की कमी।
3. बुनियादी सुविधाओं की सुविधा और पुरानी व्यापार प्रणाली की कमी।
4. निवेशकों के आत्मविश्वास को प्रभावित करने वाले संचालन में पारदर्शिता की कमी।
5. पुरानी निपटान प्रणाली जो बढ़ती मात्रा को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, जिससे देरी हो रही है।
6. कानूनी संरचना और नियामक फ्रेम कार्य के साथ मिलकर काम करने के लिए विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों की अक्षमता के कारण एकल बाजार की कमी।

इन कारकों ने एनएसई की स्थापना की। एनएसई का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है

- इक्विटी, ऋण उपकरणों और संकरों के लिए राष्ट्रव्यापी व्यापार सुविधा स्थापित करना।
- उपयुक्त संचार नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में निवेशकों के बराबर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए।
- इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क का उपयोग कर निवेशकों को उचित, कुशल और पारदर्शी प्रतिभूति बाजार प्रदान करना।
- छोटे निपटारे चक्र और पुस्तक प्रविष्टि निपटान प्रणाली को सक्षम करने के लिए।
- प्रतिभूति बाजार के मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए।

एनएसई आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, एलआईसी, जीआईसी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, निगम बैंक, इंडियन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक होल्डिंग के प्रमोटर भारत का निगम और एसबीआई कैपिटल मार्केट एनएसई के प्रमोटर हैं।

एनएसई के फायदे

व्यापक पहुंच एनएसई सैटेलाइट लिंक्ड ट्रेडिंग सुविधा के माध्यम से व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है। वीएसएटी के साथ कंप्यूटर टर्मिनल और लिंक व्यापारियों को देश के अन्य हिस्सों में अपने समकक्षों से संपर्क करने में मदद करते हैं। त्वरित व्यापार प्रणाली बेहतर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करता है।

स्क्रीन आधारित व्यापार मूल रूप से, एनएसई का मूल लाभ कंप्यूटर आधारित व्यापार है। बैक ऑफिस लोड कम हो गया है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर में संग्रहीत है। वर्तमान में, बीएसई और कई अन्य स्टॉक एक्सचेंजों ने कंप्यूटर आधारित व्यापार शुरू किया है। अंगूठी आधारित व्यापार हाल के दिनों में गायब हो रहा है।

व्यापारिक सदस्यों की पहचान का खुलासा करने के दौरान ऑर्डर देने पर स्क्रीन पर सदस्य की पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह व्यापारिक सदस्य की इच्छा पर निर्भर करता है। तो कीमतों को प्रभावित करने के किसी भी डर के बिना, कोई भी सदस्य बड़े आकार के ऑर्डर दे सकता है।

पारदर्शी लेनदेन एनएसई व्यापार का प्रमुख लाभ पूर्ण पारदर्शिता है। निवेशक सौदे, प्रतिपक्ष और सौदे के निष्पादन के समय की दर का पता लगा सकता है। टर्मिनलों में दी गई पूछताछ की सुविधा निवेशक को विशेष सुरक्षा के बाजार की कीमत और गहराई को जानने में मदद करती है। निवेशक के पास उच्च और निम्न कोटेशन और विशेष सुरक्षा के अंतिम व्यापार मूल्य हो सकते हैं। यह जानकारी उन्हें अपने निवेश के बारे में स्वस्थ निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। ऑर्डर का मिलान करने के बाद कंप्यूटर में ऑर्डर दिया गया है, कंप्यूटर निवेशक या व्यापारी द्वारा दी गई शर्तों के अधीन उपयुक्त मेलिंग ऑर्डर खोजता है और पता लगाता है। शर्तें व्यापार की कीमत, मात्रा और समय से संबंधित हैं। आदेश से मेल खाते समय, मूल्य और समय के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। यदि मिलान आदेश मिलता है, तो सौदा मारा जाता है, अन्यथा निर्देशों के अनुसार आदेश लंबित या रद्द रखा जाएगा। कॉर्पोरेट लाभ का प्रभावी निपटान, सभी मौद्रिक लाभ दर्ज, लाभांश, ब्याज और रिडेम्प्शन राशि, कंपनी आपत्तियों पर दावे, को समाशोधन सदस्यों के समाशोधन खाते में सीधे डेबिट / क्रेडिट किया जाता है। यह कॉर्पोरेट लाभों के निपटारे में सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को कम करता है।

एनएसई में हालिया रुझान

एनएसई ने खुद को सफल साबित करने में कामयाब रहा है और देश की प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है। नेटवर्क, बाजार हिस्सेदारी, वॉल्यूम कारोबार, तरलता और सौदों की निकासी के विस्तार के मामले में एक्सचेंज अन्य स्टॉक एक्सचेंजों की तुलना में अच्छी तरह से अनुकूल रहा है। विस्तार मुंबई में अपना संचालन स्थापित करने के बाद, एनएसई ने अपने परिचालन को अन्य शहरों में विस्तारित किया था। एनएसई ने पूरे देश में 317 शहरों में 2580 वीएसएटीएस स्थापित किए हैं। गुणवत्ता राष्ट्रीय स्तर पर बाजार के समेकन के अलावा, खराब वितरण के साथ लेनदेन लागत में कमी आई है। शेयरों के डिमटेरियलाइजेशन ने खराब डिलीवरी में कमी में मदद की है। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रभावी कामकाज इसके लिए एक और कारण है।

अधिक तरलता इसकी ऑनलाइन प्रणाली और त्वरित व्यापार सुविधाओं के साथ, एनएसई ने पूंजी बाजार में कुछ तरलता पेश की है। 199 7 की आखिरी तिमाही में, एनएसई 835 स्क्रिप्स के लिए अधिक तरल था जो कुल व्यापार मात्रा का 9 7 प्रतिशत था। व्यापारों की संख्या में, खुदरा निवेशक की उपस्थिति का संकेतक, एनएसई बीएसई से आगे था। एनएसई में कम ब्रोकरेज पारदर्शिता ब्रोकरेज फीस, बाजार प्रभाव लागत और समाशोधन

और निपटारे में लागत को तोड़ने की अनुमति देती है। मुंबई के बाहर बीएसई टर्मिनलों में ब्रोकरेज शुल्क लेनदेन के मूल्य का 0.5 प्रतिशत है। एनएसई पर, यह लेनदेन मूल्य के लगभग 0.1 प्रतिशत है।

जोखिम के खिलाफ बीमा जब कोई निवेशक ब्रोकर या दो दलालों के साथ सौदा करता है तो एक दूसरे के साथ सौदा करता है, लेनदेन में पार्टियों में से किसी एक की भी संभावना है, भुगतान पर चूक। नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एनएसई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कानूनी गारंटी और ऐसे जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। 199 6 तक, ऐसे जोखिमों के खिलाफ कोई बीमा नहीं था। त्वरित समाशोधन और निपटारे एनएसई ने क्लियरिंग हाउस सुविधाओं की पूरी श्रृंखला पेश की है। प्रतिभूतियों का एक हिस्सा क्षेत्रीय समाशोधन केंद्रों (दिल्ली, चेन्नई और कलकत्ता) में संसाधित किया जाता है। वर्तमान में प्रदान की गई अंतर-क्षेत्र समाशोधन सुविधा, सदस्यों के जोखिम को कम करती है क्योंकि शेयरों की समय पर वितरण या पारगमन में शेयरों की हानि नहीं होती है। सुविधा से वितरण आधारित व्यापार को बढ़ावा देने की भी उम्मीद है। विदेशी संस्थागत निवेशक व्यापार ब्रोकर की पहचान लेनदेन निष्पादित होने तक अनजान बनी हुई है। एफआईआई के लिए गोपनीयता महत्वपूर्ण है, जो बीएसई पर अनुपलब्ध है, इसने एफआईआईएस को एनएसई पर व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। कॉर्पोरेट एनएसई के सदस्य बनने पर बढ़ रहा है। मार्च 2000 में 780 एनएसई सदस्यों के कॉर्पोरेट 668 में से हैं। एनएसई मौजूदा बीएसई के लिए मौजूदा एक्सचेंजों के लिए स्वस्थ खतरा बन गया है। यह एनएसई से प्रतिस्पर्धी खतरा है जिसने बीएसई को सुधारों और बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग तंत्र की शुरूआत करने के लिए तैयार किया।

सेबी की भूमिका

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी):

भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 19 88 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को अंतरिम प्रशासनिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सिक्योरिटीज के व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना था।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अपने कार्यों पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण है। 30 जनवरी 199 2 को, इसे एक अध्यादेश के माध्यम से एक सांविधिक दर्जा दिया गया था, जिसे बाद में संसद अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 199 2 के नाम से जाना जाता है। सेबी को प्रतिभूति बाजार के निगरानी के रूप में माना जाता है।

सेबी की स्थापना के कारण:

1980 के दशक के दौरान, जनता की बढ़ती भागीदारी के कारण पूंजी बाजार में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। इसने दलालों, मर्चेंट बैंकरों, कंपनियों, निवेश सलाहकारों और अन्य लोगों द्वारा शामिल शेयरों की रिगिंग, नए मुद्दों पर अनौपचारिक प्रीमियम, स्टॉक एक्सचेंजों और लिस्टिंग आवश्यकताओं के नियमों और नियमों के उल्लंघन, शेयरों के वितरण में देरी आदि जैसे कई कदाचारों का नेतृत्व किया। प्रतिभूति बाजार।

इसके परिणामस्वरूप कई निवेशक शिकायतें हुईं। उचित दंड प्रावधान और कानून की कमी के कारण, सरकार और स्टॉक मैं एक्सचेंज निवेशकों की इन शिकायतों का समाधान करने में सक्षम नहीं थे। यह (एक अलग

नियामक निकाय की आवश्यकता जरूरी है, और इसलिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी।

सेबी का उद्देश्य और भूमिका:

मुख्य उद्देश्य ऐसे वातावरण को बनाना है जो प्रतिभूति बाजार के माध्यम से कुशल मोबिलिलाइजेशन और संसाधनों के आवंटन को सुविधाजनक बनाता है। इस माहौल में तीन समूहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियम और विनियम, नीति ढांचे, प्रथाओं और आधारभूत संरचनाएं शामिल हैं जो मुख्य रूप से बाजार यानी प्रतिभूतियों (कंपनियों), निवेशकों और बाजार मध्यस्थों के जारीकर्ता बाजार का गठन करती हैं।

(i) जारीकर्ताओं को:

सेबी का लक्ष्य जारीकर्ताओं को बाजार स्थान प्रदान करना है जहां वे आत्मविश्वास से एक आसान और कुशल तरीके से आवश्यक राशि को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।

(ii) निवेशकों को:

सेबी का लक्ष्य नियमित आधार पर पर्याप्त, सटीक और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करके निवेशकों के अधिकार और हितों की रक्षा करना है।

(iii) मध्यस्थों को:

मध्यस्थों को निवेशकों और जारीकर्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए सक्षम करने के लिए, सेबी पर्याप्त और कुशल बुनियादी ढांचे वाले प्रतिस्पर्धी, पेशेवर और विस्तारित बाजार प्रदान करता है।

सेबी के उद्देश्य:

सेबी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. संरक्षण: निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा, शिक्षित और रक्षा करने के लिए।

2. प्रतिस्पर्धी और पेशेवर: मर्चेंट बैंकरों, दलालों आदि जैसे मध्यस्थों को अपनी गतिविधियों को विनियमित करके और आचार संहिता विकसित करके प्रतिस्पर्धी और पेशेवर बनाना।

3. कदाचार की रोकथाम: व्यापार कदाचार को रोकने के लिए।

4. संतुलन: प्रतिभूति उद्योग द्वारा सांविधिक विनियमन और स्वयं विनियमन के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए।

5. व्यवस्थित कार्य: उन्हें स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज उद्योग के व्यवस्थित कामकाज को विनियमित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

सेबी के कार्य

सेबी अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट किया गया है कि सेबी का मूल कर्तव्य है (ए) प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा, और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए। सेबी द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

A. स्टॉक एक्सचेंजों और किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजारों में व्यापार को विनियमित करना;
B. शेयर दलालों, उप-दलालों, शेयर ट्रांसफर एजेंटों, बैंकरों को किसी मुद्दे पर, ट्रस्ट कर्मियों के ट्रस्टी, किसी मुद्दे पर रजिस्ट्रार, व्यापारी बैंकर, अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार और ऐसे अन्य मध्यस्थों के कामकाज को विनियमित करना और विनियमित करना किसी भी तरह से प्रतिभूति बाजारों से जुड़ा हो सकता है;
C. जमाकर्ताओं, प्रतिभागियों, प्रतिभूतियों के संरक्षक, विदेशी संस्थागत निवेशकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और ऐसे अन्य मध्यस्थों के काम को पंजीकृत और विनियमित करते हुए बोर्ड के रूप में, अधिसूचना द्वारा, इस ओर निर्दिष्ट कर सकते हैं;
D. म्यूचुअल फंड समेत उद्यम पूंजीगत धन और सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज को पंजीकृत और विनियमित करना;
E. स्वयं नियामक संगठनों को बढ़ावा देना और विनियमित करना;
F. प्रतिभूति बाजारों से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना;
G. निवेशकों की शिक्षा को बढ़ावा देना और प्रतिभूति बाजारों के मध्यस्थों के प्रशिक्षण;
H. प्रतिभूतियों में अंदरूनी व्यापार को रोकना;
I. शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और कंपनियों के अधिग्रहण को विनियमित करना;
J. जानकारी के लिए कॉलिंग, निरीक्षण उपक्रम, स्टॉक एक्सचेंजों, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज मार्केट, मध्यस्थों और प्रतिभूति बाजार में स्वयं नियामक संगठनों से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पूछताछ और लेखा परीक्षा आयोजित करना;
K. किसी भी बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी या बोर्ड या निगम से किसी भी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके द्वारा गठित प्रतिभूतियों में किसी लेनदेन के संबंध में स्थापित या गठित किसी भी बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी या बोर्ड या निगम से जानकारी और रिकॉर्ड मांगना। [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा डाला गया]।
L. ऐसे कार्यों को निष्पादित करना और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 19 56 के प्रावधानों के तहत ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जा सकता है।
M. इस खंड के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य शुल्क लेना;
N. उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए शोध का आयोजन;
O. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी भी एजेंसियों को कॉल करने या प्रस्तुत करने के लिए, ऐसी जानकारी जो इसके कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक समझा जा सकता है;
P. निर्धारित किए जा सकने वाले अन्य कार्यों को निष्पादित करना।

सेबी के कार्यों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि:

(1) नियामक समारोह
(2) विकास समारोह
(3) सुरक्षात्मक समारोह।

1. नियामक कार्य:

सेबी के नियामक कार्य इस प्रकार हैं: सेबी का प्राथमिक कार्य सिक्योरिटीज बाजार जैसे स्टॉक एक्सचेंजों के मामलों को नियंत्रित करना है। यह पूंजी बाजार से जुड़े मध्यस्थों के कार्य को पंजीकृत और नियंत्रित करता है। इनमें शेयर ब्रोकर्स, उप-दलाल, व्यापारी बैंकर, बैंकर और रजिस्ट्रार, मुद्दों, अंडरराइटर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट, पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार, जमाकर्ता, प्रतिभूतियों के संरक्षक और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) शामिल हैं। रेटिंग एजेंसियों जैसे संगठन, जो मध्यस्थ नहीं हैं, लेकिन पूंजी बाजार से संबंधित हैं, को भी सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

म्यूचुअल फंड और उद्यम पूंजी जैसे सामूहिक निवेश योजनाएं सेबी के दायरे में भी आती हैं। एक सामूहिक निवेश योजना में, निवेशकों द्वारा किए गए योगदान को इस योजना के निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार पूल किया जाता है और उपयोग किया जाता है। हालांकि, सेबी कंपनियां और सहकारी समितियों से जमा योजना को नियंत्रित नहीं करती है।

सेबी ने अंदरूनी व्यापार जैसे धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित किया है। इसके बोर्ड के पास कंपनियों और मध्यस्थों से किसी भी जानकारी की तलाश करने का अधिकार है, जिसका उपयोग पूछताछ करने के लिए किया जा सकता है।

1. ब्रोकर्स और एजेंटों का पंजीकरण: यह ब्रोकर, उप-दलाल, स्थानांतरण एजेंट, व्यापारी बैंक आदि पंजीकृत करता है।
2. नियमों और विनियमों की अधिसूचनाएं: यह प्रतिभूतियों के बाजार में सभी मध्यस्थों के सुचारू कामकाज के लिए नियमों और विनियमों को सूचित करता है।
3. शुल्क का लेवी: यह अपने दिशानिर्देशों और आदेशों का उल्लंघन करने के लिए फीस, जुर्माना और अन्य शुल्क लगाता है।
4. निवेश योजनाओं के नियामक: यह सामूहिक निवेश योजनाओं और म्यूचुअल फंडों को पंजीकृत और नियंत्रित करता है।
5. अवांछित व्यापार प्रथाओं को रोकता है: सेबी धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाती है।
6. निरीक्षण और पूछताछ: यह निरीक्षण करता है और स्टॉक एक्सचेंज की पूछताछ और लेखा परीक्षा आयोजित करता है
7. प्रदर्शन और व्यायाम शक्तियां: यह सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) अधिनियम 19 56 के तहत ऐसी शक्तियों का प्रदर्शन और अभ्यास करता है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा इसे सौंपा गया है।

2. विकास कार्य:

प्रतिभूति बाजार विकसित करने के लिए सेबी कई कदम उठाता है। नियमित अंतराल पर, यह शैक्षणिक और प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित करता रहता है। यह प्रतिभूति बाजार को विनियमित और विकसित करने में मदद के लिए अनुसंधान भी आयोजित करता है। ऐसा करने के लिए, यह कई लोगों और संगठनों के साथ साझेदार है। बाजार नियामक की एक समर्पित वेबसाइट भी है, जो निवेशक शिक्षा प्रदान करती है।

सेबी के विकास कार्य निम्नानुसार हैं:

1. मध्यस्थों को प्रशिक्षण: यह प्रतिभूतियों के मध्यस्थों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है।
2. उचित व्यापार का प्रचार: यह अंडरराइटिंग वैकल्पिक बनाकर निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
3. अनुसंधान: यह शोध करने के लिए सभी बाजार प्रतिभागियों के लिए उपयोगी जानकारी प्रकाशित करता है।

3. सुरक्षात्मक कार्य:

सेबी के सुरक्षात्मक कार्य निम्नानुसार हैं:

1. अंदरूनी व्यापार से बचाता है: यह गोपनीय मूल्य संवेदनशील जानकारी का उपयोग करके प्रतिभूतियों के व्यापार के माध्यम से लाभ बनाने के लिए निदेशकों, प्रमोटर इत्यादि जैसे अंदरूनी सूत्रों को प्रतिबंधित करके ऐसा करता है।
2. धोखाधड़ी और अवांछित व्यापार प्रथाओं को रोकता है: यह सुरक्षा बाजार में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है, जैसे मूल्य निर्धारण और बिक्री या भ्रामक बयानों के माध्यम से प्रतिभूतियों की खरीद।
3. उचित व्यवहार को बढ़ावा देता है:यह सिक्योरिटीज बाजार में निष्पक्ष प्रथाओं और आचरण संहिता को बढ़ावा देता है उदा। यह ब्याज दरों आदि के किसी भी मध्य-अवधि संशोधन के संदर्भ में डिबेंचर धारकों के हितों की देखभाल करता है।
4. निवेशकों को शिक्षित करता है: यह निवेशकों के माध्यम से निवेशकों को शिक्षित करता है।

4. शिकायत तंत्र

आम तौर पर, किसी को नियामक के साथ इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, अगर कोई कंपनी या मध्यस्थ की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है जिसके खिलाफ विवाद उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको ब्रोकर जैसे मध्यस्थ के खिलाफ शिकायत है, तो आपको सबसे पहले आपके और ब्रोकर के बीच समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। यदि असंतुष्ट है, तो आप सेबी से संपर्क कर सकते हैं। सेबी पहुंचना काफी आसान है। उपलब्ध फॉर्म एक प्रकार की शिकायत से दूसरे में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, धनवापसी आदेश या आवंटन सलाह से संबंधित शिकायतों का फॉर्म लाभांश की प्राप्ति से संबंधित है। आप सेबी के कार्यालय से फॉर्म एकत्र कर सकते हैं, या सेबी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसे वापस भेज सकते हैं। यदि आप सेबी के फैसले से असंतुष्ट हैं तो आपके पास कानून की अदालत के पास आने का विकल्प भी है। सेबी की वेबसाइट पर, एक विकल्प है जो आपको अपनी शिकायत की स्थिति की जांच करने की अनुमति देता है। हालांकि, ध्यान रखें कि सेबी बाजार को कुशल बनाने के लिए काम नहीं करती है।

5. दंड उपाय

सेबी निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठा सकती है, और प्रतिभूति बाजार भी विकसित कर सकती है। लंबित जांच के मामले में या पूर्ण जांच के संबंध में इन कार्यों को या तो लागू किया जा सकता है। एक आम जुर्माना उपाय उन एक्सचेंजों पर स्टॉक के व्यापार को निलंबित करना है जिसमें यह सूचीबद्ध है। अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो सेबी व्यक्ति को बाजार में बाजार या व्यापार तक पहुंचने से रोक सकती है। यह मध्यस्थ या एक नियामक के अधिकारी को अपनी स्थिति से भी निलंबित कर सकता है। किसी भी कानून का उल्लंघन होने पर सेबी को मध्यस्थ या किसी व्यक्ति के बैंक खाते को संलग्न या प्रतिबंधित करने का भी अधिकार है। यदि कोई

लेनदेन जांच में है, तो सेबी उस व्यक्ति या इकाई से पूछ सकती है कि वह जांच में आने वाली संपत्ति का निपटान न करे।

6. सिक्योरिटीज जारी करने के लिए सेबी दिशानिर्देश:

सेबी ने जनता को प्रतिभूतियों के मुद्दे के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देश पहली बार 11 जून 199 2 को जारी किए गए थे और समय-समय पर संशोधित किए गए थे। सेबी ने 19 -1-2000 के अपने परिपत्र सं। 1 के माध्यम से सेबी (प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण) दिशानिर्देश, 2000 के रूप में समेकित दिशानिर्देश जारी किए।

ये दिशानिर्देश सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों द्वारा सभी सार्वजनिक मुद्दों पर लागू थे, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा बिक्री और अधिकार मुद्दों के लिए सभी ऑफ़र, जिनकी इक्विटी शेयर पूंजी सूचीबद्ध है, अधिकार मुद्दों के मामले में छोड़कर जहां प्रतिभूतियों की कुल कीमत 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। व्यापक रूप से, जनता को प्रतिभूति जारी करने के तीन तरीके हैं:

A. बैंकरों के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने का पारंपरिक तरीका,
B. बुक बिल्डिंग, और
C. स्टॉक एक्सचेंज (ई-आईपीओ) की लाइन सिस्टम पर।

7. सेबी द्वारा उठाए गए अन्य उपाय:

भारत के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, उपरोक्त दिशानिर्देशों के अलावा 'प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण' के अलावा, ने पूंजी बाजार के स्वस्थ विकास और विनियमन के लिए कई अन्य उपाय किए हैं।

1. मर्चेंट बैंकरों के लिए दिशानिर्देश।
2. यूरो मुद्दों के लिए दिशानिर्देश।
3. म्यूचुअल फंड और संपत्ति प्रबंधन कंपनियों के लिए दिशानिर्देश।
4. विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए दिशानिर्देश।
5. प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण के लिए विकास वित्तीय संस्थानों के दिशानिर्देश।
6. बुक बिल्डिंग, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओएस) और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के लिए दिशानिर्देश।
7. अधिमान्य मुद्दों के लिए दिशानिर्देश।
8. ओटीसीईआई मुद्दों के लिए दिशानिर्देश।
9. बाहरी वाणिज्यिक उधार पर दिशानिर्देश।

एक्स। स्टॉक ब्रोकर्स और उप-दलालों, अंडरराइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, किसी समस्या और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार, अंदरूनी व्यापार, किसी मुद्दे, जमाकर्ताओं और प्रतिभागियों के लिए बैंकर, उद्यम पूंजीफंड इत्यादि के लिए नियामक उपायों।

8. सेबी की सीमाएं:

हालांकि सेबी ने निवेशकों के हितों की रक्षा करने, स्टॉक एक्सचेंजों के काम को विनियमित करने और पूंजी बाजार को बढ़ावा देने के लिए एक निगरानी के रूप में शुरू किया है, फिर भी इसे अपने कामकाज में कई समस्याएं आ रही हैं। इनमें से कुछ सीमाएं निम्नानुसार हैं:

1. केंद्र सरकार ने पूंजी बाजारों की सक्रिय निगरानी के लिए सेबी को अपने नियमों और विनियमों को तैयार करने के लिए अधिकृत किया है। इन नियमों और विनियमों को पहले सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा। इससे वित्त मंत्रालय द्वारा अनावश्यक देरी और हस्तक्षेप होगा।
2. सेबी को नियमों के उल्लंघन के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज कराने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यह फिर से सरकारी स्तर पर देरी का कारण बन जाएगा।
3. सेबी को स्वायत्तता नहीं दी गई है। इसके निदेशक मंडल का सरकारी नामांकित व्यक्तियों का प्रभुत्व है। बोर्ड के अध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है और उसे तीन महीने के नोटिस के साथ बर्खास्त किया जा सकता है। इन नियुक्तियों को लंबे समय तक सेबी के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए एक निश्चित कार्यकाल के लिए होना चाहिए।

क्रेडिट रेटिंग:

अवधारणा, प्रकार और कार्य

कई बार, ऐसा हुआ है कि डिबेंचरों या सावधि जमा में निवेशकों को कंपनियों की गुलाबी तस्वीरों को दिखाया गया था और फर्जी कंपनियों द्वारा हितों की बहुत अधिक दरों की पेशकश की गई थी और अंत में निवेशक को न तो अपना पैसा वापस मिला और न ही वादा किया गया ब्याज। दरअसल, एक व्यक्तिगत निवेशक के लिए कंपनी की क्रेडिट योग्यता के बारे में विवरण इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है, न ही उसके पास जोखिम मूल्यांकन करने के लिए समय और न ही कौशल है।

प्रत्येक निवेशक अपने निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विभिन्न प्रकार के उपकरणों को जारी करने वाली कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच करती हैं और उनमें निवेश करने में शामिल जोखिमों का आकलन करती हैं। क्रेडिट रेटिंग की प्रणाली में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी विशेष कंपनी के उपकरणों में निवेश में शामिल जोखिमों को रेट करती है, वे इसे बहुत सुरक्षित से बहुत जोखिम भरा कर सकते हैं। वर्तमान में क्रेडिट रेटिंग केवल ऋण-उपकरणों के लिए की जाती है और शायद ही कभी वरीयता या इक्विटी शेयरों के लिए होती है।

परिभाषा

क्रेडिट रेटिंग सिस्टम को सॉल्वैसी का आकलन करके उधारकर्ता की क्षमता, ऋण चुकाने की क्षमता, और पूर्व निर्धारित प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करके क्रेडिट उपकरणों को मूल्य आवंटित करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

क्रेडिट रेटिंग सामान्य शर्तों में या किसी विशेष ऋण या वित्तीय दायित्व के संबंध में उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता का आकलन है। एक क्रेडिट रेटिंग किसी भी इकाई को सौंपा जा सकता है जो धन उधार लेना चाहता है - एक व्यक्ति, निगम, राज्य या प्रांतीय प्राधिकरण, या संप्रभु सरकार।

क्रेडिट रेटिंग की विशेषताएं

1. चुकाने के लिए जारीकर्ता की क्षमता का आकलन। यह अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए जारीकर्ता की क्षमता का आकलन करता है, यानी ब्याज का भुगतान करने की अपनी क्षमता और उधार ली गई मूल राशि चुकाने की क्षमता।

2. डेटा के आधार पर। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वित्तीय डेटा पर उधारकर्ता की वित्तीय ताकत का आकलन करती है।

3. प्रतीकों में व्यक्त किया। रेटिंग प्रतीकों में व्यक्त की जाती है उदा। एएए, बीबीबी जिसे एक आम आदमी द्वारा भी समझा जा सकता है।

4. विशेषज्ञ द्वारा किया गया। क्रेडिट रेटिंग प्रतिष्ठित, मान्यता प्राप्त संस्थानों के विशेषज्ञ द्वारा की जाती है।

5. निवेश के बारे में मार्गदर्शन-सिफारिश नहीं। क्रेडिट रेटिंग केवल निवेशकों के लिए एक मार्गदर्शन है और किसी विशेष उपकरण में निवेश करने की सिफारिश नहीं है।

समग्र क्रेडिट रेटिंग

निम्नलिखित मामलों में क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना अनिवार्य है

1. ऋण प्रतिभूतियों के लिए- भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी ने सभी गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य कर दी है जहां परिपक्वता 18 महीने से अधिक हो

2. सार्वजनिक जमा- कंपनियों में जमा की रेटिंग भी अनिवार्य कर दी गई है।

3. वाणिज्यिक कागजात (सीपी) के लिए- वाणिज्यिक कागजात के लिए क्रेडिट रेटिंग भी अनिवार्य कर दी गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार सीआरआईएसआईएल द्वारा पी 2 की दिशा-निर्देश या आईसीआरए द्वारा पी 2 या केआरई द्वारा पीपी 2 वाणिज्यिक कागजात के लिए आवश्यक है।

4. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) के साथ सावधि जमा के लिए-कंपनी अधिनियम के तहत, एनबीएफ के साथ सावधि जमा के लिए क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य कर दी गई है।

क्रेडिट रेटिंग में विचार किए गए फैक्टर

1. जारीकर्ताओं को अपने ऋण की सेवा करने की क्षमता- इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की गणना के लिए

1. जारीकर्ता कंपनी के अतीत और भविष्य में नकदी प्रवाह।
2. आकलन करें कि उधारित धन पर ब्याज के रूप में कंपनी को कितना पैसा देना होगा और इसकी कमाई कितनी होगी।
3. बकाया ऋण कितने हैं?
4. वर्तमान अनुपात की गणना के माध्यम से कंपनी की अल्पकालिक साल्वेंसी।
5. कंपनी द्वारा संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में वचनबद्ध संपत्तियों का मूल्य।
6. कच्चे माल की उपलब्धता और गुणवत्ता, अनुकूल स्थान, लागत का लाभ।

7. कर्मचारियों के प्रमोटरों, निदेशकों और विशेषज्ञता का रिकॉर्ड ट्रैक करें।

2. कंपनी के बाजार पॉजिटन-कंपनी के विभिन्न उत्पादों का बाजार हिस्सा क्या है, चाहे वह स्थिर रहेगा, क्या कंपनी वितरण नेट-वर्क, ग्राहक आधार अनुसंधान और विकास सुविधाओं आदि के कारण प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करती है।

3. प्रबंधन की गुणवत्ता- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वरिष्ठ प्रबंधन के ट्रैक रिकॉर्ड, रणनीतियों, योग्यता और दर्शन को भी ध्यान में रखेगी।

4. उपकरण की कानूनी स्थिति- इसका मतलब है कि जारी किया गया उपकरण कानूनी रूप से वैध है, मुद्दे और रिडेम्प्शन के नियम और शर्तें क्या हैं; धोखाधड़ी से उपकरण कितना सुरक्षित है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड आदि की शर्तें क्या हैं।

5. उद्योग के जोखिम- उस उद्योग के उत्पादों (जैसे कार या इलेक्ट्रॉनिक्स) के लिए मांग और आपूर्ति की स्थिति के संबंध में उद्योग जोखिम का अध्ययन किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कितनी है, उस उद्योग की भविष्य की संभावनाएं क्या हैं, क्या यह मरने या विस्तार करने जा रही है?

6. नियामक पर्यावरण- चाहे वह उद्योग सरकार (शराब उद्योग की तरह) द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो, चाहे उस पर मूल्य नियंत्रण हो, चाहे उसके लिए सरकारी सहायता हो, क्या यह कर छूट आदि का लाभ उठा सकता है।

7. अन्य कारक- उपर्युक्त के अलावा, किसी अन्य कंपनी के क्रेडिट रेटिंग के लिए अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए इसकी लागत संरचना, बीमा कवर, लेखा गुणवत्ता, बाजार प्रतिष्ठा, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, मानव संसाधन गुणवत्ता, वित्त पोषण नीति, लाभ, लचीलापन, विनिमय दर जोखिम इत्यादि

क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया

भारत में उधारकर्ताओं या जारीकर्ता कंपनियों के अनुरोध पर क्रेडिट रेटिंग अधिकतर होती है। उधारकर्ता या जारीकर्ता कंपनी प्रस्तावित उपकरण को रैंकिंग आवंटित करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अनुरोध करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बाद की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

1. समझौता- रेटिंग एजेंसी और जारीकर्ता कंपनी के बीच एक समझौता दर्ज किया गया है। इसमें रेटिंग करने के लिए नियम और शर्तों के बारे में विवरण शामिल हैं।

2. विश्लेषणात्मक टीम की नियुक्ति-रेटिंग एजेंसी विशेषज्ञों की एक टीम को नौकरी सौंपती है। टीम में आम तौर पर दो विश्लेषकों का समावेश होता है जिनके पास प्रासंगिक व्यावसायिक क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान है और रेटिंग करने के लिए जिम्मेदार है।

3. जानकारी प्राप्त करना- विश्लेषणात्मक टीम क्लाइंट कंपनी से आवश्यक जानकारी प्राप्त करती है और कंपनी की वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह, प्रकृति और प्रतिस्पर्धा के आधार, बाजार हिस्सेदारी, परिचालन दक्षता व्यवस्था, प्रबंधन ट्रैक लागत संरचना, बिक्री और वितरण रिकॉर्ड, बिजली (बिजली) और श्रम की स्थिति का अध्ययन करती है। आदि।

4. अधिकारियों से मुलाकात- स्पष्टीकरण प्राप्त करने और ग्राहक के व्यवसाय को समझने के लिए विश्लेषणात्मक टीम क्लाइंट के अधिकारियों के साथ मिलती है और बातचीत करती है।

5. निष्कर्षों के बारे में चर्चा- तथ्यों के अध्ययन और विश्लेषणात्मक टीम द्वारा उनके विश्लेषण के पूरा होने के बाद मामला आंतरिक समिति (जिसमें वरिष्ठ विश्लेषकों के शामिल हैं) से पहले रखा जाता है, रेटिंग के बारे में एक राय ली जाती है।

6. रेटिंग समिति की बैठक- आंतरिक समिति के निष्कर्षों को "रेटिंग कमेटी" कहा जाता है, जिसमें आम तौर पर कुछ निदेशकों का समावेश होता है और रेटिंग देने के लिए अंतिम अधिकार होता है।

7. निर्णय का संचार- रेटिंग समिति द्वारा निर्धारित रेटिंग अनुरोध कंपनी को सूचित की जाती है।

8. जनता के लिए सूचना- रेटिंग कंपनी रिपोर्ट और प्रेस के माध्यम से रेटिंग प्रकाशित करती है।

9. रेटिंग का संशोधन- एक बार जारीकर्ता कंपनी ने रेटिंग स्वीकार कर ली है, रेटिंग एजेंसी असाइन की गई रेटिंग की निगरानी करने के लिए दायित्व में है। रेटिंग एजेंसी उपकरण के जीवन के दौरान सभी रेटिंग पर नज़र रखती है।

क्रेडिट रेटिंग के प्रकार

1. बांड और डिबेंचरों की रेटिंग-बांड और डिबेंचरों के लिए कुछ मामलों में रेटिंग लोकप्रिय है। व्यावहारिक रूप से, सभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां डिबेंचर और बॉन्ड के लिए रेटिंग कर रही हैं।

2. इक्विटी शेयरों की रेटिंग- भारत में इक्विटी शेयरों की रेटिंग अनिवार्य नहीं है लेकिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने इक्विटी रेटिंग के लिए एक प्रणाली तैयार की है। यहां तक कि सेबी के प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) की अनिवार्य क्रेडिट रेटिंग के लिए तत्काल योजनाएं नहीं हैं।

3. वरीयता शेयरों की रेटिंग-भारत में वरीयता शेयरों को रेट नहीं किया जा रहा है, हालांकि 19 73 से मूडी की निवेशक सेवा रेटिंग वरीयता शेयर रही है और आईसीआरए के पास इसके प्रावधान हैं।

4. मध्यम अवधि के ऋण की रेटिंग (सार्वजनिक जमा, सीडी इत्यादि)-कंपनियों द्वारा ली गई सावधि जमा भारत में नियमित पैमाने पर मूल्यांकन की जाती है।

5. अल्पकालिक उपकरणों की रेटिंग [वाणिज्यिक पत्र (सीपी)-वाणिज्यिक कागजात जैसे अल्पकालिक उपकरणों की क्रेडिट रेटिंग 199 0 से शुरू की गई है। सीपीआईएस के लिए क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य है जो क्रिसिल, आईसीआरए और केयर द्वारा की जा रही है।

6. उधारकर्ताओं की रेटिंग- उधारकर्ताओं की रेटिंग, एक व्यक्ति हो सकती है या कंपनी को उधारकर्ता की रेटिंग के रूप में जाना जाता है।

7. अचल संपत्ति बिल्डरों और डेवलपर्स की रेटिंग- बड़े शहरों में बहुत सारे निजी उपनिवेशवादियों और फ्लैट बिल्डर्स काम कर रहे हैं। उनके बारे में रेटिंग यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वे एक कॉलोनी विकसित करेंगे या फ्लैट बनाएंगे। क्रिसिल ने बिल्डरों और डेवलपर्स की रेटिंग शुरू कर दी है।

8. चिट फंड की रेटिंग-चिट फंड बचतकर्ताओं से मासिक योगदान एकत्र करते हैं और उन प्रतिभागियों को ऋण देते हैं जो उच्चतम ब्याज दर देते हैं। चिट फंड को ग्राहकों को पुरस्कार राशि का समय पर भुगतान करने की उनकी क्षमता के आधार पर रेट किया जाता है। क्रिसिल चिट फंड की क्रेडिट रेटिंग करता है।

9. बीमा कंपनियों की रेटिंग- निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के प्रवेश के साथ, बीमा कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग भी जमीन हासिल कर रही है। बीमा कंपनियों को उनके दावे की भुगतान क्षमता के आधार पर रेट किया जाता है (चाहे वह उच्च, पर्याप्त, मध्यम या कमजोर दावा-भुगतान क्षमता हो)। आईसीआरए रेटिंग बीमा कंपनियों का काम कर रहा है।

10. सामूहिक निवेश योजनाओं की रेटिंग- जब बड़ी संख्या में निवेशकों के धन सामूहिक रूप से योजनाओं में निवेश किए जाते हैं, इन्हें सामूहिक निवेश योजना कहा जाता है। उनके बारे में क्रेडिट रेटिंग का मतलब है (आकलन) कि योजना सफल होगी या नहीं। आईसीआरए ऐसी योजनाओं की क्रेडिट रेटिंग कर रहा है।

11. बैंकों की रेटिंग- निजी और सहकारी बैंक भारत में नियमित रूप से असफल रहे हैं। लोग बैंकों में पैसा जमा करना पसंद करते हैं जो वित्तीय रूप से ध्वनि और जमा को वापस चुकाने में सक्षम हैं। क्रिसिल और आईसीआरए अब बैंकों की रेटिंग कर रहे हैं।

12. राज्यों की रेटिंग- भारत में राज्यों को अब भी मूल्यांकन किया जा रहा है कि वे निवेश के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले राज्य निवेशकों को देश के भीतर और विदेशों से आकर्षित करने में सक्षम हैं।

13. देशों की रेटिंग- विदेशी निवेशक और उधारकर्ता देश द्वारा चुकाए गए ऋण चुकाने के लिए पुनर्भुगतान क्षमता और इच्छा को जानने में रुचि रखते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उस देश में निवेश लाभदायक है या नहीं। एक देश को रेटिंग करते समय कारकों का मानना है कि इसका औद्योगिक और कृषि उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद, सरकारी नीतियां, मुद्रास्फीति की दर, घाटे के वित्तपोषण की सीमा आदि मूडी और मॉर्गन स्टेनली देशों की रेटिंग कर रहे हैं।

क्रेडिट रेटिंग का कार्य / महत्व

1. यह निवेशकों को निष्पक्ष राय प्रदान करता है। अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की राय निष्पक्ष है क्योंकि इसकी रेटेड कंपनी में कोई निहित रुचि नहीं है।
2. गुणवत्ता और भरोसेमंद जानकारी प्रदान करता है । क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जोखिम का आकलन करने के लिए अत्यधिक योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों को रोजगार देती हैं और उनके पास महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच होती है और इसलिए उधारकर्ता कंपनी की क्रेडिट योग्यता के बारे में सटीक जानकारी प्रदान कर सकती है।
3. भाषा को समझने में आसान जानकारी प्रदान करता है । क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जानकारी इकट्ठा करती हैं, विश्लेषण करती हैं और इसकी व्याख्या करती हैं और एएए, बीबी, सी जैसे प्रतीकों में भाषा में समझने के लिए आसानी से अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करती हैं और तकनीकी भाषा में नहीं या लंबी रिपोर्ट के रूप में होती हैं।
4. जानकारी मुफ्त या नाममात्र लागत पर प्रदान करता है । वित्तीय समाचार पत्रों और रेटेड कंपनियों के विज्ञापनों में उपकरणों की क्रेडिट रेटिंग प्रकाशित की जाती है। जनता को उनके लिए भुगतान नहीं करना

है। अन्यथा, कोई भी उन्हें मामूली शुल्क के भुगतान पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्राप्त कर सकता है। यह व्यक्तिगत निवेशकों की अपनी लागत पर ऐसी जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता से परे है।

5. निवेशकों को निवेश के निर्णय लेने में मदद करता है। क्रेडिट रेटिंग निवेशकों को जोखिमों का आकलन करने और निवेश के निर्णय लेने में मदद करती है।
6. कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं का अनुशासन प्रदान करता है । जब एक उधारकर्ता को उच्च क्रेडिट रेटिंग मिलती है, तो इससे इसकी सद्भावना बढ़ जाती है और अन्य कंपनियां भी रेटिंग में पीछे हटना नहीं चाहती हैं और अपने काम में वित्तीय अनुशासन पैदा करती हैं और अच्छी रेटिंग के योग्य बनने के लिए नैतिक अभ्यास का पालन करती हैं, यह प्रवृत्ति कंपनियों के बीच स्वस्थ अनुशासन को बढ़ावा देती है।
7. निवेश पर सार्वजनिक नीति का गठन करता है । जब ऋण उपकरण एजेंसियों द्वारा ऋण उपकरणों को रेट किया गया है, तो नियामक प्राधिकरणों (सेबी, आरबीआई) द्वारा प्रतिभूतियों की पात्रता के बारे में नीतियां निर्धारित की जा सकती हैं जिनमें म्यूचुअल फंड, भविष्य निधि ट्रस्ट इत्यादि जैसे विभिन्न संस्थानों द्वारा फंड का निवेश किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यह निर्धारित किया जा सकता है कि एक म्यूचुअल फंड किसी कंपनी के डिबेंचरों में निवेश नहीं कर सकता है जब तक कि उसे एएए की रेटिंग नहीं मिल जाती।

क्रेडिट रेटिंग के लाभ

क्रेडिट रेटिंग कई फायदे प्रदान करती है जिन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है

- निवेशकों के लिए लाभ।
- रेटेड कंपनी के लिए लाभ।
- मध्यस्थों के लिए लाभ।
- व्यापार दुनिया के लिए लाभ।

निवेशकों के लिए लाभ

1. जोखिम का आकलन- क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से निवेशक निवेश में शामिल जोखिम का आकलन कर सकता है। एक छोटे से व्यक्तिगत निवेशक के पास विस्तृत जोखिम मूल्यांकन करने के लिए कौशल, समय और संसाधन नहीं होते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जिनके पास इन मामलों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ ज्ञान, कौशल और जनशक्ति है, उनके लिए यह काम कर सकते हैं। इसके अलावा, एएए, बीबी इत्यादि जैसे प्रतीकों में व्यक्त की गई रेटिंग निवेशकों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।

2. कम लागत पर जानकारी- क्रेडिट समाचार वित्तीय समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं और रेटिंग एजेंसियों से नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध होते हैं। इस तरह निवेशकों को उधारकर्ताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है या कम लागत पर।

3. निरंतर निगरानी का लाभ- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आमतौर पर केवल एक बार प्रतिभूतियों की रेटिंग नहीं लेती हैं। वे लगातार निगरानी करते हैं और बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर रेटिंग को अपग्रेड और डाउनग्रेड करते हैं।

4. निवेशकों को निवेश का विकल्प प्रदान करता है-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां निवेशकों को विभिन्न कंपनियों की क्रेडिट योग्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करती हैं। इसलिए, निवेशकों के पास एक कंपनी या दूसरे में निवेश करने का विकल्प होता है।

5. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग भरोसेमंद है- एक रेटिंग एजेंसी को किसी सुरक्षा में कोई निहित रुचि नहीं है और जारीकर्ता कंपनी के प्रबंधन के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है। इसलिए उनके द्वारा रेटिंग निष्पक्ष और विश्वसनीय हैं।

रेटेड कंपनी के लिए लाभ

1. उधार में आसानी- अगर किसी कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों के लिए उच्च क्रेडिट रेटिंग मिलती है, तो यह पूंजी बाजार में अधिक आसानी से धन जुटाने में सक्षम हो सकती है।

2. सस्ती दरों पर उधार लेना- एक अनुकूल रेटिंग कंपनी निवेशकों के आत्मविश्वास का आनंद लेती है और इसलिए, ब्याज की कम दर पर उधार ले सकती है।

3. विकास की सुविधा प्रदान करता है- अनुकूल रेटिंग द्वारा प्रोत्साहित, प्रवर्तकों को विस्तार, विविधीकरण और विकास की योजनाओं के लिए प्रेरित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा, अत्यधिक रेटेड कंपनियों को भविष्य में स्वामित्व या क्रेडिट प्रतिभूतियों के मुद्दे के माध्यम से जनता से धन जुटाना आसान लगता है। उन्हें बैंकों से उधार लेना आसान लगता है।

4. कम ज्ञात कंपनियों की पहचान- कम ज्ञात या अज्ञात कंपनियों के उपकरणों की अनुकूल क्रेडिट रेटिंग उन्हें निवेश करने वाले लोगों की आंखों में विश्वसनीयता और मान्यता प्रदान करती है।

5. रेटेड कंपनी की सद्भावना में जोड़ता है- यदि रेटिंग एजेंसियों द्वारा किसी कंपनी को उच्च श्रेणी निर्धारण किया जाता है तो यह बाजार में अपनी सद्भावना को स्वचालित रूप से बढ़ा देगा।

6. उधारकर्ताओं पर वित्तीय अनुशासन का अनुमान लगाता है- उधार लेने वाली कंपनियों को पता है कि उन्हें केवल उच्च क्रेडिट रेटिंग मिलेगी जब वे अपने वित्त को एक अनुशासित तरीके से प्रबंधित करते हैं, यानी वे अच्छी परिचालन दक्षता, उचित तरलता, अच्छी गुणवत्ता वाली संपत्ति आदि बनाए रखते हैं। इससे उधार लेने की इच्छा रखने वाली कंपनियों के बीच वित्तीय अनुशासन की भावना विकसित होती है।

7. महत्तर सूचना प्रकटीकरण- एक मान्यता प्राप्त एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए, कंपनियों को उनके संचालन के बारे में बहुत सारी जानकारी का खुलासा करना होगा। यह अधिक जानकारी प्रकटीकरण, बेहतर लेखा मानक और बेहतर वित्तीय जानकारी को प्रोत्साहित करता है जो बदले में निवेशकों की सुरक्षा में मदद करता है।

मध्यवर्ती संस्थाएँ के लिए लाभ

व्यापारी बैंकरों और दलालों की नौकरी आसान बना दी। क्रेडिट रेटिंग की अनुपस्थिति में, व्यापारी बैंकरों या दलालों को उधारकर्ता कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में निवेशकों को मनाने की ज़रूरत है। यदि एक उधारकर्ता कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एक प्रतिष्ठित क्रेडिट एजेंसी द्वारा की जाती है, तो व्यापारी बैंकरों और दलालों का कार्य बहुत आसान हो जाता है।

व्यापार दुनिया के लिए लाभ

1. निवेशक आबादी में वृद्धि- अगर निवेशकों को क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से ऋण उपकरणों में पैसा निवेश करने के बारे में अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, तो अधिक से अधिक लोगों को कॉर्पोरेट ऋण में अपनी बचत का निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

2. विदेशी निवेशकों के लिए मार्गदर्शन- विदेशी सहयोगी या विदेशी वित्तीय संस्थान उन कंपनियों में निवेश करेंगे जिनकी क्रेडिट रेटिंग अधिक है। क्रेडिट रेटिंग उन्हें तुरंत कंपनी की स्थिति की पहचान करने में सक्षम बनाती है।

बिल छूट

BILL DISCOUNTING

सामान्य व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के दौरान उपयोग किए जाने वाले एक्सचेंज के बिल वाणिज्यिक बिल कहा जाता है। बिल वित्तपोषण, व्यापार चिंताओं के लिए उपलब्ध अल्पकालिक वित्त पोषण का एक आदर्श माध्यम है। यह बैंकिंग प्रणाली के भीतर तरलता प्रदान करने के अलावा, मुद्रा बाजार में लचीलापन प्रदान करता है। यह देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता की दिशा में भी योगदान देता है।

इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अनुसार, -बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनौपचारिक आदेश है जिसमें मार्कर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति को केवल कुछ निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है, या निश्चित रूप से व्यक्ति, या उस उपकरण के वाहक के लिए।

एक्सचेंज का बिल अनिवार्य रूप से एक व्यापार से संबंधित साधन है, और इसका उपयोग वास्तविक लेनदेन को वित्त पोषण के लिए किया जाता है। बिल वित्तपोषण, व्यापार चिंताओं के लिए उपलब्ध अल्पकालिक वित्त पोषण का एक आदर्श माध्यम है। यह बैंकिंग प्रणाली के भीतर तरलता प्रदान करने के अलावा, मुद्रा बाजार में लचीलापन प्रदान करता है। यह देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता की दिशा में भी योगदान देता है।

जब विक्रेता (आहर्ता) वास्तविक वाणिज्यिक बिल जमा करता है और बिल को छूट देने के बजाय बैंक या वित्तीय संस्थान से वित्तीय आवास प्राप्त करता है तो वह परिपक्वता की तारीख तक प्रतीक्षा कर सकता है।

जब विक्रेता (आहर्ता) वास्तविक वाणिज्यिक बिल जमा करता है और बैंक या वित्तीय संस्थान से वित्तीय आवास प्राप्त करता है, तो इसे 'बिल छूट' के रूप में जाना जाता है। विक्रेता, बिल को छूट देने के बजाय तुरंत परिपक्वता की तारीख तक प्रतीक्षा कर सकता है। वाणिज्यिक, छूट का विकल्प फायदेमंद होगा क्योंकि विक्रेता तैयार नकदी प्राप्त करता है, जिसका उपयोग तत्काल व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, इस प्रक्रिया में, विक्रेता डिस्काउंटिंग बैंकर द्वारा लगाए गए छूट के जरिए थोड़ा सा खो सकता है।

बिल छूट वित्तपोषण की मुख्य विशेषताएं:

1. छूट शुल्क: बैंक द्वारा दिए गए अग्रिम और बिल के फेस वैल्यू के बीच मार्जिन को छूट कहा जाता है, और परिपक्वता मूल्य पर प्रति वर्ष एक निश्चित प्रतिशत दर पर गणना की जाती है।

2. परिपक्वता: बिल की परिपक्वता तिथि उस तारीख के रूप में परिभाषित की जाती है जिस पर भुगतान देय होगा। सामान्य परिपक्वता अवधि 30, 60, 90 या 120 दिन होती है। हालांकि, 90 दिनों के भीतर परिपक्व बिल सबसे लोकप्रिय हैं।

3. तैयार वित्त: बैंक अपने ग्राहकों के बिलों को छूटते हैं और खरीदते हैं ताकि ग्राहकों को बैंक से तत्काल वित्त मिल सके। जब तक बैंक बिल का भुगतान नहीं करता तब तक उन्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है।

4. छूट और खरीद: बिलों की छूट का शब्द मांग बिलों के लिए उपयोग किया जाता है, जहां बिलों की खरीद शब्द का उपयोग बिलों के लिए किया जाता है। दोनों मामलों में, बैंक तुरंत बिल के राशि के साथ ग्राहक के खाते को क्रेडिट करता है, इसके शुल्कों को कम करता है। बिल खरीदने के मामले में शुल्क कम है क्योंकि बैंक भुगतान के लिए आहार्यीको तुरंत पेश करके भुगतान जमा कर सकता है। हालांकि, बिलों की छूट के मामले में शुल्क अधिक है क्योंकि बैंक के शुल्कों में न केवल सेवा के लिए शुल्क शामिल है, बल्कि बिल की छूट के दिनांक से उसकी परिपक्वता की तारीख तक की अवधि भी शामिल है। इसके अलावा, बिलों का अपमान होने पर शुल्क भी होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, बैंक ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ बिल की राशि के साथ ग्राहक के खाते को डेबिट कर देगा। चूंकि बैंक ग्राहकों को छूट और खरीद दोनों में अग्रिम प्रदान कर रहा है, इसलिए छूट और खरीदे गए बिलों को बैंक द्वारा अपनी बैलेंस शीट में अग्रिम के रूप में दिखाया जाता है।

वाणिज्यिक बिलों की छूट और खरीददारी में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

1. विधेयक की परीक्षा: बैंकर बिल और लेनदेन की प्रकृति की पुष्टि करता है। बैंकर तब सुनिश्चित करता है कि ग्राहक ने बिल के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।

2. बिल की वास्तविकता की जांच करने के बाद ग्राहक खाते को श्रेय देना, बैंकर अनुदान देता है। क्रेडिट सीमा, या तो नियमित रूप से या बिल की विज्ञापन राशि की बिल राशि यानी बिल ऋण छूट शुल्क के मूल्य पर। छूट की राशि बैंक द्वारा अर्जित आय / छूट पर अर्जित आय है। बिल की राशि बैंक द्वारा अग्रिम के रूप में ली जाती है।

3. खातों पर नियंत्रण: यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी ग्राहक स्वीकृत सीमा से अधिक उधार लेता है, प्रत्येक ग्राहक द्वारा प्राप्त राशि का निर्धारण करने के लिए एक अलग रजिस्टर बनाए रखा जाता है। ग्राहकों के नाम, स्वीकृत सीमाएं, बिलों की छूट, एकत्रित बिल, ऋण प्रदान किए गए और ऋण चुकाए जाने के लिए अलग-अलग कॉलम आवंटित किए जाते हैं। इस प्रकार, किसी भी समय दिए गए बिंदु पर ग्राहक द्वारा उपयोग की गई सीमा की सीमा को आसानी से जाना जा सकता है।

4. संग्रह के लिए विधेयक भेजना: बिल, जो बैंकर द्वारा विधिवत मुद्रित दस्तावेजों के साथ है, बिल के लिए बैंक पेश करने के लिए बैंकर की शाखा (या किसी अन्य बैंक शाखा को बैंकर को अपनी शाखा नहीं है) भेजा जाता है स्वीकृति या भुगतान, बिल के साथ निर्देशों के अनुसार।

5. शाखा द्वारा कार्यवाही: भुगतान की प्राप्ति पर, एकत्रित बैंक बैंकर को भुगतान भेजता है जिसने संग्रह के लिए बिल भेजा है।

6. अस्वीकृत: अपमान की स्थिति में, अपमानजनक सलाह बिल के आहर्ता को भेजी जाती है। एकत्रित बैंकर के लिए अपमान के लिए विरोध करना उचित होगा। इस उद्देश्य के लिए, बैंक की एकत्रित बैंकर या शाखा एक अलग

रजिस्टर रखती है जिसमें विवरण, जिस पर बिल प्रस्तुत किए जाने हैं, जिस पार्टी को प्रस्तुत किया जाना है, आदि दर्ज किया गया है। बैंकर उन्हें आवश्यकतानुसार स्वीकृति या भुगतान के लिए प्रस्तुत करता है। बैंकर बिल की राशि और बिल के अपमान के कारण किए गए सभी शुल्कों के साथ ग्राहकों के (आहर्ता / उधारकर्ता) खाते को डेबिट करता है। ऐसा बिल फिर से पेश किए जाने की स्थिति में खरीदा नहीं जाना चाहिए। हालांकि, बैंकर इसे संग्रह के लिए स्वीकार करने के लिए सहमत हो सकता है।

बिल सिस्टम / BILL SYSTEMS

अनिवार्य रूप से बिलों की दो प्रणालि है, जिन्हें समझाया गया है:

1. आहर्ता बिल प्रणाली और
2. आहार्यी बिल सिस्टम हैं,

आहर्ता बिल सिस्टम / Drawer Bills System

1. आहर्ता बिल सिस्टम माल के खरीदार पर माल के विक्रेताओं की विशेषता है

2. बिलों के आहर्ता के उदाहरण पर बिलों को छूट या खरीदा जा रहा है

3. बैंकर मुख्य रूप से बिल के आहर्ता के क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए , जबकि इन बिलों को छूट या खरीदते समय वित्त पोषण वस्तुओं की यह प्रणाली हमारे देश में काफी लोकप्रिय है।

आहार्यी बिल सिस्टम / Drawee Bills System

आहार्यी बिल सिस्टम की विशेषता:

1. विक्रेता द्वारा खरीदे गए बिल को स्वीकार करने वाले बैंकर (आहार्यी)
2. बैंकर मुख्य रूप से खरीदार की क्रेडिट योग्यता की ताकत पर सहायता प्रदान करता है।

आहार्यी बिल सिस्टम के दो प्रकार हैं:

1. स्वीकृति क्रेडिट सिस्टम: इस प्रणाली के तहत, खरीदार बैंकर आहार्यीद्वारा खरीदे गए सामानों के आदान-प्रदान के बिल को स्वीकार करता है। ऐसा बिल खरीदार या बैंकर पर खींचा जा सकता है। बैंकर को उधारकर्ता को अलग-अलग दिखाने की भी आवश्यकता होती है, बैंकर को आवधिक स्टॉक स्टेटमेंट में स्वीकृति क्रेडिट के तहत खरीदे गए सामान।

2. बिल छूट प्रणाली: इस प्रणाली के तहत, विक्रेता सीधे खरीदार के बैंक पर बिल खींचता है और बिल को छूट देता है और आय को विक्रेता को भेजता है। खरीदार का बैंकर बिल छूट के रूप में बिल दिखाएगा। दोनों प्रणालियों के तहत, बैंकर बिलों का रिकॉर्ड रखता है, दोनों स्वीकार किए जाते हैं और अभी भी बकाया हैं। यह सुनिश्चित करना है कि अग्रिम स्वीकृत क्रेडिट सीमा से अधिक न हो।

आहार्यी बिल योजना का मुख्य लाभ

1. आश्वासित भुगतान: चूंकि बैंकर ने बिल स्वीकार कर लिया है, विक्रेता को भुगतान का आश्वासन दिया जाता है। इसके अलावा, अगर विक्रेता इसे छूट प्राप्त करने का फैसला करता है, तो छूट दर कम हो जाएगी क्योंकि आहार्यीबैंकर स्वयं ही है।

2. लाभ ख़रीदना: बैंकर की ज़मानत और खड़े होने के कारण, खरीदार के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर सामान प्राप्त करना संभव है।

3. धन की सुरक्षा: खरीदार बैंक के लिए शायद ही कोई जोखिम है क्योंकि बिल खरीदार द्वारा खरीदे गए सामान की सुरक्षा के खिलाफ स्वीकार या छूट दी जाती है। इसके अलावा, सामान बैंकर के नियंत्रण में हैं। यह विक्रेता के बैंक के लिए समान रूप से फायदेमंद है, क्योंकि छूट वाले बिल को किसी अन्य वित्तीय संस्थान के साथ फिर से विभाजित किया जा सकता है।

उद्यम पूंजी

उद्यम पूंजी "जोखिम पूंजी" का एक रूप है जिसे एक परियोजना या व्यवसाय में निवेश किया जाता है जहां लाभ और नकद प्रवाह के भविष्य के निर्माण से संबंधित जोखिम का पर्याप्त तत्व होता है। जोखिम पूंजी को ऋण के बजाय शेयर (इक्विटी) के रूप में निवेश किया जाता है और निवेशक को अपने जोखिम के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए "वापसी की दर" की आवश्यकता होती है।

उद्यम पूंजी शेयर पूंजी के रूप में कंपनियों के विस्तार के लिए बीज पूंजी या वित्त पोषण प्रदान करती है, ताकि निर्विवाद कंपनियां बढ़ने और सफल होने में मदद मिल सके। यदि कोई उद्यमी स्टार्ट-अप, विस्तार, व्यवसाय में खरीदारी करने की तलाश में है, तो वह व्यवसाय खरीदता है जिसमें वह काम करता है, कंपनी को बदलता है या पुनरुद्धार करता है, उद्यम पूंजी ऐसा करने में मदद कर सकती है। उद्यम पूंजी प्राप्त करना ऋणदाता या ऋणदाता से ऋण उठाने से काफी अलग है। उधारदाताओं के पास व्यापार की सफलता या विफलता के बावजूद, पूंजी के ऋण और पुनर्भुगतान पर ब्याज का कानूनी अधिकार है।

उद्यम पूंजी एंड डेवलपमेंट कैपिटल

उद्यम पूंजी एक नई तकनीक या नए नवाचार का उपयोग कर उद्यमों के लिए उन्नत है। उद्यम पूंजी कंपनी उद्यम में शामिल उच्च जोखिम के कारण परियोजना के समग्र प्रबंधन में रूचि रखती है। इस परियोजना में फंड उपलब्ध कराए जाते हैं, जो व्यावसायिक उत्पादन से उत्पादों के सफल विपणन तक शुरू होते हैं, ताकि लगातार राजस्व कमाई, निवेश के बढ़े मूल्य और निवेश को तरल करने के लिए उचित निकास मार्ग उपलब्ध कराया जा सके।

औद्योगिक पूंजी स्थापित करने के लिए और विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी ऋण पूंजी के रूप में विकास पूंजी दी जाती है। ऋणदाता का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने में ऋणदाता विशेष देखभाल करता है और उसे ब्याज का तत्काल भुगतान और ऋण राशि की चुकौती की आवश्यकता होती है।

उद्यम पूंजी फाइनेंसिंग के प्रकार

तीन मुख्य समूह हैं जिनमें उद्यम पूंजी निवेश को विभाजित किया जा सकता है। वे शुरुआती चरण, विस्तार, और खरीददारी हैं। इन समूहों में से प्रत्येक को अगले पृष्ठ पर चार्ट में दिखाए गए अनुसार उपसमूहों में बांटा गया है:

प्राथमिक अवस्था

प्रारंभिक चरण निवेश तीन उपसमूहों में बांटा गया है: बीज वित्त पोषण, स्टार्टअप वित्तपोषण, और प्रथम चरण वित्त पोषण।

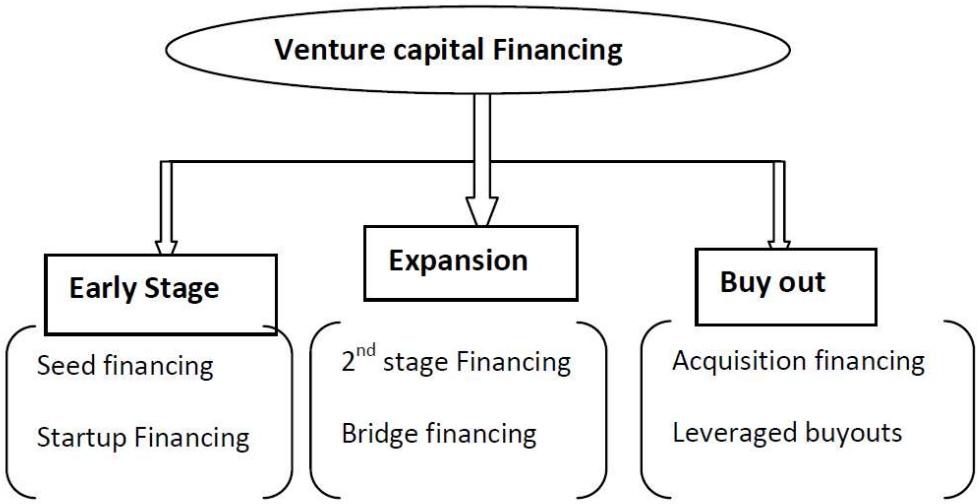

बीज वित्तपोषण

इस प्रकार का वित्तपोषण व्यवसाय के जीवन में बहुत जल्दी होगा, आमतौर पर प्री-राजस्व और कभी-कभी उत्पाद या सेवा के निर्माण से पहले भी। इस तरह वित्त पोषित होने के बाद उद्यमी को ऋण प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा। उद्यमी बाजार अनुसंधान और प्रारंभिक उत्पाद या सेवा विकास के लिए बीज धन का उपयोग करेगा।

उद्यम पूंजी फर्म - फंड स्रोत

उद्यम पूंजीफर्मों द्वारा धन जुटाने के लिए कई स्रोत हैं। अपने धन प्राप्त करने के लिए, उद्यम पूंजी फर्मों को एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड प्रकट करना होगा और निश्चित ब्याज या उद्धृत इक्विटी निवेश के माध्यम से हासिल किए जा सकने वाले रिटर्न के उत्पादन की संभावना है। अधिकांश यूके उद्यम पूंजी फर्म बाहरी स्रोतों, मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों, जैसे पेंशन फंड और बीमा कंपनियों से निवेश के लिए अपने धन जुटाने।

उद्यम पूंजीफर्मों की निवेश प्राथमिकताएं उनके फंड के स्रोत से प्रभावित हो सकती हैं। बाहरी स्रोतों से उठाए गए कई धन सीमित साझेदारी के रूप में संरचित होते हैं और आमतौर पर 10 वर्षों का निश्चित जीवन होता है। इस अवधि के भीतर फंड उनके लिए किए गए पैसे का निवेश करते हैं और 10 वें वर्ष के अंत तक उन्हें निवेशकों के मूल धन, साथ ही कोई अतिरिक्त रिटर्न वापस करना होगा। आम तौर पर फंड के अंत से पहले, निवेश किए जाने वाले निवेशों को उद्धृत शेयरों के रूप में होना चाहिए।

उद्यम पूंजी- निवेश प्रक्रिया

निवेश प्रक्रिया, वास्तव में प्रस्ताव में निवेश करने के लिए व्यापार योजना की समीक्षा करने से, एक उद्यम पूंजीपति को एक महीने से एक वर्ष तक की अवधि ले सकती है लेकिन आम तौर पर इसमें 3 से 6 महीने लगते हैं। नियम के

हमेशा अपवाद होते हैं और सौदों को बेहद कम समय के फ्रेम में किया जा सकता है। प्रदान की गई जानकारी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है और उपलब्ध कराया जाता है।

निवेश प्रक्रिया का मुख्य चरण एक व्यापार योजना का प्रारंभिक मूल्यांकन है। उद्यम पूंजीपतियों के लिए अधिकांश दृष्टिकोण इस चरण में खारिज कर दिए गए हैं। व्यापार योजना पर विचार करते हुए, उद्यम पूंजीपति कई प्रमुख पहलुओं पर विचार करेंगे जैसे कि:

1. क्या उत्पाद या सेवा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य है?
2. क्या कंपनी के निरंतर विकास की संभावना है?
3. क्या प्रबंधन में इस अस्थिरता का फायदा उठाने और विकास चरणों के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित करने की क्षमता है?
4. क्या संभव इनाम जोखिम को औचित्य देता है?
5. क्या निवेश पर संभावित वित्तीय वापसी उनके निवेश मानदंडों को पूरा करती है?

अपने निवेश की संरचना में, उद्यम पूंजीपति निम्न में से एक या अधिक प्रकार की शेयर पूंजी का उपयोग कर सकता है:

साधारण शेयर

ये इक्विटी शेयर हैं जो पूंजी और लेनदारों के सभी अन्य वर्गों के अधिकारों के बाद सभी आय और पूंजी के हकदार हैं। साधारण शेयर धारकों के पास वोटिंग अधिकार हैं। एक उद्यम पूंजीगत सौदे में ये आमतौर पर उद्यम पूंजी फर्म की बजाय प्रबंधन और परिवार के शेयरधारकों द्वारा आयोजित शेयर होते हैं।

अधिमान सामान्य शेयर

ये विशेष अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर हैं। उदाहरण के लिए, वे एक निश्चित लाभांश या मुनाफे के हिस्से के हकदार हो सकते हैं। अधिमान सामान्य शेयरधारकों के पास मतदान अधिकार हैं।

प्रक्रिया के कर्ता - धर्ता

ये गैर-इक्विटी शेयर हैं। वे आय और पूंजी दोनों के लिए सामान्य शेयरों के सभी वर्गों से पहले रैंक करते हैं। उनके आय अधिकारों को परिभाषित किया जाता है और वे आमतौर पर एक निश्चित लाभांश के हकदार होते हैं। शेयर निश्चित तिथियों पर रिडीमबल हो सकते हैं या वे अपरिहार्य हो सकते हैं। कभी-कभी वे निश्चित प्रीमियम पर रिडीमबल हो सकते हैं (उदाहरण के लिए 120% लागत पर)। वे सामान्य शेयरों की कक्षा में परिवर्तनीय हो सकते हैं।

ऋण पूंजी

उद्यम पूंजी ऋण आमतौर पर ब्याज के हकदार होते हैं और आमतौर पर, हालांकि, जरूरी नहीं, पुनर्भुगतान योग्य होते हैं। ऋण कंपनी की संपत्ति पर सुरक्षित हो सकता है या असुरक्षित हो सकता है। एक सुरक्षित ऋण असुरक्षित ऋण और कंपनी के कुछ अन्य लेनदारों से पहले रैंक होगा। एक ऋण इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो सकता है। वैकल्पिक रूप से, इसमें एक वारंट संलग्न हो सकता है जो ऋणधारक को वारंट में निर्धारित शर्तों पर नए इक्विटी

शेयरों के लिए सब्सक्राइब करने का विकल्प देता है। वे आमतौर पर ब्याज के भुगतान और पूंजी के पुनर्भुगतान के लिए बैंक अवधि के ऋण और बैंक के पीछे रैंक की तुलना में ब्याज की उच्च दर लेते हैं।

उद्यम पूंजीगत निवेश अक्सर निवेश के बिंदु पर अतिरिक्त वित्तपोषण के साथ होते हैं। यह लगभग हमेशा ऐसा मामला है जहां निवेश किया जा रहा व्यवसाय अपेक्षाकृत परिपक्व या अच्छी तरह से स्थापित है। इस मामले में, एक व्यापार के लिए एक वित्त पोषण संरचना के लिए उपयुक्त है जिसमें इक्विटी और ऋण दोनों शामिल हैं।

उद्यम पूंजीवादी इक्विटी के अतिरिक्त प्रदान किए गए वित्त के अन्य रूपों में शामिल हैं:

- **समाशोधन बैंक -** वे मुख्य रूप से ब्याज की परिवर्तनीय दरों पर निश्चित रूप से ओवरड्राफ्ट और मध्यम से मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करते हैं।
- **व्यापारी बैंक -** वे आमतौर पर लंबी अवधि के ऋण के प्रावधान को व्यवस्थित करते हैं, आमतौर पर बैंकों को समाशोधन की तुलना में बड़ी मात्रा में। बाद में वे सार्वजनिक मुद्दों के नियमों और मूल्यों पर सलाह देकर और जब आवश्यक हो तो अंडरराइटिंग की व्यवस्था करके "सार्वजनिक जा रहे" की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **वित्त घर -** वे किश्त खरीद से लीजिंग तक लेकर किश्त क्रेडिट के विभिन्न रूप प्रदान करते हैं; अक्सर संपत्ति आधारित और आमतौर पर एक निश्चित अवधि के लिए और निश्चित ब्याज दरों पर।
- **फैक्टरिंग कंपनियां -** वे छूट पर व्यापार ऋण खरीदकर वित्त प्रदान करते हैं, या तो एक सहारा के आधार पर (आप ऋण पर क्रेडिट जोखिम बनाए रखते हैं) या गैर-सहारा के आधार पर (फैक्टरिंग कंपनी क्रेडिट जोखिम लेती है)।
- **सरकारी और यूरोपीय आयोग के स्रोत -** वे चुनिंदा क्षेत्रों में उद्यम ऋण के लिए परियोजना अनुदान (नौकरियों से संबंधित और संरक्षित) से लेकर ब्रिटेन की कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।
- **मेज़ानाइन फर्म -** वे ऋण वित्त प्रदान करते हैं जो इक्विटी और सुरक्षित ऋण के बीच आधा रास्ते है। इन सुविधाओं के लिए कंपनी की संपत्ति पर दूसरे शुल्क की आवश्यकता होती है या असुरक्षित होती है। चूंकि जोखिम वरिष्ठ ऋण से अधिक है, इसलिए मेज़ानाइन ऋण प्रदाता द्वारा लगाए गए ब्याज प्रमुख उधारदाताओं द्वारा उससे अधिक होंगे और कभी-कभी विकल्प या वारंट के माध्यम से मामूली इक्विटी "अप-साइड" की आवश्यकता होगी। यह आमतौर पर बड़े लेनदेन के लिए सबसे उपयुक्त है।

भारत में उद्यम पूंजी

उद्यम पूंजीका जन्म भारत में बहुत देर हो गया था। वर्ष 19 72 में भट्ट समिति (लघु और मध्यम उद्यमियों के विकास पर समिति) ने उद्यम पूंजी के निर्माण की सिफारिश की। समिति ने उद्योगों की स्थापना में नए उद्यमियों और तकनीशियनों की मदद करने के लिए ऐसी पूंजी प्रदान करने की आवश्यकता से आग्रह किया। भारत के कुछ उद्यम पूंजी निधि का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

- **जोखिम पूंजी नींव:** भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) ने वर्ष 19 75 में पहला उद्यम पूंजी निधि लॉन्च किया। फंड, 'जोखिम कैपिटल फाउंडेशन' (आरसीएफ) का उद्देश्य प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमोटरों की इक्विटी को पूरक बनाना है। नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पेशेवर।

- **बीज पूंजी योजना:** इस उद्यम पूंजी निधि को 19 76 में आईडीबीआई द्वारा उसी उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था।
- **उद्यम पूंजी योजनाएं:** उद्यम पूंजी फंडिंग ने 1983 में "प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य" की केंद्र सरकार द्वारा घोषणा के साथ आधिकारिक प्रायोजन प्राप्त किया। यह व्यावसायीकरण और प्रौद्योगिकियों के शोषण के माध्यम से तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है। आईसीआईसीआई, निजी क्षेत्र में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान ने 1986 में निजी क्षेत्र में नए टेक्नोक्रेट को प्रोत्साहित करने के लिए निहित पूंजी योजना की स्थापना की, ताकि उच्च जोखिम वाले उच्च प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में प्रवेश किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य जोखिम वाली आर्थिक गतिविधियों के लिए उद्यम पूंजी के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए धन आवंटित करना है, बल्कि उच्च लाभ क्षमता भी है।
- **PACT:** आईसीआईसीआई ने यूएसडीआईडी द्वारा सहायता प्राप्त वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी (पीएसीटी) के कार्यक्रम के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रारंभिक अनुदान के साथ कार्यक्रम का प्रशासन किया। कार्यक्रम का लक्ष्य उद्यम पूंजी वित्त पोषण के आधार पर कॉर्पोरेट क्षेत्र औद्योगिक इकाइयों की विशिष्ट आवश्यकताओं को वित्त पोषित करना है।

सरकारी निधि:

आईडीबीआई, नोडल एजेंसी के रूप में, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 19 86 को बनाए गए उद्यम पूंजी निधि का प्रबंधन करती है। सरकार ने अनुसंधान और विकास आर एंड डी सेस अधिनियम, 1986 के तहत, विदेश से प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए किए गए सभी भुगतानों पर लेवी, रॉयल्टी भुगतान, विदेशी सहयोग के लिए एकमुश्त भुगतान और डिजाइन और चित्रों के लिए भुगतान।

- **TDICI:** 19 88 में, आईसीआईसीआई प्रायोजित कंपनी, जैसे प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीडीआईसीआई) की स्थापना की गई थी, और 1 जुलाई, 19 88 से आईसीआईसीआई के उद्यम पूंजी संचालन को इसके द्वारा लिया गया था।
- **RCTFC**: आईएफसीआई द्वारा प्रायोजित जोखिम पूंजी फाउंडेशन (आरसीएफ) को वर्ष 19 88 में जोखिम पूंजी और प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड (आरसीटीएफसी) में परिवर्तित कर दिया गया था। इसने अन्य वित्त पोषण प्रौद्योगिकी विकास के प्रबंधन के अलावा आरसीएफ की गतिविधियों को संभाला योजनाएं और उद्यम पूंजी निधि।
- **VECAUS:** VECAUS-I, यूटीआई प्रायोजित "उद्यम पूंजीयूनिट स्कीम" वर्ष 19 8 9 में लॉन्च किया गया था। प्रौद्योगिकी विकास और सूचना कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (टीडीआईसीआई) को इसके प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 199 0 में, निगम को "वेकस-द्वितीय" नामक एक और यूटीआई प्रायोजित उद्यम निधि के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सौंपा गया था। 199 1 में, यूटीआई ने वीईसीएयूएस -III लॉन्च किया और आरसीटीसी को फंड मैनेजर नियुक्त किया गया।
- अन्य धन: 19 88 में सरकार द्वारा उदारीकृत उदारीकृत दिशानिर्देशों ने विशेष रूप से निजी क्षेत्र में कई उद्यम पूंजीगत धन की स्थापना को जन्म दिया।

उद्यम पट्टा उधार

एक पट्टे की व्यवस्था जिसमें 'कमदाता' दोनों संपत्तियों और इक्विटी पूंजी को पट्टेदार को प्रदान करता है उसे उद्यम पट्टे कहा जाता है

लाभ

- स्टार्टअप द्वारा शुरुआती निवेश को कम करता है
- किराया नकद प्रवाह प्रोफ़ाइल के अनुरूप बनाया जा सकता है
- इक्विटी भागीदारी पट्टा किराया कम कर सकते हैं
- संपत्ति जोखिम कम करने के लिए स्थानांतरित कर दिया

नुकसान

- इक्विटी हिस्सेदारी को कम करना मुश्किल हो सकता है
- अवमूल्यन कर ढाल कम करने के लिए स्थानांतरित कर दिया
- परिसंपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च एजेंसी लागत
- पट्टेदार के लिए कम ऋण क्षमता।

सारांश

व्यापारी बैंकिंग एक प्रकार की वित्तीय सेवा है जिसमें मुद्दों के प्रबंधन और अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। व्यापारी बैंकर कॉर्पोरेट संस्थाओं को व्यापारी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में लगे संस्थान हैं। व्यापारी बैंकरों द्वारा प्रदान की जाने वाली कई प्रकार की सेवाएं हैं। इनमें परियोजना परामर्श, क्रेडिट सिंडिकेशन, कॉर्पोरेट परामर्श, पोर्टफोलियो प्रबंधन, स्टॉक ब्रोकिंग, उद्यम पूंजी, बिल छूट, पट्टेबाजी, फैक्टरिंग, अंडरराइटिंग इत्यादि शामिल हैं। सेबी ने मर्चेंट बैंकिंग पर सेबी (मर्चेंट बैंकिंग) विनियमन जारी किया है। विनियमन केवल व्यापारी बैंकर द्वारा की गई सीमित गतिविधियों पर लागू होता है। इसके अलावा, मर्चेंट बैंकरों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में परिचालन दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। उनके पास प्री-इश्यु और पोस्ट-इश्यू दायित्व हैं, जो इश्यु प्रबंधन का हिस्सा हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. व्यापारी बैंकरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर चर्चा करें।

2. भारत में व्यापारी बैंकिंग परिचालन को विनियमित करने में सेबी की भूमिका की व्याख्या करें

3. लीड मैनेजर कौन है? अपने कर्तव्यों और देनदारियों पर चर्चा करें।

4. सेबी द्वारा व्यापारी बैंकरों के लिए निर्धारित आचरण संहिता पर चर्चा करें। इसकी क्या ज़रूरत है?

5. सेबी के अनुसार व्यापारी बैंकरों की अधिकृत गतिविधियों का विस्तार से चर्चा करें।

पाठन स्त्रोत

1. Bhatia, B.S., and Batra, G.S., Financial Services, Deep & Deep Publishers, New Delhi.
2. Bansal, L.K., Merchant Banking and Financial Services, Unistar Books Pvt. Ltd., Chandigarh.
3. Bhole, L.M., Financial Institutions and Markets, Tata McGraw Hill, New Delhi.
4. Chandra, P., Financial Management, Tata McGraw Hill, New Delhi.
5. Khan, M.Y., Financial Services, Tata McGraw Hill, New Delhi.
6. Kothari, C.R., Investment Banking and Customer Service, Arihand Publishers, Jaipur.

इकाई - V:

म्युचुअल फंड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स
(Mutual funds and Money Market Instruments)

विषय सूचि

- म्युचुअल फंड : संरचना, प्रकार और लाभ (Mutual Funds: structure, Types and Advantages)
- ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक बिल (Treasury bill and Commercial bill)
- कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी (Call money, Notice money and Term money)
- क्रेडिट कार्ड (Credit card)

म्यूचुअल फंड का विनियमन और विकास

1929 के शेयर बाजार दुर्घटना से पहले 19 ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड और लगभग 700 बंद-अंत फंड मौजूद थे। उस दुर्घटना के कारण, बंद-अंत फंडों को मिटा दिया गया था। छोटे ओपन-एंड फंड जीवित रहने में कामयाब रहे। निवेशकों की रक्षा के लिए, सरकारी नियामकों ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) बनाया। इसने 19 34 के सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। नतीजतन, म्यूचुअल फंड को एसईसी के साथ पंजीकरण करना होगा और इसे अपने प्रॉस्पेक्टस में प्रकट करना होगा।

म्यूचुअल फंड उद्योग धीरे-धीरे 1950 के दशक में 100 शीर्ष ओपन-एंड फंडों के साथ बढ़ गया। और इसके अलावा, दशक के दौरान 50 नए फंड उभरे। 1960 के दशकों के दौरान सैकड़ों नए फंड लॉन्च किए गए थे, जिसकी 1969 की भालू बाजार की स्थिति तक आक्रामक वृद्धि हुई थी। पहली इंडेक्स फंड अवधारणा की स्थापना वर्ष 1971 में विलियस फौज और वेल्स फार्गो बैंक के जॉन मैकक्वाउन ने की थी। कम लागत वाली इंडेक्स फंड और नो-लोड फंड के उदय के प्रभाव के कारण म्यूचुअल फंड उद्योग और बढ़ गया। म्यूचुअल फंड की परिसंपत्तियों और घरेलू स्वामित्व ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भी तेजी से विकास का अनुभव किया। वित्त के वैश्वीकरण में वृद्धि, बड़े बहुराष्ट्रीय वित्तीय समूहों की उपस्थिति और इक्विटी और बॉन्ड बाजारों के मजबूत प्रदर्शन के कारण, 1990 के दशक के दौरान म्यूचुअल फंडों की वैश्विक वृद्धि में वृद्धि हुई।

म्यूचुअल फंड के प्रकार

बैंक जमा, धातु, वास्तविक संपत्ति, और शेयर बाजार उपकरणों जैसे पैसे निवेश के लिए कई उपकरण हैं। जोखिम और वापसी का स्तर निवेश के प्रकार पर आधारित है। निवेशकों को जोखिम और वापसी के बीच व्यापार करना चाहिए। यदि वे बैंक जमा में निवेश करते हैं, तो जोखिम बहुत कम होता है और साथ ही साथ निवेश के किसी भी अन्य साधन की तुलना में रिटर्न भी बहुत कम होता है। धातुओं और अचल संपत्ति संपत्तियों को आसानी से बेचा नहीं जाता है।

निवेशकों की अपेक्षा कम जोखिम के साथ उच्च रिटर्न या कम अवधि के भीतर इष्टतम रिटर्न के साथ कम जोखिम है। यह केवल स्टॉक मार्केट निवेश में ही संभव है। लेकिन आम निवेशक के लिए यह संभव नहीं है क्योंकि वह स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस को समझने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है। एक आम आदमी बचावकर्ता, म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर बाजार में अपने पैसे को सुरक्षित रूप से निवेश कर सकता है।

म्यूचुअल फंड गतिशील वित्तीय संस्थान हैं जो बचत को एकत्रित करके और पूंजी बाजार में निवेश करके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटे निवेशकों से जुड़ी बचत स्टॉक या बॉन्ड के विविध पोर्टफोलियो खरीदने के लिए एक फंड मैनेजर के माध्यम से निवेश की जाती है। एक निवेशक विविधीकरण के लाभ के साथ कम लागत पर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है। विविधीकरण का अर्थ है "कई अलग-अलग प्रकार के निवेशों में पैसा फैलाना"। जब एक निवेश में उच्च जोखिम शामिल होता है, तो दूसरा कम हो सकता है। निवेश होल्डिंग्स का विविधीकरण खतरे को कम कर देता है।

उनकी संरचना और उद्देश्य के आधार पर, म्यूचुअल फंड को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आम तौर पर, म्यूचुअल फंड के दो प्रमुख प्रकार होते हैं: -

1. ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स
2. क्लोज्ड एन्ड म्यूचुअल फंड

ओपन एंड म्यूचुअल फंड

एक ओपन-एंड फंड या योजना वह है जो निरंतर आधार पर सदस्यता और पुनर्खरीद के लिए उपलब्ध है। इन योजनाओं में निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं है। निवेशक नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) से संबंधित कीमतों पर आसानी से इकाइयों को खरीद और बेच सकते हैं, जिन्हें दैनिक अधिसूचित किया जाता है। ओपन-एंड योजनाओं की मुख्य विशेषता उनकी तरलता है।

क्लोज्ड एन्ड म्यूचुअल फंड

एक क्लोज-एंडेड फंड या योजना में निर्धारित परिपक्वता अवधि निर्धारित होती है उदाहरण 5-7 साल। साल यह योजना केवल योजना के लॉन्च होने के समय निर्दिष्ट अवधि के दौरान सदस्यता के लिए खुली है। निवेशक प्रारंभिक सार्वजनिक मुद्दे के समय इस योजना में निवेश कर सकते हैं और इसके बाद वे स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से योजना की इकाइयों को खरीद या बेच सकते हैं, जहां इकाइयां सूचीबद्ध हैं। निवेशकों को निकास मार्ग प्रदान करने के लिए, कुछ क्लोज-एंडेड फंड एनएवी से संबंधित कीमतों पर आवधिक पुनर्खरीद के माध्यम से इकाइयों को म्यूचुअल फंड में वापस बेचने का विकल्प देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) विनियम यह निर्धारित करते हैं कि कम से कम दो निकास मार्ग निवेशकों को प्रदान किए जाते हैं या तो पुनर्खरीद सुविधा या स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के माध्यम से। ये म्यूचुअल फंड योजना आम तौर पर साप्ताहिक आधार पर एनएवी का खुलासा करती है। वे सामान्य शेयरों की तरह अधिक व्यापार कर रहे हैं।

इस श्रेणी में निवेश करने के कारण हैं:

कीमत बाजार की मांगों द्वारा निर्धारित की जाती है और इस प्रकार, ऑफ़र मूल्य से कम पर क्लोज्ड एन्ड फंड व्यापार अधिक बार होता है। ओपन एंड फंड निवेशकों के लिए विस्तृत विकल्प प्रदान करते हैं

1. स्टॉक फंड और संतुलित फंड जो पूर्ण परिसंपत्ति आवंटन लाभ और
2. बॉन्ड फंड देते हैं।

प्रस्ताव को बंद करने के बाद, निवेशकों द्वारा सीधे फंडों से इकाइयों की खरीद और रिडेम्प्शन की अनुमति नहीं है। हालांकि, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, सेबी निवेशकों को अपनी स्थिति को समाप्त करने के लिए दो मार्गों के साथ प्रदान करता है:

1. क्लोज-एंड फंड स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होते हैं जहां निवेशक इकाइयों को एक-दूसरे से खरीद / बेच सकते हैं। व्यापार आमतौर पर एक छूट दर पर एनएवी के आधार पर किया जाता है। एक बंद-अंत फंड का एनएवी साप्ताहिक आधार पर गणना की जाती है (हर गुरुवार को अपडेट किया जाता है)।
2. क्लोज-एंड फंड यूनिट धारकों को "इकाइयों की खरीद-वापसी" भी प्रदान कर सकते हैं। इस मामले में, फंड का कॉर्पस और इसकी उत्कृष्ट इकाइयां बदल दी जाती हैं।

म्यूचुअल फंड वर्गीकरण

एक योजना को अपने निवेश के उद्देश्य पर विकास योजना, आय योजना या संतुलित योजना के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसी योजनाएं ओपन-एंडेड या क्लोज-एंडेड स्कीम हो सकती हैं। इस तरह की योजनाओं को मुख्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है।

इक्विटी फंड

इक्विटी फंड उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं और साथ ही किसी भी अन्य फंड की तुलना में यह अधिक जोखिम भरा होता है। दीर्घकालिक निवेश के उद्देश्य के लिए, एक निवेशक को इक्विटी में निवेश करने की सलाह दी जाती है। निम्न स्तर के जोखिम के तहत विभिन्न प्रकार के इक्विटी फंड हैं:

1. **आक्रामक विकास फंड -** पूंजी सराहना का अधिकतम लाभ फंड प्रबंधकों के लिए मंत्र है। इसलिए वे अत्यधिक उगाई गई कंपनियों की इक्विटी में निवेश करते हैं और सट्टा निवेश में कम निवेश करते हैं। इक्विटी की सट्टा प्रकृति में निवेश से उच्च जोखिम हो सकता है।
2. **विकास निधि -** यहां, उद्देश्य पूंजी सराहना के माध्यम से निवेश के मूल्य में वृद्धि हासिल करना है, न कि नियमित आय में। फंड मैनेजर उन कंपनियों का चयन करता है जो भविष्य में विकास निधि के निवेश के लिए औसत से अधिक कमाई करने की उम्मीद कर रहे हैं।

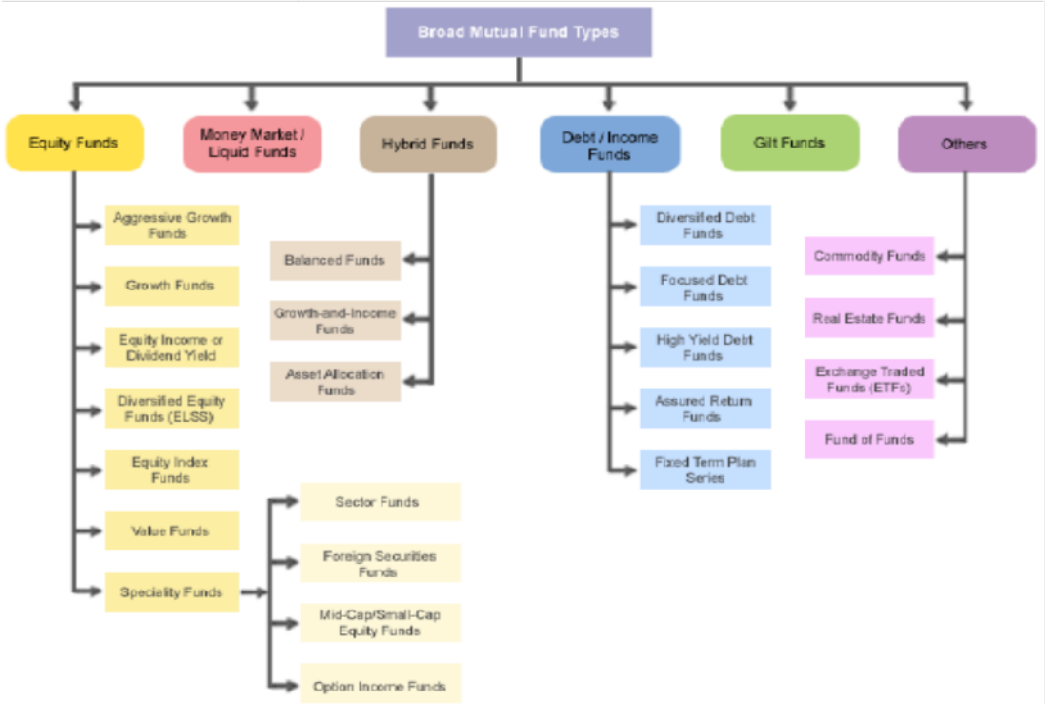

3. **इक्विटी आय या लाभांश यील्ड फंड -** ये निवेशकों के लिए हैं जो निवेश से नियमित रिटर्न के बारे में अधिक चिंतित हैं। फंड मैनेजर उन कंपनियों में निवेश करता है जो लाभांश की उच्च दर घोषित करते हैं। अन्य इक्विटी फंड की तुलना में पूंजीगत प्रशंसा और जोखिम स्तर कम है।
4. **डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड -** फंड मैनेजर किसी भी निर्दिष्ट उद्योग या क्षेत्र के बिना सभी कंपनियों और उद्योगों की इक्विटी में इस प्रकार के फंड निवेश करता है। निवेश के इस विविधीकरण के कारण, बाजार जोखिम भी विविधतापूर्ण है। उदाहरण इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ईएलएसएस)। (ईएलएसएस निवेशक आयकर रिटर्न दाखिल करने के समय कर योग्य आय (1 लाख रुपये तक) से कटौती का दावा कर सकते हैं)।
5. **इक्विटी इंडेक्स फंड -** यह एक विशिष्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन पर आधारित है। इक्विटी इंडेक्स फंड दो प्रकार हैं जैसे व्यापक सूचकांक (जैसे एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी, सेंसेक्स) और संकीर्ण सूचकांक (जैसे बीएसईबीएएनकेएक्स या सीएनएक्स बैंक इंडेक्स इत्यादि)। संकी इंडेक्स इंडेक्स फंड में निवेश कम विविधतापूर्ण हैं; इसलिए यह व्यापक सूचकांक सूचकांक फंड की तुलना में अधिक जोखिम भरा है।
6. **वैल्यू फंड -** फंड मैनेजर उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जिनके पास मजबूत वित्तीय प्रदर्शन है लेकिन जिनकी कीमत-कमाई अनुपात कम है। मूल्य-कमाई अनुपात प्रति शेयर बाजार मूल्य और कमाई प्रति शेयर के बीच संबंध है। शेयरों की इन कंपनियों की पुस्तक मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है। भविष्य में इन शेयरों का बाजार मूल्य बढ़ सकता है। इस धारणा के साथ फंड प्रबंधक दीर्घकालिक समय क्षितिज के लिए विशाल फंड निवेश करता है। सीमेंट, स्टील, चीनी इत्यादि जैसे चक्रीय उद्योग मूल्य स्टॉक के उदाहरण हैं।
7. **स्पेशलिटी फंड -** स्पेशलिटी फंड विशेष उद्योग या कंपनियों पर केंद्रित हैं। एकाग्रता निवेश के लिए कुछ मानदंडों पर आधारित है और उन मानदंडों को उनके पोर्टफोलियो के साथ मेल खाना चाहिए। यह अन्य धन की तुलना में अधिक जोखिम भरा है।

a) **सेक्टर फंड:** सेक्टर फंड के पोर्टफोलियो में केवल उन्हीं कंपनियां शामिल हैं जो उनके मानदंडों को पूरा करती हैं।
b) **विदेशी प्रतिभूति निधि:** फंड प्रबंधक एक या अधिक विदेशी कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इस फंड को अंतरराष्ट्रीय विविधीकरण का लाभ मिलता है, लेकिन इसे विदेशी मुद्रा दर जोखिम और देश के जोखिम का सामना करना पड़ता है।
c) **मिड-कैप या स्मॉल-कैप फंड:** म्यूचुअल फंड उन कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश करता है जिनके बाजार पूंजीकरण कम है। मिड-कैप कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 500 करोड़ और` 2500 के बीच है। स्मॉल-कैप कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के मामले में 500 करोड़ से कम है। बाजार पूंजीकरण कंपनी के बकाया शेयरों की संख्या से गुणा शेयर का बाजार मूल्य है। इस प्रकार की कंपनियों की प्रतिभूतियों की अस्थिरता बहुत अधिक है लेकिन तरलता बहुत कम है। इस उच्च अस्थिरता और कम तरलता के कारण इस तरह की कंपनियों की प्रतिभूतियों का जोखिम बहुत अधिक होगा।
d) **विकल्प आय फंड:** विकल्प आय फंड वह उपज है जो उच्च उपज कंपनियों में निवेश किया जाता है। जोखिम या अस्थिरता को कम करने के लिए विकल्प हेजिंग गतिविधि के लिए उपयोग किए जाते हैं। जोखिम विकल्पों के उचित उपयोग के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। यह निवेशकों के लिए स्थिर आय उत्पन्न करता है।

मनी मार्केट / लिक्विड फंड्स

मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अल्पावधि ब्याज वाले ऋण प्रतिभूतियां हैं, यानी सरकारों द्वारा जारी ट्रेजरी बिल, (30 दिन, 60 दिन, 90 दिन इत्यादि, लेकिन एक वर्ष के भीतर परिपक्व), बैंकों द्वारा जारी जमा राशि का प्रमाण पत्र, कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक दस्तावेज आदि। इन प्रतिभूतियों में उच्च तरलता और सुरक्षा है। इन फंडों में निवेश को मनी मार्केट / तरल निधि कहा जाता है। इन फंडों का जोखिम ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण है।

हाइब्रिड फंड

हाइब्रिड फंडों में इक्विटी, ऋण और मनी मार्केट सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो शामिल है। ऋण और इक्विटी निवेश के अनुपात में बराबर है। भारत में हाइब्रिड फंड के प्रकार निम्नानुसार हैं:

a) **संतुलित फंड:** ऋण, इक्विटी, वरीयता और परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का बराबर अनुपात संतुलित धन का पोर्टफोलियो है। यह नियमित आय देता है और निवेशकों को पूंजी सराहना करता है। पूंजी का जोखिम न्यूनतम स्तर पर है। यह फंड उन लोगों के पारंपरिक निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो दीर्घकालिक निवेश पसंद करते हैं।
b) **विकास और आय फंड:** विकास निधि और आय फंड की सुविधाओं का संयोजन विकास और आय फंड के रूप में जाना जाता है। पूंजी सराहना के साथ-साथ उच्च लाभांश कंपनियों की प्रतिभूतियों की घोषणा इस फंड के पोर्टफोलियो में शामिल है।
c) **संपत्ति आवंटन निधि:** दो प्रकार के निवेश के साधन हैं अर्थात् वित्तीय संपत्ति (इक्विटी, ऋण, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स) और गैर-वित्तीय संपत्तियां (रियल एस्टेट, सोना, कमोडिटीज)। निधि प्रबंधक परिवर्तनीय परिसंपत्ति आवंटन की रणनीति अपना सकता है। यह बाजार के रुझानों के आधार पर किसी भी समय एक परिसंपत्ति से दूसरे में परिवर्तन की अनुमति देता है।

ऋण / आय फंड

ऋण या आय फंड का निवेश पूरी तरह से निजी कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सरकारों और अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किए गए ऋण उपकरणों पर ही है। ये फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं जो नियमित आय और कम जोखिम की अपेक्षा करते हैं। ऋण उपकरण क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। ग्रेडिंग ऋण प्रतिभूतियों का जोखिम इंगित करता है। निवेश उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऋण फंड हैं, जो निम्नानुसार हैं: -

a) **विविध ऋण निधि:** फंड के पोर्टफोलियो में सभी उद्योगों की सभी कंपनियों की ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में विविध निवेश का नतीजा जोखिम में कमी है।
b) **केंद्रित ऋण फंड:** किसी विशेष क्षेत्र या बाजार की कंपनियों से जुड़ी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले ऋण फंड को केंद्रित ऋण निधि के रूप में जाना जाता है।
c) **हाई यील्ड डेट फंड:** आम तौर पर, सभी ऋण फंडों में डिफ़ॉल्ट जोखिम होता है। बड़े पैमाने पर, निवेशक "उच्च निवेश ग्रेड" प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप से जोखिम की रक्षा करते हैं। "निवेश निवेश ग्रेड" प्रतिभूतियों में निवेश किए गए उच्च उपज ऋण फंड उच्च रिटर्न प्रदान करते हैं लेकिन अधिक अस्थिरता के कारण डिफ़ॉल्ट जोखिम का अस्तित्व अधिक होता है।
d) **आश्वासित रिटर्न फंड:** इस फंड के निवेशकों को कम जोखिम वाले निवेश के अवसर के साथ आश्वासन दिया जाएगा। लेकिन संपत्ति प्रबंधन कंपनी या प्रायोजक द्वारा अर्जित रिटर्न में कमी हो सकती है। निवेश की सुरक्षा गारंटर के शुद्ध मूल्य पर निर्भर करती है, जिसका नाम ऑफ़र दस्तावेज़ में निर्दिष्ट है। निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, प्रायोजकों को निश्चित वापसी योजनाओं की पेशकश करने के लिए सेबी के मानदंडों के अनुसार रिटर्न की गारंटी के लिए पर्याप्त शुद्ध मूल्य होना चाहिए। भारत के यूनिट ट्रस्ट ने आश्वासित रिटर्न योजनाओं की योजना के तहत 'मासिक आय योजना' की पेशकश की थी। लेकिन यूटीआई रिटर्न में भारी कमी के कारण अपने वादों को पूरा करने में असफल रहा। यूटीआई के भुगतान दायित्वों को सरकार द्वारा लिया गया। आजकल भारत में कोई आश्वासन वापसी योजना नहीं दी जाती है।
e) **फिक्स्ड टर्म प्लान सीरीज:** फंड 'अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों में अल्पकालिक निवेशकों और निवेशों को आकर्षित करता है। यह एक बंद-अंत योजना है जो निवेशकों को नियमित अंतराल पर योजनाओं और मुद्दों की एक श्रृंखला प्रदान करती है। लेकिन इन योजनाओं को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

गिल्ट फंड

गिल्ट फंड का पोर्टफोलियो केवल मध्यम और दीर्घकालिक परिपक्व बॉन्ड की सरकारी प्रतिभूतियां है। यह निवेशकों को कोई क्रेडिट जोखिम नहीं देता है। लेकिन यह ब्याज दर के जोखिम से अवगत कराया गया है।

कमोडिटी फंड

इस फंड के निवेश का ध्यान अलग-अलग वस्तुओं पर है, जैसे कि धातु (जैसे सोने, चांदी, तांबा इत्यादि), अनाज, तेल, आदि, या विकल्प और वायदा, वस्तुओं के अनुबंध, कमोडिटी उत्पादक कंपनियां आदि। एक विशेष वस्तु पर या विविधतापूर्ण कमोडिटी फंड पर निवेश की एकाग्रता की जा सकती है। विशिष्ट कमोडिटी फंड विविधता वाले कमोडिटी फंड की तुलना में अधिक जोखिम रखता है।

रियल एस्टेट फंड

रियल एस्टेट निवेश उच्च पूंजी सराहना प्रदान करता है और निवेशकों को नियमित और उच्च आय उत्पन्न करता है। रियल एस्टेट निवेश में न केवल अचल संपत्ति में प्रत्यक्ष निवेश में बल्कि आवास वित्त कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश या रियल एस्टेट डेवलपर्स को उधार देने में भी शामिल है।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)

एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों को इंडेक्स लिंक्ड कीमतों पर एक स्टॉक जैसे स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जाता है और यह स्टॉक मार्केट इंडेक्स का पालन करता है। इस फंड के निवेशकों को क्लोज-एंड फंड और ओपन एंड म्यूचुअल फंड दोनों के लाभ मिलते हैं। यह लंदन और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजों में बहुत लोकप्रिय है। भारत में, इसे हाल ही में पेश किया गया है। यह फंड एक विविध शेयर की तरह अधिक विविधतापूर्ण और लचीला है।

निधि का निधि/ Fund of Funds

इसका मतलब है कि अन्य संपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली म्यूचुअल फंड योजनाओं की इकाइयों में निवेश किए गए एक म्यूचुअल फंड का धन। वित्तीय (शेयर, बॉन्ड) या फंड ऑफ फंड की भौतिक संपत्ति पर कोई निवेश नहीं किया जाता है। इस फंड के निवेशकों को विभिन्न म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश की एक छोटी राशि के साथ विविधता का लाभ मिलता है। और यह भी जोखिमों के विविधीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

म्यूचुअल फंड के महत्व / लाभ

1. **छोटे बचत को मोबिलिज़ करना:** इकाइयों को बेचने के माध्यम से फंडों को एकत्रित किया जाता है। एक इकाई एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों का आनुपातिक हिस्सा है। छोटे फंड निवेशकों को अपनी बचत की छोटी राशि के साथ पोर्टफोलियो निवेश का लाभ मिलता है।
2. **निवेश एवेन्यू:** मोबिलिज्ड फंड विभिन्न प्रकार के निवेश के रास्ते में निवेश किए जाते हैं। निवेश के रास्ते विभिन्न कंपनियों और उद्योगों, सोने, जमा, सरकार के शेयर और बांड हैं। बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि, निवेशक संपत्ति के पोर्टफोलियो पर आनुपातिक रूप से अवसर प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत निवेशक इन सभी निवेश के रास्ते में निवेश नहीं कर सकते हैं।
3. **व्यावसायिक प्रबंधन:** 'म्यूचुअल फंड' पेशेवर विशेषज्ञों का उपयोग करता है और विशेषज्ञ निवेश पोर्टफोलियो को कुशलतापूर्वक और लाभप्रद तरीके से प्रबंधित करते हैं। निवेशक शेयर खरीदने और बेचने का जोखिम लेने से मुक्त हैं।
4. **विविध निवेश:** छोटे निवेशक म्यूचुअल फंड के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश के लाभ का आनंद ले सकते हैं। म्यूचुअल फंडों के पास विभिन्न उद्योग खंडों में विविध निवेश का लाभ है।
5. **लिक्विडिटी:** म्यूचुअल फंड निवेशक क्लोज-एंडेड म्यूचुअल फंड के मामले में द्वितीयक बाजार में अपनी इकाइयां खरीद और बेच सकते हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के मामले में, निवेशक नेट एसेट वैल्यू पर किसी भी समय होल्डिंग वापस ले सकते हैं।
6. **कम जोखिम:** म्यूचुअल फंड निवेश में बहुत कम जोखिम शामिल है। क्योंकि, फंड पेशेवर विशेषज्ञता, पोर्टफोलियो निवेश, विविधीकरण और लेनदेन लागत में पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रबंधित किया जाता है।

7. **कानूनी सुरक्षा:** भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक निकाय है; यह म्यूचुअल फंड के लिए नियम और दिशानिर्देश प्रदान करता है।
8. **कर लाभ:** आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत, म्यूचुअल फंड के निवेशक म्यूचुअल फंड में अपने निवेश पर टैक्स आश्रय प्राप्त कर सकते हैं।
9. **न्यूनतम लेनदेन लागत:** म्यूचुअल फंड इकाइयों की खरीद और बिक्री की लेनदेन लागत बहुत कम है। इससे निवेशकों को एक योजना से दूसरी योजना में स्विच करने की सुविधा मिलती है और उन्हें लचीले निवेश के अवसरों का लाभ मिलता है।
10. **आर्थिक विकास:** बचत का मोबिलिलाइजेशन निवेश की ओर जाता है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के लिए म्यूचुअल फंड धन का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास से देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है।

म्यूचुअल फंड बनाम बीमा

म्यूचुअल फंड	**बीमा**
• रिटर्न अधिक हैं • फंड प्रबंधन सक्रिय है • कम वितरण शुल्क • कुछ योजनाओं में कर देनदारियां • ऋण और इक्विटी में उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है	• कम रिटर्न, लेकिन जोखिम भी कम है • दीर्घकालिक निवेशकों के लिए आदर्श • बिना किसी भार के संपत्ति वर्गों के बीच स्विचिंग ऑफर करें • कोई कर देयता नहीं है • सुरक्षा निवेश के लिए एक बड़ा ट्रिगर है

भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग

भारत में म्यूचुअल फंड पहली बार यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) ने 19 64 में निवेश ट्रस्ट के रूप में शुरू किया था। यूटीआई शुरू में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड के साथ शुरू हुआ; पहली इकाई योजना "यूएस -64" थी और मध्यम और निम्न आय वाले लोगों को आकर्षित करने के लिए एकल इकाई का चेहरा मूल्य `10 था। यूटीआई ने 19 87 तक म्यूचुअल फंड के एकाधिकार का आनंद लिया और बाद में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन करके भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों को म्यूचुअल फंड के कार्यों को करने के लिए ट्रस्ट के रूप में परिचालन करने वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की अनुमति दी।

इससे पहले, बाजार के एकाधिकार ने एक अंतिम चरण देखा था; प्रबंधन के तहत संपत्तियां (एयूएम) 67 बिलियन थीं। फंड परिवार में निजी क्षेत्र की प्रविष्टि ने मार्च 1993 में एयूएम को 470 अरब डॉलर और अप्रैल 2004 के अंत में बढ़ा दिया; यह 1,540 अरब की ऊंचाई तक पहुंच गया।

भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग की तुलना में एयूएम को तुलना में, कुल मिलाकर एसबीआई की जमा राशि और भारतीय बैंकिंग उद्योग द्वारा आयोजित कुल जमा का 11% से कम है। इसकी खराब वृद्धि का मुख्य कारण यह है

कि भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग देश के लिए नया है। इसलिए, यह सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों की मुख्य ज़िम्मेदारी है, बिक्री के अलावा उत्पाद को सही ढंग से बाजार में बेचने के लिए।

सेबी विनियम

1. भारतीय प्रतिभूति विनिमय (सेबी) के निम्नलिखित नियम और विनियम म्यूचुअल फंड की योजनाओं की स्थापना और मुद्दे से संबंधित हैं।
2. म्यूचुअल फंड भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाएगा और अलग-अलग गठित संपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
3. एएमसी के निदेशक मंडल में संगठन को प्रायोजित करने के प्रभाव के बिना 50% सदस्य स्वतंत्र होना चाहिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन के क्षेत्र में उन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
4. कम से कम `10 करोड़ के पास एएमसी नेट वर्थ के रूप में होना चाहिए
5. एक एएमसी केवल एक म्यूचुअल फंड के लिए काम कर सकता है और यह किसी अन्य के लिए काम करने के लिए निषिद्ध है।
6. एएमसी को अन्य फंड आधारित व्यवसाय करने की भी अनुमति है जैसे ऑफशोर फंड, उद्यम पूंजी निधि और बीमा कंपनियों को निवेश प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना।
7. क्लोज-एंड स्कीम और ओपन एंड स्कीम के लिए फंड का न्यूनतम अंक क्रमशः `20 करोड़ और` 50 करोड़ होना चाहिए।
8. क्लोज-एंड स्कीम के मामले में सब्सक्रिप्शन की अधिकतम अवधि 45 दिन है, लेकिन ओपन एंड स्कीम के मामले में ऐसी कोई सीमा नहीं है।
9. पूरी सदस्यता निवेशकों को वापस करनी होगी जब न्यूनतम राशि या लक्ष्य राशि का 60% उठाया नहीं जाता है।
10. प्रत्येक योजना के लिए एक अलग और जिम्मेदार निधि प्रबंधक होना चाहिए।
11. छोटे निवेशकों की रक्षा के लिए, सेबी एक योजना में नेट एसेट्स वैल्यू के 10% द्वारा एक कंपनी में म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो निवेश को प्रतिबंधित करता है।
12. मुद्दा योजना प्रत्येक योजना के तहत धन जुटाने के 6% तक सीमित है।
13. मुनाफे का कम से कम 9 0% किसी भी वर्ष में यूनिट धारकों को वितरित करना होगा।
14. म्यूचुअल फंड का लेखा और लेखा परीक्षा अनिवार्य है और सेबी को लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण प्रस्तुत करते हैं।
15. सेबी के पास सेबी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए म्यूचुअल फंड पर दंड लगाने की शक्ति है।

ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक बिल

TREASURY BILL AND COMMERCIAL BILL

ट्रेजरी बिल, या आमतौर पर टी-बिल के रूप में जानते हैं, सरकार द्वारा जारी बांड हैं। यह एक अल्पकालिक (एक वर्ष से भी कम) सरकार शून्य कूपन बंधन है। यह सरकार के अल्पकालिक उधार का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि टी-बिल जनता से पैसे जुटाने का एक तरीका है। उन्हें स्थानीय और राज्य करों से मुक्त किया जाता है। ये रियायती प्रतिभूतियां हैं और इस प्रकार अंकित मूल्य पर छूट पर जारी की जाती हैं। ट्रेजरी बिल ब्याज का भुगतान नहीं करता है, निवेशक को वापसी परिपक्वता मूल्य और जारी मूल्य के बीच अंतर है। उदाहरण के लिए, यदि आपने

9, 750 के लिए 10,000, 26 सप्ताह के ट्रेजरी बिल खरीदे और परिपक्वता तक इसे रखा, तो आपकी रुचि 250 होगी। टी-बिल अल्पकालिक प्रतिभूतियां हैं जो उनकी जारी तिथि से एक वर्ष या उससे कम समय में परिपक्व होती हैं। उन्हें तीन महीने, छह महीने और एक वर्ष की परिपक्वता जारी की जाती है। टी-बिलों को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार उन्हें वापस लेती है। वास्तव में, उन्हें जोखिम मुक्त माना जाता है। राज्य सरकार को छोड़कर व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, कॉर्पोरेट निकायों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा ट्रेजरी बिल खरीदे जा सकते हैं। ये सरकार की तरफ से केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और बोलियों के आधार पर अलग-अलग छूट दर पर पखवाड़े या मासिक नीलामी के माध्यम से बेचे जाते हैं। बिलों के लिए निविदाएं (बोलियां) आमंत्रित की जाती हैं और सर्वोत्तम ऑफ़र स्वीकार किए जाते हैं। बिल बनाने के लिए बोलियों की न्यूनतम राशि देश से देश में भिन्न होती है। टी-बिल अल्पकालिक निवेश का एक आदर्श रूप है।

टी-बिलों का एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि आपको बड़ी वापसी नहीं मिलेगी क्योंकि ट्रेजरी बेहद सुरक्षित हैं और यदि आप परिपक्वता तिथि से पहले नकद करते हैं तो आप अपने सभी निवेश वापस नहीं ले सकते हैं।

मूल रूप से 3 मुख्य प्रकार की ट्रेजरी सिक्योरिटीज हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं:

ट्रेजरी विधेयक: एक ट्रेजरी बिल (टी-बिल), वह ऋण है जिसे एक वर्ष के भीतर जारी किया जाएगा, जिसमें सामान्य तिथि की तारीख से सामान्य परिपक्वता तिथियां होंगी। टी-बिलों में निवेशकों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी ऋण की सबसे छोटी चुकौती अवधि होती है और उन्हें सभी का सबसे सुरक्षित निवेश निवेश माना जाता है। अधिकांश अन्य निवेशों के विपरीत जहां ब्याज का भुगतान किया जाता है, निवेशकों को सकारात्मक रिटर्न देने के लिए नीलामी के समय छूट के बजाय ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं।

ट्रेजरी नोट: ट्रेजरी नोट्स (टी-नोट्स), ऋण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं कि सरकार चुकानी होगी लेकिन इनकी परिपक्वता तिथियां आम तौर पर दो से दस साल तक होती हैं। हालांकि, ट्रेजरी बिलों के विपरीत, ट्रेजरी नोट्स हर छह महीने के हितों का भुगतान करते हैं।

ट्रेजरी बांड: ट्रेजरी बांड (टी-बांड), बीस या तीस साल में परिपक्व होता है। ट्रेजरी नोट्स की तरह, वे हर छह महीने और पेंशन फंड के लिए ब्याज देते हैं और बहुत लंबे समय तक संस्थागत निवेशकों के लिए उपयोगी होते हैं जिन्हें अपने जोखिम को कम करने की आवश्यकता होती है।

यह कैसे काम करता है

परिपक्वता मूल्य पर छूट पर टी-बिल जारी किए जाते हैं। ब्याज की कूपन दर का भुगतान करने के बजाय, जारी मूल्य और परिपक्वता मूल्य के बीच सराहना निवेश वापसी प्रदान करती है।

उदाहरण के लिए, छह महीने में $ 10,000 का भुगतान करने के लिए 26 सप्ताह के टी-बिल की कीमत 9,800 डॉलर है। कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है। निवेश वापसी मूल रूप से भुगतान किए गए रियायती मूल्य और परिपक्वता पर प्राप्त राशि, या $ 200 ($ 10,000 - $ 9,800) के बीच के अंतर से आता है। इस मामले में, टी-बिल छह महीने की अवधि के लिए 2.04% ब्याज दर ($ 200 / $ 9,800 = 2.04%) का भुगतान करता है।

यह क्यों मायने रखता है:

टी-बिल को सबसे सुरक्षित संभावित निवेश माना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेडिट योग्यता के आधार पर "जोखिम की जोखिम मुक्त दर" के रूप में जाना जाता है। रिटर्न की यह जोखिम मुक्त दर नगरपालिका बांड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और बैंक ब्याज पर दरों के लिए बेंचमार्क के कुछ हद तक उपयोग की जाती है।

इसके अतिरिक्त, क्योंकि टी-बिल बहुत ही अल्पकालिक निवेश होते हैं (ट्रेजरी नोट्स और ट्रेजरी बॉन्ड के विपरीत) बहुत कम ब्याज दर का जोखिम होता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो निश्चित आय प्रतिभूतियों की कीमत गिरती है क्योंकि उनकी भविष्य की आय धारा के सापेक्ष मूल्य को छूट दी जाती है। हालांकि, अल्पकालिक प्रतिभूतियां लंबी अवधि की प्रतिभूतियों की तुलना में बहुत कम प्रभावित होती हैं क्योंकि उच्च दरों का भविष्य की आय धाराओं पर बहुत सीमित प्रभाव पड़ता है।

पारस्परिक प्रतिरक्षा के कानून की वजह से ट्रेजरी ब्याज राज्य और स्थानीय करों से मुक्त है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य संघीय प्रतिभूतियों और इसके विपरीत कर नहीं लगा सकते हैं।

वाणिज्यिक बिल

ट्रेजरी बिलों की तरह, वाणिज्यिक बिलों का भी अपना बाजार होता है। बाद के बिल व्यापार में लगे फर्मों द्वारा जारी किए जाते हैं। आम तौर पर, वे तीन महीने की परिपक्वता के होते हैं। वे मूल्य के लिए माल के खरीदारों पर माल के विक्रेताओं द्वारा तैयार की गई पोस्टेड चेक की तरह हैं।

इस प्रकार, बिल व्यापार और उद्योग को अल्पकालिक वित्त प्रदान करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण हैं। उनके पास परिपक्वता नामक परिपक्वता के लिए एक निश्चित अवधि है। बैंकों के लिए उनके पुनर्विक्रय या प्रसंस्करण और बिक्री से माल की लागत वसूलने के लिए सामानों के खरीदारों (बिलों के ढांचे) के लिए उचित रूप से लंबे समय तक उनके धन का निवेश करने के लिए यह उपयोग काफी कम है। बाद वाला विचार बिलों को स्वयं-परिसमापन बनाता है। इससे बिलों पर डिफ़ॉल्ट रूप से जोखिम का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा, बिल मार्केबल पेपर हैं, यानी, उन्हें मनी मार्केट में कई बार फिर से बेचा जा सकता है।

वे ब्याज की प्रतिस्पर्धी दर भी लेते हैं। इन सभी कारणों से, बैंकों को ऐसे बिलों में निवेश के लिए प्राथमिकता है। अतीत में, कई मौद्रिक अर्थशास्त्री इस विचार से थे कि बैंकों को केवल बिलों में निवेश करना चाहिए। इस विचार को साहित्य में 'असली बिल सिद्धांत' के रूप में जाना जाता है। लेकिन अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने इसे एक चरम दृष्टिकोण के रूप में माना है।

एक अच्छी संपत्ति शो को एकाधिकार नहीं करना चाहिए। साथ ही, व्यापार मंदी या क्रेडिट की अवधि के दौरान अपेक्षित बिक्री या प्राप्तियां निचोड़ नहीं हो सकती हैं और ड्रायस को अपने बिलों का सम्मान करना मुश्किल हो सकता है। इस प्रकार, बिलों का आत्म-परिसमापन चरित्र एक उचित मौसम मित्र है।

वाणिज्यिक बिल विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें से भेद के आधार कई हैं। एक अंतर यह है कि विनिमय और स्वदेशी बिलों के आधुनिक बिलों के बीच। हमने ऊपर बताए गए आधुनिक बिल हैं। स्वदेशी बिलों को हुंडिस कहा जाता है। एक और भेद यह है कि अंतर्देशीय बिल और विदेशी (व्यापार) बिलों के बीच। जैसा कि नाम इंगित करता है, पूर्व का उपयोग अंतर्देशीय व्यापार को वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है, बाद में विदेशी व्यापार को वित्त पोषित किया जाता है। यह इस प्रकार है कि आयात बिलों का आयात आयात और वित्तपोषण के लिए बिल निर्यात करने के लिए किया जाता है। एक तीसरा प्रकार का भेद यह है कि व्यापार बिल और वित्त बीमारियों के बीच।

वाणिज्यिक बिलों को दस्तावेजी बिल भी कहा जाता है क्योंकि वे वास्तविक व्यापार लेनदेन से संबंधित कागजात लेते हैं। ऐसे में, उन्हें वास्तविक (व्यापार) बिल भी कहा जाता है। दूसरी तरफ, वित्त बिल 'साफ' बिल हैं। उनके पास सामानों की बिक्री के किसी दस्तावेज नहीं हैं, क्योंकि वे किसी भी वास्तविक व्यापार लेनदेन से उत्पन्न नहीं होते हैं। भारत में बिल बाजार के विकास को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारक मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं:

(i) बैंक ऋण के मुख्य रूप के रूप में नकदी क्रेडिट प्रणाली का प्रसार, और
(ii) बिल बाजार में शामिल भुगतान अनुशासन को स्वीकार करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में बड़े खरीदार की अनिच्छा।

इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में बिल खींचने में एकरूपता की कमी; किसी भी निर्दिष्ट समय सीमा के बिना क्रेडिट पर बिक्री का अभ्यास, आमतौर पर बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है; और उपयोग पर उच्च स्टाम्प ड्यूटी (समय बिल) ने भी बिल वित्त के विकास में बाधा डाली है।

बिलों की उपयोगिता को व्यापार और बैंकों, उनके स्वयं-परिसमापन चरित्र, और आरबीआई द्वारा बैंकों के बिल वित्त के आसान विनियमन के रूप में क्रेडिट के साधनों के रूप में देखते हुए बाद में बिलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने और बिल विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में अब तक केवल सीमित सफलता मिली है। इसकी मुख्य रणनीति बैंकों को अपने उधारकर्ताओं को बिल वित्त के लिए अधिक से अधिक सहारा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करती है। समय-समय पर व्यक्तिगत बैंक नकद से कम हो जाते हैं। वे आरबीआई को ट्रेजरी बिल बेचकर आंशिक रूप से सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ उधार लेकर आंशिक रूप से कॉल मनी मार्केट से नकदी के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं।

आरबीआई ने पात्र वाणिज्यिक बिलों के खिलाफ बैंकों को भी अपनी पुनर्वित्त उपलब्ध कराने की पेशकश की है। इसने आरबीआई से बैंकों के उधार लेने के दायरे को बढ़ा दिया है और देश में बिल वित्त के विकास के लिए एक प्रवृत्ति के रूप में कार्य किया है।

वाणिज्यिक बिलों में टी-बिलों की तुलना में अधिक पैदावार क्यों होती है?

टी बिलों की तुलना में वाणिज्यिक बिलों की उच्च पैदावार का कारण यह है कि प्रत्येक बिल प्रकार की अलग-अलग क्रेडिट गुणवत्ता के कारण होता है। बिल जारी करने वाली इकाई की क्रेडिट रेटिंग निवेशकों को इस संभावना का एक विचार देती है कि उन्हें पूरी तरह से भुगतान किया जाएगा। संघीय सरकार के ऋण (टी-बिल) को बाजार में उच्चतम क्रेडिट रेटिंग माना जाता है क्योंकि इसके आकार और करों के माध्यम से धन जुटाने की क्षमता है। दूसरी तरफ, एक कंपनी जो वाणिज्यिक बिलों को जारी करती है, उसके पास नकद प्रवाह उत्पन्न करने की समान क्षमता नहीं होती है क्योंकि इसमें उपभोक्ताओं पर समान शक्ति नहीं होती है कि सरकार के पास अपने मतदाता हैं। दूसरे शब्दों में, वाणिज्यिक बिल और टी-बिल उन निकायों की क्रेडिट गुणवत्ता में भिन्न होते हैं जो उन्हें जारी करते हैं। एक उच्च उपज उन निवेशकों के लिए मुआवजे के रूप में कार्य करती है जो उच्च जोखिम वाले व्यावसायिक बिल चुनते हैं।

आम तौर पर, जब समान परिपक्वता वाले दो बिल होते हैं, तो बिल जो कम क्रेडिट गुणवत्ता या रेटिंग है, निवेशकों को उच्च उपज प्रदान करेगा क्योंकि अधिक संभावना है कि लेनदार अपने ऋण दायित्व को पूरा करने में असमर्थ होगा।

कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी

(Call money, Notice money and Term money)

मनी मार्केट प्राथमिक रूप से प्राथमिक व्यापारियों (Primary Dealers) जैसे बैंकों और संस्थाओं के बीच धन की उधार और उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है। बैंक और पीडी फंड की स्थिति में अपने अल्पकालिक विसंगतियों को पूरा करने के लिए रातोंरात या छोटी अवधि के लिए उधार लेते हैं और उधार देते हैं। यह उधार और उधार असुरक्षित आधार पर है। 'कॉल मनी' 1 दिन के लिए धन उधार या उधार है। जहां धन उधार लिया जाता है या 2 दिनों और 14 दिनों के बीच अवधि के लिए उधार दिया जाता है, इसे 'नोटिस मनी' के नाम से जाना जाता है। और 'टर्म मनी' का अर्थ 14 दिनों से अधिक अवधि के लिए धन उधार / उधार देना है।

'कॉल मनी' क्या है

कॉल कॉल एक बैंक द्वारा लोन किया जाता है जिसे मांग पर चुकाया जाना चाहिए। एक सावधि ऋण के विपरीत, जिसमें एक निर्धारित परिपक्वता और भुगतान अनुसूची है, कॉल कॉल को निश्चित समय-सारिणी का पालन नहीं करना पड़ता है, न ही ऋणदाता को पुनर्भुगतान का कोई नोटिस देना पड़ता है। ब्रोकरेज अपने ग्राहकों के लाभ के लिए मार्जिन खातों को बनाए रखने के लिए फंडिंग के अल्पकालिक स्रोत के रूप में कॉल मनी का उपयोग करते हैं जो अपने निवेश का लाभ उठाना चाहते हैं। धन उधारदाताओं और ब्रोकरेज फर्मों के बीच तेजी से बढ़ सकता है।

बैंकों के लिए, नकदी के बाद पैसा कॉल सबसे अधिक परिसंपत्ति है। कॉल मनी में लेनदेन बैंकों को अधिशेष बैलेंस शीट फंड पर ब्याज कमाने का मौका देता है। काउंटरपार्टी पक्ष पर, ब्रोकरेज जानते हैं कि वे किसी भी समय धनराशि का उपयोग करके जोखिम ले रहे हैं, इसलिए वे आमतौर पर लेनदेन के लिए कॉल मनी का उपयोग करते हैं जिसे जल्दी से हल किया जाएगा। यदि बैंक धन को याद करता है, तो ब्रोकर मार्जिन कॉल जारी कर सकता है, जो आम तौर पर बैंक को पुनर्भुगतान के लिए ग्राहक के खाते में प्रतिभूतियों की स्वचालित बिक्री (प्रतिभूतियों को नकद में परिवर्तित करने) के परिणामस्वरूप होगा। मार्जिन दरें, या प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए ऋण पर लगाए गए ब्याज, बैंकों द्वारा निर्धारित कॉल मनी दर के आधार पर भिन्न होते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में कॉल मनी दर "मनी दरें" के तहत पाई जा सकती है। कॉल पर पैसा कम से कम 5% अल्पकालिक वित्त मांग पर चुकाया जाता है, परिपक्वता अवधि के साथ एक से चौदह दिन या रात भर पखवाड़े तक। इसका उपयोग अंतर बैंक लेनदेन के लिए किया जाता है। इस बाजार में एक दिन के लिए दी गई धन को "कॉल मनी" के रूप में जाना जाता है और यदि यह एक दिन से अधिक है, तो इसे "नोटिस मनी" कहा जाता है।

वाणिज्यिक बैंकों को नकदी आरक्षित अनुपात के रूप में जाना जाने वाला न्यूनतम नकद शेषराशि बनाए रखना है। कॉल पैसा एक तरीका है जिसके द्वारा बैंक नकद आरक्षित अनुपात को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए एक-दूसरे को उधार देते हैं। कॉल मनी पर ब्याज दर कॉल दर के रूप में जानी जाती है। यह एक बेहद अस्थिर दर है जो दिन-प्रतिदिन और कभी-कभी घंटे-घंटे तक भिन्न होती है। कॉल दरों और अन्य अल्पकालिक मनी मार्केट उपकरणों जैसे कि जमा प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर के बीच एक व्यस्त संबंध है। कॉल मनी दरों में वृद्धि वित्त के अन्य स्रोत बनाती है, जैसे वाणिज्यिक पेपर और जमा प्रमाणपत्र, इन स्रोतों से धन जुटाने के लिए बैंकों की तुलना में सस्ता है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में, आमतौर पर शब्द मार्जिन खाते को बनाए रखने के लिए दलालों को बैंकिंग संस्थानों द्वारा अल्पकालिक वित्तपोषण को संदर्भित करता है। यह 'ऋण' शब्द से अलग है क्योंकि ब्याज के भुगतान के लिए अनुसूची और प्रिंसिपल तय नहीं है। चूंकि, ऋण किसी भी समय बुलाया जा सकता है, यह अन्य प्रकार के ऋणों की तुलना में जोखिम भरा है। यह छोटी सूचना पर तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है।

क्रेडिट कार्ड Credit Cards

क्रेडिट खरीदार के हाथ में नकद रखने के बिना माल या सेवाओं को बेचने का एक तरीका है। क्रेडिट कार्ड की अवधारणा "अब खरीदें, बाद में भुगतान करें" और यह उपभोक्ता को क्रेडिट देने का एक तरीका है। क्रेडिट कार्ड में एक पहचान संख्या होती है जो खरीदारी लेनदेन को गति देती है।

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक, "1920 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए क्रेडिट कार्ड का उपयोग, जब तेल कंपनियों और होटल श्रृंखलाओं जैसी व्यक्तिगत फर्मों ने उन्हें ग्राहकों को जारी करना शुरू किया।" पुराने दिनों में, व्यापारियों द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे उनके ग्राहकों को क्रेडिट बिक्री पर। ये कार्ड केवल जारीकर्ता द्वारा ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए जाते थे और विक्रेता दूसरों के कार्ड को स्वीकार नहीं करेगा। 19 38 के आसपास, कंपनियों ने एक-दूसरे के कार्ड स्वीकार करना शुरू कर दिया। आज, क्रेडिट कार्ड अनगिनत तृतीय पक्षों के साथ खरीदारी करने की अनुमति देते हैं।

क्रेडिट कार्ड का आकार

बहुत पहले, धातु के सिक्कों, धातु प्लेटों, सेलूलॉयड, धातु, फाइबर, और कागज से क्रेडिट कार्ड बनाए गए थे। आजकल, क्रेडिट कार्ड ज्यादातर प्लास्टिक से बने होते हैं।

फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड

फ्लैटबश नेशनल बैंक ऑफ ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 19 46 में क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक था। इस कार्ड का आविष्कार जॉन बिगिनस ने कार्यक्रम में किया था जिसका अर्थ है "चार्ज-इट" बैंक ग्राहकों और स्थानीय व्यापारियों के बीच आयोजित किया गया था। व्यापारियों ने बैंक में बिक्री पर्ची जमा की और बैंक ने कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को बिल भेजा।

डिनर क्लब क्रेडिट कार्ड

1950 में, डिनर क्लब ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना क्रेडिट कार्ड जारी किया। डायनर्स क्लब के संस्थापक फ्रैंक मैकनामरा ने डिनर क्लब क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया और रेस्तरां के बिलों का भुगतान करने के इरादे से अपने ग्राहकों से परिचय दिया। डिनर क्लब का कार्ड धारक बिना किसी रेस्तरां में पैसे खा सकता है जो डिनर्स क्लब से धन इकट्ठा करेगा। डायनर्स क्लब पहले रेस्तरां के बिल को व्यवस्थित करेगा और बाद में वे ग्राहक (कार्डधारक) से कुछ शुल्कों के साथ बिल राशि एकत्र करेंगे। तो, डिनर क्लब कार्ड को चार्ज कार्ड कहा जाता था। 19 58 में, पहला क्रेडिट कार्ड अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा जारी किया गया था। बाद में बैंक ऑफ अमेरिका ने अमेरिका बैंक क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जिसे लोकप्रिय रूप से वीज़ा कार्ड के नाम से जाना जाता है।

क्रेडिट कार्ड की लोकप्रियता

1960 के दशक के दौरान, अधिक कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड की पेशकश की, उन्हें क्रेडिट के रूप में एक समय बचाने वाली डिवाइस के रूप में विज्ञापन दिया। अमेरिकी एक्सप्रेस और मास्टर कार्ड रात भर लोकप्रिय हो गया।

मानक क्रेडिट कार्ड

मानक क्रेडिट कार्ड को अन्यथा " plain-vanilla " क्रेडिट कार्ड कहा जाता है जो कोई अतिरिक्त या पुरस्कार प्रदान नहीं करते हैं। यह एक आम प्रकार का क्रेडिट कार्ड है जो कार्डधारक को एक निश्चित क्रेडिट सीमा तक घूमने

वाली शेष राशि की अनुमति देता है। कार्डधारक अपनी जरूरतों के हिसाब से कार्ड का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें देय तिथि से पहले अपने खाते को व्यवस्थित करना होगा। यदि वह प्रत्येक महीने के अंत में बकाया शेष राशि पर देय तिथि ब्याज से पहले भुगतान करने में विफल रहता है।

प्रीमियम क्रेडिट कार्ड

प्रीमियम क्रेडिट कार्ड द्वारा कई प्रोत्साहन और लाभ प्रदान किए जाते हैं उदा। गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड जो नकद वापस, इनाम अंक, यात्रा उन्नयन, और कार्डधारकों को अन्य पुरस्कार प्रदान करते हैं। प्रीमियम कार्ड के कार्डधारक को अधिक शुल्क वसूल किया जाता है और कार्ड उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने उच्च आय और क्रेडिट स्कोर आवश्यकताओं को निर्धारित किया है।

चार्ज कार्ड

चार्ज कार्ड एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए कार्डधारकों को कई महीनों में शेष राशि पर भुगतान करने की बजाय प्रत्येक बिलिंग चक्र के अंत में अपनी शेष राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। चार्ज कार्ड में खर्च सीमा और वित्त (ब्याज दर) शुल्क नहीं है। देर से भुगतान कार्ड समझौते के आधार पर शुल्क, शुल्क प्रतिबंध, या कार्ड रद्दीकरण के अधीन हैं।

सीमित प्रयोजन कार्ड

सीमित उद्देश्य क्रेडिट कार्ड केवल विशिष्ट स्थानों पर उपयोग किया जा सकता है। सीमित प्रयोजन कार्ड का उपयोग न्यूनतम भुगतान और वित्त शुल्क के साथ क्रेडिट कार्ड की तरह किया जाता है। क्रेडिट कार्ड और गैस क्रेडिट कार्ड स्टोर करें, पेट्रो कार्ड सीमित उद्देश्य क्रेडिट कार्ड के उदाहरण हैं।

सुरक्षित क्रेडिट कार्ड

क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के बजाय, एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए कुछ धन जमा किया जाना है। एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा जमा राशि तक ही सीमित है। कुछ मामलों में क्रेडिट सीमा बढ़ा दी जा सकती है। कार्डधारक को अपने सुरक्षित क्रेडिट कार्ड की शेष राशि पर मासिक भुगतान करना होगा।

पूर्वदत्त कार्ड

प्रीपेड कार्ड डेबिट कार्ड के समान हैं। अग्रिम में कुछ पैसे के भुगतान के बाद कार्डधारक कार्ड का उपयोग कर सकता है। खर्च सीमा कार्डधारक द्वारा अग्रिम भुगतान की गई राशि तक ही सीमित है। यदि कार्डधारक अधिक क्रेडिट सीमा चाहता है, तो उसे कार्ड में अधिक पैसा लोड करना होगा। जमा राशि से शेष राशि वापस लेने के बाद प्रीपेड कार्ड में वित्त शुल्क या न्यूनतम भुगतान नहीं होते हैं।

बिजनेस क्रेडिट कार्ड

एक कार्ड जिसे विशेष रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है उसे व्यवसाय क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। व्यावसायिक लोगों के लिए व्यापार और निजी नकदी लेनदेन को अलग-अलग बनाए रखने के लिए यह एक आसान तरीका है। भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले 12 प्रमुख प्रकार के क्रेडिट कार्ड हैं। ये कार्ड धारकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं।

भारत में विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्ड

भारत में विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हैं:

- प्रीमियम क्रेडिट कार्ड
- नकद वापस क्रेडिट कार्ड
- गोल्ड क्रेडिट कार्ड
- एयरलाइन क्रेडिट कार्ड
- सिल्वर क्रेडिट कार्ड
- बिजनेस क्रेडिट कार्ड
- बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड
- सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड
- कम ब्याज क्रेडिट कार्ड
- लाइफटाइम मुफ्त क्रेडिट कार्ड
- पुरस्कार

भारत में उपलब्ध क्रेडिट कार्ड को छह श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - अंक, होटल और यात्रा, खुदरा, ऑटो और ईंधन।

क्रेडिट कार्ड की विशेषताएं

ब्याज दर: ब्याज दर किसी भी क्रेडिट कार्ड की प्रमुख विशेषता है। ब्याज दर सीधे क्रेडिट कार्ड पर उधार लेने के लिए भुगतान को प्रभावित कर रही है। आम तौर पर, ब्याज दर वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) के रूप में व्यक्त की जाती है।

मुहलत: कार्ड जारीकर्ता शेष राशि का भुगतान करने के लिए एक अनुग्रह अवधि प्रदान कर सकते हैं। ब्याज अवधि ब्याज शुल्क से बचने के लिए पूरी तरह से अपने क्रेडिट कार्ड की शेष राशि के भुगतान के लिए कार्डधारक को दी गई समय की राशि है। क्रेडिट कार्ड अनुग्रह अवधि सीमा कार्ड जारीकर्ताओं की शर्तों के अधीन है।

सामान्य शुल्क कार्ड जारीकर्ता द्वारा आम तौर पर लिया जाता है। कार्डधारक की क्रेडिट सीमा से अधिक राशि पर ओवर-सीमा शुल्क लिया जाता है। नकद अग्रिम शुल्क चार्ज किया जाता है जब कार्डधारक अपने क्रेडिट कार्ड पर नकद अग्रिम बनाता है। बैलेंस ट्रांसफर शुल्क तब जोड़े जाते हैं जब कार्डधारक अपने क्रेडिट कार्ड में शेष राशि स्थानांतरित करता है।

क्रेडिट सीमाएं: क्रेडिट कार्ड कार्डधारक की अधिकतम खर्च राशि उसके कार्ड का उपयोग कर है। कार्डधारक अपनी क्रेडिट सीमा से अधिक हो सकता है अगर उसने 'ओवर-द-सीमा' विकल्प चुना है। लेनदेन क्रेडिट सीमा से अधिक होने पर सीमा से अधिक शुल्क के लिए शुल्क लिया जाता है।

क्रेडिट कार्ड बनाम डेबिट कार्ड

डेबिट कार्ड	क्रेडिट कार्ड
• व्यय शक्ति ड्राइंग क्षमता पर निर्भर करती है जो डेबिट कार्ड के मामले में बैंक के साथ आपकी अपनी संपत्ति है। • बैंक के साथ खातों में डेबिट कार्ड उतना ही अच्छा है जितना बैंक • ओवरपेन्डिंग का कोई खतरा नहीं है, और इसमें ब्याज भुगतान शामिल नहीं है	• यह बैंक पर उधार लेने की शक्ति की अनुमति देता है, जिसके लिए आपको कुछ शुल्क या शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। • यदि आवश्यक हो तो क्रेडिट कार्ड को आपके ओवरड्राउंग का अतिरिक्त लाभ होता है, बैंक द्वारा खरीद की सीमा तक भुगतान किया जाता है और यदि वे सीमा से अधिक हो जाते हैं, तो ब्याज को अतिरिक्त राशि खर्च पर भुगतान करना होगा। • उधार देना संभव है और अतिदेय राशि पर भुगतान किया जाना ब्याज है।

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के अग्रदूत हैं जो बैंक इंटरनेट के माध्यम से जुड़े बैंक की विभिन्न शाखाओं में सभी नकद खाते को समेकित करते हैं और रसीदों के साथ सबसे अधिक आर्थिक रूप से भुगतान का प्रबंधन करने और प्रभावी नकद को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।

	Travelers' Cheque	**Credit Cards**
• यह क्या है? • द्वारा जारी? • पात्रता • आवधिक क्रेडिट सुविधा	• एक यात्री चेक पूर्व निर्धारित मूल्य के लिए विदेशी मुद्रा में वाहक चेक है। • विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत डीलरों • यात्रियों की जांच करने के लिए हमें अपना पासपोर्ट और एक पुष्टिकरण टिकट प्रस्तुत करना होगा • एक यात्री चेक प्राप्त करते समय चेक करते हैं, इसमें अग्रिम भुगतान या तत्काल डेबिट बैंक खाता शामिल होता है। • यात्रियों की जांच पहले से ही विशेष राशि के लिए तैयार की जाती है, इसे पार नहीं	• एक क्रेडिट कार्ड एक को तुरंत "नकद रहित खरीद" करने और बाद में भुगतान करने में सक्षम बनाता है। • बैंकों • क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए, हम आय और क्रेडिट योग्यता के मामले में बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। • क्रेडिट कार्ड केवल न्यूनतम शेष राशि का भुगतान करते समय एक माह से महीने के आधार पर बकाया राशि को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं। इसे घूमने वाली क्रेडिट सुविधा कहा जाता है। बैंक बकाया राशि के बकाया राशि के लिए ब्याज पर शुल्क लेते हैं। • क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट योग्यता के बैंक के मूल्यांकन के आधार पर पूर्व निर्धारित व्यय सीमा होती है। हम इस सीमा के भीतर खर्च कर सकते हैं और बकाया आगे बढ़ सकते हैं अगर

• पूर्व निर्धारित खर्च सीमा	किया जा सकता है	हम इसे महीने के अंत में भुगतान नहीं कर सकते हैं।

क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लाभ और विपक्ष

लाभ

- **तत्काल नकद:** जब भी और जहां भी आवश्यकता हो, क्रेडिट कार्ड धारक तुरंत नकद प्राप्त कर सकते हैं।
- **सुविधा:** क्रेडिट कार्ड कार्डधारकों के लिए एटीएम की तलाश करने या नकद रखने से समय बचाने के लिए सुविधाजनक और समय बचाने के लिए सुविधाजनक हैं।
- **खरीद शक्ति और खरीद की आसानी:** क्रेडिट कार्ड धारक की खरीद शक्ति क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके क्रेडिट खरीद की अनुमति के कारण बढ़ सकती है। चीजों को खरीदने में आसान बनाता है। माल की खरीद के लिए कार्ड धारक के साथ भारी मात्रा में नकद ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ई-टिकट बुकिंग (ट्रेन, वायु, बस, होटल, रंगमंच, तीर्थस्थरण धारण इत्यादि) के लिए बहुत उपयोगी और आसान है।
- **खरीद की सुरक्षा:** मूल रसीद खो जाने पर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट खरीदारी के लिए वाउचर हो सकता है। कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनी बड़ी खरीद पर बीमा कवरेज की पेशकश कर सकती है।
- **एक अच्छी क्रेडिट योग्यता बनाएँ:** तत्काल भुगतान करने के माध्यम से कार्डधारकों की क्रेडिट योग्यता साबित होती है। ऋण, नौकरियों इत्यादि के लिए आवेदन करने जैसी कुछ परिस्थितियों में कार्डधारक के लिए अच्छी क्रेडिट योग्यता का निर्माण उपयोगी है।
- **आपात स्थिति:** क्रेडिट कार्ड मोटर वाहन किस्त देय, किराया, अस्पताल बिल इत्यादि जैसी कुछ बकाया राशि के लिए कुछ आपातकालीन भुगतान करने में मदद करता है, और यह कार टूटने, बाढ़, आग इत्यादि जैसी आपात स्थिति में भी बहुत उपयोगी होगा।
- **क्रेडिट कार्ड लाभ:** क्रेडिट कार्ड कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं जैसे कि विशेष स्टोर या कंपनियों से छूट, मुफ्त एयरलाइन मील या यात्रा छूट जैसे बोनस, और विशेष बीमा (जैसे यात्रा या जीवन बीमा।)।

विपक्ष

- **उच्च ब्याज दरें:** ऋण की उच्च लागत चार्ज करना क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी कमी है। खरीद, बैलेंस ट्रांसफर, नकदी अग्रिम इत्यादि के लिए ब्याज दर बहुत अधिक है। उच्च ब्याज दर घटक की वजह से ये

ब्याज दरें किसी भी खरीद की वास्तविक लागत को अधिक बनाती हैं। ब्याज की उच्च दर के साथ क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पैसा प्राप्त करना आसान है।

- **भव्य खर्च:** आम तौर पर, जब मानव द्रव्यमान अधिक तरल नकद होता है तो मानव प्रवृत्ति को भारी खर्च करना होता है। क्रेडिट कार्डधारकों को आकर्षक छूट, नकदी वापस इत्यादि जैसे कुछ प्रस्तावों के माध्यम से अधिक पैसे खर्च करने के लिए आसानी से प्रभावित किया जाता है जो कार्डधारकों को अपना कर्ज बढ़ाने के लिए ड्राइव करते हैं।
- **भारी जुर्माना:** क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कार्डधारकों द्वारा किए गए देर से भुगतान के लिए भारी जुर्माना लगा रहे हैं। जारीकर्ता ऋण के पुनर्भुगतान में डिफ़ॉल्ट रूप से कार्डधारकों के खिलाफ दंड के साथ बहुत गंभीर कार्रवाई कर सकता है।

क्रेडिट कार्ड वित्तीय संस्थानों द्वारा पैसे की आसान उपलब्धता बढ़ाने में पेश की गई वित्तीय सेवाओं में एक नया नवाचार है। क्रेडिट कार्ड भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बदल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड तेजी से लोगों की कल्पना को पकड़ रहा है, विशेष रूप से, युवा पीढ़ी एक महान तरीके से। क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक होते हैं जो नकद काउंटर पर पैसे के भुगतान के बिना विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते|

सारांश

म्यूचुअल फंड ऐसे ट्रस्ट हैं जो उचित वित्तीय लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय उपकरणों, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में निवेश करने के उद्देश्य से असंख्य छोटे निवेशकों की बचत को पूल करते हैं। म्यूचुअल फंड छोटी बचत के निवेश के लिए सुविधाजनक बचत और आदर्श एवेन्यू का लाभ प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड एक विविध निवेश अवसर के अलावा, पेशेवर प्रबंधन का लाभ प्रदान करते हैं। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड निवेशकों के विस्तृत स्पेक्ट्रम की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण में खुली और बंद अंत योजनाएं, आय फंड योजनाएं, विकास निधि योजनाएं, इक्विटी फंड योजनाएं, बॉन्ड फंड योजनाएं, गिल्ट फंड, इंडेक्स फंड आदि शामिल हैं। म्यूचुअल फंड की परिचालन दक्षता को फंड के एनएवी द्वारा तय किया जा सकता है ।

अभ्यास प्रश्न

1. म्यूचुअल फंड परिभाषित करें। म्यूचुअल फंड से जुड़े जोखिम क्या हैं?

2. "म्यूचुअल फंड संभावित उद्यमियों को कीमतों, निवेशकों और संसाधनों को सुरक्षा साझा करने की स्थिरता प्रदान करते हैं।" चर्चा करें।

3. म्यूचुअल फंड के निवेशक को कौन से अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध हैं? म्यूचुअल फंड का चयन करने से पहले किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए?

4. म्यूचुअल फंड व्यवसाय को लेने के लिए भारत में वाणिज्यिक बैंक कितने हद तक फिट हैं? इस दिशा में उन्हें क्या समस्याएं आती हैं।

5. नेट संपत्ति मूल्य क्या है? इसकी गणना कैसे की जाती है?

पाठन स्त्रोत

1. Bhatia, B.S., and Batra, G.S., Financial Services, Deep & Deep Publishers, New Delhi.
2. Bansal, L.K., Merchant Banking and Financial Services, Unistar Books Pvt. Ltd., Chandigarh.
3. Bhole, L.M., Financial Institutions and Markets, Tata McGraw Hill, New Delhi.
4. Chandra, P., Financial Management, Tata McGraw Hill, New Delhi.
5. Khan, M.Y., Financial Services, Tata McGraw Hill, New Delhi.
6. Kothari, C.R., Investment Banking and Customer Service, Arihand Publishers, Jaipur.